



DECEMBER 2020

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE

**इंटरफेथ विवाह: "लव जिहाद" को लेकर विवाद
ऐतिहासिक मंदी: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मंदी
स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020
भारत जल प्रभाव 2020
आत्मानिर्भर भारत योजना (ABRY)**

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामयिकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तैयार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट www.iasbaba.com दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – ‘इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए?’

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 67 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें <https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/> से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots** अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।
- इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए snippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक कंट अफेयर्स पर आधारित Prelims MCQs) प्रस्तुत किया है जो आपको बेहतर revision के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- **‘Must Read’ section**, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

‘Must Read’ section: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनुसरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

<https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/>

“Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them.”

विषय सूची (CONTENT)

इतिहास / संस्कृति / भूगोल (HISTORY/CULTURE/GEOGRAPHY)

- अन्नपूर्णा मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जायेगा (Annapurna Idol to be brought back from Canada)
- हम्पी स्टोन रथ (Hampi Stone Chariot)
- ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहर में शामिल किया गया (Gwalior and Orchha included in World Heritage City)
- सिंगापुर की हॉकर संस्कृति मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ (Hawker Culture in Singapore included in UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity)
- तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के लिए मंजूरी प्रदान की (T.N. government gives nod for Jallikattu)
- मध्य प्रदेश सरकार ने जरी-जरदोजीको बढ़ावा देने के लिए 'राग-भोपाली' प्रदर्शनी का आयोजन किया (Madhya Pradesh Government organizes 'Raag-Bhopali' exhibition to promote Zari-Zardozi)

राज्यव्यवस्था/ गवर्नेंस (POLITY/GOVERNANCE)

- गैर-निवासी भारतीय मतदान (NRI Voting)
- कर्नाटक का नया गौहत्या विरोधी बिल (Karnataka's New Anti-Cow Slaughter Bill)
- विदेशी वन्यजीव प्रजातियों के संबंध में SC ने इलाहाबाद HC के फैसले को बरकरार रखा (SC upholds Allahabad HC decision with regard to exotic wildlife species)
- न्याय वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता (Inadequacies of Justice Delivery System)
- संसद का शीतकालीन सत्र इस साल Covid-19 के कारण रद्द हो गया (Winter session Of Parliament cancelled this year due to Covid-19)
- चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की सुविधा को विदेशी और अनिवासी भारतीयों तक पहुँचाने का प्रस्ताव दिया है (Election Commission proposes to extend the facility of postal ballots to overseas and NRIs)
- संसद की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में वृद्धि (Increasing Parliament's efficacy and effectiveness)
- मणिपुर के ZOMI ने ज़ोलैंड प्रादेशिक परिषद के निर्माण की अपनी मांग को नवीनीकृत किया (Manipur's ZOMI renews its demand for the creation of Zoland Territorial Council)
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 356 (A.P. High Court order and Article 356)

सामाजिक मुद्दे/ कल्याण (SOCIAL ISSUE/WELFARE)

- IIT- बॉम्बे ने शहरी गुणवत्ता वाले जीवन सूचकांक को प्रस्तुत किया है (IIT-Bombay comes up with Urban Quality Of Life Index)

- जाति-के अनुसार डेटा के लिए तमिलनाडु आयोग (Tamil Nadu Commission for Cast-wise Data)
- यूपी सरकार ने थारू आदिवासियों के लिए योजना शुरू की (UP government launches scheme for Tharu Tribals)
- वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना)
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई 'स्कूल बैग 2020' नीति (New 'Policy on School Bag 2020' by the Ministry of Education)
- नर्स और मिडवाइफ (Nurses and midwives)
- कच्छ क्षेत्र में विकास परियोजनाएं (Development Projects In Kutch Region)
- प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (Prime Minister's Special Scholarship Scheme-PMSSS)
- आठ सदस्यीय समिति ने आईआईटी में आरक्षण पर सिफारिशें करती है (Eight-member committee makes Recommendations on Reservation in IITs)
- मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 (Human Freedom Index 2020)
- IIT और आरक्षण में शिक्षक के रिक्त पद (Teacher vacancies at IITs and reservation)
- मध्यप्रदेश में मातृ सहयोगिनी समिति के लिए आदेश जारी (Order issued for Matru Sahyogini Samiti in MP)
- ई-सम्पदा: एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया (E-Sampada: A new Web Portal and Mobile App launched)

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे (WOMEN ISSUE)

- महाराष्ट्र कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा से सम्बंधित बिल का प्रस्ताव दिया (Bills proposing death penalty for rape approved by Maharashtra cabinet)
- वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)

स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दे (HEALTH ISSUE)

- विश्व एड्स दिवस 2020 (World AIDS Day 2020)
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance)
- इन्फ्लुएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है: स्वीडन का कारोलींस्का संस्थान (Influenza makes people more susceptible to bacterial infections: Sweden's Karolinska Institute)
- यूएन ने कैनबिस को एक खतरनाक नार्कोटिक नहीं माना है (UN Decides Cannabis Not A Dangerous Narcotic)
- द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस (टीसीजीए) का उद्घाटन (The 2nd Cancer Genome Atlas (TCGA) inaugurated)
- IRDAI रोबोटिक और बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए स्वास्थ्य नीतियों का मानकीकरण करता है (IRDAI standardises health policies for Robotic and bariatric surgeries)

- भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन HGCO19 को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी (HGCO19: India's first indigenous mRNA vaccine candidate receives approval)
- 5 वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जारी किया गया (5th National Family Health Survey (NFHS) released)
- प्लास्मिडियम ओवले: असामान्य प्रकार का मलेरिया (Plasmodium Ovale: Uncommon type of Malaria)
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए लांसेट नागरिक आयोग (Lancet Citizens' Commission for Universal Health Coverage)
- विज़न 2035: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी (Vision 2035: Public Health Surveillance In India)
- हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों के लिए मान्यता योजना की शुरुआत (Recognition Scheme for Hygiene Rating Audit Agencies)
- गैल्सेफ सूअर को एफडीए द्वारा अनुमोदन (GalSafe Pigs approved by FDA)
- B.1.1.7 वंश: SARS-CoV-2 का नया संस्करण (B.1.1.7 Lineage: New variant of SARS-CoV-2)
- NFHS डेटा को पढ़ना (Reading NFHS data)
- केरल में शिगेला (Shigella) के विरुद्ध निवारक उपायों की शुरुआत हुई (Preventive measures started against Shigellosis in Kerala)
- डब्ल्यूएचओ की 2019 की वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान (WHO's 2019 Global Health Estimates)
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत की शुरुआत करेंगे, योजना में जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा (PM to launch Ayushman Bharat PM-JAY SEHAT to extend coverage to all residents of J&K)
- अंटार्कटिका में कोरोनावायरस (Coronavirus In Antarctica)
- एक प्रभावी टीकाकरण वितरण नीति की ओर (Towards an effective vaccination distribution policy)
- औषधीय पादप के लिए NMPB कंसोर्टिया (NMPB Consortia For Medicinal Plants)
- न्यूमोसिल: पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumosil: First pneumococcal conjugate vaccine)
- भारत में पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम में अच्छे, रिप्लेकेबल प्रैक्टिस और इनोवेशन पर नेशनल समिट (National Summit On Good, Replicable Practices And Innovations In Public Healthcare Systems In India)
- पहली स्वदेशी रूथेनियम -106 के रूप में नेत्र कैंसर चिकित्सा

सरकारी योजनाएँ (GOVERNMENT SCHEMES)

- मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरा प्रोत्साहन पैकेज (Third stimulus package for Mission Covid Suraksha)
- शहद मिशन में शामिल हुए प्रवासी श्रमिक (Migrant workers engaged in Honey Mission)
- आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जायेगी (Ayush Export Promotion Council to be set up)
- आत्मनिर्भर भारत योजना (ABRY) को मंजूरी (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) approved)

- पीएम स्वीनिधि की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा का कार्यक्रम शुरू (Programme of Socio-Economic Profiling of PM SVANidhi launched)
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया (Indigenous Games to be a part of Khelo India Youth Games 2021)
- अनुसूचित जाति से सम्बंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) में बदलाव की मंजूरी (Post Matric Scholarship To Students Belonging To Scheduled Castes - PMS-SC)
- जल गुणवत्ता परीक्षण इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया (Water Quality Testing Innovation Challenge launched)
- भारतीय कौशल संस्थान, मुंबई में उद्घाटन हुआ (Indian Institute Of Skills, Mumbai inaugurated)
- नामघर को वित्तीय अनुदान वितरित किया गया (Financial grants distributed to Namghars)
- 34वीं प्रगति सहभागिता का आयोजन (34th PRAGATI interaction held)
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM SVANIDhi योजना (PM SVANidhi scheme for street vendors)

अंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL)

- ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या (Assassination of Iranian Nuclear Scientist)
- क्षेत्रीय प्राथमिकताएं: SCO शिखर सम्मेलन में (Regional priorities: On the SCO summit)
- SCO ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया (SCO Online International Exhibition launched)
- समाचार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्थल-भूभाग चार द्वीप (Place in news: Bhashan Char Island)
- फ्रांस का नया सुरक्षा कानून (France's New Security Law)
- पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विशेष चिंता का विषय बने देशों (कंटीज ऑफ पर्टीक्यूलर कंसर्न या सीपीसी) के लिए नामित (Pakistan and China designated among countries of Particular Concern by the USA)
- मोरक्को ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए (Morocco Normalises Relations with Israel)
- फेसबुक के खिलाफ अभियोग मुकदमा (Antitrust suit against Facebook)
- मोरक्को-इजराइल सौदा (Morocco-Israel deal)
- क्यूबा में सैन इसिद्रो आंदोलन (San Isidro Movement in Cuba)
- रोहिंग्या शरणार्थी: बांग्लादेश उन्हें स्थानांतरित कर रहा है (Rohingya Refugees: Bangladesh Relocating them)
- चीन का ब्रह्मपुत्र बांध: दक्षिण एशिया में ट्रांस-बॉर्डर वॉटर गवर्नेंस (China's Brahmaputra dam: Trans-boundary water governance in South Asia)
- भारत-बांग्लादेश वर्चुअल समिट आयोजित (India-Bangladesh Virtual Summit held)
- भारत ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) को 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वादा किया (India pledges a sum of USD 1 million to the World Anti-Doping Agency - WADA)

- Fordow ईंधन संवर्धन संयंत्र (Fordow Fuel Enrichment Plant -FFEP)
- तुर्की द्वारा पारित सामूहिक विनाश बिल के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकना (Preventing Financing Of Proliferation Of Weapons Of Mass Destruction bill passed by Turkey)

भारत और विश्व (INDIA AND THE WORLD)

- भारत-वियतनाम वार्ता हुई (India-Vietnam Talks held)
- ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करेगा चीन (China gives 'go ahead' for New Dam on Brahmaputr)
- भारत ने ADMM-PLUS बैठक में भाग लिया (India attends ADMM-PLUS Meeting virtually)
- चाबहार बंदरगाह पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच TWG बैठक (TWG meeting held between India, Iran, and Uzbekistan on Chabahar port)
- भारत संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में 131 वें स्थान पर है (India ranks 131 in 2020 UN Human Development Index)
- भारत – बांग्लादेश (India – Bangladesh)
- भारत-वियतनाम नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-Vietnam Leaders' Virtual Summit)
- मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी (Cabinet approves MoU between India and Bhutan on Cooperation in the peaceful uses of outer space)
- कैबिनेट ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिकन में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी (Cabinet approves Opening of 3 Indian Missions in Estonia, Paraguay and Dominican Republic)

अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

- ऐतिहासिक मंदी: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मंदी
- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर (International Association of Insurance Supervisors- IAIS))
- मुनि बांड्स (Muni Bonds)
- आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्यमी (Aatmanirbhar Bharat & Small Entrepreneurs)
- इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता (Invest India wins UN Investment Promotion Award)
- भारत और बेटर दैन कैश अलाउंस (Better Than Cash Alliance) के बीच आयोजित फिनटेक समाधान पर पीयर लर्निंग एक्सचेंज (Peer learning exchange on fintech solutions held between India and Better Than Cash Alliance)

- वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (RTGS) अब चौबीसों घंटे लेनदेन के लिए उपलब्ध है (Real Time Gross Settlement System (RTGS) now available for round the clock transactions)
- भारतीय कंपनियों में विविधता की आवश्यकताएं (Diversity Requirements In Indian Companies)
- पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना (Special Assistance To States For Capital Expenditure Scheme)
- हस्तशिल्प एवं जीआई खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट मिली (Handicraft And GI Toys Exempted From Quality Control Order)
- नए WTO D-G के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां (The many challenges for new WTO D-G)
- अग्रिम मूल्य समझौते (Advance pricing agreements (APAs))
- यूएस वॉच इंडिया ऑन करेंसी वॉचलिस्ट (US Puts India on Currency Watchlist)
- 'करेंसी मैनिपुलेशन' (Currency manipulation)
- केयर्न आर्बिट्रेशन केस (Cairn Arbitration case)
- विस्ट्रॉन (Apple आपूर्तिकर्ता) हिंसा (Wistron (Apple Supplier) Violence)
- वडोदरा नगर निगम (VMC) जनवरी 2021 में नगरपालिका बांड लॉन्च करने के लिए (Reviving the economy: 3C approach to atmanirbharta)
- अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना: 3C आत्मनिर्भर दृष्टिकोण (Reviving the economy: 3C approach to atmanirbharta)
- शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और नगर निगम बांड (Urban Local bodies (ULBs) & Municipal Bonds)
- सरकार ने जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यवसाय परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य करती है (Government introduces mandatory physical verification of business premises for GST registration)
- 1000 वर्ष पुरानी हस्तनिर्मित कागज उद्योग 'मोनपा' को जिंदा किया गया है (1000-yrs Old Monpa Handmade Paper Industry brought alive in AP)
- 4% पर मुद्रास्फीति लक्ष्य भारत के लिए उपयुक्त है: RBI (Inflation Target at 4% is appropriate for India: RBI)
- पंजाब और सिंध बैंक को पुनर्पूँजीकृत करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड (Zero Coupon bonds to recapitalise Punjab & Sind Bank)
- लचीला आपूर्ति चेन (Resilient Supply Chains)

कृषि (AGRICULTURE)

- हनी किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का NAFED द्वारा उद्घाटन किया गया है। Honey FPO Programme inaugurated under NAFED)
- दिल्ली चलो किसान विरोध प्रदर्शन (Dilli Chalo Farmers Protest)
- किरो ऑफ जीरो वैली (Kiwis Of Ziro Valley)

- नीति निर्माण और कृषि विरोध (Policy Making and Farm Protests)
- पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध (Punjab & Haryana farmers' protests)
- किसान विरोध: पारिश्रमिक फसल के पैटर्न की जरूरत (Farmer's Protest: Remunerative Cropping Patterns needed)
- लक्षद्वीप ने एक ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया (Lakshadweep Declared an Organic Union Territory)
- किसान प्रोटेस्ट: असफल वार्ता (Farmer's Protest: Failed Negotiations)
- एमएसपी - मिथक बनाम तथ्य (MSP — the factoids versus the facts)
- 100 वीं किसान रेल को हाल ही में रवाना किया गया (100th Kisan Rail flagged off recently)

पर्यावरण प्रदूषण (ENVIRONMENT/POLLUTION)

- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति (AIPA) का गठन (Apex Committee For Implementation Of Paris Agreement (AIPA) constituted)
- भारतीय मयूर सोफ्टशेल कछुए को बचाया गया (Indian Peacock Softshell Turtle rescued)
- 2050 तक भारत में मलायन विशालकाय गिलहरी की संख्या 90% तक गिर सकती है: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (Malayan Giant Squirrel could decline by 90% in India by 2050: Zoological Survey of India -ZSI)
- समाचारों में प्रजाति: हाउबारा बस्टर्ड्स (Species in news: Houbara Bustards)
- उत्तराखंड में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए पहला इको-ब्रिज (First eco-bridge for reptiles and smaller mammals in Uttarakhand)
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में भारत शीर्ष 10 में (India in top 10 in Climate Change Performance Index -CCPI)
- गोवा में वैज्ञानिकों द्वारा स्पॉट की गई भारतीय मुरिंग्रास की नई प्रजातियां (New species of Indian Muraingrasses spotted by scientists in Goa)
- सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन (SMDS) शुरू हुआ (Sustainable Mountain Development Summit (SMDS) begins)
- जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020 आभासी रूप से आयोजित किया गया (Climate Ambition Summit 2020 held virtually)
- पेरिस जलवायु सौदा: भारत की प्रगति, महामारी और चुनौतियां Paris Climate Deal: India's Progress, Pandemic and Challenges
- भारत जल प्रभाव 2020 (India Water Impact 2020)
- 12 वीं GRIHA (एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग) शिखर सम्मेलन (12th GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) Summit)

- दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए चार-सूत्रीय कार्य योजना (A four-point action plan to improve Delhi's air)
- सेंटिनल द्वीप का कोई भी दोहन आदिवासियों का विनाश कर देगा: एएनएसआई (Any exploitation of Sentinel Island will wipe out tribals: AnSI)
- उष्णकटिबंधीय मॉन्टेन ग्रासलैंड (TMG) में पहचाने जाने वाले घास के मैदान की बहाली और संरक्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्र (Areas suitable for grassland restoration and conservation identified in Tropical Montane Grasslands -TMG)
- गैस्ट्रोडिया एगनिकेलस को दुनिया का सबसे बदसूरत आर्किड कहा जाता है (Gastrodia Agnicellus named as the ugliest orchid in the world)
- बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Centre For Monkeys)
- JSA II: कैच द रेन" अवेयरनेस जनरेशन अभियान प्रारंभ (JSA II: Catch The Rain Awareness Generation Campaign)
- भारत में 75% जिले चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं (75% districts in India hotspots of extreme climate events)
- त्सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42 वां रामसर साइट बन गया (Tso Kar Wetland Complex becomes India's 42nd Ramsar site)
- व्हेल गीत (Whale Songs)
- अंटार्कटिक हिमखंड A68 दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के लिए चिंता का कारण बन गया है (Antarctic iceberg A68 becomes cause for concern for South Georgia Island)
- पोर्टुलका लालजी: वाइल्ड सन रोज (जंगली सूरज गुलाब) की एक नई प्रजाति (Portulaca Laljii: A new species of wild sun rose)

जीव - जंतु/ समाचारों में राष्ट्रीय पार्क (ANIMALS/NATIONAL PARKS IN NEWS)

- जेब्राफिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया गया है और ऐसे जीन की पहचान की है जो हृदय उत्थान को बढ़ावा दे सकते हैं (Zebrafish being used as a research model to promote heart regeneration)
- पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता (Pilibhit Tiger Reserve bags international award TX2)
- ट्रांसबाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र को संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया (The Transboundary Manas Conservation Area receives the Conservation Excellence Award, 2020)
- दो नए चिड़िया घरों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी (Two New Zoos Granted Recognition by Central Government)
- मायारिस्टिका स्वाम्प ट्रीफ्रॉग' (Myristica swamp Treefrog) की उपस्थिति को पहली बार दर्ज किया गया

- समाचार में प्रजातियां: हिमालयन सीरो (Species in news: Himalayan Serow) खबरों में प्रजातियां: भारतीय गौर (Species in news: Indian Gaur)
- तेंदुए की स्थिति 2018' रिपोर्ट जारी (Status Of Leopards Report released)
- असम के मिनी काजीरंगा में एक सींग वाले गैंड गैंडों में प्रतिस्पर्धा (Cattle competing one-horned rhino's in Assam's Mini Kaziranga)
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु 'फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर' (Firefly bird diverters for Great Indian Bustards)

अवसंरचना/ऊर्जा (INFRASTRUCTURE/ENERGY)

- पेट्रोलियम बोर्ड की नई एकीकृत प्रशुल्क संरचना (Petroleum Board's notifies New Unified Tariff Structure)
- शहरी क्षेत्रों के लिए DUET (विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण) (DUET (Decentralised Urban Employment and Training) for urban areas)
- फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के तकनीकी विनिर्देशों के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी (Draft Guidelines Of Technical Specifications Of Floating Structures)
- बांग्लादेश द्वारा प्रथम अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर (Bangladesh Signs First Preferential Trade Agreement-PTA)
- सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क()
- पीएम वाणी योजना (PM WANI Scheme)
- रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन: ग्रीन पावर मार्केट पर दांव लगाना (Renewable Energy Generation: Betting on the green power market)
- पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना Comprehensive Telecom Development Plan (CTDP) For North Eastern Region (NER) approved
- KLI प्रोजेक्ट: सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का प्रावधान (KLI Project: Provision of Submarine Optical Fibre Cable Connectivity)
- भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना (Indian Railways launches Hospital Management Information System -HMIS)
- भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा (Draft Indian Ports Bill, 2020)
- 'डाकपे' नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप (DakPay: New digital Payment App)
- आईएफएससीए ने प्रस्तावित एयरक्राफ्ट लीजिंग विनियमों पर परामर्श पत्र जारी किया (IFSCA issues consultation paper on proposed Aircraft Leasing Regulations)
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की समीक्षा (National Hydrology Project reviewed)
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान को मंजूरी (Revised Cost Estimate of North Eastern Region Power System Improvement Project (NERPSIP) approved)

- भारत सरकार और एनडीबी के बीच 100 करोड़ डॉलर का समझौता, इसके जरिए आत्म निर्भर अभियान के तहत मनरेगा स्कीम में वित्तीय सहयोग दिया जाएगा(Government of India and New Development Bank sign a loan agreement for \$1,000 million to provide support to Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan through MGNREGS)
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी (Proposal of Spectrum Auction approved)
- दूरसंचार क्षेत्र के लिये नए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (Cabinet Committee on Security approves the setting up of a new National Security Directive)
- भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा जारी किया (Indian Railways issues draft National Rail Plan)
- परिवहन मंत्रालय ने ई 20 ईंधन को अपनाने के संदर्भ में जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की (Government publishes a draft notification on E20 Fuel)
- जीपीएस आधारित टोल संग्रहण व्यवस्था (GPS-Based Toll Collection System)
- तटीय रडार चेन नेटवर्क स्थापित करने के लिए उन्नत चरणों में प्रयास(Efforts in advanced stages to set up Coastal Radar Chain Network)
- भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की परियोजना पर हस्ताक्षर किए ((India and World Bank sign USD 500 million worth project for Green National Highway Corridors))
- बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उत्पाद विशेष माल गोदाम/साइलो होंगे (Products Specific Warehouses/Silos to come up at Ports and National Waterways)
- भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो (India's First Driverless Metro to be inaugurated)
- असम में 27 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन (Foundation stone for highway projects in Assam inaugurated)
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का उद्घाटन(National Common Mobility Card (NCMC) inaugurated)
- जैव ईंधन कैसे कृषि आय को दोगुना कर सकती हैं(How biofuels can double farm incomes)
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के 'न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा सेक्शन' का उद्घाटन(New Bhaupur-New Khurja Section of Eastern Dedicated Freight Corridor)
- प्रधानमंत्री ने छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) की आधारशिला रखी PM to lay Foundation Stone of Light House Projects under GHTC-India
- बिजली के वाहन (Electric Vehicles)

विज्ञान और तकनीक (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

- CSIR-CCMB को ड्राई स्वेब RT-PCR कोविड -19 टेस्ट की अनुमति मिली (CSIR-CCMB gets permission for Dry Swab RT-PCR Covid-19 Test)
- C32-LH2 टैंक: सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को दिया गया (C32-LH2 Tank: Biggest cryogenic propellant tank delivered to ISRO)
- अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्न ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के लिए आवेदन किया (US drugmaker Moderna applies for Emergency Use Authorisation -EUA)
- 'डमरू'इंस्पायर्ड लैटिस (Damaru' Inspired Lattice)
- आर्टपार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया (Artpark set up in Bengaluru)
- ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (ASKAP) लाखों आकाशगंगाओं का मानचित्र बनाता है (Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) maps millions of galaxies)
- HL-2M टोकामक: चीन का कृत्रिम सूर्य (HL-2M Tokamak: The Artificial Sun of China)
- भारत और प्रौद्योगिकी के भू-राजनीति (India and the geopolitics of technology)
- जापान का हायाबुसा 2 मिशन वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है (Japan's Hayabusa2 Mission set to return back to Earth)
- सिंगापुर एजेंसी ने लैब-ग्रोन मीट के बिक्री को मंजूरी दी (Singapore Agency approves sale of Lab-Grown Meat)
- बृहस्पति व शनि ग्रह के मिलन की अब्दुत खगोलीय घटना (Jupiter and Saturn to be seen in Great Conjunction)
- BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड-IoT की घोषणा की (BSNL announces Satellite-Based Narrow Band-IoT)
- भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV-C50 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया (India's communication satellite CMS-01 was successfully launched by PSLV-C50)
- 'चांग ई 5' मिशन चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लेकर लौटा (Chang'e 5 returns with first fresh rock samples from the moon)
- इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन : आरंभिक आँकड़े सार्वजनिक रूप से जारी किये (ISRO released to public the initial data from Chandrayaan-2)
- BBX11: एक जीन जो पौधों की हरियाली में सुविधा प्रदान करता है (BBX11: A gene that facilitates in the greening of plants)
- वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला संभव रेडियो संकेत पाया (Scientists find first possible radio signal from a planet beyond our solar system)
- यूके में कोरोनावायरस वैरिएबल परिसंचारी कई म्यूटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है (Coronavirus variant circulating in the UK defined by many mutations)
- संयुक्त राज्य अमेरिका की चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की योजना है (USA's plan to have Nuclear Reactor On Moon)

- डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया (Digital Ocean web-based application inaugurated)
- प्रॉक्सीमा सेन्टॉरी की दिशा से रेडियो तरंग उत्सर्जन का पता चला (Radio wave emission detected from the direction of Proxima Centauri)

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा (DEFENCE/INTERNAL SECURITY/SECURITY)

- MARCOS को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा रहा है (MARCOS being deployed in the Eastern Ladakh)
- सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (रणनीति) की मंजूरी दी (Government approves Deputy Chief of Strategy post)
- खालिस्तान की धमकी: लगातार सतर्कता की जरूरत (Khalistan threat: Need for Constant vigilance)
- यूएस ने एस -400 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों के अधिग्रहण पर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है (USA imposes sanctions on Turkey over S-400 Air Defence Missile System)
- स्वदेशी रूप से विकसित DRDO प्रणाली सेना, नौसेना और वायु सेना को सौंपी गई (Indigenously developed DRDO systems handed over to Army, Navy and Air Force)
- सोलर विंड्स हैक: संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया एक साइबरहमला (SolarWinds Hack: A cyberattack discovered in the USA)
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी देती है (The Defence Acquisition Council (DAC) approves proposals to procure equipment)
- मीडियम रेंज सतह से मिसाइल (MRSAM) लॉन्च की गई (Medium Range Surface To Air Missile (MRSAM) launched)
- बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज (Baroda Military Salary Package)
- भारतीय सेना ने कामोव -226 टी हेलिकॉप्टरों सौदे को आगे बढ़ाने के लिए एक छूट का अनुरोध किया है (Indian Army to request waiver to take Kamov-226T Utility Helicopters)
- अमेरिकी साइबर हमला: सोलर विंड हैक (US Cyber Attack: SolarWinds hack)
- कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी (Cabinet Approves Export of Akash Missile System)

विविध (MISCELLANEOUS)

अपने ज्ञान का परीक्षण करें (TEST YOUR KNOWLEDGE)

दिसम्बर 2020 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

इतिहास / संस्कृति / भूगोल (HISTORY / CULTURE / GEOGRAPHY)

अन्नपूर्णा मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जायेगा (Annapurna Idol to be brought back from Canada)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I – संस्कृति और और GS- II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- लगभग एक शताब्दी पहले भारत से चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा को भोजन की देवी माना जाता है।
- बनारस शैली में उकेरी गई 18 वीं शताब्दी की मूर्ति, रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित है, यह मैकेंजी आर्ट गैलरी में कनाडा के संग्रह का हिस्सा है।



क्या आप जानते हैं?

- कुछ हफ्ते पहले, भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की 13 वीं शताब्दी की कांस्य मूर्तियों को हाल ही में यूके ने तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया था।
- 2014 से 2020 के बीच, सरकार विभिन्न देशों से 40 पुरावशेषों (antiquities) को पुनः प्राप्त करने में सक्षम रही है।
- 1976 और 2014 के बीच, ASI के रिकॉर्ड के अनुसार, 13 प्राचीन टुकड़े भारत में वापस लाए गए थे।

हम्पी स्टोन रथ (Hampi Stone Chariot)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-I - मंदिर और वास्तुकला

समाचार में

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कर्नाटक के हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर विटला मंदिर परिसर के अंदर पत्थर के रथ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं।
- पर्यटक अब प्रतिष्ठित पत्थर के रथ के बहुत करीब नहीं जा सकते।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन (Important value addition)

हम्पी रथ

- मंदिर परिसर के अंदर स्थित रथ गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है, लेकिन वर्तमान में गरुड़ की मूर्ति गायब है।
- हम्पी रथ, भारत के तीन प्रसिद्ध पत्थर से निर्मित रथों में से एक है।
- अन्य दो रथ कोणार्क (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में हैं।
- इसे 16 वीं शताब्दी में एक विजयनगर शासक, राजा कृष्णदेवराय के निर्देश से बनाया गया था।
- हम्पी में कलात्मक नक्काशीदार रथ, विजयनगर शासकों के संरक्षण में मंदिर वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है, जिन्होंने 14 से 17 वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था।



विट्टल मंदिर

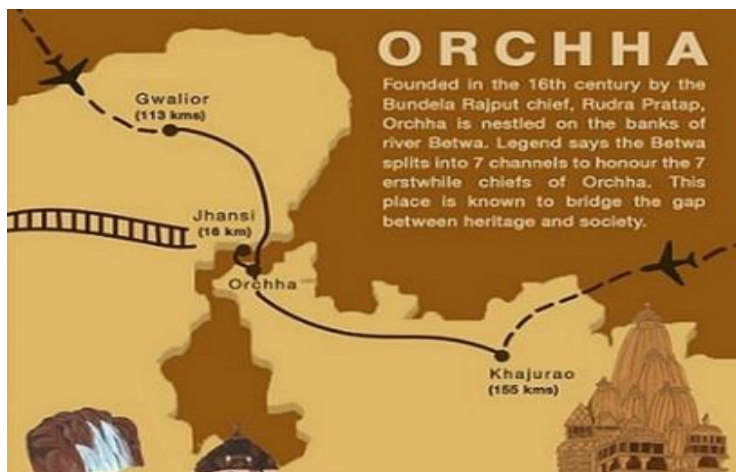
- इसे 15 वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासन के दौरान निर्मित किया गया था।
- यह विट्टला को समर्पित है।
- विट्टल को भगवान विष्णु का एक अवतार कहा जाता है।
- द्रविड़ियन शैली इस जटिल संरचना के निर्माण को सुशोभित करती है, जिसे विस्तृत नक्काशी के साथ आगे बढ़ाया गया है।

ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहर में शामिल किया गया (Gwalior and Orchha included in World Heritage City)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I - समाज; संस्कृति; इतिहास

समाचार में

- मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है।



महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन (Important value addition)

ओरछा

- ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है।
- ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है।
- यह 16 वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी।
- शहर के प्रसिद्ध स्थान राज महल, जहांगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मीनारायण मंदिर हैं।
- विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद, मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्रबाहु मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का रासायनिक उपचार (chemical treatment) किया जाएगा, ताकि उन पर अंकित कला और अधिक दृश्यमान (more visible) हो जाए।

ग्वालियर

- ग्वालियर की स्थापना 9 वीं शताब्दी में हुई थी।
- इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहो और सिंधिया का शासन था।
- उनके द्वारा छोड़े गए संस्मरण क्षेत्र में स्मारक, किले और महल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- यह अपने महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसमें जटिल नक्काशीदार सास बहू का मंदिर भी शामिल है।
- ग्वालियर का किला शहर के ऊपर स्थित एक बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है और पवित्र जैन मूर्तियों के साथ एक घुमावदार सड़क के माध्यम से यंहा पहुँचा जा सकता है।
- किलों के भीतर ऊँची दीवारों पर 15 वीं सदी का गुजरी महल स्थित है, जो वर्तमान में यह एक पुरातात्विक संग्रहालय है।

संबंधित आलेख:

- हमपी हेरिटेज साइट: [Click here](#)

सिंगापुर की हॉकर संस्कृति मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ (Hawker Culture in Singapore included in UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- I- संस्कृति और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) ने अंतर-सरकारी समिति के 15वें सत्र में 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति (Hawker Culture) को शामिल किया है।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन(Important value additions)

सिंगापुर में हॉकर संस्कृति

- सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति (Living Heritage) है जो स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है।
- यह सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक पहचान (Multicultural Identity) को एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में दर्शाती है तथा सभी जातियों व सामाजिक स्तरों से परे सिंगापुर की यह पहचान दृढ़ता के साथ प्रदर्शित होती है।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची

- यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
- यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी।
- यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

13 ICH traditions recognised by UNESCO			
1.	Tradition of Vedic chanting, 2008	8.	Buddhist chanting of Ladakh: recitation of sacred Buddhist texts in the trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir, India, 2012
2.	Ramlila, the traditional performance of the Ramayana, 2008	9.	Sankirtana, ritual singing, drumming and dancing of Manipur, 2013
3.	Kutiyattam, Sanskrit theatre, 2008	10.	Traditional brass and copper craft of utensil making among the Thatheras of Jandiala Guru, Punjab, India, 2014
4.	Ramman, religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India, 2009	11.	Yoga, 2016
5.	Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala, 2010	12.	Nowruz, 2016
6.	Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan, 2010	13.	Kumbh Mela, 2017
7.	Chhau dance, 2010		

- संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने भी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची (National List of Intangible Cultural Heritage) का मसौदा लॉन्च किया है

संबंधित आलेख:

- संस्कृति से संबंधित शब्द: [Click here](#)

तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के लिए मंजूरी प्रदान की (T.N. government gives nod for Jallikattu)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I- संस्कृति

समाचार में

- तमिलनाडु सरकार ने आगामी फसल उत्पादन के त्योहार पोंगल के लिए जल्लीकट्टू को राज्य भर में आयोजित करने की अनुमति प्रदान के दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- खेल COVID-19 महामारी को देखते हुए यह आयोजन नए प्रतिबंधों के अधीन होगा।
- बैल को काबू करने वाले 300 से अधिक खिलाड़ियों को जल्लीकट्टू, 'मंजुविरट्टु' या 'वदामादु' कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम हेतु प्रचलित COVID-19 महामारी के संबंध में सभी आवश्यक सावधानियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन (Important value additions)

- जल्लीकट्टू को बुल टैमिंग इवेंट या बैल को काबू करने वाले त्यौहार के रूप में जाना जाता है।
- पोंगल के एक भाग के रूप में, इसे तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है।
- 'जल्लीकट्टू' तमिल शब्द से लिया गया है, जली का अर्थ सोने या चांदी के सिक्कों को संदर्भित करता है, कट्टू का अर्थ है 'बंधा हुआ' है।
- संगम साहित्य (2500 साल पहले) में इसका उल्लेख है।
- यह विवादास्पद है क्योंकि खेल में अक्सर अत्यंत गंभीर चोट लगती है और यहां तक कि इन चोटों के कारण बैल और मनुष्यों दोनों की मृत्यु हो जाती है।
- 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board of India- AWBI) और पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (People for Ethical Treatment of Animals- PETA) की याचिकाओं के जवाब में जानवरों के प्रति क्रूरता का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया था।
- संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि नागरिकों को वन्यजीवों और जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और जीवित प्राणियों के लिए दया करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार ने जरी-जरदोजीको बढ़ावा देने के लिए ' राग-भोपाली ' प्रदर्शनी का आयोजन किया (Madhya Pradesh Government organizes 'Raag-Bhopali' exhibition to promote Zari-Zardozi)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I- संस्कृति

समाचार में

- मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के जरी-जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए 'राग-भोपाली' प्रदर्शनी का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन (Important value additions)

- धातु के धागों से की गई कढ़ाई को कलाबटू (kalabattu) कहा जाता है और इससे जरी का निर्माण किया जाता है।
- जरी का मुख्य उत्पादन केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश है।

प्रक्रिया

- धातु की सिल्लियों को पिघला कर धातु की सलाखों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पासा कहा जाता है, इसके बाद इसको पीट कर लम्बे धागे प्राप्त किये जाते हैं।
- फिर इसे छिद्रित स्टील प्लेटों के माध्यम से खींचा जाता है ताकि इसे तारों में बनाया जा सके, इसके बाद इसे रबर और हीरे से पतला करने के लिए तारकशी प्रक्रिया होती है।
- अंतिम चरण को बिल्ला कहा जाता है जहाँ तार को चपटा किया जाता है और रेशम या सूती धागे से कासब या कलाबटू (kalabattu) का निर्माण किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के जरी के काम

- **जरदोजी:** यह एक भारी और अधिक भव्य कशीदाकारी कार्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वर्ण तार, सितारे, मनके, मोती, तार और गोटा प्रयोग किया जाता है।
- इसका प्रयोग वैवाहिक पहनावे, भारी कोटों, गद्दीयां, पर्दे, चंदोवे, पशु साज-समान, थैले, पर्स, बेल्ट तथा जूतियां सजाने-संवारने में होता है।
- **कामदानी:** यह एक हल्का सिलाई-कढ़ाई कार्य है जो हल्की सामग्री जैसे स्कार्फ, बुर्के, तथा टोपियों पर की जाती है। साधारण धागा प्रयोग किया जाता है तथा तार को सिलाई के साथ नीचे दबा दिया जाता है जो साटिन सिलाई प्रभाव उत्पन्न करता है।
- **मीना कार्य:** इसे ऐसा इसकी मीनाकारी से समानता होने के कारण कहा जाता है।
- कशीदाकारी स्वर्ण में की जाती है।

राजव्यवस्था/ गवर्नेंस (POLITY/GOVERNANCE)

गैर-निवासी भारतीय (NRI) मतदान (NRI Voting)

संदर्भ:

- चुनाव आयोग (ईसी) ने सरकार से गैर-निवासी भारतीय (NRI) को पोस्टल बैलट (डाक-मतपत्र) के जरिये अपना वोट डालने की अनुमति देने के लिए कानून मंत्रालय से संपर्क किया है।

- भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) ने कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया है कि वह अगले वर्ष असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) का प्रयोग गैर-निवासी भारतीय (NRI) के लिये करने हेतु "तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है"।

विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया क्या है?

- एक NRIs पासपोर्ट में उल्लेखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है।
- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये उसे अपने पासपोर्ट की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- NRIs के लिये मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2011 में पुरःस्थापित किया गया था।

NRIs मतदाताओं के पास वर्तमान शक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रवासी आबादी विश्व में सबसे ज्यादा (16 मिलियन) है।
- यद्यपि भारत में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत एक लाख से कुछ ही अधिक प्रवासी भारतीयों के साथ NRI मतदाताओं का पंजीकरण बहुत कम है।
- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में उनमें से लगभग 25,000 लोग मतदान करने के लिये भारत आए।

अगर यह मंजूरी मिल जाती है, तो NRI के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की प्रक्रिया:

- पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले किसी भी NRI को चुनाव की अधिसूचना के पाँच दिन के अंदर मतदान के बारे में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer-RO) को सूचित करना होगा। संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का RO संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिये जिम्मेदार होता है।
- इस तरह की सूचना प्राप्त करने के बाद RO इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैलेट पेपर भेजेगा।
- NRI मतदाता बैलेट पेपर का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपनी पसंद को चिह्नित करेंगे और इसे देश के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र के साथ वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ का वह NRI निवासी है।
- इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय, मतदाता साधारण डाक के माध्यम से मतपत्र को वापस कर देगा या उसे भारतीय दूतावास में पहुँचाना होगा, जो तब लिफाफो को निर्वाचन क्षेत्र अनुसार अलग कर सकता है और उन्हें RO को अग्रेषित करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज सकता है।

इस प्रस्ताव की उत्पत्ति कैसे और कब हुई?

- चुनाव आयोग ने NRI को विदेश से वोट देने के लिए सक्षम करने के लिए विकल्पों की तलाश शुरू की, इसके बाद कई उन्हें इस सन्दर्भ में कई अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें एक पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल और विदेश मंत्रालय द्वारा

प्राप्त हुआ था, और 2013 और 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में अनिवासी भारतीयों द्वारा तीन रिट याचिकाएं दायर की गई थीं।

- मुख्य रूप से तीन विकल्पों का अध्ययन करने के लिए 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद एक 12-सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी - डाक द्वारा मतदान, विदेश में भारतीय मिशनो पर मतदान और ऑनलाइन वोटिंग।
- 2015 में पैनल ने समिति से सिफारिश की कि NRIs को व्यक्तिगत रूप से मतदान के अलावा "ई-पोस्टल बैलट और प्रॉक्सी वोटिंग जैसे अतिरिक्त वैकल्पिक विकल्प" दिये जाएँ।
- प्रॉक्सी वोटिंग के तहत एक पंजीकृत मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग एक प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है।

इस पर विदेश मंत्रालय (MEA) की प्रतिक्रिया क्या रही है?

- MEA ने इस पर ध्यान देते हुए इस पर मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि एनआरआई मतदाताओं को अपने चिह्नित मत पत्रों के साथ इसे भेजना होगा।
- MEA ने कहा था कि "राजनयिक मिशनो के पास बड़ी संख्या में विदेशी मतदाताओं के लिए सत्यापन को संभालने के लिए लॉजिस्टिक व्हाँविथल नहीं है" और उन्हें इस तरह की गतिविधि के आयोजन के लिए मेजबान देश की अनुमति लेनी होगी, जो गैर-लोकतांत्रिक देशों में मुश्किल हो सकता है।

विदेशी मतदाताओं को प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार देने के प्रस्ताव का क्या हुआ?

- वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRIs के लिये प्रॉक्सी वोटिंग अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के लिये एक विधेयक लाया गया।
- यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और यह राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा था, हालाँकि 16वीं लोकसभा के विघटन होने के कारण यह बिल राज्यसभा में निरस्त हो गया और इस प्रस्ताव को दोबारा नहीं लाया गया।
- ECI ने गैर-निवासी भारतीयों के लिये प्रॉक्सी वोटिंग के बजाय केवल पोस्टल मतदान के अधिकार पर जोर दिया। विदेशी मतदाताओं को पोस्टल मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार को केवल चुनाव नियम, 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिये संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

वर्तमान में, भारत में रहने वाले मतदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों द्वारा मतदान की अनुमति है। नया प्रस्ताव विदेशी मतदाताओं के लिए है।

इंटरफेथ विवाह: "लव जिहाद" को लेकर विवाद (Interfaith marriages: Controversy surrounding "Love Jihad")

संदर्भ:

- उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, राज्यों का एक समूह अब "लव जिहाद" कहने के लिए कानूनों को पारित करने की योजना बना रहा है।

“लव जेहाद” क्या है?

- लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से मुस्लिम लड़को द्वारा गैर मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के संदर्भ में किया जाता है।
- लव जिहाद जैसे राजनीतिक शब्दों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
- भले ही व्यक्तिगत रूप से ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं, भारत में इस सन्दर्भ में सभी आधिकारिक जांच 2009, 2010, 2012 और 2014 में शुरू की गई, लेकिन इस गतिविधि का कोई भी सबूत नहीं मिला।

उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मान्तरण से निषेध अध्यादेश 2020 के बारे में

- **तत्काल संदर्भ:** इस तरह के कानून के निर्माण के लिए तत्काल संदर्भ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक हालिया निर्णय है, उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में घोषित किया है कि ऐसा विवाह जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्मपरिवर्तन है, वह "शून्य और अमान्य" है।
- **जबरदस्ती या कपटपूर्ण रूपांतरण पर रोक:** प्रस्तावित कानून कहता है कि जबरन, प्रलोभन, अथवा किसी अन्य दबाव से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस प्रावधान में आरोपी पाए जाने पर न्यूनतम कम से कम 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है। जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- **ऐसा विवाह जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्मपरिवर्तन है, अमान्य होगा:** कानून यह भी कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का "एकमात्र उद्देश्य" किसी लड़की के धर्म को बदलना है, तो विवाह को "शून्य" (शून्य और अमान्य) घोषित किया जाएगा।
- **संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध:** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लिखित; इस कानून के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा।
- **बातचीत के लिए स्वीकृति:** कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे कम से कम दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में देना होगा। सूचना मिलने पर, उक्त अधिकारी प्रस्तावित धार्मिक रूपांतरण के वास्तविक उद्देश्य और कारण की जांच करेगा। यदि प्रस्तावित रूपांतरण इस कानून के प्रावधानों का खंडन करता है, तो यह अवैध और शून्य होगा।
- **साक्ष्य प्रस्तुत करने का दबाव:** धार्मिक रूपांतरण करने जा रहे व्यक्ति पर साक्ष्य को प्रस्तुत करने का दबाव और उत्तरदायित्व होगी कि यह जबरदस्ती या किसी कपटपूर्ण साधन के साथ नहीं हो रहा है। यदि इस प्रावधान के तहत कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो इस प्रावधान के उलंघन पर 10000 के अर्थदंड तथा 6 माह के कारावास का प्रावधान है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

यूपी में लागू इस कानून की आलोचना क्यों हो रही है

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप:** कानून धार्मिक रूपांतरण को रेखांकित करने की योजना बना रहा है जो शादी के उद्देश्यों के लिए हो सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करता है।
- **धर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है:** अनुच्छेद 25 से 28 के आधार पर, एक भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उपरोक्त यूपी कानून इस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। इसके द्वारा राज्य न केवल नागरिकों के ईश्वर के साथ निजी संबंधों में, बल्कि उनके जीवनसाथी की पसंद में भी हस्तक्षेप करना चाहता है।
- **अनुच्छेद 21 के विरुद्ध (जीवन का अधिकार):** किसी व्यक्ति की पसंद का विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। यह विवाह गोपनीयता के अधीन है, जो कि अनुल्लंघनीय है और जीवन साथी की पसंद, चाहे वह विवाह के द्वारा या उसके बाहर, किसी व्यक्ति की 'व्यक्तित्व और पहचान' का हिस्सा है।
- **निजता के विरुद्ध:** मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ (2017) मामले का फैसला सुनाते हुए कहा कि "पारिवारिक जीवन के चुनाव का अधिकार" एक मौलिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया हालिया अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों से मेल नहीं खाता क्योंकि यह एक भावी जीवनसाथी के रूप में पसंद करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित करता है, इसके अनुसार किसी महिला/पुरुष का पति/पत्नी केवल वही हो सकता है जो राज्य द्वारा अनुमोदित होगा।
- **अंतर-विश्वास विवाह से निपटने के लिए कानून मौजूद हैं:** धार्मिक परंपराओं के तहत होने वाली शादियों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कानूनों और विशेष विवाह अधिनियम जो एक धर्मनिरपेक्ष विवाह को सक्षम बनाता है, पर विवाह के इस प्रावधान के अतिक्रमण की संभावना है।

निष्कर्ष

भारत एक 'स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश' है और राज्य द्वारा किसी वयस्क के प्रेम और विवाह के अधिकार में हस्तक्षेप का स्वतंत्रता पर 'खराब प्रभाव' पड़ता है।

Connecting the dots

- विशेष विवाह अधिनियम: Click [Here](#)
- महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु

नये संसद भवन के लिए आधारशिला रखी गयी (Foundation stone laid for New Parliament Building)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - संसद

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में नये संसद भवन की आधारशिला रखी है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- नया संसद भवन 20,000 करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

- यह चार मंजिला इमारत त्रिकोणीय होगी और इसके अंदरूनी हिस्सों में तीन राष्ट्रीय प्रतीक होंगे – कमल, मोर और बरगद का पेड़ - यह इसका थीम भी है।
- संसद भवन 2022 में तैयार होगा।
- पुराने संसद भवन को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- नए लोकसभा और राज्यसभा हॉल में बैठने की क्षमता में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा, संयुक्त सत्र की मेजबानी के लिए लोकसभा हॉल में बैठने की क्षमता का विस्तार 1272 तक किया जा सकता है।
- धौलपुर पत्थर, इसके निर्माण की प्राथमिक सामग्री होगी और लाल ग्रेनाइट कुछ आंतरिक खंडों में लाल बलुआ पत्थर की जगह ले सकता है।
- इमारत आधुनिक ऑडियो-विजुअल संचार प्रणालियों से सुसज्जित होंगे।
- यह पूरी तरह से व्हीलचेयर- और दिव्यांग के लिए अनुकूल भी होंगे।

कर्नाटक का नया गौहत्या विरोधी बिल (Karnataka's New Anti-Cow Slaughter Bill)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- कर्नाटक विधानसभा में गौहत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 के कर्नाटक प्रतिबंध को पारित कर दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- विधेयक में राज्य में गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ गायों की हत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
- 'बीफ' के किसी भी रूप को मवेशियों के मांस के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 'मवेशी' शब्द को "गाय, गाय और बछड़े के बछड़े, बैल के रूप में परिभाषित किया गया है, और साथ ही 13 साल से कम उम्र की भैंस" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के साथ पंजीकृत मवेशियों के संरक्षण और बचाने के लिए आश्रयों को 'गौ शालाओं' के रूप में स्थापित किया गया है।
- पुलिस अधिकारियों उप-निरीक्षक और उससे ऊपर या एक सक्षम प्राधिकारी को इस सन्दर्भ में पूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है, उसके पास परिसर की तलाशी लेने और अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले मवेशियों और सामग्रियों को जब्त करने की शक्ति होगी।
- गोहत्या को बिल में संज्ञेय अपराध माना गया है।

- उल्लंघनकर्ता के लिए 3 से 7 साल के कारावास का प्रावधान है।
- जबकि पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये और 5 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है, दूसरे और बाद के अपराधों में 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

विदेशी वन्यजीव प्रजातियों के संबंध में SC ने इलाहाबाद HC के फैसले को बरकरार रखा (SC upholds Allahabad HC decision with regard to exotic wildlife species)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - न्यायपालिका

समाचार में

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने जून और दिसंबर, 2020 के बीच विदेशी वन्यजीव प्रजातियों पर अवैध कब्जे की घोषणा की जाती है, तो जांच और अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी।
- उच्चतम न्यायालय ने इससे केंद्र सरकार के उस आदेश पर मुहर लगा दी है जिसमें कि विदेशी पशु पक्षियों को रखने वालों या उनके मालिकों को अभियोजन से संरक्षण देने की बात कही गई है।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन(Important value addition)

सरकार की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना

- **मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- विदेशी (एक्सोटिक) जीवित प्रजातियां, पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है, जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है। इन प्रजातियों को अक्सर लोगों द्वारा नए स्थान पर ले जाया जाता है। देश के बहुत से नागरिकों ने सीआईटीईएस (संकटग्रस्त प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन) को अपने पास रखा है, जिसमें विदेशी पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन राज्य/केंद्र स्तर पर ऐसी प्रजातियों के स्टॉक से सम्बंधित कोई एकीकृत सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले छह महीनों में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।
- पंजीकरण, पशुओं व नए शावकों के स्टॉक साथ-साथ आयात और विनिमय के लिए किया जाएगा। इससे प्रजातियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और यह धारकों को उचित पशु चिकित्सा देखभाल, आवास और प्रजातियों की भलाई के अन्य पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करेगा।
- विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशु-रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा।

- घोषणाकर्ता को विदेशी जीवित प्रजातियों के संबंध में किसी भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि परामर्श जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर घोषणा की जाती है। 6 महीने के बाद की गई किसी भी घोषणा के लिए, घोषणाकर्ता को मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत दस्तावेज की आवश्यकता के नियम का पालन करना होगा।
- ऐसी प्रजातियों के धारकों को वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर जाना होगा और स्टॉक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरने होंगे।
- वर्तमान में, माफी योजना सिर्फ एक सलाह है और यह कानून नहीं है।
- सलाहकार ने विदेशी जीवित प्रजातियों को CITES के परिशिष्ट I, II और III के तहत नामित जानवरों के रूप में परिभाषित किया है।
- इसमें वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसूचियों से प्रजातियां शामिल नहीं हैं।

न्याय वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता (Inadequacies of Justice Delivery System)

संदर्भ:

- देश के नागरिक न्यायिक संस्था और उसके घटकों से आदर्श होने की अपेक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के असंबद्ध फोकस के परिणामस्वरूप, सिस्टम की अन्य अपर्याप्तता पर अधिक सार्वजनिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं।

1. न्यायपालिका पर खर्च

- न्यायपालिका पर खर्च करने के मुद्दे को न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि और अदालत के बेहतर बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसी धारणाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
- **1987 का कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम**, भारत में दुनिया के सबसे व्यापक कानूनी सहायता कार्यक्रमों में से एक है। इस कानून के तहत, सभी महिलाएं, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बच्चे निः शुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं।
- इसका अर्थ यह है कि आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात एक मुफ्त कानूनी सहायता शासन के तहत अंतर्गत आते हैं - या उसके अंतर्गत आने चाहिए। हालांकि, वास्तव में, यह कानून एक मृत पत्र है।
- इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक चयनित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उचित रूप से भुगतान किए गए अधिवक्ताओं की एक टास्क फोर्स प्रदान करने के लिए क्रमिक सरकारों की ओर से बहुत कम प्रयास किया गया है।
- हमारी तुलना में यू.के. की कानूनी सहायता की प्रणाली ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए कई स्वतंत्र वकील कार्यालयों से परिचय करती है और उन्हें धन देती है। यदि यह समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो इन अमूल्य सेवाओं को प्रदान करने वाले कई सॉलिसिटर कार्यालय ध्वस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही, विधी का शासन भी समाप्त हो जाएगा। भारत को अभी भी इसके समान कुछ भी नहीं लगाना है।

2. खराब न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात

- अमेरिका में प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 100 न्यायाधीश हैं। कनाडा में लगभग 75 और यू.के. में लगभग 50 हैं।
- दूसरी ओर, भारत में प्रति मिलियन आबादी पर केवल 19 न्यायाधीश हैं। इनमें से, किसी भी बिंदु पर, कम से कम एक-चौथाई पद हमेशा खाली रहते हैं।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रिक्तियों पर बहुत बहस की जाती है, शायद ही कोई ध्यान निचली अदालतों में इस अंतरहीनता पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ आम आदमी सबसे पहले न्याय वितरण प्रणाली के संपर्क में आता है।
- अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ (2001) में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्णय की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को कम से कम 50 प्रति मिलियन जनसंख्या तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसे लागू नहीं किया गया है।

3. न्याय तक पहुंच

- हालांकि 'न्याय तक पहुंच' को विशेष रूप से संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन इसे हमेशा भारतीय अदालतों के रूप में माना जाता है।
- अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन (2016) में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि "जीवन" का तात्पर्य केवल भौतिक अर्थों में जीवन नहीं है, बल्कि अधिकारों का एक समूह भी है जो न्याय तक पहुंचने के अधिकार प्रदान करता है।
- इसके अलावा, अदालत ने न्याय तक पहुंच के चार महत्वपूर्ण घटकों को इंगित किया। इसमें सहायक तंत्रों की आवश्यकता की ओर इशारा किया गया। इसने कहा कि तंत्र को दूरी के संदर्भ में सुविधाजनक रूप से सुलभ होना चाहिए और विवाद के लिए स्थगन की प्रक्रिया शीघ्र और सस्ती होनी चाहिए।

4. अन्य मुद्दे

- सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर ध्यान देने की एक अनुपातहीन राशि का प्रावधान करने के लिए कहा है, जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि ऊपर और इसी तरह के मुद्दों से विचलित होता है।
- सरकार द्वारा बैकलॉग को समाप्त करने और न्यायिक वितरण को सुचारू और कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और रोड मैप तैयार करना बाकी है
- न्याय वितरण प्रक्रिया का बढ़ता हुआ न्यायाधिकरण
- कुछ राज्यों में सिविल न्याय तक पहुंचने के लिए अदालत की फीस;
- प्रणाली में प्रौद्योगिकी का खराब एकीकरण

निष्कर्ष

आइए हम मानते हैं कि शीर्ष अदालत निकट भविष्य में "आदर्श" होने का गौरव हासिल करती है, सभी लोगों के लिए सभी चीजें प्राप्त होती हैं। फिर भी, एक अच्छा मस्तिष्क अकेले ही बहुत कम है, यदि शरीर का शेष भाग अक्षम है, जैसा कि न्याय वितरण प्रणाली आज है।

संसद का शीतकालीन सत्र इस साल Covid-19 के कारण रद्द हो गया (Winter session Of Parliament cancelled this year due to Covid-19)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - संसद; संविधान

समाचार में

- Covid-19 के कारण, इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया है।
- बजट सत्र जनवरी, 2021 में आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास रहती है।
- यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें वर्तमान में रक्षा, गृह, वित्त और कानून मंत्रियों सहित नौ मंत्री शामिल हैं।
- समिति के निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिनके नाम पर सांसदों को एक सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया जाता है।
- संसद का सम्मन संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है।
- इस प्रावधान ने निर्दिष्ट किया कि केंद्रीय विधायिका को वर्ष में कम से कम एक बार मिलने के लिए बुलाया जाना था, और दो सत्रों के बीच 12 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है।
- भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है।
- सम्मेलन द्वारा, संसद एक वर्ष में तीन सत्रों के लिए बैठक का आयोजन करता है।

चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की सुविधा को विदेशी और अनिवासी भारतीयों तक पहुँचाने का प्रस्ताव दिया है
(Election Commission proposes to extend the facility of postal ballots to overseas and NRIs)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - संविधान

समाचार में

- भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) ने कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया है कि वह अगले वर्ष 2021 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) का प्रयोग गैर-निवासी भारतीय (NRI) के लिये करने हेतु "तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है"।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- चुनाव आयोग ने इस सुविधा की अनुमति देने के लिए चुनाव नियम, 1961 के आचरण में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
- डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से गैर-निवासी भारतीय (NRI) को भेजे जाएंगे और वे डाक के माध्यम से अपना उम्मीदवार चुनने के बाद इन मतपत्रों को भेजेंगे
- यह आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक सुविधा वर्तमान में, सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम, या ETPBS के माध्यम से उपलब्ध है (इलेक्ट्रॉनिक सशस्त्र बलों के संघ के सदस्य होने के नाते, या सेना के अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का एक सदस्य)

क्या आप जानते हैं?

भारतीय चुनावों में वर्तमान में विदेशी मतदाता कैसे मतदान कर सकते हैं?

- 2010 से पहले, एक भारतीय नागरिक जो एक योग्य मतदाता है और रोजगार, शिक्षा या अन्यथा के कारण छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा था, चुनावों में मतदान करने में सक्षम नहीं होता था।
- जनप्रतिनिधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 के पारित होने के बाद, पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक विदेश में रहे थे, उन्हें मतदान करने के लिए सक्षम किया गया है, लेकिन वह केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहां उन्हें विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है, वहां वोट कर सकते हैं।

संबंधित लेख:

- चुनाव आयोग: [Mind map](#)

संसद की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में वृद्धि (Increasing Parliament's efficacy and effectiveness)

संदर्भ:

- क्रमबद्ध व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र तरीका समितियों द्वारा अधिकांश व्यवसाय का लेन-देन करना होगा।

समिति प्रणाली

यदि समिति प्रणाली को प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जाना है, तो उनके कामकाज को गैर-पक्षपाती बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कुछ चरण निम्नानुसार हैं:

- **अधिक पारदर्शिता:** इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए समितियों के विचार-विमर्श को जनता के लिए खोलना
- **नागरिक भागीदारी:** संबंधित क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों और गैर-लाभकारी संगठनों की समितियों को सहायता देना।

- **व्यापक प्रसार के लिए चैनल:** समितियों के विचार-विमर्श के व्यापक प्रसार के लिए यूके और यूएसए में एक सार्वजनिक प्रसारण सेवा चैनल शुरू करना।
- **अधिकार और विशेषाधिकार:** यदि संसद को समितियों के माध्यम से अपने व्यवसाय का लेन-देन करना है, तो उनके पास पूरे सदन के सभी अधिकार और विशेषाधिकार होने चाहिए।
- **मंत्रियों द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी:** मंत्रिपरिषद के साथ ही प्रधान मंत्री को समितियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त संसदीय समिति:** संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका को पुनः स्थापित करना और इसकी विश्वसनीयता को बहाल करना भी अनिवार्य है।

अन्य देशों में संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं

- संसद के कामकाज से संबंधित मामलों पर कानून बनाया जाना चाहिए - जैसे कि कई देशों में संसद सत्रों के लिए वार्षिक कैलेंडर, एक वर्ष में सत्रों की न्यूनतम अवधि आदि।
- संसद के प्रशासन को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रूप में विनियमित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए।
- बजट प्रस्तावों की स्वतंत्र जांच और संसद की समितियों के समक्ष उनके स्थापन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के रूप में संसदीय बजट कार्यालय बनाने के लिए भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों को मंजूरी देने और खुफिया और जांच एजेंसियों के काम की समीक्षा करने के लिए संसद की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।

Connecting the dots

- भारतीय संसद के संबंध में क्या मुद्दे हैं?
- पीएमओ कार्यालय बहुत मजबूत हो गया है जो संसद को दरकिनार कर रहा है?

मणिपुर के ZOMI ने ज़ोलैंड प्रादेशिक परिषद के निर्माण की अपनी मांग को नवीनीकृत किया (Manipur's ZOMI renews its demand for the creation of Zoland Territorial Council)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - I - जनजातीय मुद्दे और GS-II – संविधान

समाचार में

- मणिपुर के ज़ोमी जातीय समूह ने असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की तर्ज पर एक स्व-प्रशासित क्षेत्र, संविधान की छठी अनुसूची के तहत ज़ोलैंड प्रादेशिक परिषद (ZTC) के निर्माण की अपनी मांग को नवीनीकृत किया है।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन (Important value additions)

ज़ोमी

- Zou लोग या Zomi भारत और बर्मा की सीमा के साथ रहने वाले एक स्वदेशी समुदाय हैं।
- वे जो लोगों (मिज़ो-कूकी-चिन) का एक उप-समूह हैं।
- भारत में, वे पैइट और सिमटे लोगों की भाषा और आदतों के समान हैं।
- भारत में, Zou को आधिकारिक तौर पर मणिपुर राज्य के 33 स्वदेशी लोगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, और अनुसूचित जनजातियों में से एक है।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, मणिपुर में Zou / Jou की आबादी कुल जनसंख्या के 3% से कम 20,000 के आसपास है।
- समुदाय मणिपुर के चुरचंदपुर और चंदेल जिलों में केंद्रित है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 356 (A.P. High Court order and Article 356)

संदर्भ:

- अक्टूबर में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को न्यायमूर्ति उमा देवी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई में परिवर्तित कर दिया और पुलिस पर अतिरिक्त ज्यादाती का आरोप लगाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य में व्याप्त परिस्थितियों के मद्देनजर है, क्या अदालत यह पता लगा सकती है कि राज्य में संवैधानिक टूट स्थिति है।"

राज्य ने क्या तर्क दिया है?

- **अभूतपूर्व:** 1 अक्टूबर को उच्च न्यायालय का आदेश, न्यायिक हिरासत में या जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का फैसला करते हुए आया। उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को " आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद परिस्थितियों में यह तय करने में सहायता करने के लिए" बुलाया कि अदालत राज्य में संवैधानिक विघटन है या नहीं, यह पता लगा सकते हैं।
- **लैक्स बेसिस:** इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य ने एक याचिका दायर किए और आदेश को वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका में किसी भी दलील के अभाव में अदालत राज्य में संवैधानिक टूट के विषय में जांच नहीं कर सकती है।
- **अनुच्छेद 356 के विरुद्ध:** राज्य में संवैधानिक टूट की स्थिति है, राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, यह तय करने में न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्यकारी में निहित है।
- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध:** उच्च न्यायालय का आदेश, कार्यकारी की शक्तियों पर एक "गंभीर अतिक्रमण" है क्योंकि संविधान के तहत गणना की गई है और इस प्रकार यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- **सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई:** आदेश को स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अति-सक्रियता के मामले के रूप में देखा गया और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- सुप्रीम कोर्ट ने एपी उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या राज्य में संवैधानिक मशीनरी का टूटने वाली है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्होंने एपी हाईकोर्ट द्वारा किसी भी मामले में इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया था और शीर्ष अदालत ने इसे गड़बड़ा पाया था।
- कोर्ट ने नोटिस जारी करने और रहने का निर्देश दिया और रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

घटना का प्रभाव

- न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग या यहां तक कि दुरुपयोग की संभावना के साथ ही उच्च न्यायालय का ये आदेश चौंकाने वाला था।
- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश न्यायपालिका और आंध्र प्रदेश में निर्वाचित सरकार के बीच झगड़े की ओर इशारा करने वाली घटनाओं के मद्देनजर आता है।
- सीएम जगन मोहन रेड्डी ने CJI को एक अभूतपूर्व पत्र में, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ विवादास्पद आरोप लगाने के अलावा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के कथित शत्रुतापूर्ण रवैये के बारे में शिकायत की थी।
- राज्य में न्यायपालिका और सरकार के बीच होने वाले बेवजह के झगड़े को खत्म करने के लिए वह अब सुप्रीम कोर्ट के पास स्थित है। मुख्यमंत्री के पत्र की आंतरिक जांच का आदेश देना एक अच्छी शुरुआत है।
- उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अशक्तता यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में शक्तियों के पृथक्करण पर लगने वाले ऐसे कानूनी कारनामों को दोहराया नहीं जाए।

अनुच्छेद 356 के बारे में मूल्य वर्धन (Value Addition about Article 356)

- संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार देता है यदि वह राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा, संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सरकार बहुमत में नहीं है।
- दुनिया के किसी भी उदार लोकतांत्रिक संविधान में अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान नहीं हैं जो केंद्र सरकार को पाकिस्तान के संविधान को छोड़कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार को खारिज करने की शक्ति देता है।
- भारत और पाकिस्तान दोनों ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 से इस प्रावधान को उधार लिया।
- दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता इस प्रावधान के बहुत विरोधी थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसे निलंबित करने के लिए मजबूर किया; इस प्रकार, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 को कभी प्रभाव में नहीं लाया गया।
- हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस प्रावधान का हमने विरोध किया था वह संविधान में लोकतंत्र, संघवाद और स्थिरता के नाम पर अजीब तरीके से शामिल था।

Connecting the dots:

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
- न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक

IASbaba
One Stop Destination for UPSC Preparation

**ONLINE CLASSROOM PROGRAM
FOR HISTORY OPTIONAL**

- ▶ Quality Lectures
- ▶ Mentorship Available
- ▶ Value Added Notes
- ▶ Test Series : Detailed Evaluation of Answers
- ▶ Discussion of Previous Year Questions

Starting from 15th November

By M. TARIQUE SIR
THE BEST HISTORY FACULTY IN INDIA

eCLP
e-Classroom Mentorship Program
(Foundation Course)

ILP
ONLINE Integrated Learning Program
(Mentorship Based)

AIPTS+
All India Prelims Test Series
+ Video Discussions

ILP Basic ILP Plus ILP Connect

LEARN MORE

सामाजिक मुद्दे/ कल्याण (SOCIAL ISSUE/WELFARE)

IIT- बॉम्बे ने शहरी गुणवत्ता वाले जीवन सूचकांक को प्रस्तुत किया है (IIT-Bombay comes up with Urban Quality Of Life Index)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - I - सोसायटी

समाचार में

- आईआईटी-बॉम्बे के शोधकर्ता शहरी गुणवत्ता वाले जीवन सूचकांक के साथ आए हैं जो वर्तमान में भारत में वास्तविक शहरी जीवन से संबंधित है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- शीर्ष शहर: मुंबई

- अन्य शीर्ष शहर: दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई
- अधिकांश महिला-अनुकूल: चेन्नई
- कम से कम महिलाओं के अनुकूल: पटना
- महिलाओं के खिलाफ उच्चतम अपराध दर: जयपुर
- महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध दर: चेन्नई
- पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में व्यापक अंतर: जयपुर (13.2%)
- पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में सबसे कम: कोलकाता (5.4%)।
- उच्चतम समग्र साक्षरता दर: पुणे (91%)
- सबसे कम समग्र साक्षरता दर: हैदराबाद (83%)।
- महिलाओं के लिए उच्चतम बेरोजगारी दर: पटना
- लिंग समानता को पहली बार ध्यान में रखा गया था।
- शोध के अनुसार, महिलाएं शहरों को अलग तरह से अनुभव करती हैं।
- स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक हो जाता है।
- इसके अलावा पटना में केवल 36% शहरी घरों में ही टैप द्वारा नल के पानी की पहुंच है।

IIT-B RANKING OF INDIAN CITIES

Index	Highest ranked	Lowest ranked
Basic amenities	Pune	Patna
Economic development	Mumbai	Patna
Safety and security	Kolkata	Patna
Transportation access	Delhi	Indore
Environmental impact	Mumbai	Lucknow
Infrastructure development	Kolkata	Patna
Gender role	Chennai	Patna

संबंधित आलेख:

- स्मार्ट शहरों का विकास और लिविंग इंडेक्स में आसानी: [Click here](#)

जाति-के अनुसार डेटा के लिए तमिलनाडु आयोग (Tamil Nadu Commission for Cast-wise Data)

संदर्भ:

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी (Chief Minister Edappadi Palaniswami) ने घोषणा की है कि तमिलनाडु में जाति-वार डेटा एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
- यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसमें हर जाति के सभी सदस्यों का एक पूरा शीर्षक शामिल होगा, या क्या इसे 'जनगणना' की तुलना में 'सर्वेक्षण' के रूप में वर्णित किया जाना बेहतर है।

क्या आपको पता है?

- केंद्र ने 2011 में देश भर में एक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) का आयोजन किया, लेकिन इसने निष्कर्षों के जाति घटक को सार्वजनिक नहीं किया।
- कर्नाटक में, इस प्रकार के परिणाम का जनता के सामने खुलासा नहीं किया गया है।

क्या जाति विवरण का संग्रह जनगणना का हिस्सा है?

- जाति 1931 तक भारत की सौ साल की जनगणना के दौरान प्रणकों द्वारा एकत्र किए गए विवरणों में से एक थी।
- इसे 1941 में शामिल किया गया था, एक वर्ष जिसमें जनगणना ऑपरेशन द्वितीय विश्व युद्ध से आंशिक रूप से प्रभावित था, क्योंकि इसमें अतिरिक्त लागत शामिल थी।

क्या जनगणना में जाति को शामिल करने की आलोचना की गई है?

- व्यक्तियों के जाति विशेष के डाटा को एकत्र करने का मुख्य तर्क यह है कि यह जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- यह आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति को एक जाति के रूप में लेबल करने का एकमात्र कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए जाता है।
- वर्तमान में, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है, जिसमें MBCs के लिए 20 प्रतिशत शामिल है, जिसकी सूची में 108 समुदाय हैं।

आजादी के बाद क्या विचार था?

- स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय रजिस्ट्रार-जनरल, गोपालस्वामी ने 1951 की रिपोर्ट में कहा था: "1951 की जनगणना 'विशेष समूहों' से संबंधित आवश्यक सांख्यिकीय को छोड़कर, जातियों, नस्लों और जनजातियों के बारे में सवालों के साथ चिंता करने के लिए नहीं थी। पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ अन्य सामग्री को पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा एकत्र किया गया और बनाया गया।"
- विशेष समूहों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एंग्लो-भारतियों और कुछ जातियों को जनगणना के प्रयोजनों के लिए अनंतिम रूप से 'पिछड़ा' के रूप में माना जाता है।
- इसका तात्पर्य है कि BC डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसे संकलित या प्रकाशित नहीं किया गया।

अब तक जाति का विवरण कैसे एकत्र किया गया है?

- जबकि एससी/एसटी का विवरण जनगणना के हिस्से के रूप में एकत्र किया जाता है, अन्य जातियों का विवरण प्रणकों द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है।

- प्रगणक को स्व-घोषणा द्वारा मुख्य विधि है।
- अब तक, विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों के आयोगों ने पिछड़ी जातियों की आबादी का पता लगाने के लिए अपनी-अपनी गिनती की है।
- कार्यप्रणाली राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है।
- सार्वजनिक डोमेन में कुछ आयोगों के बारे में उपलब्ध विवरण बताते हैं कि ये पैनल प्रश्नावली के वितरण, हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, प्रासंगिक क्षेत्रों और क्षेत्रों का दौरा करने जैसी विधियों का उपयोग करते हैं।
- कुछ मामलों में, जैसे कि तमिलनाडु में अंबासकर आयोग और कर्नाटक में वेंकटस्वामी आयोग में, डोर-टू-डोर गणना की गई है।

SECC 2011 के बारे में क्या?

- 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास थी।
- भले ही उस वर्ष की गई जनगणना 2011 के साथ SECC 2011 के डेटासेट में ओवरलैप हो सकता है, लेकिन निष्कर्षों को अलग तरह से चिह्नित किया जा सकता है।
- सामान्य जनगणना एक महीने की एक छोटी अवधि में आयोजित की जाती है, जबकि जाति की जनगणना एक लंबी अवधि में आयोजित की जाती है, और इसमें संशोधन और सुधार का एक अच्छा अवसर होता है।
- SECC 2011 में दो घटक थे: ग्रामीण और शहरी परिवारों का सर्वेक्षण और पूर्व निर्धारित मापदंडों और एक जाति की जनगणना के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग।
- हालांकि, केवल ग्रामीण और शहरी घरों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था। जाति के आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

SECC 2011 का जाति डेटा अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया है?

- हालांकि एक सटीक कारण का खुलासा किया जाना बाकी है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता था।
- प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली जातियों का विरोध करने के डर से, जो यह पा सकते हैं कि आबादी में उनकी अनुमानित शक्ति उतनी अधिक नहीं है जितना दावा किया जाना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

जाति गणना के लिए कानूनी अनिवार्यता क्या है?

- **आरक्षण के लिए आधार:** पिछले दो दशकों में, सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न राज्यों में आरक्षण के स्तर के आधार के बारे में सवाल उठा रहा है।
- **मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता:** विशेष रूप से, यह निर्धारित किया गया है कि पिछड़े वर्ग की सूची में एक जाति की उपस्थिति को सही ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा होना चाहिए, साथ ही साथ सेवाओं में इसके अंतर्गत-प्रतिनिधित्व का प्रमाण भी होना चाहिए।

- **नियमित संशोधन:** सर्वोच्च न्यायालय ने समुदाय-वार सूचियों की समय-समय पर समीक्षा करने का भी आह्वान किया है ताकि लाभ कुछ जातियों के पक्ष में न जाएं।
- **समान आरक्षण:** कई समुदाय के नेताओं का तर्क है कि प्रत्येक जाति की आबादी की सटीक संख्या जानने से आरक्षण नीति को उन सभी का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

जातीय जनगणना से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सामाजिक अशांति:** प्रासंगिक और सटीक डेटा प्राप्त करते समय एक जाति की जनगणना से प्रमुख लाभ हो सकता है, परन्तु संभावना है कि यह कुछ वर्गों के बीच यह नाराजगी पैदा करेगा और सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है।
- **कोटा के भीतर कोटा:** जाति का विवरण भी समूह में बड़े या अलग कोटा की मांग कर सकता है जो संख्या में महत्वपूर्ण पाया जाता है एक संभावित नुकसान है।
- **जाति के नाम की जटिलताएँ:** एक जैसी दिखने वाली जाति के नामों का सारणीकरण और वर्गीकरण करना और यह तय करना कि कुछ वर्गों को एक समुदाय की अलग-अलग जातियों या उप-जातियों के रूप में मानना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

निष्कर्ष

सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना सामाजिक परिवर्तन का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है

Connecting the dots

- आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण : Click [here](#)
- अधिवास आधारित नौकरी में आरक्षण

यूपी सरकार ने थारू आदिवासियों के लिए योजना शुरू की (UP government launches scheme for Tharu Tribals)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - I - सोसायटी

समाचार में

- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना है। यह रोजगार पैदा करेगा और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।



महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत जिलों को थारू जनजातीय लोगों के गाँवों को जोड़ने की योजना बना रही है।
- यह एक होमस्टे योजना है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। ये झोपड़ियाँ जंगल से एकत्रित घास से बनाई जाती हैं।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन(Important value addition)

थारू जनजाति

- थारू लोगों का समुदाय तराई क्षेत्रों से संबंधित है।
- उनमें से अधिकांश वनवासी हैं और कुछ कृषि करते हैं।
- थारू महादेव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और उनको परम "नारायण" कहते हैं, वह मानते हैं कि वह धूप, बारिश और फसल के प्रदाता हैं।
- थारू भारत और नेपाल दोनों में रहते हैं।
- भारतीय तराई में यह ज्यादातर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं।
- इनकी अधिकांश संख्या अभी भी जंगल में निवास करती है।

क्या आप जानते हैं?

- थारू जनजातीय लोग थारू भाषा बोलते हैं। यह इंडो आर्यन उपसमूह और उर्दू, हिंदी और अवधी से ही सम्बंधित हैं।
- मध्य नेपाल में, वे भोजपुरी का एक संस्करण बोलते हैं, जबकि पूर्वी नेपाल में, वे मैथिली का एक संस्करण बोलते हैं।
- थारू महिलाओं के पास उत्तर भारतीय हिंदू रीति-रिवाज की मुख्यधारा में महिलाओं की तुलना में अधिक संपत्ति के अधिकार हैं।

वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - एससी और एसटी

समाचार में

- हाल ही में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने 'वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MoA में प्रवेश किया।
- मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- यह आर्थिक रूप से हाशिये पर ओबीसी / एससी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तियों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए एक ब्याज सबवेंशन स्कीम है।
- यह योजना ओबीसी / एससी एसएचजी को 4 लाख रुपये तक के ऋण के साथ और ओबीसी / एससी व्यक्तियों को 2 लाख रुपये तक के ऋण के साथ लाभान्वित करेगी जो उधारकर्ताओं के मानक खातों में सीधे 5% के त्वरित ब्याज उप-लाभ लाभ के साथ है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई 'स्कूल बैग 2020 नीति (New 'Policy on School Bag 2020' by the Ministry of Education)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- स्कूल बैग पर नई नीति के अनुसार, स्कूल बैग कक्षा I से X तक के छात्रों के शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा II तक के छात्रों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- नई नीति में यह भी सिफारिश की गई है कि बैग के वजन की स्कूलों में नियमित रूप से निगरानी करने की आवश्यकता है।
- उन्हें दो गद्देदार और समायोज्य पट्टियों के साथ हल्के वजन का होना चाहिए जो दोनों कंधों पर आसानी से फिट हो सकते हैं और किसी भी पहिये वाले वाहक को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- नीति यहां तक कि सिफारिश करती है कि प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का भार उन पर प्रकाशकों द्वारा छापा जा सकता है।
- यह सिफारिशें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों के आधार पर की गई हैं।
- नीति ने सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाले मध्याह्न भोजन और पीने योग्य पानी की सिफारिश की है ताकि उन्हें दोपहर के भोजन के बक्से या पानी की बोतलें ले जाने की आवश्यकता न हो।
- नीति में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी में कोई बैग नहीं होना चाहिए।

नर्स और मिडवाइफ (Nurses and midwives)

संदर्भ:

- वर्ष 2020 को "नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" के रूप में नामित किया गया है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि नर्स और मिडवाइफ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (universal health coverage) प्राप्त करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगी।

क्या आपको पता है?

- भारत का नर्सिंग कार्यबल अपने स्वास्थ्य कार्यबल का लगभग दो-तिहाई है।
- प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1.7 नर्सों का अनुपात के साथ यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 43% कम है; इसे पूरा करने के लिए 2.4 मिलियन नर्सों की आवश्यकता है।

मुद्दे

- **निजी क्षेत्र पर भारी निर्भरता:** 91% नर्सिंग शिक्षा संस्थान निजी और कमजोर रूप से विनियमित हैं।
- **अपर्याप्त संकाय:** नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों में रिक्त होने वाले संकाय क्रमशः 86% और 80% हैं।
- **प्रशिक्षण के साथ संरचनात्मक मुद्दे:** उनके वेतन, समानता और पदोन्नति के संबंध में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर नर्सों के बीच नौकरी की कमी है।
- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता:** वर्तमान नर्सिंग शिक्षा पुरानी है और जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है। असमान और कमजोर विनियमन से नर्सों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी कम हो गई है।
- **विशेषता पाठ्यक्रमों की कमी:** विशिष्टताओं विशिष्टताओं में कौशल विकसित करने के लिए अपर्याप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं, और गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मामले में महत्वपूर्ण संकाय की कमी को संबोधित करते हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** नर्सिंग शिक्षा संस्थानों के वितरण में असमानताएँ व्याप्त हैं। उनमें से लगभग 62% दक्षिणी भारत में स्थित हैं।
- **व्यापक नीति फोकस का अभाव:** भारतीय नर्सिंग अधिनियम मुख्य रूप से नर्सिंग शिक्षा के आसपास घूमता है और विभिन्न संवर्गों में नर्सों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में कोई नीति मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है।
- **गैर-मानकीकृत प्रथाएं:** भारत में नर्सों के पास अपने अभ्यास के दायरे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं और देखभाल के कोई निर्धारित मानक नहीं हैं। इस भूमिका विवरण और पारिश्रमिक का मिसमैच जो भूमिका को प्रभावित करता है, नर्सों के शोषण के लिए मंच निर्धारित करता है।
- **जवाबदेही मुद्दे:** नर्सों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। यह विकसित देशों में उन प्रथाओं के विपरीत है जहां नर्स अपने काम में त्रुटियों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं।
- **सामाजिक स्थिति:** सिस्टम में प्रचलित पर्यावरण के कारण स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के पदानुक्रम में नर्सों की कम स्थिति पैदा हुई है। वास्तव में, नर्सिंग ने कैरियर विकल्प के रूप में अपने अस्तित्व को खो दिया है।

आगे का रास्ता

- **गुणवत्ता में सुधार:** राष्ट्रीय लाइसेंस निकास द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसे प्रैक्टिस से प्रारंभ करने से पूर्व पास करना हो।
- **आपूर्ति-मांग को जानने के लिए डेटाबेस:** नर्सों, पदों और अवसरों की एक जीवित रजिस्ट्री इस क्षेत्र में मांग-आपूर्ति अंतर से निपटने के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **नियमित निगरानी:** सतत नर्सिंग शिक्षा से जुड़े लाइसेंस का आवधिक नवीनीकरण काफी हद तक नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित और मजबूत करेगा।
- **विधायी संशोधन:** 1947 के इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट में सेवा और रोगी देखभाल के लिए स्पष्ट रूप से मानदंड में संशोधन करना चाहिए, नर्स को रोगी अनुपात, स्टाफिंग मानदंडों और वेतन को ठीक करना चाहिए।
- **संघीय सहयोग:** भारतीय नर्सिंग परिषद और राज्य नर्सिंग परिषदों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट और समन्वित किया जाना चाहिए ताकि वे तालमेल में हों।
- **नर्सिंग को कैरियर के रूप में बढ़ावा देना:** अपनी योग्यता, स्पष्ट कैरियर, नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अवसर और एक पेशे के रूप में नर्सिंग की स्थिति में सुधार के लिए उन्नत डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- **निजी नर्सिंग स्कूलों / कॉलेजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच सार्वजनिक-निजी साझेदारी** नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक और रणनीति है।

कच्छ क्षेत्र में विकास परियोजनाएं (Development Projects In Kutch Region)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क

- हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसे कच्छ जिले के खवड़ा गांव के पास, भारत पाक सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है।
- यह बंजर भूमि के विशाल विस्तार पर 30 गीगा वाट सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा।

विलवणीकरण संयंत्र

- कच्छ जिले में एक विलवणीकरण संयंत्र भी लगाया जा रहा है।
- इस संयंत्र का लक्ष्य 300 गांवों की 8 लाख की आबादी के लिए समुद्री जल को पीने योग्य उद्देश्यों में परिवर्तित करना है।
- यह कच्छ प्रायद्वीप के लिए बहुत महत्व रखता है जो पानी के अन्य स्रोत के साथ बारहमासी वर्षा की कमी वाले क्षेत्र है।

सरहद डेयरी का पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण

- सरहद डेयरी के दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 130 करोड़ रुपये के साथ एक शीर्ष डेयरी सहकारी इकाई का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया।
- राष्ट्रीय किसान विकास योजना के अंतर्गत यह 2 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा प्रदान करेगा।

‘स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण रिपोर्ट (2020 State Of The Education Report For India: Vocational Education First)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- हाल ही में यूनेस्को द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया था।
- हाल ही में भारत के लिए ‘स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (‘2020 State of the Education Report for India: Vocational Education First’ -TVET) रिपोर्ट को नई दिल्ली में यूनेस्को ने लांच किया।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- यह शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। यह रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) पर केंद्रित है।
- इस रिपोर्ट का उद्देश्य स्किल इंडिया मिशन के लिए भारत सरकार का समर्थन करना है। स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने कौशल निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है। इस रिपोर्ट में पिछली शिक्षा नीतियों पर भी चर्चा की गई है।
- इस रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने यूनेस्को के मार्गदर्शन में विकसित किया है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) इसका तकनीकी और वित्तीय भागीदार है।
- भारत ने 2022 तक 110 मिलियन लोगों के कुशल कार्यबल बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में काफी प्रगति की है, जैसा कि 2015 में जारी राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता (NPSDE) नीति में कहा गया है।
- यह वर्तमान में सालाना 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है।
- रिपोर्ट में दस सिफारिशों का एक सेट है जो देश में टीवीईटी के लिए घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

इस रिपोर्ट में दस सिफारिशों की गई हैं:

- शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र में रखना

- शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- आजीवन सीखने और निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
- महिलाओं के लिए TVET के लिए समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण का विस्तार।
- आजीविका प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन करना।
- सतत विकास के 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना।
- TVET के वित्तपोषण के नवीन मॉडल का उपयोग।
- बेहतर नियोजन और निगरानी।
- अंतर-मंत्रालयी सहयोग के लिए एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना।

प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (Prime Minister's Special Scholarship Scheme-PMSSS)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- एआईसीटीई ने रुपये की किस्त जारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा की तरफ जागरूक करने और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए एआईसीटीई ने 20 हजार रुपये छात्रों के खाते में डालने का निर्णय लिया है

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन (Important value additions)

प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS)

- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।
- **कार्यान्वित:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का जम्मू-कश्मीर प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।
- यह योजना जम्मू और कश्मीर के छात्रों को केंद्रशासित प्रदेश के बाहर स्नातक की पढ़ाई करने में मदद करती है।
- **उद्देश्य:** जेएंडके और लद्दाख के युवाओं को शिक्षित करने, उन्हें सक्षम करने और उन्हें सक्षम करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में सक्षम बनाने के लिए।
- युवाओं को दो भागों में छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता दी जाती है - शैक्षणिक शुल्क और रखरखाव भत्ता।
- मुख्य उद्देश्य: (1) उचित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना; (2) योजना के बारे में जागरूकता कार्यशालाओं का संचालन करना; (3) विभिन्न कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए परामर्श आयोजित करना; (4) पात्र उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति का वितरण; (5) पीएमएसएसएस उम्मीदवारों की शिकायतों का निवारण।

भारत के कोविड -19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी (Accelerating India's Covid-19 Social Protection Response Programme)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य

समाचार में

- भारत सरकार और विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए COVID-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने पर भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन \$ की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
- क्रेडिट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) - विश्व बैंक की रियायती ऋण शाखा से दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- यह दो की एक प्रोग्रामेटिक श्रृंखला में दूसरा ऑपरेशन है।
- 750 मिलियन डॉलर के पहले ऑपरेशन को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी।
- यह कार्यक्रम भारत में राज्य और राष्ट्रीय सरकारों की क्षमता को मजबूत करेगा, जो COVID-19 महामारी से उत्पन्न झटके से गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
- यह शहरी और पेरी-शहरी क्षेत्रों में इन कमजोर समूहों की मदद करके भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कवरेज को और अधिक विस्तारित और गहरा बनाने में मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
- आईडीए विश्व बैंक समूह का सदस्य है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी, यूएसए में स्थित है।

संबंधित लेख:

- विश्व बैंक का 750 मिलियन \$ समझौता: [Click here](#)

आठ सदस्यीय समिति ने आईआईटी में आरक्षण पर सिफारिशें करती है (Eight-member committee makes Recommendations on Reservation in IITs)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - शिक्षा

समाचार में

- हाल ही में, सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्यीय समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में छात्रों के प्रवेश और संकाय भर्ती में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कीं।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- इसकी अध्यक्षता IIT दिल्ली के निदेशक ने की
- इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विकलांग व्यक्तियों के विभागों के सचिवों के प्रतिनिधि थे।
- इसकी रिपोर्ट जून 2020 में शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी।
- इसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत भी उपलब्ध कराया गया है।

सिफारिशें

- राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित और मान्यता प्राप्त होने के नाते, IIT को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (CEI अधिनियम) की अनुसूची में उल्लिखित "उत्कृष्टता के संस्थानों" की सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन केवल सहायक प्रोफेसर ग्रेड I और ग्रेड II तक ही सीमित है और ऊपर के स्तरों के लिए नहीं।
- अनुपलब्धता के कारण किसी विशेष वर्ष में रिक्त पद भरे नहीं जाते हैं, बाद के वर्ष में पद आरक्षित किए जाते हैं।
- आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती अभियान का संचालन।
- समय की अवधि में लक्षित लक्ष्यों पर जोर देने वाली प्रणाली और विशिष्ट कोटा का पालन नहीं किया जाता है ताकि आईआईटी उत्कृष्टता, उत्पादन, अनुसंधान और शिक्षण के मामले में दुनिया के अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।
- पैनल पीएचडी कार्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए दो-वर्षीय अनुसंधान सहायता का प्रस्ताव करता है।

मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 (Human Freedom Index 2020)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS - I - सामाजिक मुद्दे

समाचार में

- हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 (Human Freedom Index-2020) को जारी किया गया है। 162 देशों की इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 में भारत को 111 वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- जबकि 2019 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 94 थी। इस प्रकार भारत की रैंक में 17 पायदान नीचे हुई है। जो एक चिंता का विषय है।
- **प्रकाशन:** अमेरिकी थिंक कैटो इंस्टीट्यूट (Cato Institute) और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट (Fraser Institute)

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- **भारत का स्कोर:**
 - व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30
 - आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56
- भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 में समग्र स्कोर (Overall Score) 10 में से 6.43 है
 - शीर्ष देश: न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग
 - यूएसए और यूके: 17 वीं रैंक पर है
 - युद्धग्रस्त सीरिया सूची में अंतिम स्थान पर रहा।
 - भारत के पड़ोसी देश: (1) चीन - 129 (2) बांग्लादेश – 139 (3) पाकिस्तान -140

क्या आप जानते हैं?

- रिपोर्ट में 2008 से 2018 तक 162 देशों को रैंक करने के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों (Indicators) को कवर किया गया है।
- संस्थानों ने उल्लेख किया कि वैश्विक स्तर पर 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता(Personal Freedoms) में कमी आई है।

IIT और आरक्षण में शिक्षक के रिक्त पद (Teacher vacancies at IITs and reservation)

पृष्ठभूमि

- **आरक्षण के कारण अतिरिक्त सीटें:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में बड़ी संख्या में संकाय रिक्तियां हैं, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण के बाद 2008-10 के दौरान छात्र सेवन क्षमता 50% से अधिक बढ़ा दी गई थी। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण जोड़ा गया है।
- **हाल के दशक में आईआईटी का विस्तार:** इसके अलावा, 2008-17 के दौरान अधिक आईआईटी खोले गए, वर्तमान में, 23 आईआईटी हैं।
- **अपर्याप्त शिक्षक:** चूंकि छात्रों का अनुपात शिक्षकों के तनाव में आ गया है, और शिक्षकों की प्रवेश के लिए उच्च पढ़ी, डॉक्टरेट की डिग्री के साथ शुरू, आरक्षित श्रेणियों से पात्र उम्मीदवारों के पूल सिकुड़ गया है
- **समिति का गठन:** इस पृष्ठभूमि में, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी। रामगोपाल राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ताकि आरक्षण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों को ढूंढना मुश्किल क्यों है?

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय और यहां तक कि वैश्विक विकास में योगदान करने के लिए एक विशेष कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित आईआईटी को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाना था।
- इसलिए उम्मीदवारों को एक पीएचडी की डिग्री, साथ ही साथ एक बेहतर अकादमिक रिकॉर्ड और शिक्षण के लिए "उच्च शोध उपलब्धियां" होना चाहिए।
- लगभग एक दशक पहले, छात्र का संकाय अनुपात लगभग 6: 1 था, जो आईआईटी पाठ्यक्रमों को अद्वितीय बनाने वाली परियोजनाओं की नज़दीकी निगरानी और पीछा करने की सुविधा प्रदान करता था। यह संकाय अनुपात बाद में 12: 1 पर गिर गया, और आगे तनाव के तहत प्रतीत होता है।
- शिक्षा मंत्रालय की समिति ने बताया है कि इष्टतम 10: 1 का अनुपात है, जिसके आधार पर संकाय संख्या निर्धारित की गई है।
- वास्तविकता यह है कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित पर्याप्त उम्मीदवार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि जो लोग करते हैं, उनमें से केवल एक छोटा समूह एक शिक्षण कैरियर का विकल्प चुनता है। इसने उपलब्ध पूल को तेजी से कम कर दिया है जिससे आईआईटी आरक्षण मानदंडों का पालन करते हुए शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं।
- समिति का मानना था कि IIT की वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए पर्याप्त योग्य संकाय की अनुपस्थिति आ रही थी, हालांकि शैक्षणिक प्रणाली शीर्ष 50 में प्रवेश करने में सक्षम थी।

समिति ने क्या प्रस्ताव दिया है (सिफारिशें)?

सरकार की स्थिति क्या है?

- समिति की रिपोर्ट, जो एक इच्छुक नागरिक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई थी, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा "परीक्षा के तहत" है।
- यद्यपि इसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण अंतर को संबोधित करना है, लेकिन आरक्षण को दूर करने की सिफारिश केंद्र सरकार की घोषित स्थिति के साथ है।

- पिछले साल नवंबर में, शिक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (CED) को शामिल किया गया था, जिसमें IIT और IIM शामिल होंगे, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ पदों सहित संकाय के पद पूरी तरह से आरक्षण के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- मंत्रालय के पास अब कोई आरक्षण नहीं होने के पक्ष में सिफारिश है, और व्यक्तिगत विभागों द्वारा जाने के बजाय आरक्षित पदों का रोस्टर तैयार करने के उद्देश्य के लिए एक इकाई के रूप में एक आईआईटी के इलाज के विचार का पुनर्विचार है।
- एकल इकाई का विचार 2019 के कानून की मंशा भी है, जिसे पहली बार अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था, ताकि अदालत के फैसले से उत्पन्न कानूनी कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो तर्क को स्वीकार नहीं करते थे।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एक विश्लेषण का अनुमान है कि गणना की समग्र विधि आमतौर पर व्यक्तिगत विभागों की विधि से अधिक आरक्षित पदों में एक छोटे से वृद्धि की ओर ले जाती है। दूसरी ओर, इसका मतलब यह भी है कि आरक्षित पदों का प्रतिनिधित्व एक विभाग में किया जा सकता है, लेकिन अन्य में कोई नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- नागरिकों के कुछ वर्गों के पक्ष में प्रतिपूरक भेदभाव जैसे सकारात्मक कार्यवाई के माध्यम से प्राप्त विविधता ऐतिहासिक विकृतियों को सही करती है। इसके लिए पूरी तरह से महसूस किया जाना चाहिए, हालांकि, सहवर्ती सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर निवेश है, जो छात्रों की क्षमता बढ़ा सकता है।
- सरकारों को प्रगतिशील पुनर्वितरण का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए नीति को समान रूप से समान अवसर का विस्तार करना चाहिए, एक मजबूत, उदार पब्लिक स्कूल प्रणाली के साथ शुरू करना चाहिए। यह विविधता को मजबूत करेगा, और उस तरह की छात्रवृत्ति के लिए नींव रखेगा जो उत्कृष्टता की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में मातृ सहयोगिनी समिति के लिए आदेश जारी (Order issued for Matru Sahyogini Samiti in MP)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आंगनवाड़ी या डे केयर सेंटरों में वितरित सेवाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए माताओं के नेतृत्व वाली समितियों की नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे मातृ सहयोगिनी समिति 'या माताओं की सहयोग समितियाँ कहा जाएगा,
- इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा, या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत लाभार्थियों के विभिन्न समूहों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक आंगनवाड़ी में 10 माताएं शामिल होंगी।
- समितियों में लाभार्थी बच्चों की माताओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिन्हें इस योजना के तहत नामांकित किया गया है।

- समितियों में एक महिला पंच, समुदाय में सक्रिय महिलाएं और योजना के लिए अपना समर्थन देने के लिए उत्सुक, स्थानीय स्कूल के शिक्षक और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला प्रमुख भी शामिल होंगी।
- ये माताएँ लाभार्थियों को साप्ताहिक राशन वितरण पर नज़र रखेंगी और साथ ही केंद्रों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों का सुझाव देंगी।
- यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के आदेश के अनुसार लिया जा रहा है।

ई-सम्पदा: एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया (E-Sampada: A new Web Portal and Mobile App launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने हाल ही में एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई-संपाडा लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नया आवेदन इन सभी सेवाओं के लिए एक खिड़की प्रदान करता है, जिसमें एक लाख से अधिक सरकारी आवासीय आवासों के लिए आवंटन, सरकारी संगठनों को कार्यालय स्थान आवंटन, आदि शामिल हैं।
- 'वन नेशन, वन सिस्टम' प्रदान करने के अपने प्रयास में, पूर्ववर्ती चार वेबसाइट (gpra.nic.in, eawas.nic.in, estates.gov.in, holidayhomes.nic.in), और दो मोबाइल ऐप्स (मी) संपदा निदेशालय के आवास और एम-अशोका 5 को एक में एकीकृत किया गया है।



PEP-2021 PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME

EXCLUSIVE MENTORSHIP PROGRAMME FOR PRELIMS

STARTING FROM 18th JAN - 2021



6 Months to UPSC PRELIMS



महिलाओं सम्बंधित मुद्दे (WOMEN ISSUE)

महाराष्ट्र कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा से सम्बंधित बिल का प्रस्ताव दिया (Bills proposing death penalty for rape approved by Maharashtra cabinet)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने दो मसौदा बिलों को मंजूरी दी जो बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण के मामलों में मौत की सजा का प्रस्ताव करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह दो परस्पर बिल महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम 2020 और महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून 2020 के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालय और मशीनरी का प्रावधान किया हैं।
- यह बिल शक्ति अधिनियम का हिस्सा हैं।
- यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक अनुभागों में संशोधन करना चाहते हैं।
- विधेयकों में सजा की मात्रा बढ़ाने, जीवन अवधि सहित, अपराधों की नई श्रेणियों को शामिल करने और त्वरित परीक्षणों के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करने का भी प्रावधान है।
- मीडिया को बलात्कार पीड़िता के नाम की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है।
- प्रस्तावित अधिनियम छेड़छाड़ और यहां तक कि एसिड हमले के पीड़ितों को समान सुरक्षा प्रदान करेगा।
- मसौदा बिल में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें जघन्य मामलों में पर्याप्त साक्ष्य या अनुकरणीय सजा के वारंट की सजा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)

संदर्भ:

- भारत में घरेलू हिंसा एक उलझी हुई समस्या है, और इसे हाल के वर्षों में तीव्र हो गया है।

भारतीय महिलाओं की समस्या

- **घरेलू हिंसा:** भारत में लगभग 70% महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं।
- **बलात्कार:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट बताती है कि हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, और हर चार मिनट में वह अपने ससुराल वालों के हाथों क्रूरता का अनुभव करती है।
- **यौन हिंसा की रिपोर्टिंग:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2015-16 के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि अनुमानित 99.1 प्रतिशत यौन हिंसा के मामले असंवैधानिक हैं।
- **वैवाहिक हिंसा:** भारतीय महिला का दूसरों की तुलना में अपने पति से यौन हिंसा का सामना करने की संभावना औसत से 17 गुना अधिक है।

वैवाहिक बलात्कार क्या है?

- पति द्वारा पत्नी को बिना सहमति के यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का कार्य, वैवाहिक बलात्कार कहलाता है।
- यह महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने का असामान्य तरीका है।

वैवाहिक बलात्कार के संबंध में समितियों की सिफारिश क्या है?

- 2013 में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति (CEDAW) ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करना चाहिए।
- 16 दिसंबर, 2012 को हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद जे एस वर्मा समिति ने सामूहिक बलात्कार मामले की भी सिफारिश की थी।

भारतीय कानून शासन वैवाहिक बलात्कार से कैसे निपटता है?

- भारतीय कानूनी व्यवस्था के साथ सबसे भयानक और दमनकारी मुद्दों में से एक यह है कि वैवाहिक बलात्कार पूरी तरह से कानूनी है।
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में छह बिंदु की मदद से बलात्कार के अपराध को परिभाषित किया गया है। इस अपराध के अपवादों में से एक “अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा यौन संबंध या यौन कार्य, 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी नहीं है, बलात्कार नहीं है”।

वैवाहिक बलात्कार पर भारत के कानूनी शासन की आलोचना क्या है?

- इंटरनेशनल नियमों के विरुद्ध: वर्तमान में, 100 से अधिक देशों में महाभियोग लगाया गया है, लेकिन, दुर्भाग्य से, भारत उन 36 देशों में से एक है, जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण नहीं हुआ है।
- निहित सहमति की चिंता: भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को हम "निहित सहमति" कहते हैं। यहाँ एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का अर्थ है कि दोनों ने संभोग के लिए सहमति दी है और यह इसके अन्यथा नहीं हो सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 भी ऐसा ही बताता है।
- जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की पवित्रता, और अनुच्छेद 21 के दायरे में यौन गतिविधि से संबंधित विकल्प बनाने की स्वतंत्रता को शामिल किया है। इसलिए, यह अपवाद खंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- कानूनों का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण: हमारे देश में बलात्कार के कानूनों को पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के साथ जारी रखा जाता है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के विवाह के बाद की संपत्ति माना जाता है, उनके शरीर पर कोई स्वायत्तता या एजेंसी नहीं है। वे विवाहित महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करते हैं।
- विवाहित और अविवाहित महिलाओं को अलग करता है: एक विवाहित महिला को अपने शरीर को नियंत्रित करने का उतना ही अधिकार है जितना एक अविवाहित महिला को है। दुर्भाग्य से, भारतीय बलात्कार कानूनों में इस सिद्धांत को बरकरार नहीं रखा गया है।

- **वैवाहिक बलात्कार महिलाओं के जीवन के लिए अधिक खतरनाक है:** बलात्कार बलात्कार है, भले ही अपराधी की पहचान और उम्र कुछ भी हो। एक महिला जिसका एक अजनबी द्वारा बलात्कार किया जाता है, यह एक भयानक हमले की याद के साथ जीवित रहती है; एक महिला जिसका बलात्कार उसके पति द्वारा होता है वह अपने बलात्कारी के साथ रहती है।
- **औपनिवेशिक हैंगओवर:** हमारे दंडात्मक कानून, हमें अंग्रेजों के हाथों सौंप दिए गए थे, और आजादी के 73 साल बाद भी इनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन अंग्रेजी कानूनों में संशोधन किया गया है और 1991 में वैवाहिक बलात्कार का आपराधिक घोषित किया गया है। किसी भी भारतीय सरकार ने अब तक इस समस्या को दूर करने में सक्रिय रुचि नहीं दिखाई है।
- **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन:** आईपीसी की धारा 375 (अपवाद) महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के इन सिद्धांतों के साथ असंगत और उसका उल्लंघन है।
- **"समझदार भिन्नता" का परीक्षण पास नहीं किया जा सकता है:** अनिवार्य रूप से, धारा 375 (अपवाद) एक विवाहित और अविवाहित महिला द्वारा दी गई सहमति के बीच ही नहीं बल्कि 15 साल से कम उम्र और 15 साल से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के बीच एक वर्गीकरण बनाती है। इस तरह के एक वर्गीकरण "समझदार विभिन्नता" की परीक्षा पास नहीं करता है।

क्या आपको पता है?

- 2017 में, एक गैर-सरकारी संगठन, इंडिपेंडेंट थॉट द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस अनायास वर्गीकरण को चुनौती दी और दावा किया कि 15 साल से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को भी यह सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक इन औसत के साथ सहमति दी और धारा 375 में आयु सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी।
- उपरोक्त निर्णय वैवाहिक बलात्कार के वैधीकरण को कम करने की दिशा में केवल एक छोटा कदम था।

निष्कर्ष

- यह उपयुक्त समय है कि विधायिका को वैवाहिक बलात्कार का संज्ञान लेना चाहिए और इसे आईपीसी की धारा 375 (अपवाद) को समाप्त करके बलात्कार कानूनों के दायरे में लाना चाहिए।
- इस कानून को हटाने से, महिलाएं अपमानजनक पति-पत्नी से सुरक्षित रहेंगी, वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और घरेलू हिंसा और यौन शोषण से खुद को बचा सकती हैं।

Connecting the dots

- यौन शोषण और बच्चों की सुरक्षा: Click [here](#)



TLP 2021

Think Learn Perform (TLP) CONNECT 2021

TEST SERIES (Prelims + Mains) Based Mentorship Program

Key Features :

- **INTEGRATED PROGRAMME** – includes Prelims, Mains and Interview
- Includes **MAINS TESTS & SYNOPSIS** – TOTAL = 40 TESTS
- Includes **PRELIMS TEST SERIES** – TOTAL = 53 TESTS
- One-to-One **MENTORSHIP** and top notch feedback
- It is an **INCENTIVE-BASED PROGRAMME***
- **WELL-PLANNED SCHEDULE AND APPROACH PAPER** before the test
- **DISCUSSION (VIDEO & OFFLINE), SYNOPSIS, EVALUATION, RANKING** after every MAINS test
- Includes **BABAPEDIA** – One-Stop Destination of Current Affairs Preparation
- **PRACTICAL PLANNING** maintaining quantity and quality
- **TESTS** are **FLEXIBLE**

***INCENTIVE-BASED PROGRAMME** – TLP 2nd Phase and Interview Mentorship Programme (IMP) will be free for those who clear Prelims and Mains respectively

Why TLP Connect Plus (+)?

- ☞ Includes both **Prelims and Mains Test Series**
- ☞ **Dedicated Mentorship** and **Incentive-based Programme**
- ☞ Special sessions for Essay, Ethics and other GS Mains Papers under the **SERIES OF INTERACTIVE LECTURES (SOIL)**

- ☞ Total No. of Prelims tests - **53 TESTS**
(43 GS Paper I tests + 10 CSAT Paper II Tests)
- ☞ Total No. of Mains tests - **40 TESTS**
(24 Sectional tests + 8 Essay tests + 8 Comprehensive Mocks)
- ☞ Includes **Babapedia** – both Prelimspedia and Mainspedia

WHY IASbaba?

VISION: Enabling an aspirant located at the remotest corner of the country, in not only fulfilling his/her dreams of clearing the toughest UPSC/Civil Services Exam, but securing Rank 1.

2M+

MONTHLY ACTIVE
USERS

350+

RANKS FROM
ILP/TLP

1200+

RANKS FROM
WEBSITE

>70%

HIT RATIO IN
UPSC PRELIMS

>80%

HIT RATIO IN
UPSC MAINS

Contact us

Admission Centre
#38, 3rd Cross Rd, 60feet Main Road,
Chandra Layout, Bengaluru-560040
Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit

Vijayanagara Centre
1737/37, Mrcr Layout, Vijayanagar Service Road,
Vijayanagar, Bengaluru - 560040
Landmark: Opp. to Vijayanagar Metro Station

Delhi Centre
5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro
Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

www.iasbaba.com

tlp@iasbaba.com

+91 91691 91888

स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दे (HEALTH ISSUE)

विश्व एड्स दिवस 2020 (World AIDS Day 2020)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में

- विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- इसकी स्थापना 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई थी।
- 2020 के लिए थीम: “Global solidarity, resilient HIV services.”
- 2019 में, एचआईवी से संबंधित कारणों से 6,90,000 लोग मारे गए और 1.7 मिलियन लोग नए संक्रमित हुए, इनमें से लगभग 62% नए संक्रमण प्रमुख आबादी और उनके सहयोगियों के बीच हुए।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Important value addition)

- एड्स मानव इम्यूनोडिफेंसिवेस वायरस (एचआईवी) के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है।
- यह एक पुरानी, संभावित जीवन-के लिए खतरनाक वाली स्थिति है।
- यह प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर, एचआईवी संक्रमण और बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता में हस्तक्षेप करता है।
- वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य या योनि द्रव के संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है।
- एड्स के लक्षणों में वजन कम होना, बुखार या रात को पसीना आना, थकान और बार-बार संक्रमण शामिल हैं।
- एड्स के लिए कोई इलाज मौजूद नहीं है।
- एंटीरेट्रोवायरल रेजिमेंस (एआरवी) के सख्त पालन से रोग की प्रगति धीमी हो सकती है और द्वितीयक संक्रमण और जटिलताओं को रोका जा सकता है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 जारी (World Malaria Report, 2020 released)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I – स्वास्थ्य

समाचार में

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट (WMR), 2020 हाल ही में WHO द्वारा जारी की गई थी।
- यह इंगित करता है कि भारत ने अपने यहां मलेरिया को कम करने में काफी प्रगति की है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- भारत इस बीमारी से प्रभावित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- भारत का एनुअल पेरासिटिक इंसीडेंस (एपीआई) 2017 के मुकाबले 2018 में 27.6 प्रतिशत था और ये 2019 में 2018 के मुकाबले 18.4 पर आ गया।
- भारत ने वर्ष 2012 से एपीआई को एक से भी कम पर बरकरार रखा है।
- भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है यह 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8 प्रतिशत की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- भारत ने साल 2000 (20,31,790 मामले और 932 मौतें) और 2019 (3,38,494 मामले और 77 मौतें) के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34 प्रतिशत की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92 प्रतिशत की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है और इस तरह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से छठे लक्ष्य (वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50-75 प्रतिशत की गिरावट लाना) को हासिल कर लिया है।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों में इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी लाई है।
- इन्हीं राज्यों से 64 प्रतिशत मौतें भी दर्ज हुईं।

क्या आप जानते हैं?

- डब्ल्यूएचओ ने भारत सहित 11 उच्च मलेरिया बोझ वाले देशों में High Burden to High Impact (HBHI) पहल शुरू की है।
- जुलाई, 2019 में चार राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में HBHI पहल का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में भारत में मलेरिया उन्मूलन (NFME) के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा शुरू की गई थी।
- मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना (2017-22) जुलाई, 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसने अगले पांच वर्षों के लिए रणनीति बनाई।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance)

संदर्भ:

- जबकि COVID-19 महामारी हमारे दैनिक जीवन पर कहर बरपा रहा है, एक मूक महामारी (AMR) दशकों से पृष्ठभूमि में चल रही है
- भारत में, दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता, यह एक गंभीर समस्या है।

AMR डेटा

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर, लगभग 35% आम मानव संक्रमण उपलब्ध दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं।
- हर साल लगभग 700,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उपलब्ध रोगाणुरोधी दवाएं - एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक और एंटीफंगल - रोगजनक का मुकाबला करने में कम प्रभावी हो जाती हैं।
- दूसरी और तीसरी पंक्ति के एंटीबायोटिक्स का प्रतिरोध - कुछ सामान्य बीमारियों के खिलाफ रक्षा की अंतिम लाइनें - 2005 और 2030 के बीच लगभग दोगुनी होने का अनुमान है।
- द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अनुमानित 58,000 नवजात बच्चे अकेले भारत में सेप्सिस से मरते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स अब कुछ जीवाणु संक्रमण का इलाज नहीं हैं।

कारण

- **प्राकृतिक प्रक्रिया उत्प्रेरित:** सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में रोगाणुरोधी एजेंटों के प्रतिरोध को विकसित करते हैं। लेकिन, मानव गतिविधि ने प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है।
- **एंटीबायोटिक का दुरुपयोग:** मनुष्यों, पशुधन और कृषि के लिए रोगाणुरोधकों का दुरुपयोग और अति प्रयोग संभवतः इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसमें अन्य कारक भी योगदान करते हैं।
- **अपशिष्ट रिलीज:** एक बार सेवन करने पर, एंटीबायोटिक दवाओं के 80% तक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के साथ-साथ अन-मेटाबोलाइज्ड उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा, वे घरों और स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल सुविधाओं से अपशिष्टों को निर्मुक्त करते हैं, और कृषि रन-ऑफ, प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का प्रचार कर रहे हैं।
- **अप्रभावी अपशिष्ट जल उपचार:** दवा निर्माताओं के लिए भारत में उपचार की सुविधा से एकल अपशिष्ट जल निर्वहन के विश्लेषण से प्रतिदिन 40,000 से अधिक लोगों का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की सांद्रता अधिक पाई गई। इस प्रकार, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं सभी एंटीबायोटिक दवाओं और प्रतिरोधी बैक्टीरिया को समाप्त करने में असमर्थ हैं।
- **प्रदूषण:** एमआर पर्यावरण और प्रदूषण की भूमिका के लिए अनुसंधान का विषय है।
- **अन्य कारण:** एमआर के प्रसार के लिए पानी एक प्रमुख साधन हो सकता है, विशेष रूप से अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता वाले स्थानों में। वाइल्डलाइफ जो रोगाणुरोधी युक्त निर्वहन के संपर्क में आता है, वह भी दवा प्रतिरोधी जीवों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

हस्तक्षेप

- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां एक स्वास्थ्य एमआर ग्लोबल एक्शन प्लान (जीएपी) को विकसित करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं जो मानव, पशु और पौधे स्वास्थ्य और खाद्य एवं पर्यावरण क्षेत्रों में इस मुद्दे को संबोधित करता है।

- भारत में केंद्र और राज्य सरकारें एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए अपनी योजनाओं के पर्यावरण आयामों को मजबूत कर सकती हैं।
- ऐसे उपायों को बढ़ावा देना जो अस्पतालों और विनिर्माण एवं अपशिष्ट उपचार सुविधाओं जैसे ज्ञात हॉटस्पॉट को संबोधित करते हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एमओईएफ और सीसी ने डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी से प्रतिनिधित्व के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति का गठन किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने मसौदा मानकों को जारी किया, जो दवा उत्पादन इकाइयों से उपचारित अपशिष्टों में 121 एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों की सीमा निर्धारित करते हैं।

निष्कर्ष

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध तेजी से बढ़ रहा है और देर होने से पहले इससे निपटने की आवश्यकता है

[इन्फ्लूएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है: स्वीडन का कारोलींस्का संस्थान \(Influenza makes people more susceptible to bacterial infections: Sweden's Karolinska Institute\)](#)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I – स्वास्थ्य

समाचार में

- हाल ही में स्वीडन के कारोलींस्का इंस्टीट्यूट (Sweden's Karolinska Institute) में हुए शोधों ने सुपर संक्रमण (Super Infections) पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं।
- उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि इन्फ्लूएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- जब कोई व्यक्ति इन्फ्लूएंजा से संक्रमित होता है तो उसके रक्त से विभिन्न पोषक तत्वों एवं एंटीऑक्सीडेंट जैसे- विटामिन C का रिसाव होता है।
- पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट की अनुपस्थिति फेफड़ों में बैक्टीरिया के लिये अनुकूल वातावरण बनाती है।
- बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स A (High Temperature Requirement A -HtrA) नामक एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाकर उत्तेजक वातावरण के अनुरूप हो जाते हैं।
- HtrA की उपस्थिति प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है और इन्फ्लूएंजा-संक्रमित वायुमार्ग में बैक्टीरिया के विकास को भी बढ़ावा देती है।

- न्यूमोकोकस (Pneumococcus- एक जीवाणु जो निमोनिया एवं दिमागी बुखार के कुछ रूपों से संबंधित है) के बढ़ने की क्षमता उच्च स्तर के ऑक्सीकरणरोधी (Antioxidants) के साथ पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण पर निर्भर करती है जो उच्च स्तर के ऑक्सीकरणरोधी के साथ एक वायरल संक्रमण के दौरान होता है।
- इन परिणामों का उपयोग इन्फ्लूएंजा वायरस और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के बीच दोहरे संक्रमण के लिये नए उपचारों को खोजने हेतु किया जा सकता है। इसलिये एक संभावित रणनीति के तहत फेफड़ों में न्यूमोकोकल की वृद्धि को रोकने के लिये प्रोटीन अवरोधकों का उपयोग किया जा सकता है।
- यह जानकारी कोविड -19 पर शोध में योगदान कर सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Important value addition)

सुपर संक्रमण (Super Infections):

- यह पूर्व संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण है, यह विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक (Broad-Spectrum Antibiotics) दवाओं से उपचार के बाद होता है।
- यह एंटीबायोटिक दवाओं से होने वाले जीवाणु या किण्व (Yeast) असंतुलन के कारण बहुत तेजी से वृद्धि करता है।
- उदाहरण के लिये इन्फ्लूएंजा एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इन्फ्लूएंजा रोगियों में मृत्यु का सबसे आम कारण द्वितीयक निमोनिया (Pneumonia) है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है।

इन्फ्लूएंजा

- यह एक वायरल संक्रमण है जो श्वसन प्रणाली यानी नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है।
- इसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है।
- **लक्षण:** बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, जमाव, नाक बहना, सिरदर्द और थकान।
- फ्लू मुख्य रूप से शरीर को संक्रमण से लड़ने की अनुमति देने के लिए आराम और तरल पदार्थ के सेवन के साथ लिया जाता है।
- छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारी या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग में उच्च जोखिम होता है।

न्यूमोनिया

- यह एक संक्रमण है जो हवा के थक्के को एक या दोनों फेफड़ों में प्रवाहित करता है।
- हवा की थैलियों द्रव या कफ से भर सकती हैं।
- **कारण:** बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित जीवों की विविधता।
- **लक्षण:** कफ के साथ खांसी, बुखार, ठंड लगना और साँस लेने में कठिनाई।
- संक्रमण किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और 65 से अधिक आयु वाले लोगों के लिए।

यूएन ने कैनबिस को एक खतरनाक नार्कोटिक नहीं माना है (UN Decides Cannabis Not A Dangerous Narcotic)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- I – स्वास्थ्य

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए ऐतिहासिक मतदान के बाद कैनबिस को खतरनाक ड्रग की सूची से हटा दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- CND ने नार्कोटिक ड्रग्स पर 1961 के एकल सम्मेलन की अनुसूची IV से कैनबिस को हटाने का फैसला किया है।
- इससे पहले, कैनबिस को नशे की लत वाली हेरोइन सहित सूचीबद्ध किया गया था।
- अब, इसे सख्त नियंत्रण अनुसूची से हटा दिया गया है, जिसने चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को भी हतोत्साहित किया है।
- निष्कासन ने आमतौर पर उपयोग की जाने वाली औषधीय और चिकित्सीय क्षमता को पहचानने के लिए दरवाजे खोल दिये हैं, लेकिन अभी भी काफी हद तक अवैध रूप से दवा के रूप में इसका उपयोग हो रहा है।
- यह निर्णय संयंत्र के लंबे-औषधीय औषधीय गुणों में अतिरिक्त वैज्ञानिक शोध भी कर सकता है और औषधीय उपयोग के लिए दवा को वैध बनाने के लिए देशों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, और इसके मनोरंजक उपयोग पर कानूनों पर पुनर्विचार कर सकता है।
- सीएनडी के 53 सदस्य राज्यों में से सत्ताईस - भारत, अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने - 1961 कन्वेंशन की अनुसूची IV से कैनबिस और कैनबिस राल को हटाने के लिए प्रस्ताव पर "हाँ" वोट दिया।
- भारत के नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत, भांग या कैनबिस का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध है।

आगे पढ़ने के लिए: नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

- [Fighting Drug Menace](#)
- भारत का नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 क्या है? [Click here](#)

द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस (टीसीजीए) का उद्घाटन (The 2nd Cancer Genome Atlas (TCGA) inaugurated)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- I – स्वास्थ्य

समाचार में

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस (टीसीजीए) 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- टीसीजीए अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (NCI) और राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान (NHGRI) द्वारा 2005 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक परियोजना है।
- इसका विचार आनुवंशिक उत्परिवर्तन की एक सूची बनाने का था जो कैंसर का कारण बनता है।
- इसके लिए रोगियों से ट्यूमर के नमूने और रक्त के नमूने एकत्र किए गए।
- उन्हें जीन अनुक्रमण और जैव सूचना विज्ञान का उपयोग करके संसाधित किया गया था।
- TCGA ने 11,000 से अधिक रोगियों के लिए 2.5 से अधिक पेटाबाइट डेटा उत्पन्न किया है।
- डेटा का उपयोग कैंसर के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया गया है।
- भारतीय कैंसर जीनोम एटलस (ICGA) भी भारत में CSIR के नेतृत्व वाले प्रमुख हितधारकों के एक संघ द्वारा शुरू किया गया है जिसमें कई सरकारी एजेंसियां, कैंसर अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र के भागीदार हैं।
- **लक्ष्य:** कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों में नैदानिक परिणामों में सुधार करने के लिए।

क्या आप जानते हैं?

- डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व कैंसर रिपोर्ट के अनुसार, 10 भारतीयों में से एक अपने जीवनकाल में कैंसर का विकास करता है और 15 में से एक बीमारी से मर जाता है।

IRDAI रोबोटिक और बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए स्वास्थ्य नीतियों का मानकीकरण करता है (IRDAI standardises health policies for Robotic and bariatric surgeries)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य और GS- III - व्यापार

समाचार में

- हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनियों की स्वास्थ्य नीतियों को मानकीकृत किया है ताकि वे रोबोटिक और बैरिएट्रिक सर्जरी को भी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर सकें।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।
- इस तरह की सर्जरी की शुरुआत ने जटिल प्रक्रियाओं को बहुत आसान बना दिया है।
- वे डॉक्टरों को अधिक सटीक, लचीलेपन और नियंत्रण के साथ विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं को करने की अनुमति देते हैं।
- भारत में ऐसी प्रक्रियाओं का लाभ विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम लागत पर आता है, जिससे यह आबादी के एक बड़े हिस्से तक आसानी से पहुँच सकता है।

- रोबोट सर्जरी से मरीज को बड़े चीरों के बजाय छोटे 'कीहोल' के माध्यम से सर्जरी करने की अनुमति देकर आघात को कम किया जाता है।
- यह कम जटिलताओं और कम अस्पताल में रहने के साथ कम समय में मदद करता है।
- इनक न्यूनतम खर्च, दर्द रहित प्रक्रिया और एक बड़ा कॉस्मेटिक लाभ है।
- सर्जरी की कम लागत का मतलब ऐसे कवर के लिए कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

क्या आप जानते हैं?

- बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऑपरेशन है जो पाचन तंत्र में बदलाव करके वजन कम करने में मदद करता है।
- इश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) एक नियामक संस्था है, जिसका उद्देश्य बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।
- यह बीमा संबंधी गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता है और देखता है।

भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन HGC019 को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी (HGC019: India's first indigenous mRNA vaccine candidate receives approval)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- भारत की एमआरएनए तकनीक आधारित वाली कोरोना वैक्सीन HGC019 को पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य(Key takeaways)

- HGC019 वैक्सीन को पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स बना रही है। जेनोवा इस वैक्सीन को अमेरिकी कंपनी एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बना रही है।
- mRNA टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का उत्पादन करने के लिए पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं।
- इसके बजाय, वे वायरस के सिंथेटिक आरएनए के माध्यम से शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आणविक निर्देशों को ले जाते हैं।
- एमआरएनए-आधारित टीके वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श विकल्प हैं, जो तेजी से विकास की समय-सीमा के कारण एक महामारी को संबोधित करते हैं।
- एमआरएनए वैक्सीन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह गैर-संक्रामक, प्रकृति में गैर-एकीकृत, और मानक सेलुलर तंत्र द्वारा नीचा है।

5 वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जारी किया गया (5th National Family Health Survey (NFHS) released)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य

समाचार में

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) जारी किया।
- सर्वेक्षण में भारत और इसके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण पर विस्तृत जानकारी शामिल है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के परिणाम चरण- I जारी किए गए हैं।
- शेष 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले चरण II को कोविड -19 के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिसे नवंबर से फिर से शुरू किया गया है और मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- वर्तमान सर्वेक्षण में NFHS-4 (2015-16) में मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया।
- प्रजनन दर में गिरावट आई है।
- गर्भनिरोधक उपायकी दर(सीपीआर)भी ज्यादातर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में काफी बढ़ी है,
- सर्वेक्षण में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12-23 महीने की उम्र के बच्चों के टीकाकरण कवरेज में काफी सुधार पाया गया।
- कुपोषण संकेतक खराब हैं।
- 18 राज्यों में से 11 में स्टंटिंग में वृद्धि दर्ज की गई थी। 14 राज्यों में वास्टिंग और 17 राज्यों में एनीमिया से पीड़ित लोगों में वृद्धि देखी गई।

प्लास्मोडियम ओवले: असामान्य प्रकार का मलेरिया (Plasmodium Ovale: Uncommon type of Malaria)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- हाल ही में केरल में मलेरिया के एक प्रकार 'प्लास्मोडियम ओवेल' (Plasmodium Ovale) के लक्षणों की पहचान एक सैनिक में की गई है।
- संभवतः यह सैनिक सूडान में इस रोग से प्रभावित हुआ था जो प्लास्मोडियम ओवेल का स्थानिक क्षेत्र माना जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, यदि मच्छर मलेरिया परजीवी से संक्रमित होता है।
- प्लास्मोडियम ओवेल मलेरिया परजीवी के पाँच प्रकारों में से एक है। इसके अलावा अन्य चार इस प्रकार से हैं- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लास्मोडियम विवैक्स-सबसे सामान्य, प्लास्मोडियम मलेरिया और प्लास्मोडियम नॉलेसी।

प्लास्मोडियम ओवेल

- पी ओवले शायद ही कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है और केरल में पाए गए मामले के कारण घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पी ओवले, पी विवैक्स के समान है, जो कि खतरनाक नहीं है। यह वायरल संक्रमण होने से ज्यादा खतरनाक नहीं है।
- **लक्षण:** इसके लक्षणों में 48 घंटों तक बुखार, सिरदर्द और मतली की शिकायत शामिल है और शायद ही यह कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है।
- इसे ओवल कहा जाता है क्योंकि लगभग 20% परजीवी कोशिकाओं का आकार अंडाकार होता है।
- प्लास्मोडियम ओवेल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है।
- यह अफ्रीका के बाहर अपेक्षाकृत असामान्य है।

विविध

एलुरु बीमारी

- आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु शहर में 550 से अधिक लोग चक्कर आना, सिरदर्द और मतली से पीड़ित हो गये।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने कुछ पीड़ितों के रक्त के नमूनों में लेड और निकल पाए हैं।
- भारी धातुओं द्वारा पानी के संदूषण पर प्राथमिक संदेह है।
- वैज्ञानिकों को संदेह है कि कीटनाशक या कीटनाशक पीने के पानी के स्रोतों में फैल गए हैं।
- एलुरु ने गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों से नहरों के माध्यम से पानी प्राप्त किया है।
- नहरें कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहाँ अपवाह कीटनाशकों के साथ मिला कर नहरों के पानी में मिल जाता है।
- रहस्य बीमारी के कई पहलुओं ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है।
- जो लोग केवल पैकेज्ड पेयजल का उपयोग करते हैं, वे भी बीमार पड़ गए हैं।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए लांसेट नागरिक आयोग (Lancet Citizens' Commission for Universal Health Coverage)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य

समाचार में

- हाल ही में, भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए लांसेट नागरिक आयोग को ऑनलाइन शुरू किया गया है जो भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- यह विश्व की प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लांसेट और लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक पहली तरह की भागीदारी वाली, देशव्यापी पहल है।
- **उद्देश्य:** यूएचसी के कार्यान्वयन के लिए नागरिकों का खाका विकसित करने के लिए सहभागितापूर्ण सार्वजनिक सहभागिता को सक्षम करना।
- **मिशन:** (1) आने वाले दशक में भारत में यूएचसी को प्राप्त करने का मार्ग तैयार करना; (2) भारत में सभी नागरिकों के लिए सुलभ, समावेशी और सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली लचीली स्वास्थ्य प्रणाली को साकार करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना; (3) जमीनी सर्वेक्षण, सार्वजनिक परामर्श और ऑनलाइन चर्चाओं के माध्यम से भारत भर से अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए; (4) शैक्षिक संस्थानों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी और निर्माण कार्य करने के लिए, पूरे क्षेत्र में संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए।
- यह भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्रथम कदम होगा।
- **सिद्धांत:** (1) यूएचसी सभी स्वास्थ्य चिंताओं को कवर करता है; (2) रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल प्रमुख विषय हैं; (3) चिंता सभी स्वास्थ्य लागतों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है; (4) एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की आकांक्षा करना जो सभी को समान गुणवत्ता का आनंद दे सके।

विज्ञान 2035: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी (Vision 2035: Public Health Surveillance In India)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III – पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में नीति आयोग ने 'विज्ञान 2035: भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी' नाम से एक श्वेत-पत्र जारी किया है,

महत्वपूर्ण तथ्य

- **विज्ञान:** इसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिये एक विज्ञान दस्तावेज प्रस्तुत करना और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करने में मदद करना है।
- यह श्वेत-पत्र त्रिस्तरीय (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिये भारत का विज्ञान-2035 प्रस्तुत करता है।
- इस दृष्टि के लिए बिल्डिंग ब्लॉक केंद्र और राज्यों के बीच एक अन्योन्याश्रित शासन प्रणाली है, एक नया डेटा-शेयरिंग तंत्र जिसमें नए एनालिटिक्स, स्वास्थ्य सूचना विज्ञान और डेटा विज्ञान का उपयोग शामिल है, जिसमें कार्रवाई के लिए सूचना का प्रसार करने के अभिनव तरीके शामिल हैं।

- नागरिक-हितैषी सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र के साथ सक्षम व्यक्तिगत गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी।
- यह रोग का बेहतर पता लगाने, रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर डेटा-साझाकरण तंत्र है।
- भारत का लक्ष्य उन घटनाओं को प्रबंधित करने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन करते हैं।

हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों के लिए मान्यता योजना की शुरुआत (Recognition Scheme for Hygiene Rating Audit Agencies)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य

समाचार में

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) एफएसएसएआई की ओर से देश में मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करके हाइजीन रेटिंग बढ़ाने के लिए हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों के अनुमोदन की योजना के साथ आगे आई है

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- एफएसएसएआई की फूड हाइजीन रेटिंग योजना की पहल अपने परिसर या उससे बाहर उपभोक्ताओं को सीधे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के व्यापार के लिए प्रमाणन प्रणाली की योजना है।
- खाद्य प्रतिष्ठानों का ऑडिट के समय खाने की स्वच्छता और सुरक्षा की स्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
- स्वच्छता रेटिंग स्माली (1 से 5 तक) के रूप में होगी और इसे उपभोक्ता को दिखाई देने वाले स्थान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- खाद्य प्रतिष्ठानों को ऑडिट के समय देखी गई खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा स्थितियों के आधार पर रेट किया जाता है।
- स्वच्छता रेटिंग स्माली (1 से 5 तक) के रूप में होगी और प्रमाण पत्र उपभोक्ता के सामने वाले क्षेत्र में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता और सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए खाने-पीने के व्यवसायों को प्रोत्साहित करके वे जिन खाद्य दुकानों में खाते हैं उनके संबंध में अवगत विकल्प और निर्णय करने की अनुमति प्रदान करना है।
- मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और प्रक्रियाओं के बारे में एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI)

- स्थापना : 1997

- **संयुक्त रूप से स्थापित:** भारत सरकार और भारतीय उद्योग के तीन प्रमुख उद्योग संघों अर्थात एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा प्रतिनिधित्व किया
- **मंत्रालय:** औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय मान्यता संरचना की स्थापना और संचालन और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

गैल्सेफ सूअर को एफडीए द्वारा अनुमोदन (GalSafe Pigs approved by FDA)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II- स्वास्थ्य और GS- III - जैव प्रौद्योगिकी

समाचार में

- यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने हाल ही में गैल्सेफ सूअरों के रूप में संदर्भित घरेलू सूअरों पर जीनोमिक परिवर्तन (IGA) करने की मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- संयुक्त राज्य अमेरिका में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सूअरों को भोजन और चिकित्सा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।
- सूअर केवल 2015 में जीएम सलमोन के बाद भोजन के लिए अनुमोदित होने वाले दूसरे जीएम जानवर हैं।
- जीएम सूअरों को अल्फा-गैल को खत्म करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, यह सूअरों में पाई जाने वाली एक शर्करा है जो एलर्जी का कारण बन सकता है।
- यह पहली बार था जब मानव भोजन और चिकित्सीय उपयोग के लिए एक जीएम जानवर को मंजूरी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

जानबूझकर जीनोमिक परिवर्तन

- जानवरों में जानबूझकर जीनोमिक परिवर्तन का मतलब आधुनिक आणविक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जीव के जीनोम में विशिष्ट परिवर्तन करना है जिन्हें लोकप्रिय रूप से "जीनोम संपादन" या "आनुवंशिक इंजीनियरिंग" के रूप में जाना जाता है।
- हालांकि, अन्य प्रौद्योगिकियां हैं इनका उपयोग जानवरों में IGA बनाने के लिए किया जा सकता है।
- जानवरों के डीएनए अनुक्रम में इस तरह के बदलाव अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किए जा सकते हैं, मानव उपभोग के लिए स्वस्थ मांस का उत्पादन करने और अन्य कारणों के बीच जानवरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन करने के लिए है।

B.1.1.7 वंश: SARS-CoV-2 का नया संस्करण (B.1.1.7 Lineage: New variant of SARS-CoV-2)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II – स्वास्थ्य

समाचार में

- हाल ही में, भारत ने SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण के बारे में चिंताओं के बीच 31 दिसंबर तक यूके के लिए सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है, जो वहां तेजी से फैल रहा है और बढ़ रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पिछले हफ्ते, दक्षिण और पूर्वी इंग्लैंड में कोविड -19 मामलों में तेजी से उछाल के पीछे नए SARS-CoV-2 संस्करण का कारण बताया गया था।
- इसे VUI (वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन) 202012/01 या B.1.1.7 वंश के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।
- वेरिएंट उपन्यास कोरोनोवायरस एसएआरएस-सीओवी -2 के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन का परिणाम है, साथ ही साथ आरएनए वायरस के अन्य जीनोमिक क्षेत्रों में भी उत्परिवर्तन होता है।
- प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह पहले प्रसारित वेरिएंट की तुलना में अधिक पारगम्य है।
- हालांकि, यह घातक नहीं है।

NFHS डेटा को पढ़ना (Reading NFHS data)

संदर्भ:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के पहले चरण के परिणाम जारी किए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (NFHS) क्या है?

- NFHS घरों का एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी सर्वेक्षण है। डेटा को कई राउंड में एकत्र किया जाता है।
- कार्यान्वयन एजेंसियां:** मुंबई में MoHFW ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है और सभी NFHS का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences-IIPS) मुंबई के समन्वय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में किया जाता है।
- वित्त पोषण:** सर्वेक्षण को संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसे यूनीसेफ का पूरा समर्थन प्राप्त होता है।
- पिछले सर्वेक्षण:** पहले चार NFHS क्रमशः 1992-93, 1998-99, 2005-06 और 2015-16 में आयोजित किए गए थे।

यह किस प्रकार का डेटा एकत्र करता है?

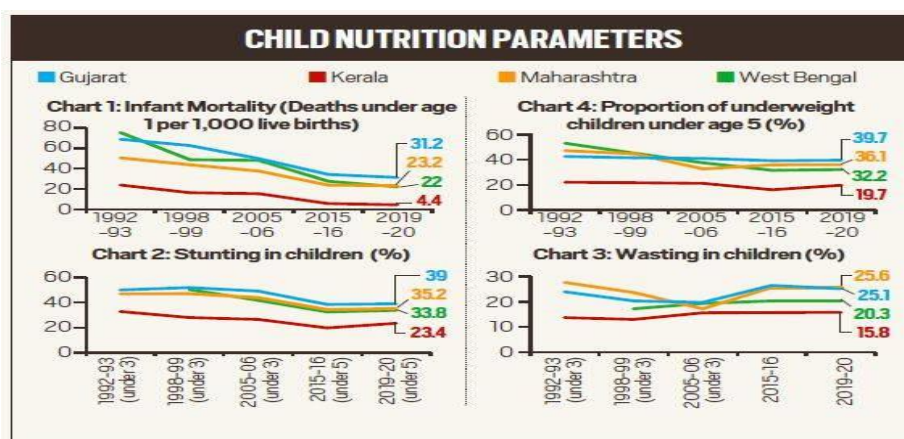
- NFHS-5 के लिए प्रारंभिक कैवटशीट 131 मापदंडों पर राज्य-वार डेटा प्रदान करता है।
- इन मापदंडों में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जैसे कि कितने घरों में पीने का पानी, बिजली और बेहतर स्वच्छता है; जन्म के समय लिंगानुपात क्या है, शिशु और बाल मृत्यु दर क्या है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कितने लोगों में उच्च रक्त मधुमेह या उच्च रक्तचाप आदि है।
- एनएचएस के प्रत्येक दौर ने जांच का दायरा भी बढ़ाया है।
- उदाहरण के लिए, पांचवें पुनरावृत्ति में, पूर्वस्कूली शिक्षा, विकलांगता, शौचालय सुविधा तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान प्रथाओं और गर्भपात के कारणों पर नए प्रश्न हैं।

एनएचएस परिणाम महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** एनएचएस डेटाबेस संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल अनुसंधान की जरूरतों को पूरा करता है और वकालत को सूचित करता है, बल्कि केंद्रीय और राज्य-स्तरीय नीति निर्धारण दोनों के लिए केंद्रीय है।
- **अंतर्राष्ट्रीय तुलना:** एनएचएस सर्वेक्षण परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय परिणाम प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रश्न और कार्यप्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इस प्रकार, यह वैश्विक संदर्भ में बिहार में बाल कुपोषण की प्रवृत्ति के परिणामों को बताता है।

NHFS-5 के बारे में

- **एनएचएस का पहला चरण** - जिसके लिए 2019 की दूसरी छमाही में डेटा एकत्र किया गया था - जिसमें 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे।
- **सर्वेक्षण का दूसरा चरण कोविड -19** महामारी द्वारा इसे बाधित किया गया था; इसके परिणाम मई 2021 में सामने आने की उम्मीद है। दूसरे चरण में कुछ सबसे बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल होंगे।
- पहले चरण के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि 2015 और 2019 के बीच, कई भारतीय राज्यों में कई बाल कुपोषण मापदंडों पर उलटा असर पड़ा है।



निष्कर्ष

- बाल कुपोषण डेटा जैसे स्वास्थ्य परिणाम कारणों के एक जटिल सेट का परिणाम है - एक परिवार की आय की स्थिति से लेकर पर्यावरणीय कारकों से लेकर सरकारी हस्तक्षेप तक पर ध्यान देना चाहिए।

केरल में शिगेला (Shigella) के विरुद्ध निवारक उपायों की शुरुआत हुई (Preventive measures started against Shigellosis in Kerala)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- केरल के कोझीकोड जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने शिगेला संक्रमण के 6 मामलों और लगभग 24 संदिग्ध मामलों का पता लगाने के बाद निवारक उपाय शुरू किए गए हैं।



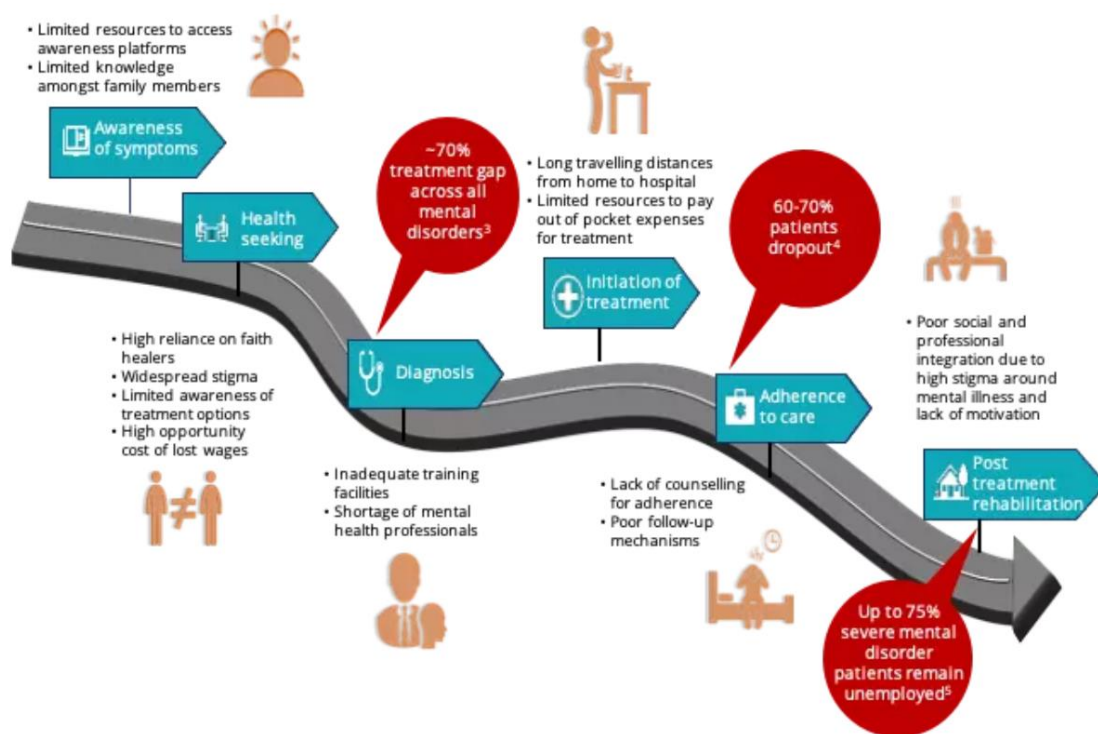
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- शिगेलॉसिस, या शिगेला संक्रमण, एक संक्रामक आंतों का संक्रमण है, जो शिगेला नामक बैक्टीरिया के एक जीनस के कारण होता है।
- बैक्टीरिया प्रमुख रोगजनकों में से एक है, जो दस्त के लिए जिम्मेदार है, यह विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में बच्चों में होता है।
- बैक्टीरिया, अंतर्ग्रहण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के बाद, यह बृहदान्त्र के उपकला अस्तर पर हमला करता है जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं की सूजन होती है और बाद में गंभीर मामलों में कोशिकाओं का विनाश होता है।
- **लक्षण:** अतिसार (अक्सर खूनी और दर्दनाक), पेट दर्द, बुखार, मतली और उल्टी।
- **संचरण:** यह व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलता है जब बैक्टीरिया को गलती से निगल लिया जाता है।
- दूषित भोजन और पानी के माध्यम से दुनिया भर में प्रसार का सबसे सामान्य रूप है।
- **रोकथाम:** विशेष रूप से बच्चे के डायपर को सही से निपटने और खाना बनाने / खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं।

मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा (Mental Healthcare)

मुद्दे

- भारत की लगभग 15% आबादी खराब मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है - और इससे पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार 1990 में 125 मिलियन से 2017 में 197 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- आत्महत्या, कार्यरत उम्र के भारतीय वयस्कों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
- भारत ने 2017 में अपने कुल हेल्थकेयर बजट का 1% मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया।
- निधियों का अवमूल्यन, व्यक्तिगत भारतीय राज्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की कम प्राथमिकता, और मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्यों के सेवन (एमएनएस) विकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की कम कवरेज।
- COVID-19 महामारी ने केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता को रेखांकित किया है।



Challenges and barriers along the mental health patient journey in India Image: Authors

आगे का रास्ता

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी और नवीन मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और उनका पता लगाना
- समुदाय स्तर पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के माध्यम से अच्छी तरह से परिभाषित तरीके से परामर्श और रेफरल।
- मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को नष्ट करने और रोगियों और देखभाल करने वालों दोनों की देखभाल के लिए विकल्प पेश करने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान का संचालन करना।

- हेल्पलाइन या ऐप जैसे मदद मांगने के अनाम तरीकों को सक्षम करना।
- डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर सुगमता में सुधार लाना।
- प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना।
- रोगी प्रबंधन में सुधार के लिए मोबाइल-आधारित (डिजिटल) निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग करना।
- मनो-सामाजिक शिक्षा के माध्यम से देखभाल के पालन में सुधार
- अनुवर्ती तंत्र की स्थापना या उपचार के परिवर्तन में वृद्धि का पालन के साथ।
- सार्वजनिक धन के पूरक के लिए और निजी क्षेत्र और परोपकार से संसाधनों को जुटाने के लिए भारत को मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएचओ की 2019 की वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान (WHO's 2019 Global Health Estimates)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- WHO के 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान हाल ही में जारी किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रिपोर्ट के अनुसार, गैर-संचारी रोग अब विश्व में शीर्ष 10 में से 7 मौतों इसके कारण होती हैं। इसने वर्ष 2000 की अवधि में मौजूद 10 प्रमुख कारणों में से 4 कारणों की वृद्धि की है।
- नया डेटा 2000 से 2019 की अवधि को कवर करता है।
- हृदय रोग: यह अब सभी कारणों से होने वाली कुल मौतों का 16% हो गया है और हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2000 के बाद से 2 मिलियन से अधिक बढ़कर 2019 में लगभग 9 मिलियन हो गई है।
- अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश के अन्य रूप: इस मामले में अमेरिका और यूरोप दोनों संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में तीसरे स्थान पर रहे।
- एड्स (AIDS): यह वर्ष 2000 में मृत्यु का 8वाँ प्रमुख कारण था जो 2019 में 19वें स्थान पर पहुँच गया, यह पिछले दो दशकों में इसके संक्रमण को रोकने, वायरस के परीक्षण और इस बीमारी के उपचार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।
- तपेदिक वर्तमान में विश्व की शीर्ष 10 बीमारियों में शामिल नहीं है। तपेदिक से होने वाली मौतों के मामलों में 30% की गिरावट के साथ यह वर्ष 2000 के 7वें स्थान से गिरकर 2019 में 13वें स्थान पर पहुँच गई।
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि: कई अनुमान वर्ष 2019 में दीर्घायु (वर्ष 2000 की तुलना में 6 वर्ष अधिक) की बढ़ती प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2000 में दीर्घायु का वैश्विक औसत 67 वर्ष था जबकि यह वर्ष 2019 में यह 73 वर्ष देखा गया।
- संचारी रोगों से होने वाली मौतों में वैश्विक गिरावट आई है, जो अभी भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

क्या आप जानते हैं?

- 2019 में, निमोनिया और अन्य निचले श्वसन संक्रमण संचारी रोगों के सबसे घातक समूह थे और एक साथ मृत्यु के चौथे प्रमुख कारण के रूप में स्थान पर थे।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत की शुरुआत करेंगे, योजना में जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा (PM to launch Ayushman Bharat PM-JAY SEHAT to extend coverage to all residents of J&K)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए आयुष्मान भारत PM-JAY SEHAT का शुभारंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करेगी।
- **फोकस:** वित्तीय जोखिम संरक्षण प्रदान करना और सभी व्यक्तियों और समुदायों को गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।
- यह योजना जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है।
- इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को प्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपये प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
- पीएम-जेएवाई के परिचालन विस्तार से 15 लाख (लगभग) अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बीमा मोड पर पीएम-जेएवाई के साथ मिलकर संचालित होगी।
- इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है।
- पीएम-जेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) में स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम और चिकित्सकीय देखभाल शामिल है।
- इसके माध्यम से सेवाओं तक सभी की पहुंच होती है, लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इलाज के चलते लोगों के गरीबी के दलदल में फंसने का जोखिम कम करता है।

- आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इसके दो स्तंभों- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की परिकल्पना की गई है

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

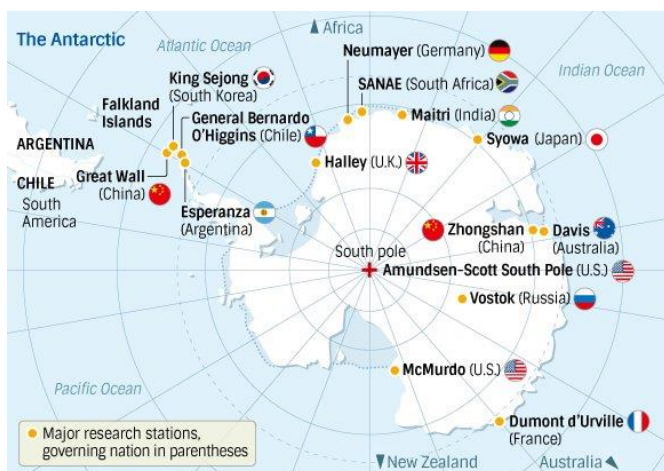
- यह भारत में 40% लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- कार्यक्रम का उपयोग करने वाले लोग डॉक्टर से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाओं का उपयोग करते हैं।
- यदि किसी को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है, तो एबी पीएम-जेवाई उन लोगों के लिए मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए विशेषज्ञ उपचार और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है।
- यह कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित है।
- यह केंद्र सरकार और राज्यों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है।

अंटार्कटिका में कोरोनावायरस (Coronavirus In Antarctica)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- अंटार्कटिका के चिली के एक अनुसंधान केंद्र में कम से कम 36 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
- यह दक्षिणी महाद्वीप पर वायरस का पहला उदाहरण है।



महत्वपूर्ण तथ्य

अंटार्कटिका

- अंटार्कटिका, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को संचालित करने वालों को छोड़कर निर्जन है।
- अब तक, अंटार्कटिका में भारतीय दल वायरस फैलने से चिंतित नहीं है।
- अंटार्कटिका, मैत्री और भारती में दो भारतीय स्थायी स्टेशन, चिली बेस से कम से कम 5,000 किमी दूर हैं।
- दोनों भारतीय स्टेशन लगभग 3,000 किमी दूर हैं।
- गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) अंटार्कटिका और आर्कटिक में भारत के वैज्ञानिक अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है।

एक प्रभावी टीकाकरण वितरण नीति की ओर (Towards an effective vaccination distribution policy)

संदर्भ:

- भारत की योजना अगले 6-7 महीनों में COVID-19 के खिलाफ 300 मिलियन लोगों का टीकाकरण करने की है।

सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां

- **त्वरित समय में बड़ी संख्या में टीकाकरण:** सरकार की योजना स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को प्राथमिकता देने की है, इसके बाद हर कोई जो 50 वर्ष से अधिक आयु का है। इसका मतलब यह होगा कि जुलाई या अगस्त 2021 तक लगभग 20% आबादी को टीका लगाया जाएगा।
- **टीकों की खरीद:** चूंकि सभी टीके जो वर्तमान में सुर्खियों में हैं, उन्हें दो खुराक की आवश्यकता होती है, सरकार को 600 मिलियन खुराक का अधिग्रहण करना होगा।

टीकाकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार ने पहले ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक हासिल करने के लिए सीरम संस्थान के साथ एक सौदा किया है।
- इस टीके के लिए आपातकालीन प्राधिकरण जल्द ही पालन करने की संभावना है।
- भारत बायोटेक के कोवाक्सिन और रूसी स्पुतनिक वी सहित अन्य वैक्सीन फ्रंटरनर हैं जिनके भारत में क्लिनिकल परीक्षण रेड्डी लैब्स द्वारा किए जा रहे हैं।
- इसलिए, सरकार को आवश्यक संख्या में खुराक प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

टीकाकरण अभियान का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए?

इस तरह के एक टीकाकरण अभियान के दो अलग-अलग उद्देश्य होने चाहिए:

- एक, टीकाकरण करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना,
- दो, वायरल ट्रांसमिशन की गति और प्रसार को कम या कम करने के लिए।

किसे प्राथमिकता दी जायेगी?

- फ्रंट-लाइन श्रमिकों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देने की सरकार की रणनीति, U.K. और U.S. में पालन किए जाने वाले अभ्यास के अनुरूप है, दो प्रमुख देश जो COVID-19 टीकाकरण अभियान में अग्रणी रहे हैं।
- इसके लिए तर्क यह है कि उन लोगों की रक्षा की जाए जो भविष्य में संक्रमित होने के साथ-साथ संक्रमण के स्वास्थ्य परिणामों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं।
- टीकाकरण स्वास्थ्य सेवा पेशेवर उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं: ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास उच्च स्तर का खतरा है और वे सक्रिय रोग वैक्टर के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे बड़ी संख्या में लोगों के साथ बातचीत करते हैं।
- हालांकि, प्राथमिकता वाले पुराने जिवंतो को वास्तव में लंबे समय में वायरस द्वारा प्रदत्त कुल सामाजिक और आर्थिक लागत को कम नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग का सामाजिक मेल जोल का स्तर कम होते हैं और इसलिए उनमें वायरस फैलने की संभावना कम होती है।
- **वैकल्पिक सुझाव:** एक छोटा व्यक्ति जो बड़ी संख्या में लोगों के साथ बातचीत करता है, दोनों के संक्रमित होने और बाद में दूसरों को संक्रमित करने की अधिक संभावना है। इससे पता चलता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों - उदाहरण के लिए, धारावी स्लम - को वर्तमान रणनीति के तहत जितना संभव हो सके, उससे अधिक ध्यान देना चाहिए।

टीकाकरण अभियान में निजी अस्पताल को शामिल करने के बारे में क्या?

- सरकार की खरीद की रणनीति पूरी तरह से घरेलू स्रोतों पर निर्भर करती है। यह निजी अस्पतालों को शामिल किए बिना वितरण के लिए पूरी तरह से सार्वजनिक संसाधनों पर भरोसा करने की भी योजना है।
- इसके अलावा, सरकार टीकाकरण की पूरी लागत वहन करने की योजना बना रही है।
- वैकल्पिक प्रस्ताव: मान लीजिए कि फाइजर या किसी अन्य बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने वैक्सीन को अधिकृत करने के साथ-साथ इसे आयात करने वालों को (लाभ के लिए) बेचने की अनुमति के लिए सरकार से संपर्क किया है।
- निजी खिलाड़ियों के लिए सरकार से किसी भी अनुमोदन से संपन्न व्यक्ति को टीकाकरण कतार में आगे आने में सक्षम बनाया जाएगा। यह अनिवार्य रूप से इस आरोप को आकर्षित करेगा कि सरकार जनसंख्या में समृद्ध समूहों के हितों के लिए खानपान कर रही है।
- लेकिन शायद अधिक विवादास्पद विश्लेषण यह सुझाव देगा कि निजी क्षेत्र को अनुमति देने से वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति प्रदान करने में मदद मिलेगी, खासकर जब गरीबों के हितों को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाता है।
- सरकार को सभी उपलब्ध घरेलू स्तर पर उत्पादित टीकों की खरीद जारी रखनी चाहिए और अपने वितरण चैनल के माध्यम से लोगों और विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के लोगों को इसकी आपूर्ति करनी चाहिए।
- निजी खिलाड़ियों को अनुमति देने का एक और संभावित लाभ यह है कि जितने बड़े टीके लगाए जाते हैं, उतने ही गैर-टीके के बीच वायरस संचरण की गति कम होगी।

निष्कर्ष

- सरकार को टीकाकरण योजना में निहित सिद्धांत की जांच करनी चाहिए और क्या निजी खिलाड़ियों को इसकी अनुमति दी जानी चाहिए

Connecting the dots

- [Vaccine Nationalism](#)

औषधीय पादप के लिए NMPB कंसोर्टिया (NMPB Consortia For Medicinal Plants)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB), आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादप के लिए कंसोर्टिया शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एनएमपीबी औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच संपर्क की आवश्यकता को बढ़ाता है।
- NMPB कंसोर्टिया गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री, अनुसंधान और विकास, खेती, औषधीय पौधों के व्यापार / बाजार लिंकेज आदि को संबोधित करेंगे।
- किसानों और निर्माताओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, एक 'बीज से शेल्फ' दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है, जिसमें गुणवत्ता रोपण सामग्री (QPM), गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज (GAP), गुड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस (GPHP) से संबंधित पहलू होंगे। संबोधित किया।
- पहले चरण में, NMPB कंसोर्टिया को औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए प्रस्तावित किया गया है - अश्वगंधा (विथानिया सोमिफेरा), पिप्पली (पाइपर लॉंगम), आओला (फीलंथस एम्बेसी), गुग्गुलु (कोमीफोरा वाइटी), सतावरी (शतावरी रेसमस)।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड (NMPB)

- यह भारत सरकार द्वारा व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास के लिए औषधीय पौधों और समर्थन नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- बोर्ड आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के तहत काम कर रहा है।

न्यूमोसिल: पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumosil: First pneumococcal conjugate vaccine)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन "न्यूमोसिल" का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे विभिन्न अन्य भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इस 'न्यूमोसिल' टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईआईपीएल) ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया है।
- निमोनिया रोग की रोकथाम में न्यूमोसिल प्रभावी है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

न्यूमोनिया

- यह एक संक्रमण है, जो फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति है—जो प्राथमिक रूप से अल्बियोली (कूपिका) कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म (माइक्रोस्कोपिक) वायु कूपों को प्रभावित करती है।
- यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु और कम आम तौर पर सूक्ष्मजीव, कुछ दवाओं और अन्य परिस्थितियों जैसे स्वप्रतिरक्षित रोगों द्वारा संक्रमण द्वारा होती है।
- यह संक्रमण किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और 65 से अधिक आयु वाले लोगों के लिए यह खतरनाक है।
- **लक्षण:** कफ के साथ खांसी, बुखार, ठंड लगना और साँस लेने में कठिनाई।
- एंटीबायोटिक्स निमोनिया के कई रूपों का इलाज कर सकते हैं।
- निमोनिया के कुछ रूपों को टीके द्वारा रोका जा सकता है।
- बैक्टीरिया निमोनिया का एक सामान्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया (न्यूमोकोकस) है।

क्या आप जानते हैं?

- एक संयुग्म वैक्सीन एक पदार्थ है जो एक वाहक अणु से पॉलीसेकेराइड एंटीजन फ्यूज (संयुग्मित) से बना है।
- यह वैक्सीन की स्थिरता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

भारत में पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम में अच्छे, रिप्लेकेबल प्रैक्टिस और इनोवेशन पर नेशनल समिट (National Summit On Good, Replicable Practices And Innovations In Public Healthcare Systems In India)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुड, रेप्लिकेबल प्रैक्टिस के लिए किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पहली बार 2013 में इसे श्रीनगर में आयोजित किया गया था।
- शिखर सम्मेलन को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को पहचानने, दिखाने और दस्तावेज करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एबी-एचडब्ल्यूसी पर टीबी सेवाओं के लिए परिचालन दिशानिर्देश और सक्रिय केस डिटेक्शन और कुछ रोग के लिए नियमित निगरानी पर परिचालन दिशानिर्देशों के साथ नई स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) भी लॉन्च किया।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय प्रधान मंत्री ने 2030 के एसडीजी लक्ष्य से पांच साल आगे 2025 तक टीबी मुक्त भारत का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है।

पहली स्वदेशी रूथेनियम -106 के रूप में नेत्र कैंसर चिकित्सा

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई ने नेत्र कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- सर्जन के लिए पट्टिका का संचालन बहुत सुविधाजनक है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना जाता है।
- अब तक परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से भारत में बनाई गई BARC पट्टिका का उपयोग Ocular Cancer के लिए सात मामलों में किया गया है।
- नेत्र संबंधी ट्यूमर आंख के अंदर के ट्यूमर हैं। वे कोशिकाओं का संग्रह होते हैं जो असामान्य रूप से बढ़ते और गुणित होते रहते हैं और द्रव्यमान बनाते हैं।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

रूथेनियम -106

- रूथेनियम -106 दुर्लभ भारी धातु रूथेनियम का एक रेडियोधर्मी रूप है, जो प्लैटिनम के समान "प्लैटिनम समूह" धातु है।
- रूथेनियम -106 यूरेनियम -235 के विखंडन या विभाजन से उत्पन्न होता है, परमाणु विखंडन रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम का एक प्रकार, इसलिए यह परमाणु ईंधन में पाया जाता है।
- यह कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से आंख और त्वचा के ट्यूमर के लिए।
- इसका उपयोग रेडियोसोटोप के थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में भी किया जाता है जो बिजली उपग्रहों का उपयोग करता है।

सरकारी योजनाएँ (GOVERNMENT SCHEMES)

मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरा प्रोत्साहन पैकेज (Third stimulus package for Mission Covid Suraksha)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड -19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।
- यह अनुदान, भारतीय कोविड -19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) को प्रदान किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

मिशन COVID सुरक्षा - भारतीय COVID-19 वैक्सीन विकास मिशन

- कोविड -19 वैक्सीन विकास मिशन; पूर्व -क्लिनिक विकास, विनिर्माण और विनियामक सुविधा के साथ तैनाती पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा। इससे 5-6 वैक्सीन कैंडिडेट के विकास में मदद मिलेगी तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- संचालन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- कार्यान्वयन: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) में मिशन कार्यान्वयन इकाई
- राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन (एनबीएम) और इंड-सीईपीआई मिशन के तहत मौजूदा गतिविधियां इस मिशन को पूरक ताकत प्रदान करेगी।

शहद मिशन में शामिल हुए प्रवासी श्रमिक (Migrant workers engaged in Honey Mission)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- प्रधानमंत्री के भारत के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए उठाए गए स्व-निरंतरता उपायों के अच्छे परिणाम आने लगे हैं।
- विपदा में फंसे प्रवासी श्रमिक अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश में केवीआईसी के शहद मिशन में शामिल हुए। श्रमिकों ने पहले शहद उत्पादन का लाभ उठाया है। आशा है दिसम्बर से मार्च महीने में उत्पादन बढ़ेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

शहद मिशन

- शहद मिशन का उद्देश्य: किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से भारत के शहद उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार उत्पन्न करना।
- उदघाटन : 3 साल पहले KVIC द्वारा

- हनी मिशन के तहत, KVIC किसानों, मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ प्रशिक्षण और 10 मधुमक्खी बक्से प्रदान करते हैं।
- KVIC मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी चलाता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत अप्रैल 1957 में स्थापित (एक आरटीआई के अनुसार) एक वैधानिक निकाय है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च संगठन है।
- विजन - ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना।
- अप्रैल 1957 में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम संभाला।
- प्रधान कार्यालय: मुंबई
- छह क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी।

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जायेगी (Ayush Export Promotion Council to be set up)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य और GS- III - व्यापार

समाचार में

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिलकर एक 'आयुष निर्यात संवर्धन परिषद' (AYUSH Export Promotion Council-AEPC) की स्थापना के लिए काम करेंगे। प्रस्तावित AEPC को आयुष मंत्रालय के तहत रखा जा सकता है।
- आयुष के लिए एचएस कोड (Harmonized System code) का मानकीकरण शीघ्र किया जाएगा।
- आयुष मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ मिलकर आयुष उत्पादों के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए काम करेगा।
- आयुष उद्योग, आयुष उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन्हें मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी काम करेगा।
- आयुष 'ब्रांड इंडिया गतिविधियों' (Brand India activities) में शामिल होगा।

आत्मानिर्भर भारत योजना (ABRY) को मंजूरी (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) approved)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - तैनाती

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- **उद्देश्य:** औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना और आत्मानिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- अगर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ पंजीकरण के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी गंवा चुके हैं, तो योजना उनके कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
- योजना के तहत लाभार्थी / नए कर्मचारी होंगे:
 - EPFO में रोजगार से जुड़ने वाले किसी भी नए कर्मचारी को मासिक वेतन पर 15,000 रुपये से कम पर पंजीकृत किया जाता है
 - EPF सदस्य, 15,000 रु. से कम मासिक वेतन का आहरण करते हैं, जो 1 मार्च से 30 सितंबर, 2020 तक COVID महामारी के दौरान रोजगार से बाहर हो गए और 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद कार्यरत हैं।
- केंद्रीय सरकार। निम्नलिखित पैमाने पर 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा:
 - 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) कुल मजदूरी का 24%
 - 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी का EPF योगदान (EPF मजदूरी का 12%)
- यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक चालू रहेगी।

संबंधित आलेख:

- आत्मानिर्भर भारत 3.0 भाग 1: [Click here](#)
- आत्मानिर्भर भारत 3.0 भाग 2: [Click here](#)

पीएम स्वीनिधि की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा का कार्यक्रम शुरू (Programme of Socio-Economic Profiling of PM SVANidhi launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- हाल ही में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों का सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा बनाने का शुभारंभ किया गया।
- मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पीएम-स्वनिधि लाभार्थी और उसके परिवार की एक रूपरेखा (Profile) तैयार की जाएगी।
- रूपरेखा द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पात्र लाभार्थी केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शुरू किए गए इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य पथ विक्रेताओं/स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त परिवार सहित उनका समग्र विकास तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है।
- सन्दर्भ-** पीएम स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना के तहत पथ विक्रेताओं को काम करने के लिए 10,000 रुपए तक कार्यशील पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराई गई, ताकि वे कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- पहले चरण में इस कार्यक्रम के लिए देश के 125 शहरों का चयन किया गया है।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत के गुणवत्ता परिषद (QCI: Quality Council of India) को भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना

- संचालन:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- उद्देश्य:** COVID-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये तक का किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया (Indigenous Games to be a part of Khelo India Youth Games 2021)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोज हरियाणा में किया जायेगा।
- खेलों जिन्हें शामिल किया गया है हैं: गतका, कलारीपयट्टु, थांग-ता और मल्लखम्बा।



महत्वपूर्ण तथ्य

- कलरीपायट्टु की उत्पत्ति केरल से हुई है और दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है।
- मल्लखंभ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के केंद्र हैं।
- गतका की उत्पत्ति पंजाब राज्य से हुई है। निहंग सिख वारियर्स की इस पारंपरिक लड़ाई शैली का उपयोग आत्मरक्षा और खेल दोनों के रूप में किया जाता है।
- थांग-ता एक मणिपुर मार्शल आर्ट है जो हाल के दशकों में गुमनामी में बदल गई है।

अनुसूचित जाति से सम्बंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) में बदलाव की मंजूरी (Post Matric Scholarship To Students Belonging To Scheduled Castes - PMS-SC)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अगले पांच वर्ष में 59000 करोड़ रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के चार करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ होगा। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्र प्रायोजित योजना को बड़े परिवर्तनों के साथ मंजूरी दी गई है ताकि छात्र अपनी उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- अगले 5 वर्षों में अपनी पसंद के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सबसे गरीब परिवारों के छात्रों को दाखिला देने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

- यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता, तथा बिना विलम्ब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।
- राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति स्थिति, आधार पहचान एवं बैंक खातों के ब्यौरे की व्यापक जांच करेगी।
- इस योजना के तहत केंद्र के हिस्से (60 प्रतिशत) की राशि प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
- यह 2021-22 से शुरू होगा।
- इसके तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और शेष 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध करायेंगी।
- प्रत्येक संस्था द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा, वार्षिक तृतीय पक्ष मूल्यांकन और अर्ध-वार्षिक स्व-लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के संचालन के माध्यम से निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
- केंद्रीय सहायता जो 2017-18 से 2019-20 के दौरान सालाना लगभग 1100 करोड़ रुपये थी, 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़कर सालाना 6000 करोड़ किया जाएगी।

जल गुणवत्ता परीक्षण इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया (Water Quality Testing Innovation Challenge launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जल परीक्षण के लिए पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार के साथ साझेदारी में एक नवाचार चुनौती शुरू की है।
- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल परीक्षण के लिए पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए इनोवेशन चैलेंज में शामिल होने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- **नवाचार चुनौती का उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों का परीक्षण किया जाता है; इसके अलावा, पानी के प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए नीति निर्धारणकर्ताओं की मदद करना।
- **मुख्य उद्देश्य:** पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अभिनव, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान लाने के लिए, जिसका उपयोग घरेलू स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए तुरंत, आसानी से और सही तरीके से किया जा सकता है।
- अपने घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले लोगों के पास अपने नलों से आने वाले पानी की क्षमता का परीक्षण करने का कोई साधन नहीं है।

- यह एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां लोग सीधे नल के पानी का सेवन करने से हिचकते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में लोग अतिरिक्त खर्च के कारण घरेलू जल उपचार इकाइयों की स्थापना भी करते हैं।
- चुनौती का उद्देश्य इन मुद्दों को एक अभिनव, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी तरीके से संबोधित करना है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

जल जीवन मिशन

- अगस्त, 2019 में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) लॉन्च किया।
- JJM का उद्देश्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति (एलपीसीडी) की सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
- केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।
- यह 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल के पानी के कनेक्शन के लिए सक्षम करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वयन के तहत है।
- **मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय
- **मिशन का उद्देश्य:** प्रत्येक ग्रामीण घरेलू पीने योग्य नल का पानी पर्याप्त मात्रा में और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता प्रदान करना।
- जल जीवन परीक्षण, केंद्रीय सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।
- जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से, 23 दिसंबर, 2020 तक, अब तक देश के ग्रामीण परिवार के 2.90 करोड़ घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, इस प्रकार अगस्त, 2019 में 3.23 करोड़ (17%) से नल का जल आपूर्ति बढ़ कर 6.13 करोड़ (32%) हो गया है।

क्या आप जानते हैं?

- यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी प्रोटोकॉल, 2019 ने बीआईएस आईएस 10500: 2012 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार पीने के पानी की पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को निर्दिष्ट किया है।



संबंधित आलेख:

- जल जीवन मिशन: [Click here](#)
- ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका: [Click here](#)

भारतीय कौशल संस्थान, मुंबई में उद्घाटन हुआ (Indian Institute Of Skills, Mumbai inaugurated)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - शिक्षा और GS- III - कौशल पीढ़ी

समाचार में

- मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान के पहले बैच का हाल ही में उद्घाटन किया गया था
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार और टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के बीच एक संयुक्त पहल है।
- TATA-Indian Institute of Skills में पहला बैच फैक्ट्री ऑटोमेशन में दो पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण शुरू करेगा, जिसमें भविष्य के पाठ्यक्रमों और स्मार्ट विनिर्माण (उद्योग 4.0) प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों की नींव रखने की परिकल्पना की गई है।

नामघर को वित्तीय अनुदान वितरित किया गया (Financial grants distributed to Namghars)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - संस्कृति और GS- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री ने असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8,000 नामघर को वित्तीय अनुदान वितरित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important value additions)

- नामघर असम के पारंपरिक वैष्णव मठ हैं।
- नामघर (शाब्दिक अर्थ प्रार्थना घर) पूरे असमिया समुदाय और हिंदू धर्म के एकासराना संप्रदाय से जुड़े मंडल पूजा के लिए स्थान हैं, विशेष रूप से, असम के मूल निवासी हैं।
- पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक ढांचे का निर्माण करने के अलावा, यह नाटकीय प्रदर्शनों (भोना) के लिए घरों और थिएटरों के रूप में भी कार्य करते हैं।
- नामघर, जिसे कीर्तनघर भी कहा जाता है, सत्रों (एकसराना धर्म के मठों) में केंद्रीय संरचना भी है जहाँ इसके आसपास अन्य इमारतें स्थित हैं।
- असम में वैष्णव संतों दामोदरदेव, माधवदेव और शंकरदेव द्वारा असम के लोगों के लिए नामघर की शुरुआत की गई थी, जहां वे संस्कृति और भगवान की भक्ति (भक्ति गीत) और भक्ति की संस्कृति का अभ्यास कर सकते हैं।

34वीं प्रगति सहभागिता का आयोजन (34th PRAGATI interaction held)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II – नीति और हस्तक्षेप

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की।
- बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI)

- प्रगति सूचना संचार और प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं।
- इस मंच का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना है, और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।

- यह वास्तविक समय की उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली है।
- PRAGATI मंच तीन नवीनतम तकनीकों को विशिष्ट रूप का संयोजन है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली (पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव) है।
- इस प्रणाली को पीएमओ टीम द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से इन-हाउस डिजाइन किया गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM SVANIDhi योजना (PM SVANidhi scheme for street vendors)

संदर्भ:

- महामारी के बीच जून में स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्म निर्भर निधि (PM SVANIDhi) योजना शुरू की गई थी।

योजना

- यह एक माइक्रो- क्रेडिट सुविधा है जो सड़क विक्रेताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की कम दरों के साथ 10,000 रुपये का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
- अब तक (दिसंबर 2020), इस योजना - AtmaNirbhar Bharat पैकेज का हिस्सा - देश भर से 31.6 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है (सिक्कम को छोड़कर, जो आधिकारिक रूप से इसमें भाग नहीं ले रहा है)।
- कुल आवेदनों में से, 16.7 लाख स्वीकृत किए गए हैं और 12.17 लाख वितरित किए गए हैं।

यह योजना क्यों चलाई गई?

- इम्पैक्टोफ महामारी और लॉकडाउन से निपटने के लिए: COVID-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने व्यापार चक्र को बाधित कर दिया और दैनिक मजदूरी श्रमिकों और सड़क विक्रेताओं को काम से बाहर कर दिया। इस योजना का उद्देश्य विक्रेताओं को वित्तीय रूप से अपने पैरों पर वापस लाना है।
- क्रेडिट स्कोर और डिजिटल रिकॉर्ड स्थापित करना: लंबी अवधि में, इसका उद्देश्य विक्रेताओं के लिए क्रेडिट स्कोर स्थापित करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है, ताकि वे बाद में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- ऋण ट्रैप को रोकता है: कई विक्रेताओं का संबंध अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से है, और अक्सर वे निजी ऋणदाताओं से उधार लेते हैं जो उन्हें ब्याज की अत्यधिक दरों का प्रभार देते हैं। यह ऋण 12% ब्याज दर से कम है, और सड़क विक्रेताओं को कर्ज के जाल में गिरने से रोकने में मदद करता है।
- अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण: यह योजना अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और उन्हें भविष्य में सुरक्षा जाल और ऋण देने का साधन प्रदान करने का प्रयास करती है।
- कौन से विक्रेता ऋण के लिए पात्र हैं, और वे इसके लिए कैसे आवेदन करते हैं?
- वे सभी विक्रेता जो 24 मार्च, 2020 से पहले या पहले से वेंडर सर्टिफिकेट के साथ लोन ले रहे हैं।

- 2014 के स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार, टाउन वेंडिंग कमेटी (जिसमें एक क्षेत्र से स्थानीय अधिकारियों और विक्रेताओं को शामिल किया गया है) ने सभी विक्रेताओं के एक सर्वेक्षण के बाद वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी किया है।
- लेकिन चूंकि कई राज्यों और शहरों ने अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया है, इसलिए कई विक्रेता वेंडिंग का ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसके बजाय, योजना के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय - इस मामले में, नगरपालिका - प्रत्येक विक्रेता के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (एलओआर) प्रदान करेगी जो ऋण लेने का इच्छुक है।
- यदि विक्रेता विक्रेता संघ का सदस्य है, तो वह आवेदन कर सकता है,
- पहचान प्रमाण सहित इन दस्तावेजों को योजना के लिए बनाए गए एक विशेष पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, और बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं और संवितरित होते हैं, आदर्श रूप से, 10-15 दिनों में।

यदि शहर ने अधिनियम के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी का सर्वेक्षण नहीं किया है तो क्या यह योजना आवेदकों की वेंडिंग को वैध बनाती है?

- एक बार
- यूएलबी द्वारा पत्र की सिफारिश जारी की जाती है, इसका जनादेश एक महीने तक रहता है, जिसके बाद वेंडिंग के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्वेक्षण यूएलबी द्वारा किया जाना चाहिए।
- लेकिन चूंकि यह एक राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऐसा करने के महत्व पर केवल प्रत्यक्ष या संवेदनशील बना सकती है, और उन विक्रेताओं को नहीं निकाल सकती जिन्होंने ऋण का लाभ उठाया है, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है।
- यूएलबी द्वारा जारी किए गए एलओआर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या वेंडिंग के लिए अधिकार नहीं देते हैं, क्योंकि यह योजना द्वारा उल्लिखित नहीं है।

ऋण के लिए आवेदन करते समय विक्रेताओं को किन विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- भले ही इस योजना को देश भर के विक्रेताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसके कारकों के कारण इसके क्रियान्वयन की बात आती है।
- **विक्रेताओं के शहर-व्यापी सर्वेक्षण का अभाव है:** देश भर के राज्यों ने असमान रूप से 2014 के स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम को लागू किया है, जो विक्रेताओं के सर्वेक्षण के लिए उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **LORs जारी करने में देरी:** व्यापक डेटा की कमी के कारण, विक्रेताओं को पहले ULBs से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LORs) के लिए आवेदन करना चाहिए, जो न केवल पूरी प्रक्रिया में देरी करता है, बल्कि आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है। कुछ नगरपालिकाएं भी एलओआर जारी करने में धीमी हैं, जिससे सैकड़ों विक्रेताओं को महीनों से ऋण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
- **आधार के साथ लिंक:** एक और मुद्दा यह था कि विभिन्न विक्रेताओं के मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। इसे संबोधित करने के लिए, विभिन्न यूएलबी ने अब शिविर लगाए हैं। कई विक्रेता संघ इस मुद्दे को सुधारने के लिए बाजारों में शिविर भी लगा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विक्रेताओं की मदद भी कर रहे हैं।
- विक्रेताओं के खिलाफ स्थानीय अधिकारियों की मानसिकता: ऋण प्राप्त करने वाले विभिन्न विक्रेताओं को अक्सर पुलिस या यूएलबी अधिकारियों द्वारा उनकी जगह से बेदखल कर दिया जाता है, जिससे उनकी आय का एकमात्र स्रोत और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर चोट लगती है।

- **ऋण के संवितरण में क्षेत्रीय असंतुलन:** तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं, जिन्होंने महामारी से पहले या पिछले कुछ महीनों में वेंडिंग के प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। अन्य राज्य पिछड़ रहे हैं।

निष्कर्ष

- भले ही इस योजना को देश भर के विक्रेताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसके कारकों के कारण इसके क्रियान्वयन की बात आती है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आत्मनिर्भर भारत

अंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL)

ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या (Assassination of Iranian Nuclear Scientist)

संदर्भ:

- पिछले हफ्ते नवंबर के दौरान तेहरान के बाहर ईरानी परमाणु वैज्ञानिक, मोहन फखरीजादे की हत्या कर दी गयी।
- फ़खरीजादेह को व्यापक रूप से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से सम्बंधित एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में माना जाता था और उनकी हत्या की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है - पश्चिम एशिया और उसके बाहर इसके गंभीर भू-राजनीतिक निहितार्थ होंगे

हत्या का समालोचनात्मक विश्लेषण

1. यह ईरान की बढ़ती रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है

- यह 2020 में दूसरी ऐसी हाई प्रोफाइल हत्या है।
- जनवरी में अमेरिकी ड्रोन हमले से रिवॉल्यूशनरी गार्ड के Quds Force के जनरल जनरल इंचार्ज जनरल कासम सोलेमानी की मौत हो गई थी।
- हाई-प्रोफाइल ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले उसके समाज के शत्रुतापूर्ण प्रवेश के बारे में सवाल उठाते हैं।
- ऐसी अटकलें हैं कि हत्यारों को देश पर स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है।

2. ईरान न्यूक्लियर डील के नवीनीकरण को लेकर यह हत्या की गई

- 2015 में, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर P5 + 1 - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के रूप में ज्ञात विश्व शक्तियों के एक समूह के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की
- समझौते के तहत, ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की अनुमति के बदले में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए अनुमति दी गयी है।
- हालांकि, मई 2018 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते को समाप्त कर दिया और ईरान एवं इसके साथ व्यापार करने वाले दोनों राज्यों पर लक्षित प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया।
- इसके बाद 2019 में, ईरान ने भी समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया। इससे यह लैंडमार्क डील समाप्त हो गई।
- हालांकि, जो बिडेन ने 20 जनवरी के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद ईरान के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की बात कही है।
- ट्रम्प प्रशासन, इज़राइल और सऊदी अरब के लिए - पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में ग्रेट गेम में ईरान के प्रतिद्वंद्वी - इस तरह का एक तालमेल उनके हितों के लिए हानिकारक होगा। फखरीजादेह की हत्या उस राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में है।

- यदि ईरान सख्ती से जवाबी कार्रवाई करता है, तो वह इजरायल और अमेरिका के साथ एक टकराव को निमंत्रण देगा और बिडेन प्रशासन के साथ उत्पादक सहयोग के लिए संभावनाओं को समाप्त कर देगा।
- इस पर पीछे हटना ईरान की कमजोरी को उजागर करेगी और व्यावहारिकता के बीच आंतरिक विभाजन को तेज करेगी, जो यूएस और हार्डलाइनर्स को संलग्न करना चाहते हैं जो टकराव को बढ़ाना चाहते हैं।

3. इजरायल के साथ अरब संबंधों में तेजी से बदलाव।

- ईरान को डर है कि इजरायल का खाड़ी के अरब देशों के साथ सम्बन्ध बदल रहा है।
- पिछले कुछ महीनों में, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल (अब्राहम समझौते) के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं
- इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों के आसन्न सामान्यीकरण की अटकलें भी हैं - इस्लामी और अरब दुनिया का वैचारिक मूल में परिवर्तन हो रहा है।
- ईरान की दक्षिण एशिया में बहुत सद्भावना प्राप्त है, लेकिन भारत और उसके पड़ोसियों को अरब या अमेरिका के साथ तेहरान के संघर्षों में प्रवेश करने की कोई इच्छा नहीं है।
- यह सब ईरान और प्रतिद्वंद्वी अरब कैप (सऊदी अरब के नेतृत्व में, अमेरिका और अब इजरायल द्वारा समर्थित) के बीच की खाई को और चौड़ा करेगा।

4. मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व के लिए सऊदी अरब और तुर्की के बीच प्रतिद्वंद्विता को गहरा करना

- सऊदी अरब, मिस्र और यूएई मध्य पूर्व को राजनीतिक और धार्मिक मॉडरेशन की ओर लौटाना चाहते हैं।
- हालांकि, रेसेप तैयप एर्दोगन के तहत एक बार धर्मनिरपेक्ष तुर्की राजनीतिक इस्लाम का नया चैंपियन बन गया है।
- तुर्की का नया धार्मिक उत्साह मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए एर्दोगन की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अच्छा वैचारिक कवर प्रदान करता है।
- हाल के घटनाक्रमों से इस क्षेत्र में भूराजनीतिक संरेखण बदल सकते हैं, जिसमें क्षेत्र के संघर्षों में अधिक आक्रामक भूमिका निभाई जा सकती है।

निष्कर्ष

- हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व के साथ अपने जुड़ाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किए हैं, लेकिन दिल्ली इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों पर अपनी नज़र नहीं रखेगी।
- नई दिल्ली इस प्रकार मध्य पूर्व में मजबूत संबंध बनाए रखने में सफल रही है। यह द्विदलीय दोस्ती की नीति को जारी रखते हुए इंतजार करने और देखने का समय है।

Connecting the dots

- भारत की चाबहार परियोजना और परिणामी परिवर्तन: Click [here](#) & [here](#)

क्षेत्रीय प्राथमिकताएं: SCO शिखर सम्मेलन में (Regional priorities: On the SCO summit)

संदर्भ:

- आठ देशों के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में शामिल होने के तीन साल बाद, भारत ने पहली बार एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की।
- एससीओ पर एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि के लिए, यहां Click [here](#)
- हालाँकि, होग काउंसिल में सभी एससीओ देशों के प्रधान मंत्री होते हैं, न ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और न ही पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने इस बैठक में भाग लिया, जो कि पूर्व सोवियत ब्लाक और चीन में उन संसदीय लोकतंत्रों में पीएम की स्थिति के बीच एक प्रोटोकॉल बेमेल के कारण था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **COVID-19 का जवाब:** इस क्षेत्र में COVID-19 के सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और खाद्य परिणामों को दूर करने के लिए 2021-2022 के लिए "प्राथमिक व्यवहारिक उपायों की योजना" विकसित करने की आवश्यकता है।
- **बहुपक्षीयवाद:** सदस्यों ने इस तथ्य का स्वागत करते हुए बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया कि समूह को अब "अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधुनिक प्रणाली में प्रभावशाली और जिम्मेदार भागीदार" के रूप में देखा जा रहा है।
- **भारत-पाकिस्तान मतभेद:** पीएम मोदी का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, जिन्होंने सीमा पार आतंकवाद पर मजबूत टिप्पणियां कीं; उन्होंने पाकिस्तान में लक्षित टिप्पणियों में इसे एससीओ क्षेत्र की "सबसे बड़ी चुनौती" कहा। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में विवादित क्षेत्रों में "राज्य आतंकवाद" कहे जाने वाले युद्ध का सामना करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। अंतिम संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद पर किसी भी कथन को परिलक्षित नहीं किया गया, जो व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था।
- **भारत- चीन अंतर:** भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर चीन के साथ अपने मतभेदों को चिन्हित किया, जिसमें SCO के अन्य सदस्यों को BRI के समर्थन में एक पैरा शामिल नहीं किया गया।

SCO के आगे बढ़ने का क्या महत्व है?

- मतभेदों के बावजूद, भारत सरकार ने SCO समूह के महत्व को लगातार बनाए रखा है, जिसे "एशियाई नाटो" कहा जाता है, हालांकि यह सुरक्षा गठजोड़ को अनिवार्य नहीं करता है
- **क्षेत्रीय जुड़ाव:** SCO भारत की कुछ क्षेत्रीय संरचनाओं में से एक है, जो अभी इसका एक हिस्सा है, जिससे SAARC, BBIN और RCEP के साथ संबंधों में गिरावट आई है।
- **मध्य एशिया से जुड़ाव:** एससीओ भारत को अपने आउटरीच के लिए एक सुविधाजनक चैनल - व्यापार और रणनीतिक संबंध - मध्य एशियाई देशों को प्रदान करता है।
- **तनावपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए मंच:** एससीओ ने एक मंच का निर्माण किया है, , चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए भारत के साथ सबसे अधिक तनावपूर्ण संबंध हैं। जबकि सरकार ने पिछले पांच वर्षों से पाकिस्तान के साथ बैठकों में भाग लिया है, इसने चीन के साथ वार्ता के लिए एससीओ का उपयोग किया है, जिसमें इस वर्ष भी LAC का मुद्दा शामिल है।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** एससीओ को एक ऐसे समूह के रूप में देखा जाता है, जो भारत के भू-राजनीतिक संतुलन को बनाए रखता है, जो भारत के पश्चिमी दुनिया के साथ कहीं अधिक मजबूत संबंधों के लिए एक उपयोगी प्रतिवाद है।

निष्कर्ष

- एससीओ, भारत के भू-राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय जुड़ाव की तलाश कर रहा है

Connecting the dots

- सार्क और बिम्सटेक का भविष्य
- दुनिया में बढ़ते ध्रुवीकरण के समय में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति

SCO ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया (SCO Online International Exhibition launched)

भाग: GS प्रीलिम्स

समाचार में

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने साझा बौद्ध विरासत पर पहली बार SCO ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **विकसित:** एससीओ सदस्य देशों के साथ सक्रिय सहयोग में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा।
- **प्रतिभागी:** भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संग्रहालय।
- इसका लॉन्च नई दिल्ली में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ़ हेड्स (SCO CHG) की 19 वीं बैठक के दौरान हुआ।
- भारत ने कहा कि क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद एससीओ देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
- मध्य एशिया के बौद्ध दर्शन और कला एससीओ देशों को एक-दूसरे से जोड़ता है और आगंतुकों को एक ही मंच पर एससीओ देशों से बौद्ध कला प्राचीन वस्तुओं के उपयोग, सराहना और तुलना करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है।
- आगंतुक 3 डी आभासी प्रारूप में गांधार और मथुरा स्कूलों, नालंदा, अमरावती, सारनाथ, आदि से भारतीय बौद्ध संपदा को देख सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एशिया भर के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित कलात्मक धन की एक झलक देती है और एक ऐतिहासिक समय के भीतर एम्बेडेड कलात्मक उत्कृष्टता का भी प्रतिनिधित्व करती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

शंघाई सहयोग संगठन

- यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय और एक यूरोशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।

- **उद्देश्य:** 2001 में बनाए गए क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना।
- एससीओ को व्यापक रूप से "पूर्व का गठबंधन" माना जाता है, एशिया-प्रशांत में इसकी बढ़ती केंद्रीयता के कारण, और इस क्षेत्र का प्राथमिक सुरक्षा स्तंभ रहा है।
- यह भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशियन महाद्वीप के तीन-पांचवें हिस्से और मानव आबादी का लगभग आधा हिस्सा है।
- **सदस्य:** कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- **पर्यवेक्षक :** अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया।
- **संवाद सहयोगी:** अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।
- इन्फ्लुएन्जा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

समाचार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्थल-भूगोल चार द्वीप (Place in news: Bhashan Char Island)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, बांग्लादेश ने 1,00,000 लोगों के विवादास्पद नियोजित पुनर्वास के पहले चरण में 1,600 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को निचले स्तर के भूगोल चार द्वीप में पहुँचाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important value addition)

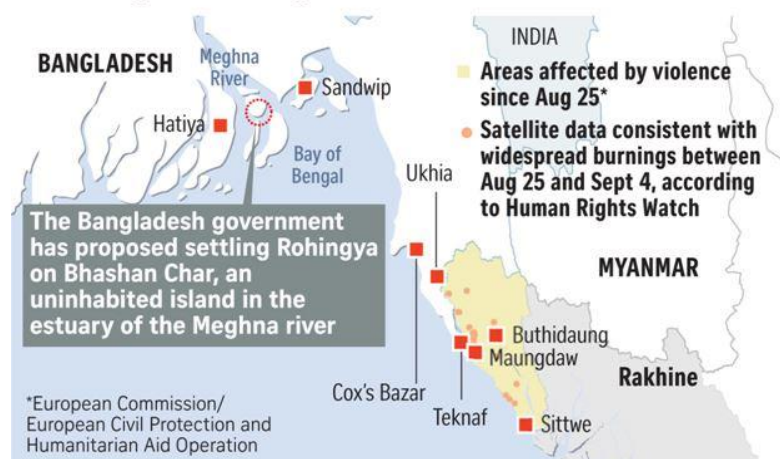
भूगोल चार द्वीप

- भूगोल चार द्वीप को चार पिया के नाम से भी जाना जाता है, यह हतिया, बांग्लादेश में एक द्वीप है।
- इस द्वीप का गठन 2006 में हिमालयन गाढ़ के साथ हुआ था।
- यह मानसून के कारण जून से सितंबर तक सालाना पानी के नीचे रहता है, और इसमें कोई बाढ़ बाढ़ नहीं है।
- जून 2015 में, बांग्लादेशी सरकार ने अपने आश्रय परियोजना के तहत द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों का निवास करने का सुझाव दिया।
- प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा "तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण" के रूप में चित्रित किया गया था।
- भूगोल चार द्वीप एक बाढ़ प्रवण द्वीप है जो 20 साल पहले समुद्र से निकला था।

चिंता:

- (1) यह बाढ़-प्रवण द्वीप है;
- (2) बार-बार आने वाले चक्रवात के लिए संवेदनशील है;
- (3) रोहिंग्या आबादी के निवास करने और उनका पोषण करने के लिए बहुत छोटा;
- (4) शिविरों में अत्यधिक भीड़ है।

Housing the refugees



आगे पढ़ने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

- [ICJ's ruling on Myanmar Rohingya](#)
- Understanding Rohingya crisis: [Click here](#)

फ्रांस का नया सुरक्षा कानून (France's New Security Law)

संदर्भ:

- सरकार द्वारा संसद में एक विवादास्पद सुरक्षा विधेयक पेश किए जाने के बाद, सड़क पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से लगातार दूसरे सप्ताह में पेरिस में पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक शक्तियां और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई।

प्रस्तावित कानून क्या करना चाहता है?

- **ग्राउंड और एयर मास सर्विलांस:** प्रस्तावित "वैश्विक सुरक्षा" कानून पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बॉडी कैमरा और ड्रोन का उपयोग करके नागरिकों की विडियो बनाने की अनुमति देता है, और रिकॉर्ड किए गए फुटेज को कमांड पोस्ट पर लाइवस्ट्रीम करने की अनुमति देता है
- **पुलिस अधिकारियों के फिल्मांकन पर प्रतिबंध:** एक अन्य प्रावधान किसी पुलिस या अर्धसैनिक अधिकारी के "चेहरे की छवि या पहचान के किसी अन्य तत्व" को प्रकाशित करने के लिए दंडित करता है जो "पुलिस ऑपरेशन" में काम कर रहा है, अगर प्रसारण "उनके शारीरिक या मानसिक अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से" किया जाता है।

नए कानून के विरोधी क्या कह रहे हैं?

- **पुलिस की कार्रवाई की जवाबदेही कमजोर हो गई:** पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि नए कानून से सार्वजनिक घटनाओं को कवर करना और पुलिस की हिंसा के उदाहरणों को रिकॉर्ड करना कठिन हो जाएगा, इस प्रकार अधिकारियों को जवाबदेह बनाना अधिक कठिन हो जाएगा।
- **पुलिस के अतिरिक्त काम नहीं चलेंगे:** आलोचकों ने नवंबर के अंत में एक सप्ताह के भीतर पुलिस की ज्यादातियों के दो उदाहरणों पर प्रकाश डाला है, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, उनका तर्क है कि प्रस्तावित कानून को छोड़ दिया गया था।
- **अधिनायकवादी कानून:** नागरिक स्वतंत्रता समूहों और वामपंथी दलों ने विधेयक को सत्तावादी और अनावश्यक कहा है, जिसमें जोर दिया गया है कि मौजूदा कानून पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं।
- **चरित्र में ड्रेकोनियन:** इसके शब्दों की आलोचना खुले-आम होने के रूप में भी की गई है, और संवाददाताओं ने चिंतित किया है कि अदालतें "नुकसान पहुंचाने के इरादे" शब्द की व्याख्या कैसे करेंगी।
- **प्रेस की स्वतंत्रता:** बिल में प्रावधान विरोध / झड़प के दौरान पुलिस अधिकारियों के कवरेज को प्रतिबंधित करके प्रेस की स्वतंत्रता को लक्षित करने का इरादा रखते हैं।

बिल के समर्थकों ने क्या कहा है?

- **पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा:** नए कानून का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों को ड्यूटी से हटने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग और उत्पीड़न से बचाना है।
- **नागरिकों द्वारा समर्थन:** ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार-कमीशन के सर्वेक्षण में पाया गया कि 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नए सुरक्षा कानून का समर्थन किया।
- **बढ़ते आतंकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में परंपरावादियों का उदय:** विशेष रूप से, विश्लेषकों ने ऐसे कानूनों का समर्थन करने वाले फ्रांसीसी मतदाताओं की एक सही पारी की ओर इशारा किया है जो पुलिस को सशक्त बनाते हैं। उदारवाद से यह बदलाव स्कूली शिक्षक सैमुअल पैटी, और नीस स्ट्रेबिंग हमले के अक्टूबर की शुरुआत सहित हाल के आतंकी हमलों के एक परिणाम के बाद अधिक स्पष्ट है।
- **घरेलू राजनीति:** राष्ट्रपति मैक्रोन लगातार 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले दक्षिणपंथी मतदाताओं से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कानून जिनमें अधिनायकवाद का तड़का है, ऐसे मतदाताओं को आकर्षित करने में उपयोगी है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- एक और विवादास्पद कानूनी उपाय, तथाकथित "विरोधी अलगाववाद" बिल का प्रस्ताव फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यह विधेयक, जिसका उद्देश्य इस्लामिक कट्टरपंथ पर नकेल कसना है, को दिसंबर में संसद में पेश किया जाना है, और इसमें कई उपायों की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्कूली शिक्षा सुधार शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुस्लिम बच्चे बाहर न निकलें, मस्जिदों और प्रचारकों पर कड़े नियंत्रण, फ्रांस में मुसलमानों के बीच चिंता का विषय है।

Connecting the dots

- George [Floyd Incident of US](#)

- [Thoothukudi violence and Judicial Deaths in India](#)

पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विशेष चिंता का विषय बने देशों (कंट्रीज ऑफ पर्टीक्यूलर कंसर्न या सीपीसी) के लिए नामित (Pakistan and China designated among countries of Particular Concern by the USA)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान और चीन को आठ अन्य देशों में नामित किया है जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष रूप से चिंतित हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key takeaways)

- सीपीसी का पदनाम, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता (USCIRF) पर अमेरिकी आयोग द्वारा शीर्ष स्तरीय सिफारिश है जब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान और चीन के अलावा म्यांमां, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को उस सूची में रखा गया है जो “धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर एवं घोर उल्लंघन” में लिप्त हैं या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं”।
- गंभीर उल्लंघनों के लिए विशेष वॉच लिस्ट देशों द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है।
- सीपीसी सूची में राष्ट्र: पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान।
- USCIRF की सिफारिश है कि भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम को भी सीपीसी में नामित किया जाना चाहिए, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।
- ऐसी सरकारें जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन करती या या फिर ये उल्लंघन, उन्हें विशेष निगरानी सूची में शामिल किया गया है।
- कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस भी सूची में हैं।

मोरक्को ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए (Morocco Normalises Relations with Israel)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, मोरक्को और इजरायल ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्तता किए गए सौदे में संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- यह यूएई, बहरीन (अब्राहम समझौते) और सूडान के बाद मोरक्को को इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाला चौथा अरब देश बनाता है।
- मोरक्को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करेगा और इजरायल के साथ आधिकारिक संपर्क को फिर से शुरू करेगा।
- इजरायल और मोरक्को कंपनियों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दूतावास जल्द ही खुलेंगे।
- मोरक्को का इरादा इजरायल के पर्यटकों के लिए और मोरक्को से सीधी उड़ानों की सुविधा प्रदान करना है।



संबंधित आलेख:

- सूडान और इजराइल: [Click here](#)
- बहरीन और इजराइल: [Click here](#)
- अब्राहम समझौते: [Click here](#)

फेसबुक के खिलाफ अभियोग मुकदमा (Antitrust suit against Facebook)

संदर्भ:

- संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार और 48 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों की सरकारों द्वारा दायर दो मुकदमों ने फेसबुक के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप द्वारा अधिग्रहण को रोक दिया है।
- अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) के मुकदमे ने फेसबुक पर अधिग्रहण के साथ प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया - भले ही एफटीसी ने खुद ही सौदों को मंजूरी दी थी।

एफटीसी का मुकदमा क्या कहता है?

- एफटीसी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक "एंटीकोमेटिक आचरण के एक साल के लंबे पाठ्यक्रम के माध्यम से अवैध रूप से अपने व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग एकाधिकार को बनाए रख रहा है"।
- मुकदमा "अमेरिका के सामान्य वकीलों के गठबंधन" द्वारा एक "लंबी जांच" का पालन किया।
- फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 1 बिलियन \$ में 2012 में अधिग्रहण किया और 2014 19 बिलियन \$ के साथ व्हाट्सएप के अधिग्रहण को अवैध प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के प्रयासों के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।
- एफटीसी ने फेसबुक पर "सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर प्रतिस्पर्धी-विरोधी स्थितियों" को लागू करने का भी आरोप लगाया है। यह कहता है कि फेसबुक की प्रथाओं ने प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाया है और "व्यक्तिगत सामाजिक नेटवर्किंग के लिए कुछ विकल्पों के साथ उपभोक्ताओं को छोड़ दिया है, और विज्ञापनदाताओं को प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित किया है।"
- मुकदमा यह बताता है कि फेसबुक ने अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई पर कड़े नियंत्रण का प्रयोग करके अपने "तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की अपने प्लेटफॉर्म पर बहुमूल्य इंटरकनेक्ट तक पहुँच" को प्रतिबंधित कर दिया है।
- यह ट्विटर के लघु वीडियो ऐप वाइन का उदाहरण देता है, जिसे 2013 में पेश किया गया था। फेसबुक ने वाइन के लिए एपीआई एक्सेस को बंद कर दिया है, जो प्रभावी रूप से बढ़ने की क्षमता को सीमित करता है।

मुकदमे में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक के एकाधिकार के कारण कंपनी को "अत्यधिक मुनाफा हुआ", है।

फेसबुक के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण के बारे में मुकदमा विशेष रूप से क्या कहता है?

- FTC ने उल्लेख किया है कि इंस्टाग्राम का अधिग्रहण ऐसे समय में हुआ था जब उपयोगकर्ता "डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्मार्टफोन पर स्विच कर रहे थे" ।
- व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक ने भी ऐसा ही किया, एफटीसी का कहना है। जब यह पता चला कि व्हाट्सएप मोबाइल मैसेजिंग में "स्पष्ट वैश्विक श्रेणी का नेता" है, तो उसने प्रतियोगिता को खरीदा।
- शिकायत के अनुसार, व्हाट्सएप का अधिग्रहण करने वाले फेसबुक का यह भी मतलब था कि "भविष्य के किसी भी खतरे में मोबाइल मैसेजिंग में अधिक कठिन समय बढ़ेगा।"
- यह काफी हद तक सही है। व्हाट्सएप मोबाइल मैसेजिंग स्पेस पर हावी रही, विश्व स्तर पर इसके 2 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं; अकेले भारत में 400 मिलियन से अधिक। कोई अन्य मैसेजिंग ऐप भी इसके करीब नहीं आता है।
- लेकिन एफटीसी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सौदों को मंजूरी दे दी थी।
- हां - लेकिन यह कहता है कि "कार्रवाई केवल अधिग्रहण से अधिक चुनौती है"। यह "व्यक्तिगत सामाजिक नेटवर्किंग बाजार के एकाधिकार का गठन करने वाले आचरण के बहु-वर्षीय पाठ्यक्रम को चुनौती देता है"।
- FTC यह भी कहता है कि यह अक्सर कानून का उल्लंघन करने पर स्वीकृत लेनदेन को चुनौती देता है।

FTC क्या चाहता है?

- मुकदमा "इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित संपत्ति का विभाजन" चाहता है।

- यदि FTC जीत जाता है, तो फेसबुक को Instagram और WhatsApp को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, दो उत्पाद जो युवा उपयोगकर्ताओं और नए भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक आकर्षक हैं, और इसलिए कंपनी के विकास को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- FTC यह भी चाहता है कि "फेसबुक को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर प्रतिस्पर्धा विरोधी परिस्थितियों को लागू करने से रोकें"। इसका मतलब है कि फेसबुक को "भविष्य के विलय और अधिग्रहण के लिए पूर्व सूचना और अनुमोदन प्राप्त करना होगा"।

फेसबुक ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?

- फेसबुक ने मुकदमों को "संशोधनवादी इतिहास" कहा है। कंपनी ने कहा है कि यह सच नहीं है कि इसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और इसका नाम "Apple, Google, Twitter, Snap, Amazon, TikTok और Microsoft" है।
- मुकदमे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि उपयोगकर्ता प्रतिस्पर्धा करने वाले ऐप्स पर अक्सर जा सकते हैं और कर सकते हैं
- फेसबुक ने इसके अधिग्रहण पर "हमले" पर भी सवाल उठाया है, और याद किया कि एफटीसी ने एक गहन समीक्षा के बाद इंस्टाग्राम सौदे को मंजूरी दे दी थी।
- व्हाट्सएप लेनदेन की समीक्षा यूरोपीय संघ द्वारा भी की गई थी।
- फेसबुक के अनुसार, "उन कठिन चुनौतियों को इंटरनेट के नियमों को अपडेट करके सबसे अच्छा हल किया जाता है।"
- एपीआई प्रतिबंधों के बारे में, फेसबुक का तर्क है कि उसे अपने व्यापारिक भागीदारों को चुनने की अनुमति है। YouTube, Twitter और WeChat ने इन API नीतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है।

निष्कर्ष

- मुकदमे का खुलासा दुनिया भर में बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि इसमें बिग टेक इंडस्ट्री और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास पर भी प्रभाव है।

मोरक्को-इजराइल सौदा (Morocco-Israel deal)

संदर्भ: मोरक्को पांच महीनों में इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब देश बन गया है।

10 दिसंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया कि अरब देशों (यूएई, बहरीन, सूडान और अब मोरक्को) और यहूदी राज्य के बीच सामान्यीकरण समझौतों की श्रृंखला पश्चिम एशिया में शांति ला रही है। अक्टूबर में, सूडान को इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए अपने सौदे के हिस्से के रूप में, वाशिंगटन ने सूडान को अपनी 'स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म' सूची से हटा दिया, जिसमें से वह 27 वर्षों से एक हिस्सा था।

बदले में मोरक्को को क्या मिलता है?

- इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने के मोरक्को के फैसले के बदले में, अमेरिका ने पश्चिमी सहारा पर, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में एक विवादित क्षेत्र, जो दशकों से मोरक्को के नियंत्रण में है, पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी है।
- मोरक्को लंबे समय से पश्चिमी सहारा के अपने दावों की मान्यता के लिए, आर्थिक दबाव और कूटनीति का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहा है।
- यह इजरायल के साथ एक देश, जिसके साथ दशकों से गुप्त संबंधों का विकास हुआ था।



छवि स्रोत: अलजजीरा

पश्चिमी सहारा विवाद का इतिहास क्या है?

- पश्चिमी सहारा बड़ा, शुष्क और कम आबादी वाला क्षेत्र है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और मॉरिटानिया के साथ एक सीमा साझा करता है और एक लंबा अटलांटिक तट एक स्पेनिश उपनिवेश था। यह क्षेत्र सहरावी जनजाति का घर है।
- 1970 के दशक में, जब अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय दबाव ने अफ्रीका में अपनी कॉलोनियों को खाली करने के लिए स्पेन पर मुहिम शुरू की, लीबिया और अल्जीरिया ने पश्चिमी सहारा में स्पेनिश शासन के खिलाफ एक सहरावी विद्रोही समूह को खोजने में मदद की।
- 1975 में, मोरक्को और मॉरिटानिया के साथ मैड्रिड समझौते के हिस्से के रूप में, स्पेन ने इस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया, जिसे तब स्पेनिश सहारा कहा जाता था।
- आरोपों के अनुसार, स्पेन 28 फरवरी, 1976 से पहले इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और तब तक, स्पेनिश गवर्नर जनरल दो मोरक्कन और मॉरिटानियन उप-राज्यपालों की मदद से क्षेत्र का प्रशासन करेगा।
- मोरक्को और मॉरिटानिया दोनों ने अपने दावों का दावा करने के लिए सैनिकों को पश्चिमी सहारा में स्थानांतरित कर दिया।
- अल्जीरिया द्वारा समर्थित सहराई विद्रोह समूह (पोलिसारियो फ्रंट) ने अपनी वापसी की मांग करते हुए गुरिल्ला प्रतिरोध जारी रखा। स्पेन में अपनी उपस्थिति समाप्त करने से एक दिन पहले 27 फरवरी, 1976 को, पोलिसारियो फ्रंट ने पश्चिमी सहारा में सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (SADR) घोषित किया।
- SADR को कई अफ्रीकी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है और अफ्रीकी संघ का सदस्य है।

विवाद और मोरक्को के दावे के आधार पर UN कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है?

- मोरक्को और मॉरिटानिया ने पश्चिमी सहारा पर दावा किया था कि जब वह एक स्पेनिश उपनिवेश था।
- 1974 में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यू.एन. महासभा द्वारा 19 वीं शताब्दी में स्पेन द्वारा अपने उपनिवेशीकरण के समय पश्चिमी सहारा और मोरक्को और मॉरिटानिया के बीच मौजूद कानूनी संबंधों को देखने के लिए कहा गया था।
- अदालत को पश्चिमी सहारा और मोरक्को या मॉरिटानिया के बीच "क्षेत्रीय संप्रभुता के किसी भी संबंध का कोई सबूत नहीं मिला", लेकिन कहा कि "संकेत" थे कि क्षेत्र में कुछ जनजातियां मोरक्को के सुल्तान के प्रति वफादार थीं।

- अपने निष्कर्ष में, अदालत ने महासभा के प्रस्ताव 1541 का समर्थन किया जो पुष्टि करता है कि विघटन को सुनिश्चित करने के लिए, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पूर्ण अनुपालन आवश्यक है।
- लेकिन मोरक्को के राजा हसन II ने देश के रुख के प्रति समर्पण के रूप में अदालत की राय का समर्थन किया और उत्तरी सीमा के पार सैनिकों को पश्चिमी सहारा में स्थानांतरित कर दिया। मॉरिटानिया बाद में शामिल हुए। इसने दोनों देशों के विरोध में पोलिसारियो फ्रंट के साथ तीन-तरफा लड़ाई के लिए मंच तैयार किया।

दशकों में संघर्ष की प्रगति कैसे हुई?

- तीन-तरफा संघर्ष लगभग चार वर्षों तक चला। अगस्त 1979 में, मॉरिटानिया ने पोलिसारियो के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे देश की पश्चिमी सहारा में सैन्य भागीदारी समाप्त हो गई।
- जब मॉरिटानियन सेना रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से से हट गई, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो मोरक्को ने तेजी से सैनिकों को उन्नत किया।
- मोरक्को के सैनिकों और पोलिसारियो फ्रंट के बीच युद्ध जारी रहा।
- 1991 में, जब एक संघर्ष विराम हासिल किया गया था, तो मोरक्को ने लगभग 80% क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। 1991 के युद्धविराम में वादा किया गया, स्वतंत्रता जनमत संग्रह अभी बाकी है
- युद्ध ने लगभग 200,000 सहारावियों को पड़ोसी देश अल्जीरिया में भागने के लिए मजबूर किया था, जहां पोलिसारियो विद्रोही शरणार्थी शिविर चला रहा है
- SADR मोटे तौर पर पश्चिमी सहारा के पूर्वी तट और शरणार्थी शिविरों से संचालित हो रहा है।
- मोरक्को के सैनिकों ने पश्चिमी सहारा के अटलांटिक तट से मोरक्को के पहाड़ों तक बरम नामक एक विशाल रेत की दीवार बनाई है, जिसे वे पोलिसारियो के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को विभाजित करते हैं।

इजरायल सौदे का संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- मोरक्को और इजरायल के बीच सामान्यीकरण के सौदे का पश्चिमी सहारा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
- लेकिन अमेरिका ने मोरक्को को जो रियायत दी है - वॉशिंगटन ने पश्चिमी सहारा के मोरक्को के कब्जे की मान्यता जो कि इजरायल के साथ मोरक्को के समझौते के बदले में थी - संघर्ष को भड़का सकता है।
- इस क्षेत्र में शत्रुता की वजह से पश्चिमी अफ्रीका को अस्थिर किया जा सकेगा और इस्लामवादी विद्रोह के क्षेत्र से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका और फ्रांस दोनों के प्रयासों के दशकों को कमजोर कर देगा।
- हाल ही में, मोरक्को ने दोनों पक्षों के बीच यू.एन.-नियंत्रित बफर क्षेत्र में एक आक्रामक शुरूआत की और बदले में, पोलिसारियो ने कहा कि यह सशस्त्र संघर्ष को फिर से शुरू करेगा।
- ट्रम्प प्रशासन द्वारा मोरक्को के दावे को मान्यता दिए जाने के बाद, पोलिसारियो ने कहा कि यह तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि मोरक्को की सेना पीछे नहीं हटती।
- अमेरिका का यह कदम पोलिसारियो के सबसे बड़े समर्थक अल्जीरिया को परेशान करेगा।
- उन देशों के बीच, जिन्होंने अमेरिकी फैसले की निंदा की, रूस ने कहा कि पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता की मान्यता "अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है"।

क्यूबा में सैन इसिद्रो आंदोलन (San Isidro Movement in Cuba)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; मौलिक अधिकार

समाचार में

- क्यूबा में, अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले कलाकारों और कार्यकर्ताओं का एक अभियान हाल ही में खबरों में रहा है।
- क्यूबा 60 से अधिक वर्षों से एक सत्तावादी कम्युनिस्ट शासन के अधीन है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- Movimiento San Isidro, या San Isidro Movement (MSI), ने कलात्मक कार्यों की राज्य सेंसरशिप का विरोध करने के लिए दो साल पहले शुरू किया था।
- यह सितंबर 2018 में शुरू हुआ, जब क्यूबा सरकार ने डिक्ली 349 को लागू करने की मांग की, जो एक ऐसा कानून है जिसने सांस्कृतिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए देश के संस्कृति मंत्रालय को शक्तियां दी होंगी, जिसे उसने मंजूरी नहीं दी।
- सैन इसिद्रो में एकत्रित हुए डिक्ली, कलाकारों, कवियों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के विरोध में, यह एक काले-बहुमत वाला इलाका है जो हवाना के सबसे गरीब और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय वार्डों में से है, और जो पुराने हवाना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है।
- क्यूबा और अमेरिका के बीच 2015 के सौदे के बाद, जिनके प्रावधानों में से एक ने यह तय किया कि क्यूबा शासन को अपने लोगों को अधिक से अधिक इंटरनेट स्वतंत्रता की अनुमति देनी चाहिए, प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट पर अपने संदेश को सापेक्ष सहजता के साथ जोड़ने और बढ़ाने में कामयाब रहे।
- यह अब देश के भीतर और बाहर दोनों क्यूबा के असंतुष्टों के लिए एक मंच बन गया है।

रोहिंग्या शरणार्थी: बांग्लादेश उन्हें स्थानांतरित कर रहा है (Rohingya Refugees: Bangladesh Relocating them)

संदर्भ: बांग्लादेश ने 1,600 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को एक निचले स्तर के भूतल चार द्वीप पर पहुंचाया।

हाल ही हुए परिवर्त,

- बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के 1,00,000 को भूतल चार द्वीप में स्थानांतरित करने के लिए विवादास्पद पुनर्वास नीति की घोषणा की है।
- लगभग एक लाख रोहिंग्या - जिनमें से अधिकांश तीन साल पहले पड़ोसी म्यांमार में एक सैन्य हमले के बाद भाग गए थे - दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में स्क्वल्ड शिविरों में रहते हैं। म्यांमार में इनकी कोई भी वापसी की संभावना नहीं है।

- 10 दिसंबर को, एजेंसियों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार अन्वेषक ने बांग्लादेश से भाशन चार के रिमोट आइलेट के सुरक्षा मूल्यांकन की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जहां सरकार ने 1,600-रोहिंग्या शरणार्थियों को भेज दिया था।

क्या यह द्वीप सुरक्षित है?

- भशान चार द्वीप, लगभग 13,000 एकड़ की एक चार-भूमि है, जो गाद के संचय द्वारा बनाई गई है जहाँ मेघना नदी बंगाल की खाड़ी से समृद्ध जलोढ़ निक्षेपों के साथ मिलती है।
- चार-भूमि मेघना और पद्मा नदियों में एक सामान्य विशेषता है और इसका शाब्दिक अर्थ है "भूस्खलन को पार करना"।
- जैसा कि नाम से पता चलता है, चार बांग्लादेश की स्थायी भूमि विशेषता का हिस्सा नहीं था, लेकिन हाल ही में दिखाई दिया।
- भशान चार द्वीप एक मैंग्रोव जंगल से घिरा हुआ है जिसने इसे भौगोलिक स्थिरता दी है।
 - एक पर्यटन अवसर को ध्यान में रखते हुए, बांग्लादेश सरकार ने 2013 में भशान चार द्वीप को संरक्षित वन भूमि घोषित किया था।
- यह चटगांव के कॉक्स बाजार से ढाई घंटे की दूरी पर है।
- भशान चार द्वीप के असुरक्षित होने का मुख्य तर्क यह है कि इन जमीनों को अस्थिर और बाढ़-ग्रस्त माना जाता है। अन्य भय कारक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात शामिल हैं जो हर इस साल क्षेत्र में आते करते हैं।

रोहिंग्या के लिए क्या व्यवस्था है?

- पिछले कुछ वर्षों में, बांग्लादेश ने सड़कों का निर्माण किया है और आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क को भशान चार द्वीप में लाया गया है।
- बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए लगभग 1,350 एकड़ जमीन रखी है, जिसमें से 432 एकड़ उनके पुनर्वास के लिए समर्पित है और बाकी भविष्य की परियोजनाओं के लिए बनी हुई है।
- सरकार ने रोहिंग्या के लिए नामित अनुभाग में बड़ी संख्या में आवास इकाइयों का निर्माण किया है।
- 1600 रोहिंग्या शरणार्थियों को अब लाल-छत वाली आवासीय इकाइयों में रखा जा रहा है और अधिकांश घर अप्रत्याशित उच्च ज्वार की लहरों का सामना करने में मदद करने के लिए जमीन से चार फीट ऊपर बनाए गए हैं

क्यों बांग्लादेश शरणार्थियों को स्थानांतरित कर रहा है?

- कॉक्स बाजार के निकट कुतुपलॉग के रोहिंग्या शरणार्थी 2017 से म्यांमार के साथ वन सीमाओं के पास एक बड़े शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, जब उन्हें जंगल और नदियों को पार करने के लिए मजबूर किया गया था, जो बांग्लादेश और म्यांमार के राखीन प्रांत के बीच की सीमा का गठन करते थे।
- उनके आगमन के बाद से, 1 मिलियन शरणार्थी, बांस और तिरपाल संरचनाओं के तहत कुटुपालोंग शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं।
- यह शिविर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के लिए एक अभयारण्य था।
- साथ ही, कुटुपालोंग अपने बढ़ते अपराध दर के कारण भी चर्चा में रहे हैं।
- बांग्लादेश का तर्क है कि यह द्वीप एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा।

मानवाधिकार एजेंसियां क्यों परेशान हैं?

- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों को भूषण चार में स्थानांतरित करने की अपनी योजना को छोड़ना चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बस्ती के लिए चार-भूमि को अभी तक सुरक्षित घोषित नहीं किया गया था।
- यह आरोप लगाया गया है कि कई रोहिंग्या जिन्हें स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी।
- मानवाधिकार एजेंसियां तर्क दे रही हैं कि शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित कोई भी निर्णय पारदर्शी होना चाहिए और इसमें रोहिंग्या लोगों की पूर्ण भागीदारी शामिल होनी चाहिए।

आगे क्या होगा?

- राजनयिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि ढाका पूरे शरणार्थी को स्थानांतरित करने की योजना नहीं बनाता है और केवल कुतुपलॉग में भीड़ को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए देश की दीर्घकालिक योजना म्यांमार के राखीन प्रांत में उनके प्रत्यावर्तन की तलाश है।

Connecting the dots

- ICJ's ruling on Myanmar Rohingyas: Click [here](#)

इजरायल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं (Israel establishes diplomatic ties with Bhutan)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, इजरायल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं।



महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे पहले, इजरायल ने 1982 से भूटानी मानव संसाधन विकास का समर्थन किया है, खासकर कृषि विकास के क्षेत्र में जिसने सैकड़ों भूटान युवाओं को लाभान्वित किया है।
- दोनों देशों ने एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया और विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्ष दूतावास स्थापित नहीं करेंगे और दिल्ली में अपने मिशनो के माध्यम से समन्वय करेंगे।
- राजनयिक संबंधों की स्थापना से दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, कृषि विज्ञान और आपसी लाभ के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए रास्ते बनेंगे।
- पर्यटन के लिए, भूटान जो बाहरी लोगों की संख्या को सीमित करता है जो अब इजरायल के लिए अधिक खुले होंगे।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ाया जाएगा।

सम्बंधित आलेख (Related articles):

- Israel-Morocco deal: [Click here](#)
- Sudan and Israel: [Click here](#)
- Bahrain and Israel: [Click here](#)
- Abraham Accords: [Click here](#)

चीन का ब्रह्मपुत्र बांध: दक्षिण एशिया में ट्रांस-बॉर्डर वॉटर गवर्नेंस (China's Brahmaputra dam: Trans-boundary water governance in South Asia)

संदर्भ: 29 नवंबर, 2020 को, चीनी राज्य मीडिया ने घोषणा की कि बीजिंग तिब्बत में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब यारलुंग जंगबो नदी पर एक मेगा बांध बनाएगा। इस कदम का भारत के उत्तर पूर्व में जल सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

दक्षिण एशिया और ट्रांसबाउंड्री नदियाँ

- पूरा दक्षिण एशिया उच्च 'से' अत्यंत उच्च 'जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में आता है। यह, भले ही इसमें बहुत अधिक ताजे पानी हो।
- दक्षिण एशिया हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के बाकी महाद्वीपों से अलग है।
- दक्षिण एशिया में कुछ 25 प्रमुख नदियाँ हैं। जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर की प्राथमिकताओं के रूप में पहचाने जाने वाले दुनिया के 30 प्रमुख नदी घाटियों में से नौ भारत में हैं, जो दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से का निर्माण करते हैं।
- ब्रह्मपुत्र प्रवाह की मात्रा को वहन करता है जो यूरोप की 20 प्रमुख नदियों से अधिक है। नदी बंगाल की खाड़ी में विलय से पहले दुनिया के सबसे गहरे घाट और इसके तीन सबसे अधिक आबादी वाले देशों - चीन, भारत और बांग्लादेश - से होकर गुजरती है।

मुद्दे

- **ट्रांसबाउंड्री प्रभाव:** नदियों, जंगलों और पहाड़ों जैसे प्राकृतिक संसाधन राजनीतिक सीमाओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वे लाखों वर्षों के प्राकृतिक चक्रों में विकसित हुए हैं। नदियों के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में बांध या पानी के डायवर्सन परियोजनाएं नदी के बहाव वाले देशों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
- **चीन को लाभ:** तिब्बत में उत्पन्न होने वाली नदी प्रणालियों से जल प्रवाह को कम करने या मोड़ने के लिए चीन को बांधों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में स्पष्ट लाभ है। निचले इलाकों के समुदायों को स्वीकार करना होगा कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। इस प्रकार, एक सामान्य भावना है कि चीन हेडवार्टर्स को नियंत्रित करता है।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पारिस्थितिक खतरे:** हिमालय के हिमनद और हिमखंड पीछे हटते जा रहे हैं। यदि वर्तमान में गर्मी जारी है, तो एक अनुमान है कि तिब्बती पठार के जलमार्ग पहले बाढ़ और फिर धीरे-धीरे सूख सकते हैं, जिससे विशाल परिदृश्य रेगिस्तान में बदल सकता है।
- **पानी का टकराव:** असंतोष और संघर्ष एक ऐसी स्थिति से उत्पन्न होता है जहां पानी की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक होती है। वे प्रतिस्पर्धा करने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच या ट्रांसबाउंडरी सरकारों के बीच पानी के उपयोग और आवंटन पर असममित शक्ति नियंत्रण से भी परिणाम कर सकते हैं। इसके अलावा, दक्षिण एशिया में नदी प्रणालियों के प्रबंधन के लिए एक सहकारी ढांचे की कमी से अनसुलझे संघर्ष होते हैं।
- **अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण:** रिडक्शनलिस्ट इंजीनियरिंग दृष्टिकोण केवल नदी जल संसाधन के प्रतिस्पर्धी दोहन के एक मॉडल पर अल्पकालिक लाभ को देखता है। आपूर्ति-केंद्रित सिंचाई विभाग विविधताओं, बांधों, बैराज, नहरों, सुरंगों और टर्बाइनों के संदर्भ में बात करता है।
- **घरेलू संघीय मुद्दा:** चूंकि पानी एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य जल शासन पर विशेष अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संचयी परिणाम दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता के बारे में आशावाद को प्रेरित नहीं करते हैं। यह आंशिक रूप से राज्यों और कमजोर संस्थानों द्वारा खराब विचलन के लिए जिम्मेदार है।

रास्ता आगे- दृष्टिकोण का परिवर्तन

- वास्तविक मुद्दा जल संसाधनों की कमी नहीं है। बल्कि, यह 'सामाजिक संसाधनों' की कमी है और विपक्षी लोगों के बीच 'शक्ति असमानताओं' की प्रचुरता है।
- हमें नदी बेसिन प्रबंधन के लिए फ्लूवियल परिदृश्य दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। यह दृष्टिकोण परिदृश्य और पकड़ की अखंडता का सम्मान करता है।
- यह नदी के व्यवहार और पैटर्न का सम्मान करता है, यह नदी के बाढ़ और सूखे के वैध अधिकारों का सम्मान करता है। वे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के अविभाज्य अंग हैं।
- फ्लूवियल मेमोरी कॉन्सेप्ट 'सॉल्यूशन' के आधार पर एक तदर्थ आधार पर पहुंच के आधार पर नहीं है। यह संपूर्ण प्रवाह-निवास-पकड़ने के दृष्टिकोण को लेता है।
- चूंकि गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन और हिमालय सभी द्विपदीय राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र की तरल स्मृति का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे किसी भी प्रमुख अवरोध के बिना स्रोत के लिए स्वतंत्र रूप से बहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत-बांग्लादेश वर्चुअल समिट आयोजित (India-Bangladesh Virtual Summit held)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री और बांग्लादेश के प्रधान मंत्री ने हाल ही में आभासी प्रारूप में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से बंगबंधु-बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- उन्होंने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिलाहाटी के बीच एक रेलवे लिंक का उद्घाटन किया।
- हल्दीबाड़ी - चिलाहाटी मार्ग असम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पारगमन के लिए फायदेमंद होगा।
- उन्होंने इछामाटी, कालिंदी, रायमंगोल और हरिभंगा नदियों के खंड के साथ पट्टी के नक्शे का एक नया सेट तैयार करने के लिए संयुक्त सीमा सम्मेलन की एक प्रारंभिक बैठक आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- राजशाही शहर में सौंदर्यीकरण और नगर विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया।
- खुलना में खालिसपुर कॉलेजिएट गर्ल्स स्कूल का निर्माण भी शुरू हुआ।

शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों / समझौतों की सूची:

- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर समझ की रूपरेखा
- स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन
- ट्रांसबाउंडरी हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल
- बारिसहाल सिटी कॉर्पोरेशन के लिए लमचोरी क्षेत्र में अपशिष्ट की आपूर्ति और कचरे के सुधार / ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए समझौता ज्ञापन
- कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय, ढाका, बांग्लादेश और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत के बीच समझौता ज्ञापन
- भारत-बांग्लादेश सीईओ के फोरम के संदर्भ की शर्तें



भारत ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) को 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वादा किया (India pledges a sum of USD 1 million to the World Anti-Doping Agency - WADA)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारत ने एजेंसी के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) को 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वादा किया है।
- यह WADA को नवीन एंटी-डोपिंग परीक्षण और पहचान विधियों को विकसित करने की अनुमति देगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी

- यह खेल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक योजना है।
- एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में विश्व डोपिंग रोधी संहिता की निगरानी शामिल है, जिसके प्रावधानों को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा लागू किया गया है।
- मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा।
- 1999 में स्थापित।

Fordow ईंधन संवर्धन संयंत्र (Fordow Fuel Enrichment Plant -FFEP)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- उपग्रह चित्रों के अनुसार, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के साथ तनाव के बीच फोर्डो में अपनी भूमिगत परमाणु सुविधा पर एक साइट का निर्माण शुरू कर दिया है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- Fordow ईंधन संवर्धन संयंत्र (Fordow Fuel Enrichment Plant -FFEP) एक ईरानी भूमिगत यूरेनियम संवर्धन सुविधा है जो ईरानी शहर Qom के 20 मील उत्तर में Fordow गांव के पास स्थित है।
- यह दूसरी ईरानी यूरेनियम संवर्धन सुविधा है, अन्य का नाम नटांज है।
- Fordow में ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी नए निर्माण को स्वीकार नहीं किया है।

तुर्की द्वारा पारित सामूहिक विनाश बिल के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकना (Preventing Financing Of Proliferation Of Weapons Of Mass Destruction bill passed by Turkey)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - इंटरनेशनल रिलेशंस

समाचार में

- तुर्की की संसद ने "विनाश के हथियारों के प्रसार के प्रसार को रोकने" नामक एक विधेयक पारित किया।
- इससे नागरिक समाज समूहों की निगरानी बढ़ेगी।



महत्वपूर्ण तथ्य

- बिल को 2019 की रिपोर्ट के बाद पारित किया गया था, जो कि अंतर्राज्यीय निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा तैयार तुर्की में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण से लड़ने के लिए था।
- बिल में 43 लेख शामिल हैं और इसने तुर्की के कानून के संघों के सात कानूनों में बदलाव किया है।
- यह तुर्की को आतंकी वित्तपोषण के पेरिस स्थित निगरानी समूह द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से रोकने के लिए है।
- विधेयक तुर्की सरकार को एनजीओ के लिए ट्रस्टियों को नियुक्त करने, उनकी गतिविधियों को निलंबित करने, उनकी संपत्ति को जब्त करने और धन के अपने स्रोतों की निगरानी करने की शक्ति देता है।
- आलोचकों का मानना है कि यह तुर्की के संविधान के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह संघ की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करता है

- बिलों में शामिल किए गए नए लेख, “सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की रोकथाम को रोकने पर बिल” में शामिल हैं, गैर-सरकारी संगठनों के वार्षिक निरीक्षण की अनुमति देते हैं, जो आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति देते हैं।
- तुर्की की संसद ने एक कानून को मंजूरी दी, जिससे नागरिक समाज समूहों की सरकारी निगरानी बढ़ेगी, जो अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि एसोसिएशन की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।
- बिलों में शामिल किए गए नए लेख, “सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की रोकथाम को रोकने पर बिल” में शामिल हैं, गैर-सरकारी संगठनों के वार्षिक निरीक्षण की अनुमति देते हैं, जो आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से हैं।
- कानून भी आंतरिक मंत्रालय को संघों के सदस्यों को बदलने की अनुमति देता है यदि उन्हें आतंकवाद के आरोपों पर जांच की जा रही है और यह अदालती आदेश के साथ गतिविधियों को निलंबित करने की शक्ति देता है। यह अदालतों को परमिट के बिना ऑनलाइन दान अभियानों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की भी अनुमति देता है।
- राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा प्रस्तावित विधेयक, पार्टी और उसके राष्ट्रीय सहयोगियों के वोटों के साथ पारित हुआ।
- तुर्की के आतंकवाद-रोधी कानून व्यापक हैं और इससे राजनेताओं, पत्रकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और हजारों लोगों का पलायन हुआ है।
- लगभग 680 सिविल सोसाइटी समूहों ने बिल के खिलाफ एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, यह कहते हुए कि यह धन जुटाने और मंत्रालय के दबाव में उन्हें व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता को सीमित करेगा। उन्होंने कहा कि कानून तुर्की संविधान का उल्लंघन करता है, जो एसोसिएशन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- ह्यूमन राइट्स वॉच ने वोट से पहले एक बयान में कहा, “तुर्की के अभियोजक नियमित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा और एसोसिएशन के अधिकारों का शांतिपूर्ण अभ्यास करने के लिए लोगों में आतंकवाद की जांच करते हैं।”


**e-CLASS ROOM
PROGRAM 2021**

IASbaba's e-CLASSROOM LEARNING PROGRAM (e-CLP) 2021

Foundation Course - CLASSROOM (Integrated - Prelims & Mains) MENTORSHIP Program

Key Features:

- **Complete solution for UPSC Preparation** - Includes Classes, Tests, Mentorship, Interview Guidance and Mock Interviews
- **Hybrid Model of Classes** - Pre-recorded classes + Live-streaming facility of Doubt Clearing Sessions
- **Integrated and Comprehensive Program** - Covers Prelims, Mains and Interview
- **Daily targets and plans** - To streamline your preparation
- **Value Add Notes** - For additional information and revision
- **Connecting the Dots** - Sessions by Experts & Toppers
- **Live Doubt Clearing Sessions** - Teachers will be approachable through live sessions
- **Offline Mentorship** - Though classes are Online, Mentors will be available Offline for guidance

Why e-CLP Classes?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Subject-wise Mentorship and Dedicated Mentor - for overall guidance • Focus on Fundamentals through Strategy/Approach Classes • Focus on Conceptual Understanding and Value Add Notes • Daily Prelims and Mains Tests/Assignment and Fortnightly Full Length tests | <ul style="list-style-type: none"> • Total No. of Classes - 230 sessions • Total No. of Hours - 700 hours • No. of Prelims Test - 46 Full-length Prelims Test + 160 Daily Micro Tests • No. of Mains Test - 17 Full length Mains Test + 10 Essay Tests + 165 Daily Mains Answer Writing Practice |
|---|--|

SPECIAL FEATURES OF THE PROGRAM

INCENTIVE BASED PROGRAM - TLP+ (MAINS -2021) Program & Interview Mentorship Program (IMP) along with Mock Interviews will be FREE for those who are clearing Prelims and Mains respectively

BABAPEDIA AND WEEKLY CURRENT AFFAIRS - Online access to one stop destination for Currents Affairs

ESSAY GUIDANCE - Guidelines will be provided to you on how to write an essay. 10 Essay Tests will be conducted

WHY IASbaba?

VISION: Enabling an aspirant located at the remotest corner of the country, in not only fulfilling his/her dreams of clearing the toughest UPSC/Civil Services Exam, but securing Rank 1.

2M+

MONTHLY ACTIVE
USERS

350+

RANKS FROM
ILP/TLP

1200+

RANKS FROM
WEBSITE

>70%

HIT RATIO IN
UPSC PRELIMS

>80%

HIT RATIO IN
UPSC MAINS

Contact us

Admission Centre
1st Floor, #38, 3rd Cross Rd, Nagarbhavi
1st Stage, 2nd Stage, Chandra Layout,
Bengaluru-560040 Landmark: Opp Cult Fit

Vijayanagara Centre
1737/37, Mrcr Layout, Vijayanagar Service Road,
Vijayanagar, Bengaluru - 560040
Landmark: Opp. to Vijayanagar Metro Station

Delhi Centre
5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro
Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

www.iasbaba.com

ecpl@iasbaba.com

+91 91691 91888

भारत और विश्व(INDIA AND THE WORLD)

भारत-वियतनाम वार्ता हुई (India-Vietnam Talks held)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उद्योग की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के शांति अभियानों में सहयोग, आदि पर चर्चा की।



महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों देशों ने मजबूत भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग की पुष्टि की, जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2016) का एक प्रमुख स्तंभ है।
- भारत ने निकट भविष्य में एक संस्थागत ढांचे के समझौते को समाप्त करके निकट रक्षा उद्योग सहयोग पर जोर दिया।
- वियतनाम ने विशेष रूप से मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में वियतनामी रक्षा बलों की क्षमता निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

- भारत भारतीय रक्षा संस्थानों में वियतनाम रक्षा बलों की तीनों सेवाओं के लिए प्रशिक्षण के दायरे और स्तर को बढ़ाने के लिए भी तैयार है।
- दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सहयोग पर चर्चा की।
- उन्होंने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की जो हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करने में सक्षम होगा और नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में सहायता करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- वियतनाम ने दिसंबर 2020 में वियतनाम द्वारा आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम प्लस) के लिए भारत को आमंत्रित किया है।
- ADMM- प्लस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) और इसके आठ संवाद साझेदार - ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक मंच है - सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करेगा चीन (China gives 'go ahead' for New Dam on Brahmaputr)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर पहली डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक चीनी पनबिजली कंपनी के साथ समझौता किया है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य के स्वामित्व वाली जलविद्युत कंपनी ने नई पंचवर्षीय योजना (2021-2025) के हिस्से के रूप में यारलुंग जंगबो नदी के बहाव क्षेत्र में जलविद्युत दोहन को लागू करने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह पहली बार होगा जब नदी के बहाव क्षेत्र का दोहन किया जाएगा।
- नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।
- यह 50 किमी का खंड अकेले 70 मिलियन किलोवाट घंटे (Kwh) विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

ब्रह्मपुत्र

- यह सियांग या दिहांग के नाम से होता है, जो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है।
- यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करता है।
- सहायक नदियाँ: दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही दिहिंग, तिस्ता और धनसारी।
- यह एक बारहमासी नदी है।
- इसकी भूगोल और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी कई विशिष्ट विशेषताएं हैं।
- इसमें सालाना दो बार बाढ़ आती है।
- एक बाढ़ गर्मियों में हिमालय की बर्फ के पिघलने के कारण और दूसरी मानसून के प्रवाह के कारण होती है।
- इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है।
- ये बाढ़ जलवायु परिवर्तन और उच्च और निम्न प्रवाह पर इसके प्रभाव के कारण विनाशकारी हैं।
- ये भारत और बांग्लादेश के निचले राज्यों में जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।
- नदी अपने आप में गतिशील है क्योंकि अक्सर भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधि इसे अक्सर प्रारूप बदलने के लिए मजबूर करती है।

भारत ने ADMM-PLUS बैठक में भाग लिया (India attends ADMM-PLUS Meeting virtually)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारतीय रक्षा मंत्री ने हाल ही में वियतनाम के हनोई में आयोजित 14 वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में ऑनलाइन भाग लिया, जिसने एडीएमएम प्लस की 10 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

आसियान रक्षा मंत्री की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)

- एडीएमएम-प्लस एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा मंत्री की बैठकों का एकमात्र आधिकारिक ढांचा है।

- यह आसियान और उसके आठ संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है जो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है।
- **सदस्य:** एडीएमएम-प्लस में दस आसियान देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- 2010 में स्थापित किया गया।

संबंधित लेख:

- भारत-वियतनाम वार्ता हुई
- आसियान

चाबहार बंदरगाह पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच TWG बैठक (TWG meeting held between India, Iran, and Uzbekistan on Chabahar port)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह (TWG) बैठक आयोजित की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव (नौवहन), भारत सरकार, परिवहन मंत्री, उज्बेकिस्तान और ईरान के उप परिवहन मंत्री ने की।
- बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने व्यापार और पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की।
- सभी पक्षों ने जनवरी 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन की ओर से "चाबहार दिवस" आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव का भी स्वागत किया।
- यह बैठक हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई आभासी शिखर बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुगमन के रूप में आयोजित की गई थी।

क्या आप जानते हैं?

- चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है।
- यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, और इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं, जिनका नाम शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेशती है।

संबंधित आलेख:

- चाबहार बंदरगाह और अमेरिकी प्रतिबंध: [Click here](#)
- भारत चाबहार परियोजना से बहार हो रहा है: [Click here](#)
- ईरान चाबहार रेल परियोजना से भारत को हटा रहा है: [Click here](#)

भारत संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में 131 वें स्थान पर है (India ranks 131 in 2020 UN Human Development Index)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - स्वास्थ्य; शिक्षा

समाचार में

- मानव विकास सूचकांक हाल ही में जारी किया गया था।
- जारीकर्ता : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)।
- 189 देशों के बीच भारत 131 वें स्थान पर है
- 2019 के लिए भारत का एचडीआई मूल्य 0.645 है जिसने इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाल दिया है।
- भारत 2018 में सूचकांक में 130 वें स्थान पर था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2019 में जन्म के समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी।
- बांग्लादेश में 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल की जीवन प्रत्याशा है।
- भारत, भूटान (129), बांग्लादेश (133), नेपाल (142), और पाकिस्तान (154) को अन्य देशों के साथ समान विकास के साथ स्थान दिया गया।
- शीर्ष देश: नॉर्वे (1), आयरलैंड (2), स्विट्जरलैंड (3), हांगकांग (4) और आइसलैंड (5)
- रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति भारत की सकल राष्ट्रीय आय 2019 में \$ 6,681 से गिरकर \$ 8,829 से 2018 में क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर हुई।
- कंबोडिया, भारत और थाईलैंड में बच्चे कुपोषण से संबंधित मुद्दों जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग का सामना करते दिख रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

- मानव विकास सूचकांक एक देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का माप है

- क्रय शक्ति समता या पीपीपी विभिन्न देशों में कीमतों का एक माप है जो देशों की मुद्राओं की पूर्ण क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करता है।

भारत – बांग्लादेश (India – Bangladesh)

संदर्भ: बांग्लादेश के लिए 16 दिसंबर मुक्ति संग्राम की जीत का दिन है, यह भारत-बांग्लादेश संबंधों को देखने का एक अच्छा समय है।

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- 2009-10 और 2015-16 के बीच, व्यापार घाटा 164.4% के साथ भारत के पक्ष में बढ़ गया।
- भारत से बांग्लादेश तक एफडीआई \$ 3.11 बिलियन है, जिसमें रिलायंस की \$ 642 मिलियन की 745 मेगावाट की गैस-फायर परियोजना और अडानी की मिरसराय आर्थिक क्षेत्र में \$ 400 मिलियन शामिल हैं।
- आज, भारत और बांग्लादेश बेहतर रूप से जुड़े हुए हैं और माल को बांग्लादेशी जहाजों, ट्रकों और रेलवे का उपयोग करके सड़क, रेल और नदी मार्गों द्वारा ले जाया जाता है।
- हाल के समझौतों से भारत को मोंगला बंदरगाह से सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से माल भेजने की अनुमति मिलती है।

मुद्दे

- सीमा संवेदनशील बनी हुई है। 294 बांग्लादेशी भारत-बांग्लादेश सीमा पर मारे गए।
- पानी एक और मुश्किल मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेशियों ने केंद्र और राज्य के बीच तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर रस्साकशी देखी है।
- भारत के विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और नागरिक रजिस्टर (NRC) ने बांग्लादेश पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
- बांग्लादेश चीन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यात गंतव्य है। चीनी कंपनियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने भारतीय समकक्षों को पछाड़ रही हैं।

निष्कर्ष

- यदि भारत-बांग्लादेश संबंधों को "नई ऊंचाइयों" पर ले जाना है, तो अनसुलझे मुद्दों से जल्द ही निपटना होगा।

भारत-वियतनाम नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-Vietnam Leaders' Virtual Summit)

भाग: GSप्रीलिम्स और GS- III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री ने गुयेन जुआन फुक, वियतनाम के प्रधान मंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया



महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के दस्तावेज के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया था।
- दोनों नेताओं ने संयुक्त विजन को लागू करने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के आगे कार्यान्वयन के लिए 2021-2023 की अवधि के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया।

घोषणाएँ:

- भारत सरकार द्वारा वियतनाम में विस्तारित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा लाइन के तहत वियतनाम बॉर्डर गार्ड कमांड के लिए हाई स्पीड गार्ड नाव (HSGB) विनिर्माण परियोजना का कार्यान्वयन;
- वियतनाम के निन्ह थुआन प्रांत में स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान-में-सहायता 'के साथ सात विकास परियोजनाओं को पूरा करना और सौंपना।
- वर्तमान में पांच से दस वार्षिक वित्त वर्ष 2021-2022 तक वार्षिक त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) की संख्या बढ़ाना।
- वियतनाम में विरासत संरक्षण में तीन नई विकास भागीदारी परियोजनाएं (माई सन में मंदिर का एफ-ब्लॉक; क्वांग नाम प्रांत में डोंग डुओंग बौद्ध मठ; और फु येन प्रांत में नन चाम टॉवर)।
- भारत पर एक विश्वकोश - वियतनाम सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध तैयार करने के लिए द्विपक्षीय परियोजना का शुभारंभ।

मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(Cabinet approves MoU between India and Bhutan on Cooperation in the peaceful uses of outer space)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह समझौता ज्ञापन भारत और भूटान को पृथ्वी के सुदूर संवेदन जैसे संभावित हित क्षेत्रों में सहयोग करने में सक्षम करेगा; उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणाली और जमीनी प्रणाली का उपयोग; और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग।
- यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त कार्यदल का गठन करेगा, जो समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा।
- हस्ताक्षरित एमओयू पृथ्वी के सुदूर संवेदन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इपेटस प्रदान करेगा; उपग्रह संचार; उपग्रह नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाहरी अंतरिक्ष की खोज करेगा।



कैबिनेट ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिकन में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी (Cabinet approves Opening of 3 Indian Missions in Estonia, Paraguay and Dominican Republic)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इन देशों में भारतीय मिशनों के खुलने से भारत के कूटनीतिक पदचिह्न का विस्तार करने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ावों को सक्षम बनाने, लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी, बहुपक्षीय आईएनए में राजनीतिक आउटरीच को बढ़ावा मिलेगा और भारत की विदेश नीति के उद्देश्य समर्थन प्राप्त करना है।
- इन देशों में भारतीय मिशन भी भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता करेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे।





ILP CONNECT - 2021

ONLINE MENTORSHIP for UPSC Preparation

50 SEATS LEFT



REGISTER NOW

अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

ऐतिहासिक मंदी: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मंदी

संदर्भ: 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनंतिम अनुमान आर्थिक उत्पादन में 7.5% की कमी आई है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मंदी के निशान के साथ, अर्थव्यवस्था लगातार दूसरी तिमाही के लिए सिकुड़ गई।

प्रमुख सांख्यिकी

- कुल कुल सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा, 33,14,167 करोड़ (2011-12 की कीमतों में) से पता चलता है कि उत्पादन 12 तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है।
- निजी खपत व्यय - जीडीपी को साझा करने वाला सबसे बड़ा घटक जो निरंतर कीमतों पर 50% से अधिक है और मौजूदा कीमतों में 60% की ओर बढ़ रहा है - (-11.3%) सिकुड़ना जारी रहा, महामारी और प्रभाव के बीच खर्च करने के लिए दोनों उपभोक्ता चेतना को दर्शाता है। नौकरियों में कमी और आय में कमी।
- सरकारी उपभोग खर्च जो कि 22% सार्वजनिक अनुबंधों की अनिश्चित स्थिति का खुलासा करता है, एक बल्ब से अनुबंधित किया गया था।
- वास्तविक अर्थव्यवस्था में, बिजली और अन्य उपयोगिता सेवाएं पोस्टिंग ग्रोथ में कृषि में शामिल हो गईं, 4.4% का विस्तार किया, क्योंकि औद्योगिक गतिविधि के बाद के लॉकडाउन फिर से शुरू होने से बिजली और पानी की खपत बढ़ गई।
- वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं, जो जीवीए के एक चौथाई के बारे में योगदान करती हैं, पहली तिमाही से व्यापक संकुचन, 8.3% सिकुड़ती हैं

Statement 1: Quarterly Estimates of GVA at Basic Prices in Q2 (July-September) of 2020-21 (at 2011-12 Prices)

(₹ in crore)

Industry	GVA at Basic Price									
	2018-19		2019-20		2020-21		Percentage Change Over Previous Year			
							2019-20		2020-21	
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1. Agriculture, Forestry & Fishing	4,27,177	3,55,283	4,39,843	3,67,758	4,54,658	3,80,239	3.0	3.5	3.4	3.4
2. Mining & Quarrying	88,634	69,723	92,807	68,978	71,209	62,674	4.7	-1.1	-23.3	-9.1
3. Manufacturing	5,61,875	5,79,649	5,78,936	5,76,112	3,51,396	5,79,683	3.0	-0.6	-39.3	0.6
4. Electricity, Gas, Water Supply & Other Utility Services	74,998	76,567	81,628	79,525	75,877	83,051	8.8	3.9	-7.0	4.4
5. Construction	2,49,913	2,37,907	2,62,828	2,44,092	1,30,750	2,23,121	5.2	2.6	-50.3	-8.6
6. Trade, Hotels, Transport, Communication & Services related to Broadcasting	6,09,330	5,87,337	6,30,860	6,11,609	3,34,284	5,16,500	3.5	4.1	-47.0	-15.6
7. Financial, Real Estate & Professional Services	7,57,850	8,16,260	8,03,322	8,64,974	7,60,491	7,94,995	6.0	6.0	-5.3	-8.1
8. Public Administration, Defence & Other Services	3,87,589	4,19,300	4,17,483	4,65,096	3,74,656	4,08,326	7.7	10.9	-10.3	-12.2
GVA at Basic Prices	31,57,366	31,42,027	33,07,707	32,78,144	25,53,320	30,48,589	4.8	4.3	-22.8	-7.0

चित्र 2: स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हालांकि, ऑल-राउंड चीयर्स के साथ 7.5% की गिरावट के आंकड़े मिले हैं। यह जवाबी है, लेकिन औचित्य के बिना नहीं।

- अपेक्षित परिणामों की तुलना में बेहतर: -7.5% आंकड़ा ज्यादातर सड़क अनुमानों की तुलना में कम है। तेज-से-अपेक्षित आर्थिक "रिकवरी" -Q1 में 23.9% की गिरावट आई थी - यह काफी हद तक बदल गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जा रहा है।
- वैश्विक औसत से बेहतर वसूली: भारतीय स्टेट बैंक की शोध टीम के विश्लेषण के अनुसार, 49 देशों ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी डेटा की घोषणा की है। इन 49 देशों की औसत गिरावट 12.4% है। इसकी तुलना में, भारत का 7.5% बेहतर दिखता है।
- आर्थिक सुधार काफी व्यापक-आधारित है: प्रत्येक क्षेत्र के सकल मूल्य परिवर्धन को देखते हुए, जैसा कि आंकड़े 2 में दिखाया गया है, हम देखते हैं कि Q1 में सकारात्मक मूल्य को जोड़ने वाले सिर्फ एक क्षेत्र की तुलना में, तीन क्षेत्रों ने Q2 (हरा) में सकारात्मक मान जोड़ा मंडलियां। इसके अलावा, शेष पांच क्षेत्रों में से तीन में, गिरावट की दर - हरे बॉक्स में हाइलाइट की गई।
- भारत के विनिर्माण उद्योग द्वारा दर्ज की गई सकारात्मक वृद्धि: इसका एक हिस्सा कमजोर आधार द्वारा समझाया जा सकता है - 2019-20 के क्यू 2 में माइनस 0.6% की जाँच करें। IIP विनिर्माण में 6.7% (Jul / Aug / Sep का औसत) की गिरावट दर्ज की गई जबकि GVA का निर्माण 0.6% बढ़ा। इस असंगति को कंपनियों द्वारा अपनी आय में वृद्धि करके और अधिक नहीं बेचकर, बल्कि कर्मचारियों को निर्ममता से हटाकर समझाया जा सकता है, जो स्वस्थ संकेत नहीं है और भविष्य की मांग को कम कर सकता है।
- Q4 द्वारा सकारात्मक विकास दर की आशा: अधिकांश विशेषज्ञ अब उम्मीद करते हैं कि Q4 द्वारा, नाममात्र जीडीपी विकास दर इतनी दूर हो जाएगी कि मुद्रास्फीति की दर को घटाने के बाद भी, भारत कम से कम चौथी तिमाही में सकारात्मक वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगा।

हालांकि, ऑल-राउंड चीयर्स के साथ 7.5% की गिरावट के आंकड़े मिले हैं।

- अपेक्षित परिणामों की तुलना में बेहतर: -7.5% आंकड़ा ज्यादातर सड़क अनुमानों की तुलना में कम है। तेज-से-अपेक्षित आर्थिक "रिकवरी" -Q1 में 23.9% की गिरावट आई थी - यह काफी हद तक बदल गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जा रहा है।
- वैश्विक औसत से बेहतर वसूली: भारतीय स्टेट बैंक की शोध टीम के विश्लेषण के अनुसार, 49 देशों ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी डेटा घोषित किया है। इन 49 देशों की औसत गिरावट 12.4% है। इसकी तुलना में, भारत का 7.5% बेहतर दिखता है।
- आर्थिक सुधार काफी व्यापक-आधारित है: प्रत्येक क्षेत्र के सकल मूल्य परिवर्धन को देखते हुए, जैसा कि आंकड़े 2 में दिखाया गया है, हम देखते हैं कि Q1 में सकारात्मक मूल्य को जोड़ने वाले सिर्फ एक क्षेत्र की तुलना में, तीन क्षेत्रों ने Q2 में सकारात्मक मान जोड़ा गया है। इसके अलावा, शेष पांच क्षेत्रों में से तीन में, गिरावट की दर - हरे बॉक्स में हाइलाइट की गई।
- भारत के विनिर्माण उद्योग द्वारा दर्ज की गई सकारात्मक वृद्धि: इसका एक हिस्सा कमजोर आधार द्वारा समझाया जा सकता है - 2019-20 के क्यू 2 में माइनस 0.6% की जाँच करें। IIP विनिर्माण में 6.7% (Jul / Aug / Sep का औसत) की गिरावट दर्ज की गई जबकि GVA का निर्माण 0.6% बढ़ा। इस असंगति को कंपनियों द्वारा अपनी आय में वृद्धि करके और अधिक नहीं

बेचकर, बल्कि कर्मचारियों को निर्ममता से निकालकर समझाया जा सकता है, जो स्वस्थ संकेत नहीं है और भविष्य की मांग को कम कर सकता है।

- Q4 द्वारा सकारात्मक विकास दर की आशा: अधिकांश विशेषज्ञ अब उम्मीद करते हैं कि Q4 द्वारा, नाममात्र जीडीपी विकास दर इतनी दूर हो जाएगी कि मुद्रास्फीति की दर को घटाने के बाद भी, भारत कम से कम चौथी तिमाही में सकारात्मक वास्तविक विकास दर्ज करेगा।

निष्कर्ष

- सरकार को उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक धनराशि (करोड़ों में कटौती, सब्सिडी बढ़ाना) करके मांग को पुनर्जीवित करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में विकास को वापस लाया जा सके।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र (International Association of Insurance Supervisors-IAIS))

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -ऊर्जा क्षेत्र

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (IAIS) की सदस्यता प्राप्त की।
- इस सदस्यता के साथ IFSCA के पास IAIS के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच होगी और अन्य वैश्विक नियामकों के साथ विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम होगा।
- इससे GIFT सिटी में IFSC में एक जीवंत वैश्विक बीमा हब विकसित करने में मदद मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र (IAIS)

- स्थापना: 1994
- मुख्यालय: स्विट्जरलैंड।
- यह 200 से अधिक न्यायालयों के बीमा पर्यवेक्षकों और नियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है, जिसमें दुनिया के 97% बीमा प्रीमियम शामिल हैं।
- IAIS के कुछ प्रमुख सदस्य हैं: (1) यूनाइटेड किंगडम- वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA); (2) यूएसए- नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स (NIAC); (3) भारत- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) आदि।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मानक-सेटिंग निकाय है जो बीमा क्षेत्र की देखरेख के लिए सिद्धांतों, मानकों और अन्य सहायक सामग्री के कार्यान्वयन में विकास और सहायता के लिए जिम्मेदार है।

मुनि बांड्स (Muni Bonds)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -अर्थव्यवस्था

समाचार में

- लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) द्वारा जारी किए गए बांड बीएसई पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यूपी के मुख्यमंत्री के अनुसार, गाजियाबाद एक नगरपालिका बांड जारी करने वाला अगला जिला होगा और इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर होंगे।
- लखनऊ नगरपालिका बांड के माध्यम से पूंजी जुटाने वाला देश का नौवाँ शहर है।
- अब तक, देश में मुनि बांडों के माध्यम से 3,600 करोड़ रुपये की संचयी राशि जुटाई गई है।
- ऐसे बांडों का उपयोग करके उठाया गया धन आमतौर पर सड़क, पानी और आवास जैसी इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
- 2015 में, बाजार नियामक सेबी ने मुनि बांड के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए रूपरेखा जारी की थी।
- इन बांडों को जारी करने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड के बीच यह है कि स्थानीय निकाय को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में नकारात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए और पिछले एक साल में भुगतानों पर चूक नहीं हुई है।

आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्यमी (Aatmanirbhar Bharat & Small Entrepreneurs)

विनिर्माण

- भारत के विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि नीति निर्माताओं के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है।
- भारत का विनिर्माण क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादन का 20% से कम उत्पन्न करता है, और यह चीन द्वारा ओवरशेड किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत

- इसका उद्देश्य इस कमी को दूर करना है। अधिक प्रतिबंधात्मक व्यापार उद्यमियों को निर्यात पर निर्भर होने के बजाय भारत के बड़े घरेलू बाजार में टैप करने में सक्षम करेगा।
- घरेलू बाजार के आकार को घरेलू बाजार के आकार, मध्यम वर्ग के उदय और भारत के युवा जनसांख्यिकी के कारण बदल दिया गया है।
- प्रतिबंधात्मक व्यापार शासन

- विनिर्माण क्षेत्र में भारत का विस्तार मुख्य रूप से छोटे उद्यमियों के विस्तार से हुआ, जो 99% प्रतिष्ठानों के लिए जिम्मेदार हैं और विनिर्माण क्षेत्र में 80% नौकरियां पैदा करते हैं।
- छोटे उद्यमियों का विस्तार परम्परागत क्षेत्र में हुआ लेकिन गैर-परम्परागत क्षेत्र में अनुबंधित हुआ।
- अधिक प्रतिबंधात्मक व्यापार शासन की ओर बदलाव से कुछ बड़े समूह लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन यह छोटे उद्यमियों को नुकसान पहुंचाएगा और रोजगार सृजन की गति को धीमा कर देगा।
- पिछले तीन दशकों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में संपूर्ण शुद्ध रोजगार वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र में छोटे उद्यमों से आई है।
- विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों और छोटे उद्यमों के विस्तार में यह प्रवृत्ति गैर-पारंपरिक क्षेत्र में नहीं देखी गई थी।

व्यापार उदारीकरण

- पारंपरिक क्षेत्र में छोटे उद्यमियों का विस्तार और गैर-पारंपरिक क्षेत्र में संकुचन से पता चलता है कि भारत के व्यापार ने मुख्य रूप से छोटे उद्यमियों को लाभान्वित किया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बन गए हैं।
- व्यापार उद्यमकरण ने छोटे उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अनौपचारिक क्षेत्र

- अनौपचारिक क्षेत्र के युवा उद्यमियों ने औपचारिक क्षेत्र में बड़े स्थापित समूह की तुलना में अधिक नौकरियां पैदा की हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित गरीबी कार्यक्रमों की तुलना में गरीबी में कमी का प्रमुख चालक बना हुआ है।
- बड़े उद्यमियों की तुलना में छोटे उद्यमी भारत के आर्थिक भूगोल के समग्र संदर्भों के अधिक निकट हैं।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सभी नौकरियां पैलेट्री आय नहीं देती हैं। कई स्व-नियोजित औपचारिक अर्थव्यवस्था में अकुशल या कम-कुशल श्रमिकों से अधिक कमाते हैं।
- बड़ी और छोटी फर्मों के बीच विशाल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंध हैं। छोटी फर्म बड़ी फर्मों को इनपुट का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं।

दोस्ताना व्यापार शासन

- भारत के युवा जनसांख्यिकी, और बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा उत्पन्न सीमित रोजगार, ने छोटे उद्यमियों के लिए एक अनुकूल व्यापार शासन के महत्व को बढ़ा दिया है जो भारत में अधिकांश नौकरियों का निर्माण करते हैं।
- व्यापार लचीलेपन और वैश्विक एकीकरण ने लाखों और महिलाओं को नौकरी खोजने और कार्य-जीवन के बेहतर प्रबंधन में सक्षम बनाया है।

RBI NBFCs, UCBs के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा मानदंडों को शुरू किया (RBI introduces risk-based internal audit norms for NBFCs, UCBs)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -अर्थव्यवस्था

समाचार में

- आरबीआई ने हाल ही में बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक ऑडिट मानदंडों की शुरुआत की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उद्देश्य:** पर्यवेक्षित संस्थाओं में शासन और आश्वासन कार्यों में सुधार।
- वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए थे।
- एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके परस्पर संबंधों ने इस क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए इसे अनिवार्य बना दिया है।
- इस प्रकार एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए पारदर्शी मापदंड रखने का निर्णय लिया गया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RBI की तरलता समायोजन सुविधा (LAF), सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) का उपयोग करने और मनी मार्केट को कॉल / नोटिस करने की अनुमति होगी।
- RBI ने उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा के साथ डिजिटल भुगतान चैनलों के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण निर्देश जारी करने का प्रस्ताव दिया है।

संबंधित आलेख:

- एनबीएफसी के बारे में अधिक जानकारी: [Click here](#)
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए RBI के उपाय: [Click here](#)
- सीमांत स्थायी सुविधा: [Click here](#)

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के मूल निवासी उत्पादों के लिए जीआई प्रा टैग्स करने की कोशिश कर रही है (Himachal Pradesh government trying to obtain GIs for products native to the State)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जीआई टैग

समाचार में

- हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य से पांच उत्पादों के लिए जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।
- ये उत्पाद हैं- कर्सोग कुल्थ (Karsog Kulth), पांगी के थांगी (Thangi of Pangti), चंबा धातु शिल्प (Chamba Metal Crafts), चंबा चुख (Chamba Chukh) और भरमौर के राजम (Rajmah of Bharmour)।

- **करसोग कुल्थ (Karsog Kulth):** कुलथी या कुल्थ (घोड़ा चना) हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाने वाली एक फली (legume) है। माना जाता है कि मंडी जिले के करसोग क्षेत्र (Karsog area) में पैदा होने वाले कुल्थ अमीनो एसिड (amino acids) में विशेष रूप से समृद्ध है।
- **पांगी के थांगी (Thangi of Pangti):** यह एक प्रकार का हेज़लनट (अखरोट का फल) है जो हिमाचल के उत्तर-पश्चिमी छोर में स्थित पांगी घाटी (Pangti valley) में उगता है। यह अपने अनोखे स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है।
- **चंबा धातु शिल्प (Chamba Metal Crafts):** इनमें धातु की मूर्तियाँ और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएँ शामिल हैं।
- **चंबा चुख (Chamba Chukh):** यह चंबा में उगाई जाने वाली हरी और लाल मिर्च से बनी चटनी है और पारंपरिक व अनोखे तरीकों से तैयार की जाती है।
- **भरमौरी राजमाह (Bharmouri Rajmah):** चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में कुगती दर्रे (Kugti Pass) के आस-पास के क्षेत्र में उगने के बाद से इसे विशेष रूप से कुगतालु राजमाह (Kugtalu Rajmah) कहा जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एक विशिष्ट स्वाद होता है।

क्या आप जानते हैं?

- हिमाचल में वर्तमान में चार हस्तशिल्पियों (कुल्लू शाल, चंबा रूमाल, किन्नौर शाल और कांगड़ा पेंटिंग), तीन कृषि उत्पादों (कांगड़ा चाय, बासमती और हिमाचली बाला ज़ेरा) और एक विनिर्मित उत्पाद (हिमाचली चुली तेल) में जी आई टैग हैं।

इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता (Invest India wins UN Investment Promotion Award)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था; निवेश

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र (यूएनसीटीएडी) ने इन्वेस्ट इंडिया (नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया) को साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है।
- पुरस्कार समारोह 7 दिसंबर, 2020 को जिनेवा में यूएनसीटीएडी मुख्यालय में हुआ।
- यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों (आईपीए) की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है। इसका मूल्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के यूएनसीटीएडी द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था।
- कोविड-19 महामारी ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की हैं। उन्हें नियमित निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से ध्यान हटाकर संकट प्रबंधन, सरकारी आपातकालीन व आर्थिक राहत उपायों की अधिसूचना, संकट सहायता सेवाओं के प्रावधान और राष्ट्रीय कोविड-19 व्यापार प्रतिक्रिया प्रयासों में योगदान की ओर कर दिया है।
- यह संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार निवेश संवर्धन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- UNCTAD एक केंद्रीय एजेंसी है जो IPAs के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती है।

- जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर पुरस्कार के पिछले विजेता रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

इन्वेस्ट इंडिया

- यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है
- इसे 2009 में स्थापित किया गया था
- यह एक गैर-लाभकारी उपक्रम है
- उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **फोकस:** भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए नई साझेदारी के क्षेत्र-विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और विकास।
- यह पर्याप्त निवेश संवर्धन एजेंसियों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ भी साझेदारी करता है।
- यह कई भारतीय राज्यों के साथ निवेश लक्ष्यीकरण, संवर्धन और सुविधा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- यह 1964 में एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है।
- **लक्ष्य:** विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करना और उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था में समान आधार पर एकीकृत करने के उनके प्रयासों में सहायता करना।
- 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियों का निर्माण करना।
- स्थायी सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है

भारत और बैटर दैन कैश अलाउंस (Better Than Cash Alliance) के बीच आयोजित फिनटेक समाधान पर पीयर लर्निंग एक्सचेंज (Peer learning exchange on fintech solutions held between India and Better Than Cash Alliance)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - डिजिटल अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में, भारत और संयुक्त राष्ट्र-आधारित बेटर दैन कैश अलायंस (Better Than Cash Alliance) अंतिम मील पर जिम्मेदार डिजिटल भुगतान के लिए फिनटेक समाधानों पर एक संयुक्त पीयर लर्निंग एक्सचेंज का आयोजन किया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

यह कैश अलायंस से बेहतर है

- यह संयुक्त राष्ट्र पर आधारित है।
- इसे 2012 में बनाया गया।
- प्रारंभ: संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटीग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडियार नेटवर्क और वीजा इंक द्वारा।
- यह सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है जो नकदी के लिए जिम्मेदार डिजिटल भुगतानों में संक्रमण को तेज करता है।
- एलायंस के 75 सदस्य हैं जो भुगतान अंकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- एलायंस सचिवालय द्वारा भुगतान को डिजिटल बनाने के लिए काम करता है - उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सलाहकार सेवाएं प्रदान करना; कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान और जिम्मेदार प्रथाओं पर सहकर्मियों को सीखने को बढ़ावा देना; राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर वकालत का संचालन करना।

वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (RTGS) अब चौबीसों घंटे लेनदेन के लिए उपलब्ध है (Real Time Gross Settlement System (RTGS) now available for round the clock transactions)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - बैंकिंग

समाचार में

- आरबीआई ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होने के साथ, अब रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) की सुविधा चौबीसों घंटे लेनदेन के लिए उपलब्ध होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आरटीजीएस की राउंड द क्लॉक उपलब्धता व्यवसायों को भुगतान को प्रभावित करने के लिए विस्तारित लचीलापन प्रदान करेगी।
- भारतीय वित्तीय बाजारों और सीमा पार से भुगतान के संचालन को बढ़ाने के लिए भी प्रणाली का लाभ उठाया जा सकता है।
- RTGS आईएसओ 20022 प्रारूप का उपयोग करता है जो वित्तीय लेनदेन के लिए सर्वोत्तम-इन-क्लास मैसेजिंग मानक है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) शब्द एक फंड ट्रांसफर सिस्टम को संदर्भित करता है जो पैसे और प्रतिभूतियों के तात्कालिक हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- यह केंद्रीय बैंक की पुस्तकों में क्रेडिट के साथ डेबिट के बिना व्यक्तिगत आदेश के आधार पर भुगतानों को निपटाने की निरंतर प्रक्रिया है।
- एक बार पूरा होने पर, वास्तविक समय सकल निपटान भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं।
- RTGS वर्तमान में 6.35 लाख लेनदेन प्रतिदिन संभालता है।

भारतीय कंपनियों में विविधता की आवश्यकताएं (Diversity Requirements In Indian Companies)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- अमेरिका में NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज को जल्द ही सभी सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम एक महिला बोर्ड सदस्य और एक सदस्य को अल्पसंख्यक समूह से या एलजीबीटीक्यू समुदाय से उनके निदेशक मंडल में शामिल करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय कंपनियों से भी विविधता की आवश्यकताएं हैं और उनसे इन नियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- सभी सार्वजनिक कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं और 100 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी या 300 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम के तहत कम से कम एक महिला बोर्ड सदस्य होना आवश्यक है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) को 1 अप्रैल, 2020 से आवश्यकता है कि बाजार पूंजीकरण की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में एक महिला बोर्ड की सदस्य हैं जो एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं।

क्या आप जानते हैं?

- संस्थागत निवेशक सलाहकार सेवा (IIAS) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी 500 कंपनियों में 17% निदेशक महिलाएं थीं।
- IAS की रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी 500 कंपनियों में से केवल 3% में कोई महिला निदेशक है।

संबंधित आलेख:

- SEBI: [Click here](#)

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना (Special Assistance To States For Capital Expenditure Scheme)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए नई घोषित योजना का लाभ उठाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में घोषित किया गया था।
- **उद्देश्य:** COVID 19 महामारी से उत्पन्न होने वाले कर राजस्व में कमी के कारण इस वर्ष राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना।
- पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और आर्थिक विकास की उच्च दर के परिणामस्वरूप होता है।
- सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्र रुपये की पेशकश करेगा। राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए दिया जायेगा।
- इस योजना के तीन हिस्से हैं। योजना का भाग-1 पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करता है। इस हिस्से के तहत, पूर्वोत्तर के सात राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिक आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, असम को इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- योजना का भाग-2 अन्य सभी राज्यों के लिए है, जिन्हें भाग-1 में शामिल नहीं किया गया है। इस भाग के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का आवंटन इन राज्यों के बीच वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की अंतरिम मंजूरी के अनुरूप केन्द्रीय कर के उनके हिस्से के अनुपात में किया गया है।
- योजना के भाग-3 का लक्ष्य राज्यों में विभिन्न लोक केन्द्रित सुधारों को बढ़ावा देना है। इस भाग के तहत, 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने सुधार संबंधित अतिरिक्त उधारी अनुमतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 मई, 2020 के अपने पत्र में निर्दिष्ट चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार कार्यान्वित किए हैं।
- **ये चार सुधार हैं-** एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा बिजली क्षेत्र सुधार।

हस्तशिल्प एवं जीआई खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट मिली (Handicraft And GI Toys Exempted From Quality Control Order)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से हस्तकला और जीआई खिलौने को छूट दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत को खिलौनों की बिक्री एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में कदम उठाते हुए वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने की दिशा में लिए जा रहे कदमों के साथ एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
- विभाग द्वारा खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।
- इस आदेश का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी खिलौनों के गुणवत्ता मानक को बरकरार रखते हुए 'खिलौनों के लिए टीम अप' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्यों एवं हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- देश में मझोली, छोटी तथा सूक्ष्म खिलौना उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए की जा रही पहलों के हिस्से के रूप में, डीपीआईआईटी ने खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 जारी किया है।
- यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा उत्पादित एवं बिक्री की जाने वाली वस्तुओं को बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियमन, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुरूप भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह के उपयोग से छूट प्रदान करता है।
- संशोधन आदेश, 2020 भौगोलिक संकेतकों के रूप में पंजीकृत उत्पादों को भी बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियमन, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुरूप, भारतीय खिलौना मानकों का अनुपालन करने तथा ब्यूरो से मानक चिन्ह लाइसेंस के अनिवार्य उपयोग से छूट प्रदान करता है।
- भाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 'इस आदेश में कुछ भी पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय के भौगोलिक संकेतक पंजीयक द्वारा भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत उत्पादों के पंजीकृत स्वामी तथा अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्मित तथा बेची गई वस्तुओं और सामानों पर लागू नहीं होगा।

नए WTO D-G के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां (The many challenges for new WTO D-G)

संदर्भ:

25 साल के इतिहास में पहली बार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नेतृत्व एक महिला द्वारा किया जाएगा, क्योंकि महानिदेशक (डीजी) पद के लिए दोनों प्रतियोगी उम्मीदवार क्रमशः नाइजीरिया और दक्षिण कोरिया की महिलाएं हैं।

विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के समक्ष चुनौतियां :

- **प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा:** जेनेवा में मौजूद विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल में 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उनके विविधता और हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- **बढ़ता राष्ट्रवाद:** संगठन के लिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए, उसके पास बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विचारों को समेटने पर सख्त काम किया जाता है।
- **COVID-19 प्रभाव:** अगले D-G को COVID-19 महामारी के वैश्विक आर्थिक नतीजों से जूझना पड़ेगा और गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे
- **सुधार:** संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुधारों को पूरा करने की दिशा में काम करना होगा।
- **उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन:** विश्व व्यापार संगठन के भीतर विभाजन के मूल में दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) है जो विकासशील देशों के लिए अनुकूल है। विकसित देश DDA के एक नए एजेंडे के पक्ष में काम कर रहे हैं जिसमें अन्य, ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा, एमएसएमई और लिंग शामिल हैं।
- **डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र को बहाल करना,** विशेष रूप से इसके अपीलीय निकाय का पुनरुद्धार, संगठन के कुशल कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **आम आदमी के विश्वास को बहाल करना:** डब्ल्यूटीओ को यह दिखाना है कि यह मिशन गरीब लोगों की स्थितियों को बढ़ाने के लिए है न कि कॉर्पोरेटों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए
- **पोस्ट COVID दुनिया में सहयोग की आवश्यकता:** COVID-19 संकट ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहयोग की तत्काल और स्थायी आवश्यकता का खुलासा किया है, क्योंकि कोई भी देश अकेले महामारी से नहीं लड़ सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना :** डीजी यह सुनिश्चित करने पर स्पष्ट निर्देश देकर कि महामारी आपूर्ति के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला मुक्त और खुले रहें, टीकों के लिए वर्गीकरण के साथ एक मानक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की सिफारिश, और आयात / निर्यात प्रतिबंधों को हटाना।
- **टीके वितरण के लिए आईपीआर बाधाओं को दूर करना:** पीएम मोदी का यह कहना कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता पूरी मानवता की मदद करेगी डीओ-जी को बौद्धिक संपदा की बाधाओं को दूर करने और डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स समझौते के भीतर एक कानूनी ढांचा हासिल करने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- अगले डी-जी को अपने सदस्यों के बीच विश्वास पैदा करने की आवश्यकता होगी कि डब्ल्यूटीओ को सभी देशों द्वारा अधिक से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है, सभी देशों के बड़े हित में निष्पक्ष नियमों से जोड़ना और कुछ के अनुचित व्यापार प्रथाओं को विफल करने के लिए।

अग्रिम मूल्य समझौते (Advance pricing agreements (APAs))

- एपीए एक कर दाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है जो भविष्य के वर्षों के लिए करदाता के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य निर्धारण के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति का निर्धारण करता है।
- एक एपीए एकतरफा, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। उन्हें संभावित समय के लिए दर्ज किया जा सकता है और ऐतिहासिक वर्षों को भी कवर किया जा सकता है।
- APA आमतौर पर एक करदाता और कम से कम एक टैक्स प्राधिकरण के बीच ऐसा अनुबंध है, जो परस्पर संबंधित कंपनियों के बीच लेन-देन के लिये मूल्य-निर्धारण विधि को पहले से ही तय करता है।
- इस समझौते के तहत किसी अनिश्चितता से बचने के लिये, आर्म्स-लेंथ प्राइस (Arm's-length Price-ALP) के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यदि परस्पर संबंधित कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो तब वसूल की जाने वाली कीमत आर्म्स-लेंथ प्राइस कहलाती है।

APA के लाभ इस प्रकार हैं

- **सक्रिय कर दाता:** एपीए में मूल्य निर्धारण की शर्तों पर सहमत होने और किसी भी बाद के विवाद को खत्म करने के लिए सक्रिय आधार पर कर प्रशासन के साथ अंतर-कंपनी लेनदेन पर चर्चा करना शामिल है।
- **अनुपालन लागत को कम करता है:** करदाताओं के लिए, वे कुछ मामलों में दोहरे कर को कम करने और व्यवसाय के लिए निश्चितता को कम करके, प्रलेखन और टैक्स प्राधिकरण के ऑडिट से स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं।
- **सरकारी व्यय को कम करता है:** सरकार कम विवादों के माध्यम से हासिल करने के लिए खड़ी है, दुर्लभ प्रशासनिक संसाधनों के पुनर्निर्देशन और कर के अपने निष्पक्ष संग्रह को इकट्ठा करती है।
- **विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है:** APAs एक निश्चित और अनुमानित नीति शासन प्रदान करके निवेशकों के लिए देश के आकर्षण को बढ़ाता है।
- **अच्छी प्रक्रिया:** 2012 में शुरू किया गया भारत का APA कार्यक्रम दुनिया भर के करदाताओं और कर प्रशासन द्वारा सफल और सराहा गया है। नवंबर 2019 में सीबीडीटी द्वारा जारी 2018-19 के लिए एपीए की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि छह साल के दाखिलों में 10,000 करोड़ रुपये के 271 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था:** पिछले 12 महीनों में अतिरिक्त एपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसने गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
- **व्यवसायों को आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है:** करदाताओं के लिए, APAs इन समयों में और भी अधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि व्यवसाय-संचालित पुनर्गठन और बदलते हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नीतियां APAs को आगे बढ़ाने के लिए एक आकर्षक कारण हो सकती हैं।
- **मुकदमेबाजी से बचने में मदद करता है:** सीमित संसाधनों के साथ, कंपनियां एपीए के माध्यम से निश्चितता प्राप्त करने के लिए अनिश्चित और लंबे समय तक मुकदमेबाजी के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में निवेश करना चुन सकती हैं।
- **सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है:** APAs एक विश्वसनीय उदाहरण है कि भारतीय कर अधिकारियों और करदाताओं ने कैसे स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग किया है।

यूएस वॉच इंडिया ऑन करेंसी वॉचलिस्ट (US Puts India on Currency Watchlist)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में, अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत को चीन, ताइवान आदि देशों के साथ 'करेंसी मैनिपुलेटर्स' यानी मुद्रा में हेर-फेर करने वाले देशों की 'निगरानी सूची (Currency Monitoring watch list)' में डाल दिया है।
- अमेरिका ने वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड को पहले ही करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में रखा हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये अपने देश की मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच की विनिमय दर को प्रभावित (मुद्रा अवमूल्यन या अधिमूल्यन दोनों ही मामलों में) करने की कोशिश करता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा उसे करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर निगरानी सूची में डाल दिया जाता है।
- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग एक अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे विकास और विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण किया जाता है।
- सूची में शामिल होने पर अमेरिका की तरफ से किसी भी प्रकार की सजा या प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है, लेकिन यह सूची में शामिल किये गए देश की वैश्विक वित्तीय छवि को खराब करता है।

निगरानी सूची के लिये निर्धारित मानदंड

- अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इनफोर्समेंट एक्ट, 2015 के अनुसार यदि कोई देश निम्नलिखित तीन में से दो मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे वॉच लिस्ट/ मॉनिटरिंग लिस्ट/ निगरानी सूची में रखा जाता है :
 1. यदि लगातार 12 महीनों से कोई देश अमेरिका के साथ अत्यधिक व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।
 2. यदि वह देश 12 महीनों की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के कम से कम 2 प्रतिशत के बराबर चालू खाता अधिशेष की स्थिति में है।
 3. यदि विगत 12 महीनों (या कम से कम 6 महीनों में) में किसी देश द्वारा उस देश की जी.डी.पी. के कम से कम 2% के बराबर की विदेशी मुद्रा खरीद लगातार की जा रही है।
- सूची में शामिल करना किसी भी तरह के दंड और प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, लेकिन यह देश की वैश्विक वित्तीय छवि को खराब करता है।

WHAT IT MEANS...

For India | There will be pressure on RBI to cut down intervention, allow the rupee to appreciate

For economy | A stronger rupee would partially offset the impact of rising oil prices on imports

In terms of restrictions | The tag does not involve any kind of trade restrictions

For RBI | The central bank can increase diversification of its reserves to include non-dollar assets



'करेंसी मैनिपुलेंटर्स' (Currency manipulation)

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संभावित "संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों" और करेंसी मैनिपुलेंटर्स वाले देशों की अपनी निगरानी सूची में भारत को शामिल किया है। यह एक साल बाद फिर से है जब भारत को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की अर्ध-वार्षिक विदेशी-विनिमय रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस के वॉचलिस्ट से हटा दिया गया था।

'करेंसी मैनिपुलेंटर्स' शब्द का क्या अर्थ है?

- कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये अपने देश की मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच की विनिमय दर को प्रभावित (मुद्रा अवमूल्यन या अधिमूल्यन दोनों ही मामलों में) करने की कोशिश करता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा उसे करेंसी मैनिपुलेंटर घोषित कर निगरानी सूची में डाल दिया जाता है।
- अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछली चार तिमाहियों (जून 2020 तक) में अमेरिका के चार प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों-भारत, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ने लगातार अपने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में दखल दिया है।
- अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वियतनाम और स्विट्जरलैंड द्वारा सम्भावित रूप से अनुचित हेर-फेर की वजह से अमेरिका की प्रगति पर असर पड़ा है तथा अमेरिकी कामगारों और कंपनियों को नुकसान पहुँचा है।
- गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 की दूसरी छमाही में भारत द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद में तेज़ी आई है। इसी तरह वर्ष 2020 की पहली छमाही में भी भारत के द्वारा विदेशी मुद्रा खरीद में तेज़ी देखी गई है।

किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है?

- अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इनफोर्समेंट एक्ट, 2015 के अनुसार यदि कोई देश निम्नलिखित तीन में से दो मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे वॉच लिस्ट/ मॉनिटरिंग लिस्ट/ निगरानी सूची में रखा जाता है :
 1. यदि लगातार 12 महीनों से कोई देश अमेरिका के साथ अत्यधिक व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।
 2. यदि वह देश 12 महीनों की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के कम से कम 2 प्रतिशत के बराबर चालू खाता अधिशेष की स्थिति में है।
 3. यदि विगत 12 महीनों (या कम से कम 6 महीनों में) में किसी देश द्वारा उस देश की जी.डी.पी. के कम से कम 2% के बराबर की विदेशी मुद्रा खरीद लगातार की जा रही है।
- अमेरिकी प्रशासन मॉनिटरिंग सूची में किसी भी प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक भागीदार को भी जोड़ेगा और बनाए रखेगा, जो समग्र अमेरिकी व्यापार घाटे के "बड़े और असंगत" हिस्से के लिए जिम्मेदार है, भले ही वह अर्थव्यवस्था 2015 के अधिनियम से तीन मानदंडों में से दो से पूरी नहीं हुई हो "।

नवीनतम निगरानी सूची में अन्य देश कौन से हैं?

- अमेरिकी मामलों के ट्रेजरी कार्यालय के अमेरिकी विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को अपनी ताजा रिपोर्ट में, भारत, ताइवान और थाईलैंड को अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की निगरानी सूची में शामिल किया है जो उनकी मुद्रा प्रथाओं और मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियों के लिए "करीब ध्यान दें" रहे हैं।
- नवीनतम सूची में अन्य देशों में चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया शामिल हैं।
- भारत को आखिरी बार अक्टूबर 2018 में मुद्रा वॉचलिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन मई 2019 में सामने आई सूची से हटा दिया गया था।

भारत फिर से निगरानी सूची में क्यों है?

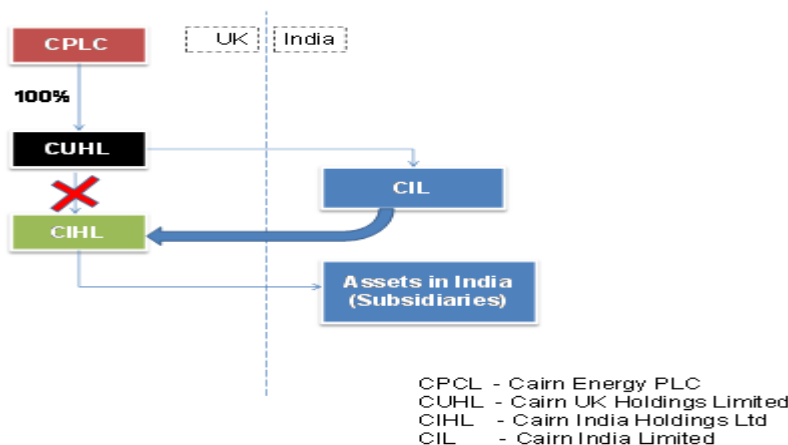
भारत, जिसने कई वर्षों तक अमेरिका के साथ "महत्वपूर्ण" द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष को बनाए रखा है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 20 बिलियन \$ का आंकड़ा पार कर गया है। द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष जून 2020 के माध्यम से पहली चार तिमाहियों में 22 बिलियन \$ था।

- केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के आंकड़ों के आधार पर, भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद 2019 की दूसरी छमाही में विशेष रूप से तेज हो गई।
- महामारी की शुरुआत के दौरान बिक्री के बाद, भारत ने 2020 की पहली छमाही के लिए शुद्ध खरीद को बरकरार रखा, जिसने जून 2020 के माध्यम से विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद को 64 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से चार तिमाहियों में धकेल दिया।

केयरन आर्बिट्रेशन केस (Cairn Arbitration case)

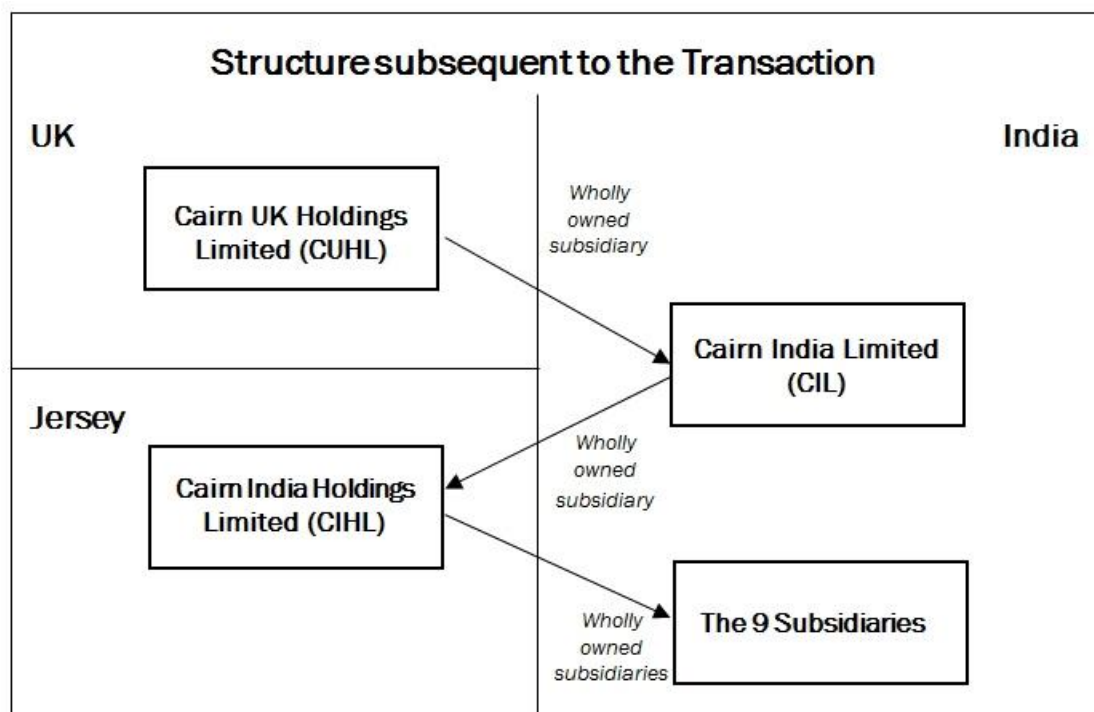
संदर्भ:

हेग स्थित स्थायी न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि भारत सरकार केयर्न पर पूर्वव्यापी कर लगाने में गलत थी। अंतरराष्ट्रीय पंचाट न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि भारत सरकार को केयर्न को हर्जाने में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।



विवाद क्या है?

- भारत सरकार और केयर्न के बीच विवाद पूर्वव्यापी कर से संबंधित है।
- 2006 से पहले (बीएसई में लिस्टिंग), केयर्न एनर्जी के भारत संचालन को केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड (CIHL) नामक कंपनी के स्वामित्व में जर्सी, यूके में शामिल किया गया था।
- केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड (CIHL) केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, जिसके परिणामस्वरूप केयर्न एनर्जी (CPLC) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
- आईपीओ (2006) के समय, भारत की संपत्ति का स्वामित्व केयर्न यूके होल्डिंग्स से एक नई कंपनी, केयर्न इंडिया लिमिटेड (CIL) को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- 2006 में, केयर्न इंडिया लिमिटेड (CIL) ने केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) से केयर्न इंडिया होल्डिंग्स (CIHL) की संपूर्ण शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया। बदले में, केयर्न इंडिया में 69 प्रतिशत शेयर केयर्न यूके होल्डिंग्स (सीएचएचएल) को जारी किए गए थे। केयर्न यूके होल्डिंग्स (सीयूएचएल) के माध्यम से केयर्न इंडिया होल्डिंग्स (सीएचसीएल), केयर्न इंडिया में 69 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते थे।
- बाद में, 2011 में, केयर्न एनर्जी ने केयर्न इंडिया को 9.8 प्रतिशत की मामूली हिस्सेदारी को छोड़कर, अरबपति अनिल अग्रवाल के वेदांत समूह को बेच दिया। यह अवशिष्ट हिस्सेदारी को भी बेचना चाहता था लेकिन I-T विभाग ने ऐसा करने से रोक दिया था। सरकार ने केयर्न इंडिया द्वारा केयर्न एनर्जी को लाभांश के भुगतान में भी देरी की।
- 2012 में, सरकार ने वित्त विधेयक में पूर्वव्यापी कर संशोधन की शुरुआत की और 2014 में आईटी अधिकारियों ने आईपीओ से पहले किए गए लेनदेन में एक पूर्वव्यापी कर जांच शुरू की।



आईटी अथॉरिटीज ने क्या आपत्ति जताई थी?

- आयकर अधिकारियों ने तब संतोष व्यक्त किया कि केयरन यूके ने पूंजीगत लाभ कमाया था और इसे 24,500 करोड़ रुपये की कर भरना पड़ेगा।
- पूंजीगत लाभ की विभिन्न व्याख्याओं के कारण, कंपनी ने कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण (ITAT) और उच्च न्यायालय में मामले दर्ज किए गए।
- जबकि केयरन ITAT में केस हार गए थे, परन्तु कैपिटल गेंस के वैल्यूएशन पर एक केस अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने लंबित है।
- 2015 में, केयरन का दावा यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि की शर्तों के तहत लाया गया था, ट्रिब्यूनल की कानूनी सीट नीदरलैंड की थी, और कार्यवाही पंचाट न्यायालय के पंचाट की रजिस्ट्री के अंतर्गत थी।

मध्यस्थता अदालत ने क्या कहा है?

हेग में स्थायी न्यायालय ने कहा है कि केयरन कर मुद्दा एक कर विवाद नहीं है, बल्कि कर-संबंधी निवेश विवाद है और इसलिए, यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

- पिछले करों में भारत की मांग पर यह कहा गया कि यह यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत उचित उपचार का उल्लंघन था।
- ट्रिब्यूनल ने सरकार को आदेश दिया कि वह बेचे गए शेयरों के मूल्य को लौटाए, जब्त किए गए लाभांश और कर रिफंड को कर की मांग को पुनर्प्राप्त करने के लिए रोक दिया गया।

- सरकार को मध्यस्थता के ब्याज और लागत के साथ "कुल नुकसान का सामना करने के लिए" केयरन की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया था।

सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है?

- भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि "एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक संप्रभु संसद द्वारा पारित कानून को चुनौती नहीं दे सकता है, हालांकि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भारत के संप्रभु कराधान अधिकारों पर जोर दिया है, "यह द्विपक्षीय निवेश संधियों के अधीन नहीं हो सकता है," पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों को आश्वासन दिया था कि "पूर्वव्यापी कराधान पर चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा"।
- इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड पर कहा है कि, "हम पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वव्यापी कराधान का उपयोग नहीं करते हैं"।
- यह फैसला मुश्किल से तीन महीने बाद आया जब भारत ने पूर्वव्यापी कर कानून संशोधन पर वोडाफोन पीएलसी को मध्यस्थता खो दी।

Connecting the dots

- Vodafone case: Click [here](#)

विस्ट्रॉन (Apple आपूर्तिकर्ता) हिंसा (Wistron (Apple Supplier) Violence)

संदर्भ:

एप्पल और अन्य उत्पादों के लिए आईफोन बनाने वाली विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक नई फैक्ट्री में भुगतान और समयोपरि मुद्दों के गैर-निवारण के बाद श्रमिक अशांति उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप 12 दिसंबर को संयंत्र में दंगा हुआ।

हिंसा के बाद बेंगलुरु से 60 किमी दूर कोलार जिले में प्लांट में उत्पादन, 1,343 नियमित श्रमिकों और 8,490 ठेका श्रमिकों को नियुक्त किया गया।

विस्ट्रॉन का निवेश

- विस्ट्रॉन, जो प्रमुख वैश्विक टेक कंपनियों के लिए उपकरण और परिधीय प्रणाली बनाता है, इसने दुनिया भर में दो दर्जन स्थानों पर विनिर्माण सुविधाएं और आरएंडडी केंद्र की स्थापना की हैं।
- कंपनी ने iPhone बनाने के लिए 2017 में बेंगलुरु में एक छोटे पायलट प्लांट की शुरुआत की और 2018 में, एक पूर्ण प्लांट के लिए भारत में एक बड़ा निवेश (3,000 करोड़ रुपये) करने का फैसला किया।
- कंपनी को 2019 के मध्य में पर्यावरणीय मंजूरी मिली और, 2020 में, कोलार संयंत्र के लिए उपकरण और मशीनरी में 1,220 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जिसे सेवा और विनिर्माण केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

- अगस्त 2020 में, संयंत्र पूरी तरह से चालू हो गया, जिसमें लगभग 5,000 कर्मचारियों ने iPhone SE (2020) और iPhone 7 मॉडल का निर्माण किया।

श्रमिक अशांति क्यों उत्पन्न हुई?

- **संविदात्मक श्रम का तेजी से विस्तार:** विस्ट्रॉन ने सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 के बीच लगभग 3,000 से 8,500 के बीच अपनी संविदात्मक कर्मचारी शक्ति को तेजी से बढ़ाया।
- अनुबंध कर्मचारियों को छह जनशक्ति आपूर्ति ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा गया था और भुगतान किया गया था, लेकिन उनके काम की निगरानी और प्रबंधन विस्ट्रॉन के अधिकारियों द्वारा किया गया था
- **ओवरटाइम काम:** विनिर्माण सुविधा भी आठ घंटे से 12-घंटे की पाली में चली गई। श्रमिक दो अनिवार्य 12-घंटे की पाली में काम कर रहे थे। फैक्ट्री को स्वीट शॉप की तरह चलाया जा रहा था।
- **अनियमित भुगतान:** प्रारंभिक पुलिस जांच में पता चला है कि ठेकेदार श्रमिकों को उनके अनुबंध के अनुसार, या ओवरटाइम काम के लिए पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे थे। “जबकि मजदूरी कुछ मामलों में 22,000 रुपये से 8,000 रुपये तक घटा दी गई थी, नवंबर के लिए मजदूरी का भुगतान 12 दिसंबर तक नहीं किया गया था।
- **श्रम अधिकार समझौता:** फर्म या संघ में किसी भी कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली के साथ, श्रमिक लगातार कंपनी के अधिकारियों से अपने बकाया के लिए पूछ रहे थे।
- **हिंसा के लिए तत्कालिक कारण:** श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 12 दिसंबर को सुबह 6 बजे की शिफ्ट में बदलाव के दौरान हिंसा हुई, एक तर्क यह भी था कि श्रमिकों द्वारा लॉग किए गए सटीक कार्य घंटों को विवरण दर्ज नहीं किया गया था।
- **ओवरब्लान्ड डैमेज:** विस्ट्रॉन के अधिकारियों ने शुरुआत में 437 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए लगभग 43 करोड़ रुपये में बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि “हिंसा से बड़े विनिर्माण उपकरण और गोदामों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा”।

Apple की प्रतिक्रिया क्या रही है?

- Apple ने विस्ट्रॉन को परीक्षा पर रखा है, और कहा कि कंपनी को तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि यह समस्याओं को ठीक नहीं करता
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ Apple कर्मचारी, उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे।
- उपभोक्ताओं की तरफ से बढ़ते दबाव और अपनी ब्रांड छवि के प्रति अत्यधिक जागरूक होने के बावजूद, Apple ने अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं को मजदूर आचार संहिता प्रदान की है, जो श्रम मानकों और सुरक्षा उपायों की निगरानी और ऑडिट की मांग कर रहे हैं।
- Apple की प्रतिक्रिया से उत्पन्न दबाव ने, विस्ट्रॉन को भी श्रमिकों से माफी मांगने, अपने भारत के संचालन के प्रभारी उपाध्यक्ष को हटाने और श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए मजबूर किया गया है।

वडोदरा नगर निगम (VMC) जनवरी 2021 में नगरपालिका बांड लॉन्च करने के लिए (Reviving the economy: 3C approach to atmanirbharta)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- वडोदरा नगर निगम (VMC) द्वारा जनवरी 2021 में नगरपालिका बांड लॉन्च करने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसके साथ, यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के लिए अटल मिशन के तहत स्वीकृत धन विकास कार्य के लिए धन जुटाने के लिए गुजरात में तीसरा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) बन जाएगा।
- इसने राज्य सरकार से उसी के लिए अनुमोदन मांगा है।
- अहमदाबाद दक्षिण एशिया का पहला शहर था जिसने 1998 में 100 करोड़ रुपये का नगरपालिका बांड लॉन्च किया था।
- सूरत नगर निगम 2018 में बांड की घोषणा करने वाला गुजरात का दूसरा शहर था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

नगर निगम का बांड

- एक नगरपालिका बांड एक प्रकार का ऋण साधन है जहां निवेशक स्थानीय सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं।
- वे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नागरिक निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं और आमतौर पर 10 साल का कार्यकाल होता है।
- ULB निवेशक को निर्धारित दर पर बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है।
- बैंक ऋण और नगरपालिका बांड के बीच अंतर यह है कि कोई भी संस्था केवल तभी बॉन्ड को सुरक्षित कर सकती है जब उसके पास अनुकूल क्रेडिट रेटिंग हो।
- **लाभ:** बॉन्ड शेयर बाजार से धन जुटाने में मदद करता है। यह एकल बैंक से ऋण की तुलना में नागरिक निकाय के लिए उपलब्ध निवेशकों की संख्या भी बढ़ाता है।

क्या आप जानते हैं?

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) योजना के लिए अटल मिशन के तहत, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बॉन्ड बाजार का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- बांड बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल, केंद्र द्वारा धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण, पारदर्शिता और कुशल राजस्व सृजन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

संबंधित आलेख:

- AMRUT के बारे में: [Click here](#)

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना: 3C आत्मनिर्भर दृष्टिकोण (Reviving the economy: 3C approach to atmanirbharta)

संदर्भ:

COVID -19 के आर्थिक प्रभाव विश्व आर्थिक व्यवस्था को नया रूप देने में महत्वपूर्ण असर डाल रहे हैं क्योंकि देश अपने बाहरी संपर्कों और विकास रणनीतियों की पुनः समीक्षा करते हैं।

क्या आपको पता है?

- OECD के पूर्वानुमानों के अनुसार, 2021 के अंत तक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार 2019 वाले आकार की होने की संभावना है, लेकिन चीन को 10% बढ़ने की उम्मीद है।
- यूरोप और जापान अपने उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे चले जाएंगे और ऐसा कई वर्षों तक चालत रहेगा।

भारत की स्थिति क्या है?

- भारत के दृष्टिकोण से, जीडीपी वृद्धि में रिकवरी मजबूती के ट्रैक पर है और अगले साल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी स्थिति को फिर से हासिल करने की नींव प्रदान करती है।
- भारत के लिए नई विश्व व्यवस्था में अपनी सही स्थिति का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण, विश्व स्तर पर उत्पन्न अवसरों का दोहन करने के लिए एकीकृत हो।
- इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, हमारी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी प्राथमिकताओं के साथ नई दुनिया के क्रम में आत्मनिर्भर भारत की स्थिति की दृष्टि निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान तीन परस्पर रणनीतिक प्राथमिकताओं पर होना चाहिए।

1. वाणिज्य (commerce): दुनिया के निर्यात और एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना

- व्यापार और एफडीआई पर, यह पुष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गलत नहीं है। भारत द्वारा लिया गया यह मार्ग आत्म-निहित नहीं है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना भारत के लिए अपनी जीडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के भारत के निर्यात में हिस्सेदारी 2011 में 24.5% से घटकर 2019 में 18.7% हो गई। वैश्विक स्तर पर 13 वें स्थान पर, भारत के पास सामान और सेवाओं के विश्व निर्यात में 2.2% की हिस्सेदारी है - चीन का लगभग पांचवां हिस्सा (10.6%)।

- यह उल्लेखनीय है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में व्यापार 2008 के बाद से चीन से आगे निकल गया है, लेकिन हमारे आयात से निर्यात काफी कम हो गया है।
- नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च क्षमता वाले विनिर्माण क्षेत्रों-इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐपरेला, फार्मा, के साथ अन्य लोगों के बीच निर्यात को फिर से जीवंत करना आवश्यक है।
- वैश्विक व्यवस्था के अनुसार, FDI के संबंध में, G20 देशों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने 1990 और 2019 के बीच FDI अंतर्वाह में 20.3% (CAGR) की उच्चतम वृद्धि हासिल की। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में, भारत 2019 में विश्व स्तर पर 9 वें स्थान पर रहा, जो आगे बढ़ने की क्षमता दिखाता है।

2. प्रतिस्पर्धा (competitiveness)

- निर्यात में अधिक हिस्सेदारी और एफडीआई को अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक धक्का के साथ उन्मुख होने की आवश्यकता है।
- इसके लिए बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से बिजली और रसद में, और कंपनियों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में उभरती हुई बदलाव भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए, जीवीसी में भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षमता और भारतीय उद्यमों के पैमाने के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- भारतीय उद्योग द्वारा सीमांत प्रौद्योगिकियों को अधिक से अधिक अपनाने के साथ उद्योग 4 (embrace Industry 4) को गले लगाना भी महत्वपूर्ण होगा।

3. मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण (currency internationalisation)

- अंत में, व्यापार और निवेश के विस्तार पर जोर बाहरी झटके और मुद्रा जोखिमों के लिए अधिक लचीला होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ पूरक हो सकता है।
- भारत को मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चीन की प्लेबुक से एक पत्ता लेने की आवश्यकता है।
- 2019 में, क्रॉस-बॉर्डर आरएमबी समझौता आरएमबी 19.7 ट्रिलियन (\$ 2.8 ट्रिलियन) की राशि, चीन के कुल क्रॉस-बॉर्डर सेटलमेंट का 38.1% है। व्यापार पर, सीमा पार से समझौता चीन के कुल व्यापार में 15% की हिस्सेदारी के साथ आरएमबी 5.2 ट्रिलियन (\$ 745 बिलियन) तक पहुंच गया।
- भारत के दृष्टिकोण से, दो तरफा प्रक्रिया में रुपए में व्यापार निपटान को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं:
 - (i) क्षेत्रीयकरण - पहले से ही नेपाल और भूटान के साथ मौजूद तंत्र को मजबूत करना और क्षेत्र के अन्य प्रमुख देशों में विस्तार करना, और
 - (ii) अंतर्राष्ट्रीयकरण - विश्व स्तर पर प्रमुख भागीदार देशों को शामिल करना।
- मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और रुपये की अधिक वैश्विक स्वीकार्यता के लिए एक व्यापक-आधारित धक्का आईएमएफ के एसडीआर टोकरी में शामिल करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने से आ सकता है।

निष्कर्ष

3C - कॉमर्स, प्रतिस्पर्धा और मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण (commerce, competitiveness & currency internationalisation) को बढ़ाने की वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को जोड़ना, महामारी की नई विश्व व्यवस्था के बाद भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक आधारशिला हो सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और नगर निगम बांड (Urban Local bodies (ULBs) & Municipal Bonds)

संदर्भ:

संसाधनों को जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की अक्षमता ने नगरपालिका आय के विकास को सीमित कर दिया है और वित्तीय संकट पैदा कर दिया है।

ULBs के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दे क्या हैं?

- **नगरपालिका राजस्व में गिरावट:** हालांकि यह परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका राजस्व जीडीपी का 1% होना चाहिए, 2010 से 2018 के बीच राजस्व 0.48% से घटकर 0.43% हो गया। यह कमी 56% से 44% के स्वयं के स्रोत राजस्व में गिरावट के कारण आई।
- **वेतन में देरी:** कम नगरपालिका की आय नगरपालिका सेवाओं के निम्न स्तर को प्रभावित करती है और कर्मचारियों के लिए वेतन में देरी करती है।
- **निम्न संपत्ति कर संग्रह:** संपत्ति कर केवल सकल घरेलू उत्पाद का 0.15% है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वे 0.6% हैं और वैश्विक औसत 1.04% है।

आगे का रास्ता

- GIS मैपिंग, बिल्डिंग लाइसेंस के साथ क्रॉस-चेकिंग, राशन कार्ड, म्यूटेशन, बिजली / गैस खातों और छूट की समीक्षा का उपयोग करके संपत्ति कर आधार का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारी संपत्तियों को परिपत्र 2009 और राजकोट निगम बनाम रेलवे में SC के निर्णय के अनुसार कवर करने की आवश्यकता है।
- वैल्यू कैप्चर करों में बिल्डिंग लाइसेंस शुल्क के ऊपर की ओर संशोधन और प्रभाव शुल्क जैसे नए स्रोतों को शामिल करने की आवश्यकता है, जैसा कि तेलंगाना में लगाया गया है, गुजरात में लगाए लेवी करा।
- **स्थानीय शुल्क** - एक विज्ञापन शुल्क लगाया जाना आवश्यक है क्योंकि बड़ी संख्या में अनधिकृत बोर्ड शहर भर में लगे हुए हैं। उपयोगकर्ता शुल्क (पानी, आदि) पर वसूली जो केवल 20% है, गैस / बिजली और फाइबर ऑप्टिक लाइनों, सेल टॉवर, बिजली के खंभे को पट्टे पर देने और आरडब्ल्यू को पार्कों के रखरखाव का अधिकार।
- सहभागी निधि (निजी क्षेत्र, सीएसआर और स्थानीय समुदाय) की क्षमता को टेप करने की आवश्यकता है क्योंकि बेंगलुरु, अहमदाबाद, मथुरा (हाइब्रिड वार्षिकी परियोजना), इंदौर और पुणे द्वारा इसे एकत्र किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 243X में नगरपालिका के स्वयं के स्रोतों के दायरे से ऊपर राजकोषीय उपकरणों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है।
- नगरपालिका बांडों को उनके राजस्व बढ़ाने और सरकारी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए ULBs द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।

म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है?

- एक नगरपालिका बांड एक प्रकार का ऋण साधन है, जहां निवेशक स्थानीय सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं। वे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नागरिक निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं और आमतौर पर 10 साल का कार्यकाल होता है। ULB निवेशक को तय दर पर बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है।
- **नगरपालिका बांड के लाभ:** बांड शेयर बाजार से धन जुटाने में मदद करता है। बांड एक एकल बैंक से ऋण की तुलना में नागरिक निकाय के लिए उपलब्ध निवेशकों की संख्या भी बढ़ाता है। बांड क्रेडिट प्रोफाइल, केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष धन के हस्तांतरण, पारदर्शिता और कुशल राजस्व सृजन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- **केंद्र से सहायता:** एएमआरयूटी (यूएलबी) के तहत बांड बाजार को टैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्र सरकार ने बॉन्ड के माध्यम से उठाए गए प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के लिए यूएलबी को 13 करोड़ रुपये का भुगतान भी करती है, जो प्रत्येक के लिए 26 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 2018-19 में आठ यूएलबी ने बांड जारी किए और मंत्रालय द्वारा 181.33 करोड़ रु प्रोत्साहन दिया गया है।
- बैंक ऋण और नगरपालिका बांड के बीच अंतर यह है कि कोई भी संस्था केवल तभी बॉन्ड को सुरक्षित कर सकती है जब उसके पास अनुकूल क्रेडिट रेटिंग हो। बॉन्ड के लिए ब्याज दरें आमतौर पर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जहां बैंक ऋण प्रकृति में बहुत अधिक अपारदर्शी और राजनीतिक हैं।
- **निष्पक्ष प्रक्रिया:** बांड के लिए बोली एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होती है जब यह एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। बोली सभी निवेशकों के लिए खुली है और उन्हें ULB द्वारा नियुक्त लेनदेन को एजेंट द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, जिन्हें आम तौर पर ULB के खाते में धन हस्तांतरित होने के बाद 0.10% का कमीशन मिलता है।
- अहमदाबाद और सूरत के मामले में एक ही निवेशक हो सकता है, जहां गुजरात राज्य वित्तीय सेवा (जीएसएफएस) ने प्रत्येक 200 करोड़ रुपये का पूरा बॉन्ड उठाया है, या कई निवेशक हो सकते हैं, जो किसी भी संख्या में प्रत्येक 10 लाख रुपये का मूल्य स्लॉट की लिए बोली लगा सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- अहमदाबाद 1998 में 100 करोड़ रुपये का नगरपालिका बांड लॉन्च करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर था, जिसे पूरी तरह से सदस्यता दी गई थी।
- सूरत नगर निगम 450 करोड़ रुपये की सीवेज उपचार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए 2018 में बॉन्ड की घोषणा करने वाला गुजरात का दूसरा शहर था।

- वडोदरा नगर निगम (VMC) को जनवरी में नगरपालिका बांड लॉन्च करने की उम्मीद है, और AMRUT योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के लिए गुजरात में तीसरा शहरी स्थानीय निकाय (ULB) बन जाएगा।

सरकार ने जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यवसाय परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य करती है (Government introduces mandatory physical verification of business premises for GST registration)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -जीएसटी; कर

समाचार में

- सरकार ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए व्यवसाय परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कदम का उद्देश्य जीएसटी नकली चालान धोखाधड़ी के खतरे को नियंत्रित करना है।
- जीएसटी परिषद की कानून समिति द्वारा अनुशंसित:
- अलग से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एक नया नियम पेश किया गया है, जिसमें ST 50 लाख से अधिक के मासिक कारोबार के साथ व्यवसायों को उनके निर्वहन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के बजाय नकद में कम से कम 1% का भुगतान करना होगा।
- एक जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई वे बिल के नियम से परिवहन और व्यवसायी वर्ग चिंतित है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई वे बिल की समय सीमा की वैधता घटाई जाएगी। वर्तमान में प्रति 100 किमी तक के लिए वाहन पर लादे गए सामान पर दो दिन के लिए ई वे बिल की समय सीमा है। यह एक जनवरी से मात्र एक दिन की रहेगी।
- अब, वैधता के प्रत्येक दिन के लिए दूरी को 200 किमी तक बढ़ा दिया गया है।

संबंधित आलेख:

- GST compensation: [Click here](#)
- Global energy companies demand Natural Gas under GST regime: [Click here](#)
- CAG report on GST: [Click here](#)

1000 वर्ष पुरानी हस्तनिर्मित कागज उद्योग 'मोनपा' को ज़िंदा किया गया है(1000-yrs Old Monpa Handmade Paper Industry brought alive in AP)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- 1000 साल पुरानी विरासत कला - अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज - जिसे विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के प्रतिबद्ध प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला 1000 साल पहले उत्पन्न हुई थी।
- यह हस्तनिर्मित कागज स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत था।
- हालांकि, हस्तनिर्मित कागज उद्योग पिछले 100 वर्षों में लगभग गायब हो गया।
- हाल ही में, KVIC ने तवांग में एक मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई शुरू की जिसका उद्देश्य कला को पुनर्जीवित करना और स्थानीय युवाओं को इस कला के साथ पेशेवर रूप से जोड़ना और आय का साधन बनाना है।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज, शुग शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा, जिसके औषधीय मूल्य भी हैं। इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता कोई समस्या नहीं होगी।

क्या आप जानते हैं?

- महीन बनावट वाला हस्तनिर्मित कागज, जिसे स्थानीय बोली में सोम शुग कहा जाता है, तवांग में स्थानीय जनजातियों की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग है।
- इस कागज का बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यह बौद्ध धर्मग्रंथों और मठों में भजन लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला पेपर है।
- हस्तनिर्मित कागज के अलावा, तवांग दो अन्य स्थानीय शिल्पों के लिए जाना जाता है - हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों और हस्तनिर्मित फर्नीचर - जो समय बीतने के साथ विलुप्त हो रहे हैं।
- यह घोषणा की गई थी कि छह महीने के भीतर, इन दो स्थानीय कलाओं के पुनरुद्धार के लिए योजना तैयार की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह संसद के अधिनियम, TI खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 'के तहत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में (एक आरटीआई के अनुसार) एक वैधानिक निकाय है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।
- दृष्टि - ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना।
- अप्रैल 1957 में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम संभाला।
- प्रधान कार्यालय: मुंबई

- छह क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, भोपाल, बेंगलूर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी।

4% पर मुद्रास्फीति लक्ष्य भारत के लिए उपयुक्त है: RBI (Inflation Target at 4% is appropriate for India: RBI)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा “भारत में मापने की प्रवृत्ति” शीर्षक से एक कार्यकारी पत्र जारी किया गया था।
- पत्र के अनुसार, मुद्रास्फीति के लक्ष्य को 4% पर बनाए रखना भारत के लिए उचित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कागज भारत में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना चाहता है।
- मुद्रास्फीति के लिए 4% लक्ष्य - 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा और 2% की कम सीमा के साथ - 2016 में RBI के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया था और इसकी वैधता 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है।
- यह पत्र 2014 के बाद से प्रवृत्ति मुद्रास्फीति में लगातार 4.1- 4.3% की गिरावट को दीखता है।
- प्रवृत्ति के नीचे निर्धारित लक्ष्य भी मौद्रिक नीति के लिए एक बचाव पक्षीय पूर्वाग्रह प्रदान करता है।
- इसी तरह, एक लक्ष्य जो प्रवृत्ति के ऊपर तय किया गया है वह मौद्रिक नीति को भी विस्तार देता है और मुद्रास्फीति के झटकों का खतरा है।
- इसलिए, मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% पर बनाए रखना भारत के लिए उचित है।

पंजाब और सिंध बैंक को पुनर्पूँजीकृत करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड (Zero Coupon bonds to recapitalise Punjab & Sind Bank)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए शून्य कूपन बांड के वित्तीय नवाचार का उपयोग किया है, जिसमें ऋणदाता को 5,500 करोड़ रुपये के गैर-ब्याज असर वाले बांड जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ये विशेष प्रकार के शून्य कूपन बॉन्ड हैं जो उचित उचित परिश्रम के बाद सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हें बराबर जारी किया जाता है।
- ये बांड व्यापार योग्य नहीं हैं।
- ऋणदाता ने उन्हें इन बांडों से किसी भी मार्क-टू-मार्केट लाभ या हानि को बुक करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हेल्ड-टू-मेच्योरिटी (HTM) के अंतर्गत रखा गया है।
- हालांकि ये ग्राहक से कोई ब्याज नहीं कमाएंगे, बाजार सहभागियों ने सरकार द्वारा इसे 'वित्तीय भ्रम' और 'महान नवाचार' दोनों कहा है, जहां यह 100 रुपये का उपयोग कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में 200 रुपये का प्रभाव पैदा हो सके।
- इन बॉन्ड में 10-15 साल की परिपक्वता है और विशेष रूप से पंजाब एंड सिंध बैंक को जारी किया गया है।

वे निजी फर्मों द्वारा जारी किए गए शून्य कूपन बांड से कैसे भिन्न हैं?

- ये बॉन्ड एक खाते पर पारंपरिक शून्य कूपन बॉन्ड से अलग हैं - जैसा कि उन्हें बराबर में जारी किया जा रहा है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
- पिछले मामलों में, चूंकि वे छूट पर जारी किए गए थे, वे तकनीकी रूप से ब्याज वहन करने वाले थे।
- निजी कंपनियों द्वारा शून्य कूपन बांड सामान्य रूप से छूट पर जारी किए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये विशेष बांड पारंपरिक नहीं हैं, इसलिए इन्हें बराबर में जारी किया जा सकता है।

लचीला आपूर्ति चेन (Resilient Supply Chains)

संदर्भ:

महामारी सबक - लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने का महत्व जो व्यवधानों का सामना कर सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकता है।

भारत - मुद्दे

- जब महामारी फैल गई, तो चीन से निकलने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ा।
- भारत में, कई कंपनियों ने मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में व्यवधान महसूस किया।
- भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रहा है, लेकिन चीन से सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई) पर अधिक निर्भरता अभी भी मूल्य श्रृंखला में कमजोरियां पैदा की है।
- चिकित्सा उपकरणों के लिए एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार होने के बावजूद, भारत में 80% का आयात निर्भरता है। इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में चीन, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर और जापान हैं।
- भारत चीन से मोटर वाहन भागों की अपनी आवश्यकता का 27% आयात करता है।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)

- इस संदर्भ में है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम, स्टील, वस्त्र, वित्तीय सेवाओं और आईटी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) की शुरुआत की।
- SCRI को फ्रांस की भविष्य की भागीदारी से प्रभावित किया जा सकता है, हालांकि यह यूरोपीय संघ की स्थिति पर निर्भर हो सकता है।
- यूनाइटेड किंगडम ने भी SCRI में रुचि दिखाई है।

आत्मनिर्भर भारत

- इसका उद्देश्य भारत की क्षमता को मजबूत करना है ताकि व्यवधानों के बिना इसमें अधिक सख्ती से भाग लिया जा सके।
- भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत रक्षा विनिर्माण को एक बड़ा बढ़ावा दे रहा है। इसने 101 वस्तुओं की एक नकारात्मक आयात सूची की पहचान की है।
- भारत अर्धचालक घटकों और पैकेजिंग उद्योग में निवेश को आकर्षित करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाना चाहता है।
- भारत में निवेश के लिए दुनिया के सबसे बड़े गंतव्यों में से एक बनने की क्षमता और क्षमता है, और महामारी के बाद दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक है।



ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (AIPTS+) – 2021

BOTH in ENGLISH and Hindi (हिन्दी)



TOTAL NO. OF TESTS = 62 TESTS

- 52 General Studies (Paper 1) Tests
- 10 CSAT (Paper 2) Tests.

ONLINE All India Prelims Test Series (AIPTS) - 2021 is available BOTH in ENGLISH and HINDI

DETAILED SOLUTION & TECHNIQUES to Decipher the Correct Answer (Elimination Technique)

With increasing **IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS (CA)** in the exam, we have Current Affairs Test held every 15 days.

All the Tests are **FLEXIBLE** and will be Valid till next Prelims Exam (2021)

ALL INDIA RANKING - the scores and ranks will be displayed after every test.

DOUBTS RESOLUTION PAGE - We have a comment section for every question in a Test.

DETAILED ASSESSMENT OF YOUR PERFORMANCE - For you to analyse your performance we provide 2 tools Time Analytics and Subject-wise Analytics.

NEW !

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES+ (AIPTS+): ALL THE FEATURES OF AIPTS with Video Discussions of BOTH GS & CSAT TESTS

Register Now

कृषि(AGRICULTURE)

हनी किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का NAFED द्वारा उद्घाटन किया गया है। Honey FPO Programme inaugurated under NAFED)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - कृषि

समाचार में

- हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) के हनी किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) कार्यक्रम का उद्घाटन किया है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह कार्यक्रम FPO के गठन और संवर्धन के तहत शुरू किया गया है।
- यह 10,000 नए FPO के प्रचार के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसके तहत, राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबंधन सलाहकार और निधि मंजूरी समिति (N-PMAFSC) ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2020-21 के लिए एफपीओ क्लस्टर आवंटित किए थे।
- FPO को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लगे विशेषज्ञ क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) द्वारा विकसित किया जाएगा।
- NAFED ने भारत के 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों और शहद संग्राहकों के FPO के गठन और संवर्धन की पहल की है।
- 5 स्थान:** पूर्वी चंपारण (बिहार), मुरैना (मध्य प्रदेश), भरतपुर (राजस्थान), मथुरा (उत्तर प्रदेश) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)।
- पहला हनी एफपीओ मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत किया गया है।
- लाभ:** (1) वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन; (2) शहद और संबद्ध मधुमक्खी पालन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं; (3) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता उन्नयन; (4) बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)

- यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है।
- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।
- यह बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।
- नाफेड वर्तमान में भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद के साथ-साथ विपणन एजेंसियों में से एक है।

- **उद्देश्य:** (1) कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करना; (2) कृषि मशीनरी, औजार और अन्य इनपुट वितरित करने के लिए; (3) कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह के लिए कार्य करना और सहायता करना

क्या आप जानते हैं?

- एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन करता है।
- इस पद्धति में मधुमक्खियों को व्यावसायिक रूप से एपीरीज में प्रतिबंधित किया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत सारे मधुमक्खियों को रखा जा सकता है।

दिल्ली चलो किसान विरोध प्रदर्शन (Dilli Chalo Farmers Protest)

संदर्भ: पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान दिल्ली के द्वार पर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

विरोधों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- सरकार के अनुसार, नए कृषि बिल के द्वारा कई निजी बाजारों की स्थापना की जाएगी और बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार, किसान किसी भी खरीदार को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे और फार्मगेट की कीमतें बढ़ेंगी।
- लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन दावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
- उनका मानना है कि कृषि बाजारों में एक कॉर्पोरेट उपस्थिति की तीव्रता के साथ फार्मगेट की कीमतें गिरेंगी। वे यह भी मानते हैं कि सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को समाप्त करना चाहती है।

आइए हम किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 (FPTC अधिनियम) पर ध्यान देने के साथ प्रमुख दावों और उनकी खूबियों को देखें।

1. किसान की उपज पर मंडियों का एकाधिकार

FPTC अधिनियम के पीछे एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा नियंत्रित मंडियां पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रेता का प्रभाव है।

- यह धारणा ही विशिष्ट है।
- पहला, आधिकारिक डेटा बताता है कि धान और गेहूं के लिए भी, क्रमशः एक मंडी में केवल 29% और 44% फसल बेची जाती है, जबकि 49% और 36% या तो एक स्थानीय निजी व्यापारी या एक इनपुट डीलर को बेची जाती है।
- 2019 में केवल 6,630 मंडियां हैं, जिनमें औसत क्षेत्र 463 किमी² है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) ने 41,000 मंडियों की सिफारिश की है जो 80 किमी² की सेवा कर रही हैं ताकि प्रत्येक भारतीय किसान एक घंटे में एक गाड़ी से मंडी तक पहुंच सके। इस प्रकार, भारत को कम नहीं बल्कि अधिक मंडियों की आवश्यकता है।

- इसके अतिरिक्त, अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों को, उनके छोटे विपणन योग्य अधिशेष को देखते हुए, मंडियों में उनकी फसल लेने के लिए परिवहन लागत वहन करना किफायती नहीं लगता है। इस प्रकार, वे अपनी फसल को गाँव के व्यापारी को कम कीमत पर बेच देते हैं।
- दूसरे शब्दों में, वास्तव में, भारतीय फसल का एक बड़ा हिस्सा संरचनात्मक कारणों से सीधे मंडी में नहीं बेचा जाता है - कम मंडियों और उच्च लागत- और एपीएमसी मंडियों द्वारा शोषण के कारण नहीं।
- इसलिए, एपीएमसी मंडियों का किसान की उपज पर एकाधिकार गलत है।

2. निजी खिलाड़ियों की उपस्थिति से बाजार की दक्षता में सुधार होगा

- डी ज्यूर, बाहर की मंडियों को बेचने की स्वतंत्रता पहले से ही कई राज्यों में मौजूद है।
- पहले से ही, 18 राज्यों ने एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों की स्थापना की अनुमति दी है; 19 राज्यों ने किसानों से कृषि उपज की सीधी खरीद की अनुमति दी है; और 13 राज्यों ने एपीएमसी के बाहर किसान बाजारों की स्थापना की अनुमति दी है।
- इस तरह के विधायी परिवर्तनों के बावजूद, इन राज्यों में निजी बाजारों की स्थापना के लिए कोई महत्वपूर्ण निजी निवेश नहीं हुआ है।
- निजी बाजार कुछ फसलों के लिए उभरे हैं, लेकिन ये व्यापक रूप से नहीं हैं।
- बाजारों में खराब निजी निवेश का कारण उत्पादन संग्रह और एकत्रीकरण में उच्च लेनदेन लागत की उपस्थिति है (संग्रह, वेतन, ग्रेडिंग, भंडारण आदि के ड्वार्टन केंद्रों में होने वाली लागत)
- छोटे और सीमांत किसानों की संख्या जितनी अधिक होगी, ये लागत उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि कई खुदरा श्रृंखलाएं किसानों से सीधे के बजाय मंडियों से भारी मात्रा में फल और सब्जियां खरीदना पसंद करती हैं।

3. मंडियों पर लगने वाले कर सही नहीं हैं

- यह कई लोगों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि मंडियों में करों को व्यर्थ माना जाता है और इस प्रकार मंडी कर (नए एफपीटीसी अधिनियम द्वारा) का उन्मूलन किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद करेगा।
- निजी बाजार उभरने पर भी, मंडी करों में किसी भी तरह की गिरावट की संभावना नहीं है। नतीजतन, कोई आश्वासन नहीं है कि किसानों को निजी बाजारों में अधिक कीमत मिलेगी।
- मंडी कर पूरी तरह से सही नहीं है। मंडी करों में से अधिकांश को बाजार के बुनियादी ढांचे और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एपीएमसी द्वारा पुनर्निवेशित किया जाता है।
- मंडियों के कमजोर होने पर ऐसे ग्रामीण निवेश भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

एमएसपी के संबंध में किसान का क्या डर है?

- विरोध कर रहे किसान समूहों की मुख्य मांग एमएसपी के तंत्र की सुरक्षा है जिससे उन्हें डर है कि नए कृषि बिलों से वे कमजोर हो जाएंगे। वे एमएसपी पर कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं।

- संदेह के बिना, एमएसपी कागज पर जीवित रहेगा क्योंकि सरकार को न्यूनतम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद करनी होगी। हालांकि, कई पॉलिसी MSPs को कमजोर करने के लिए एक रणनीतिक डिजाइन की ओर इशारा करते हैं
 - पिछले पांच से छह वर्षों में एमएसपी पिछले वर्षों की तुलना में काफी धीमी दर से बढ़ रहा है
 - सरकार ने अभी तक उत्पादन की C2 लागत से 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत के नुकसान के लिए MSP को 50% से अधिक तय करने पर सहमति नहीं दी है
 - खाद्यान्नों की खुली खरीद को रोकने के लिए CACP की सिफारिश
- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडियों सहित खरीद केंद्रों के माध्यम से अधिकांश फसल की बिक्री एमएसपी पर होती है।
- यदि मंडियां कमजोर हो जाती हैं और निजी बाजार पर्याप्त रूप से उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो उन्हें डर है कि इसशून्य को बेईमान और अनियमित व्यापारियों द्वारा भरा जाएगा।

क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?

सरकार और किसानों के बीच चर्चा दो फोकस बिंदुओं के आधार पर एक व्यापक ढांचे का उपयोग करके संरचित किया जा सकता है।

- सबसे पहले, भारत को मंडियों के घनत्व में वृद्धि, मंडियों के बुनियादी ढांचे में निवेश का विस्तार और अधिक क्षेत्रों एवं फसलों के लिए एमएसपी प्रणाली के प्रसार की आवश्यकता है।
- दूसरा, हमें न केवल अधिक मंडियों की जरूरत है, बल्कि बेहतर मंडियों की भी जरूरत है। एपीएमसी को नए खिलाड़ियों के प्रवेश को आसान बनाने, व्यापारी की मिलीभगत को कम करने और उन्हें राष्ट्रीय ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए आंतरिक सुधार की आवश्यकता है
- व्यापारियों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंसों की शुरुआत और बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी भी सही दिशा में कदम है।

निष्कर्ष

फार्म अधिनियम विधायी उपाय थे जो हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बिना पारित किए गए थे। इस प्रकार, सरकार को किसानों की वास्तविक आशंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे।

किरो ऑफ जीरो वैली (Kiwis Of Ziro Valley)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - कृषि

समाचार में

- अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में जंगली उगाने वाले कीवी भारत में अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणित जैविक फल है।

- अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER) के तहत कीवी के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- जीरो घाटी लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER)

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- यह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के तहत एक उप-मिशन है।
- इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया
- **कार्यान्वयन:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा,

क्या आप जानते हैं?

- एक कृषि अभ्यास / उत्पाद को जैविक माना जाता है जब इसकी खेती की प्रक्रिया में कोई रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक शामिल नहीं होते हैं।
- भारत में ऐसे प्रमाणपत्र नियामक निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीई) द्वारा किए गए सख्त वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं।

नीति निर्माण और कृषि विरोध (Policy Making and Farm Protests)

संदर्भ: कानून और नीति बनाते समय विस्तृत विचार-विमर्श और परामर्श की आवश्यकता है।

मुद्दे

- नए कृषि कानूनों पर असंतोष संसद में बहस और चर्चा का एक परिणाम है।

- शुरू में अध्यादेशों के माध्यम से विधेयकों को अधिनियमित किया गया था।
- अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था और तीन दिनों के भीतर इसे एक स्थायी समिति को भेजे बिना पारित कर दिया गया था।
- जबकि इन कानूनों को लागू करने के लिए संसद का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट प्रतीत होता है, वे कृषि बाजारों को प्रभावित करते हैं, जो राज्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- किसानों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।
- प्रभावित दलों के साथ सक्रिय सक्रियता की अनुपस्थिति ने मौजूदा संकट को जन्म दिया है।

चर्चाएँ और परामर्श

- आम सहमति बनाने और चिंताओं को दूर करने की प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन इससे नीतिगत उद्देश्यों की अधिक स्वीकृति होती है।
- संसद शायद इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है।
- विशेषज्ञों और हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने और एक कानून बनाते समय क्रॉस-पार्टी सर्वसम्मति बनाने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है।
- यह आमतौर पर अपनी समितियों के माध्यम से किया जाता है।
- सरकार अन्य सलाहकार तंत्रों, जैसे विशेषज्ञ समितियों और सलाहकार समूहों का उपयोग प्रतिक्रिया और नीति बनाने के लिए भी कर सकती है।
- संसदीय समितियां कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- इन समितियों ने परस्पर विरोधी हितों के माध्यम से बातचीत करने में मदद की है।

आगे का रास्ता

- स्थिर नीति-निर्माण नीति के लाभों पर एक व्यापक समझौते की आवश्यकता है। इस तरह की आम सहमति हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से बनाई जाती है।
- संसद को व्यापक जन भागीदारी को सक्षम करने के लिए अपनी समितियों को पुनर्जीवित करना चाहिए।
- यह जोर देना चाहिए कि हर विधेयक को एक समिति में जानबूझकर किया जाता है, बहुत कुछ जैसा कि ब्रिटिश संसद करती है।
- संसद को एक जानबूझकर निकाय के रूप में अपना कार्य करने की आवश्यकता है जो चिंताओं को स्वीकार करने के लिए समझौता करने में सक्षम बनाता है।

पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध (Punjab & Haryana farmers' protests)

संदर्भ: नए कृषि कृत्यों के विरोध में उत्तर भारत में किसानों का विरोध एक बार फिर से भड़क उठा है

किसान की चिंता क्या है?

- उनकी मुख्य चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संभावित वापसी और अनाज की सार्वजनिक खरीद के निराकरण को लेकर है।
- वे यह भी कहते हैं कि किसानों को खुले बाजार की दया पर छोड़ दिया गया है, बड़े निजी खिलाड़ियों को कृषि पर कब्जा करने के लिए मंच निर्धारित किया गया है।
- किसान संघ हाल ही में लागू किए गए फार्म अधिनियमों को पूरी तरह से वापस लेने से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं, जिसका दावा है कियह छोटे और सीमांत किसानों को बर्बाद कर देगा।
- यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों में हुआ है।

विवाद क्या है?

- सरकार का दावा है कि अधिनियम केवल उत्पादन बाजारों में किसानों के लिए विकल्प बढ़ाएगा और एमएसपी-खरीद प्रणाली जारी रहेगी, और इस प्रणाली को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है।
- अपने दावों का समर्थन करने के लिए, सरकार इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि अधिनियमों में एमएसपी या खरीद का कोई उल्लेख नहीं है।
- यह सच है कि पंजाब में धान की बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद चल रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन उग्र हैं, इस प्रकार इस क्षेत्र में किसानों की आशंकाओं को बल मिलता है।

पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से मुखर विरोध क्यों कर रहे हैं?

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) इन राज्यों में जीवन रेखा है। पंजाब और हरियाणा में किसान एमएसपी के माध्यम से सार्वजनिक खरीद और सुनिश्चित कीमत पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- यह किसी भी अन्य राज्य में किसानों की तुलना में कहीं अधिक है।
- धान उत्पादन का लगभग 88% और गेहूं उत्पादन का 70% सार्वजनिक खरीद के पंजाब और हरियाणा में (2017-18 \2018-19 में) के माध्यम से किया गया है।
- इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख धान राज्यों में, केवल 44% चावल का उत्पादन सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
- गेहूं के मामले में, यह प्रतिशत और भी कम है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूं राज्यों में, उत्पादन का केवल एक चौथाई (23%) सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
- यह स्पष्ट रूप से एमएसपी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली पर पंजाब और हरियाणा में किसानों की भारी निर्भरता को दर्शाता है। इसलिए, प्रणाली में कोई व्यवधान, वास्तविक या कथित, एक बड़ी उथल-पुथल का कारण हो सकता है।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में सरकार के दायित्व क्या हैं?

- **एनएफएसए के तहत दायित्व:** यदि पंजाब और हरियाणा के किसानों को खरीद प्रणाली की आवश्यकता है, तो सरकार को इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। यह पीडीएस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अपने दायित्वों के कारण है, जो एक कानूनी और अधिकार-आधारित अधिकार है।
- **बड़ी संख्या में लोगों को पीडीएस द्वारा समर्थित है:** लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी हैं और इसके अतिरिक्त आठ करोड़ प्रवासी हैं जिन्हें पीडीएस के तहत समर्थित होने की आवश्यकता है। सरकार को पीडीएस को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से इन दोनों राज्यों से अनाज की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता है।
- **पीडीएस की आपूर्ति के लिए खरीद की आवश्यकता है:** पिछले तीन वर्षों में देश में कुल धान उत्पादन का लगभग 40% (45 मिलियन टन) और 32% गेहूं उत्पादन (34 मिलियन टन) की आपूर्ति सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा पीडीएस में की गई है।
- **महामारी का प्रभाव:** इस साल, कोरोनावायरस महामारी और प्रवासी संकट की शुरुआत के कारण, सरकार ने सार्वजनिक वितरण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में - लगभग 58 मिलियन टन चावल और 37 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता है। यह देश के चावल उत्पादन (49%) और 35% गेहूं उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है।
- **ओपन मार्केट खरीद संभव नहीं है:** महामारी के कारण, सरकार को पिछले वर्षों की तुलना में भारी मात्रा में अनाज की खरीद करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार खुले बाजार में जाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। यह आपदा के लिए एक निश्चित नुस्खा है क्योंकि कीमतें आसमान छू जाएंगी, और हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के तहत किये गए स्टॉक प्रतिबंधों के साथ, बड़े पैमाने पर जमाखोरी की भी संभावना है।

यह राज्य सरकार के लिए क्यों मायने रखता है?

- अगर सरकार इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने का इरादा रखती है, तो उसे इन दोनों राज्यों की ओर रुख करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ऐसे राज्य हैं जो हमेशा खरीद एजेंसियों को अनाज की आपूर्ति करने में सबसे आगे रहे हैं।
- पिछले तीन वर्षों में लगभग 35% चावल और 62% गेहूं की खरीद इन राज्यों से हुई है। साथ ही, कुल मोटे अनाज का लगभग 50% इन दोनों राज्यों से आया।
- इस प्रकार, सरकार के पास निकट भविष्य में इन राज्यों से अपनी खरीद जारी रखने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। COVID-19 की स्थिति में सुधार होने और प्रवासी संकट समाप्त होने के बाद भी, NFSA के तहत दायित्वों को जारी रखा जाएगा।

आगे का रास्ता

- **प्रदर्शनकारियों से जुड़ाव:** यह स्पष्ट है कि खरीद प्रणाली को समाप्त करना न तो किसानों के हित में है और न ही सरकार के। इसलिए, यह जरूरी है कि सरकार किसान समूहों तक पहुंचे और उन्हें एमएसपी-खरीद प्रणाली की अपरिहार्यता का आश्वासन दे।
- **खरीद में विविधता:** सरकार को पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों से दूर इसकी खरीद में विविधता लाना चाहिए।
- **आम सहमति बनाएं:** किसानों और राज्यों के लिए एक सहमतिवादी दृष्टिकोण अपनाकर जिस तरह से फार्म बिलों की जरूरत के माध्यम से लाया गया है, उसके परिणामस्वरूप गंभीर रूप से विश्वास घटा है।

किसान विरोध: पारिश्रमिक फसल के पैटर्न की जरूरत (Farmer's Protest: Remunerative Cropping Patterns needed)

संदर्भ:

उत्तर भारत में मुख्य रूप से नए कृषि अधिनियमों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क उठा है, जो कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।

भारत में गेहूं की फसल की आपूर्ति और मांग के बीच आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच फ्लैशप्वाइंट मूल रूप से बेमेल है।

समस्या की उत्पत्ति

- **आजादी के दौरान खाद्य असुरक्षा:** वर्तमान स्थिति की उत्पत्ति आधी सदी पहले शुरू की गई नीतियों से उपजी थी, जब भारत खाद्यान्न में गंभीर रूप से कम था और अमेरिका से सहायता के रूप में PL-480 के तहत आयात पर निर्भर रहना पड़ता था।
- **खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस की स्थापना:** भारत ने राशन कार्ड जारी करके लोगों को गेहूं (और बाद में चावल) की आपूर्ति के लिए एक विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की स्थापना की, जो उन्हें नियंत्रित कीमतों पर एक निश्चित मात्रा का हकदार बनाती है।
- **पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से हरित क्रांति:** समवर्ती, उच्च उपज वाली बीजों का उत्पादन और बिजली और कुछ उर्वरकों के लिए सब्सिडी के साथ नलकूपों और उर्वरकों के उपयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ राज्य एजेंसियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।
- **पंजाब और हरियाणा से खरीद के अनुपात:** पीडीएस को खिलाने के लिए, संभावित अधिशेष उत्पादक राज्यों (विशेष रूप से, पंजाब और हरियाणा) को देश के बाकी हिस्सों से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खरीद के एकाधिकार के तहत हटा दिया गया था।) एक किसान पारिश्रमिक मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के रूप में लेबल किया गया।
- **परिणामस्वरूप यह चावल (सामान्य किस्मों) और गेहूं के उत्पादन और खरीद के लिए एक शानदार सफलता थी।** भारत उनके उत्पादन में लगातार अधिशेष बन गया है, जो पीडीएस और सरकार की नीति का केंद्र बिंदु था।
- **निजी खिलाड़ियों का डर:** वर्तमान में, तथाकथित समर्थन मूल्य राजनीतिक रूप से प्रभावित है। बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ियों के आगमन के साथ, किसानों का मानना है कि कॉर्पोरेट खिलाड़ी एमएसपी को अपने हित में पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाने के लिए सरकार को प्रभावित करेंगे।
- **किसानों को सौदेबाजी की शक्ति का डर:** किसान-राज्य सरकार-केंद्र सरकार के सत्ता समीकरण को एक किसान / राज्य सरकार बनाम कॉर्पोरेट क्षेत्र के झगड़े में ध्रुवीकृत होने की संभावना है, जिसमें किसानों की लॉबी आशातीत शक्तिहीन होगी।

आपूर्ति पक्ष पर परिदृश्य क्या है?

- आपूर्ति की ओर, सरप्लस बढ़ने वाले क्षेत्रों में फसल का प्रारूप बदल गया है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा अब रबी सीजन में कुल खेती योग्य भूमि के 90 प्रतिशत से ऊपर होने के कारण गेहूं के रकबे के साथ चावल-गेहूं चक्र के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर, खरीफ के मौसम में कुल खेती योग्य भूमि का 80 प्रतिशत चावल खाता है, यह लगभग एक-चौथाई बासमती चावल के अंतर्गत आता है।
- निवेश के साथ-साथ खेती की प्रथाओं में नियंत्रित सिंचाई और सामान्य सुधारों ने इस चावल-गेहूं को फसल चक्र निर्मित कर दिया है।
- खरीफ सीजन में चावल की बेहतर किस्में (यानी बेहतर बासमती आदि) जिनकी कम उपज, कम पानी और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्यात योग्य और अत्यधिक कीमत वाले होते हैं, संभवतः इस क्षेत्र में बेहतर फसल विकल्प हो सकते हैं।

वर्तमान खरीद नीति ने निर्यात की वृद्धि को बिगड़ा

- वर्तमान खरीद नीति के तहत, उच्च गुणवत्ता वाले अनाज के उत्पादन के लाभों को अनदेखा किया गया है।
- चूंकि नीति की उत्पत्ति में कमी की अवधि में पीडीएस प्रणाली को खिलाना था, उपज को अधिकतम करने और उत्पादन की लागत कम करने के विचारों ने उत्पादन और खरीद के फैसले तय किए।
- ये दुर्भाग्य से, निर्यात के लिए सबसे अच्छे उत्पाद नहीं थे।
- भारत में मध्यम वर्गों के लिए कीमतें कम रखने के बारे में महत्वपूर्ण चिंता इस प्रकार है, कृषि क्षेत्र के स्वस्थ विकास में बाधा।
- निर्यात पर भौतिक कोटा और नियंत्रण बासमती और चावल की उच्च गुणवत्ता के उत्पादन में वृद्धि के रास्ते में आया।
- इसके अलावा, स्थानीय और विदेशी बाजारों के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के उपभेदों की पहचान करने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी।

आगे का रास्ता

- एकमात्र तरीका यह है कि सामान्य चावल से बासमती और अन्य निर्यात योग्य किस्मों में उत्पादन को स्थानांतरित किया जाए और सूजी, रवा और नूडल्स के माध्यम से चावल को प्रतिस्थापित करने के लिए गेहूं को बढ़ावा दिया जाए।
- गेहूं की बेल्ट में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और दक्षिण भारत, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व में परिवहन को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना कृषि के स्वस्थ विकास के लिए अन्य विकल्प हैं।
- सरकार को संस्थागत लागत को कम करने और अधिक पारिश्रमिक फसल पैटर्न की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- केंद्र सरकार को उस एजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए जो चावल, गेहूं के साथ-साथ वैकल्पिक फसलों के साथ-साथ उनके बेहतर रूपांतरों की कीमतों के लिए भी स्थिर और पारिश्रमिक एमएसपी सुनिश्चित करेगी।
- सरकार को लगातार निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शी प्रयास करने चाहिए और भारतीय उपभोक्ता बाजार के लिए मूल्य नियंत्रण से निकलने वाली स्टॉप-गो नीति का पालन नहीं करना चाहिए।

लक्षद्वीप ने एक ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया (Lakshadweep Declared an Organic Union Territory)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -कृषि

समाचार में

- द्वीपों के संपूर्ण लक्षद्वीप समूह को भारत के भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत एक जैविक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
- लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना सभी की खेती की जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

लक्षद्वीप

- यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
- यह एक द्वीपसमूह है जिसमें 36 द्वीप हैं।
- द्वीपों के तीन मुख्य समूह हैं: (1) अमिंदी द्वीप; (2) लाकादिव द्वीपसमूह; (3) मिनिक्कॉय द्वीप।
- सभी प्रवाल मूल (एटोल) के छोटे द्वीप हैं और भित्तियों से घिरे हुए हैं।

भागीदारी की गारंटी प्रणाली

- पीजीएस जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो।
- प्रमाणन एक दस्तावेज लोगो या एक बयान के रूप में है।
- संचालन : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- यह केवल उन किसानों या समुदायों के लिए है जो एक गाँव या सन्निहित गाँवों के समूह के रूप में एक समूह के रूप में संगठित और प्रदर्शन कर सकते हैं।
- यह केवल कृषि गतिविधियों जैसे फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और पशुधन पालन, और अपने प्रत्यक्ष उत्पादों के पीजीएस किसानों द्वारा ऑफ-फार्म प्रसंस्करण पर लागू होता है।

क्या आप जानते हैं?

- जैविक खेती, सिंथेटिक बाहरी आदानों जैसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आदि के उपयोग के बिना कृषि उत्पादन का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए खेत डिजाइन और प्रबंधन की एक प्रणाली है।

किसान प्रोटेस्ट: असफल वार्ता (Farmer's Protest: Failed Negotiations)

संदर्भ:

- नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन बिना किसी संकेत के जारी रहा है।

किसान विरोध पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- प्रारंभ में, कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पंजाब के किसानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक की टिप्पणी है कि "लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, और अधिकारियों को उन्हें ऐसा करने देने की आवश्यकता है"।

किसानों की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं और सरकार इस पर कैसे बातचीत कर रही है?

1. एमएसपी के क्षरण का डर

- विरोध कर रहे किसान समूहों की मुख्य मांग एमएसपी के तंत्र की सुरक्षा है जिससे उन्हें डर है कि नए कृषि बिलों से वे कमजोर हो जाएंगे। वे एमएसपी पर कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं
- सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि कानून एमएसपी प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन किसानों को डर है कि इससे प्रभावी रूप से प्रचलित व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा, जो उन्हें सुरक्षा का एक माध्यम प्रदान करता है।
- **सरकारी प्रस्ताव:** केंद्र सरकार मौजूदा एमएसपी-आधारित खरीद प्रणाली के बारे में एक लिखित आश्वासन देने के लिए सहमत हुई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि लिखित आश्वासन एक संशोधन या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

2. व्यापार क्षेत्रों में कराधान

- वर्तमान में, पंजाब में सरकारी विनियमित मंडियों के माध्यम से धान और गेहूं की सभी खरीद वर्तमान में 3 प्रतिशत एपीएमसी बाजार शुल्क और 3 प्रतिशत ग्रामीण विकास उपकर को आकर्षित करती है। हरियाणा में, समान लेवी की राशि 2 प्रतिशत है।
- एफपीटीसी अधिनियम, 2020 की धारा 6, राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजार के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या व्यापार एकत्र करने से रोकती है
- किसान कहते रहे हैं कि इस तरह के शुल्क के अभाव से मंडियों के बाहर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, अंततः एपीएमसी मंडियों को महत्वहीन माना जाएगा।
- **सरकारी प्रस्ताव:** नए अधिनियम में संशोधन करके, यह प्रदान किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के पंजीकरण की प्रणाली को लागू कर सकती है। साथ ही, राज्य सरकार ऐसे व्यापारिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले उपकर / शुल्क की दर, मौजूदा एपीएमसी मंडियों पर लागू उपकर / शुल्क की दर तक निर्धारित कर सकती है।

3. अदालती प्रक्रिया

- नए फार्म अधिनियमों ने सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर एक बार लगा दिया और कहा कि विवादों को सुलह बोर्डों और अपीलीय अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए, जिन्हें स्थानीय उप-मंडल मजिस्ट्रेटों और जिला कलेक्टरों द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- **सरकारी प्रस्ताव:** यदि नए कृषि कानूनों के तहत कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो किसानों द्वारा दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है

4. अन्य मुद्दे

- किसान बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं; कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी; और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को $C2 + 50$ प्रतिशत फॉर्मूले के साथ MSP तय करने के लिए।
- केंद्र द्वारा किए गए अन्य आश्वासनों में एक नए वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश से संबंधित शिकायतों का समाधान शामिल है, जो कि जलने के मामले में कठोर दंड का आह्वान करता है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों द्वारा बिजली के उपयोग पर सब्सिडी पर मौजूदा व्यवस्था को संशोधित नहीं किया जाएगा।

क्या किसानों ने सरकारी प्रस्ताव स्वीकार किया है?

- विरोध करने वाले किसान समूहों ने संघ सरकार द्वारा की गई पेशकशों को खारिज कर दिया है और नए फार्म अधिनियमों को पूर्ण रूप से निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

एमएसपी - मिथक बनाम तथ्य (MSP — the factoids versus the facts)

संदर्भ:

- तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के पारित होने के बाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) - कानूनों में उल्लेख नहीं किया गया है - यह बहुत ध्यान देने योग्य है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

- एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से फसलों की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य है, जो भी फसलों के लिए बाजार मूल्य हो सकता है।
- एमएसपी का मतलब नीचे की सीमा तय करना है, जिससे कीमतें नहीं गिरती हैं, और सरकार द्वारा 23 वस्तुओं के लिए MSP की घोषणा की जाती है। यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से खरीदने का वादा करती है अगर बाजार की कीमतें इससे नीचे आती हैं।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर बुवाई के समय से पहले आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा MSP की घोषणा की जाती है
- समर्थन मूल्य आम तौर पर किसानों के फैसलों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, फसलों के लिए भूमि आवंटन, उत्पादित फसलों की मात्रा आदि के बारे में
- एमएसपी बाजार को एक स्पष्ट मूल्य संकेत प्रदान करने के अलावा किसानों को कृषि आय का आश्वासन देता है

- किसानों को संकट से उबारने और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद का प्रमुख उद्देश्य है।

क्या आपको पता है?

- यहां तक कि जिन वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, उनके लिए भी मंडी रेंज के माध्यम से बिक्री का अनुपात केवल 10-64% के बीच है
- एमएसपी की मांग उत्पन्न होती है क्योंकि मंडी के बाहर भुगतान की गई कीमतें बहुत कम होती हैं। देश भर में, मंडी या सरकारी खरीद एजेंसियों की बिक्री में औसतन 13.3% धान और गेहूं के लिए 5.8% अधिक दाम मिले।

एमएसपी और इसके खिलाफ तर्कों के बारे में कुछ गलत धारणाएं क्या हैं?

1. कुछ (6%) किसानों को फायदा होता है

- एक, एनएसएस डेटा 2012-13 से 6% का आंकड़ा अकेले धान और गेहूं से संबंधित है। हालांकि, यहां भी, धान / गेहूं बेचने वालों में, संख्या अधिक है - 14% और 16%

2. केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों (कुछ हद तक, पश्चिमी यूपी) को लाभ होता है।

- भारत सरकार ने विकेंद्रीकृत प्रोक्योरमेंट (DCP) योजना के माध्यम से MSP की पहुंच को अधिक से अधिक राज्यों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया है।
- इसे 1997-98 में पेश किया गया, यह प्रारंभिक वर्षों में बहुत लोकप्रिय नहीं था और 2005 तक केवल कुछ राज्यों द्वारा अपनाया जाने लगा।
- डीसीपी योजना के तहत, राज्य सरकारों को खरीदे जाने की जिम्मेदारी दी गयी, जो पूर्व अनुमोदित लागतों की प्रतिपूर्ति की गई थी।
- एफसीआई डेटा का सुझाव है कि जुलाई 2015 तक, 15 राज्यों ने इस कार्यक्रम को लिया था, हालांकि सभी इसे समान उत्साह के साथ लागू नहीं कर रहे थे।
- इसके कारण बड़े पैमाने पर, पारंपरिक राज्यों (जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) से खरीद शुरू हुई।
- 2000 तक, पारंपरिक राज्यों के बाहर मुश्किल से 10% गेहूं और चावल की खरीद की गई थी। 2012-13 तक, डीसीपी राज्यों का हिस्सा बढ़कर 25-35% हो गया।
- देश में कुल धान खरीद में छत्तीसगढ़ और ओडिशा का योगदान लगभग 10% है। गेहूं के लिए, विकेंद्रीकृत खरीद ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद का लगभग 20% हिस्सा लिया है।

3. केवल बड़े किसानों को लाभ

- खरीद ने मध्यम और बड़े किसानों की तुलना में छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी संख्या में लाभान्वित किया है।
- अखिल भारतीय स्तर पर, धान बेचने वालों में 1% बड़े किसान थे, जिनके पास 10 हेक्टेयर भूमि थी।
- छोटे और सीमांत किसानों, 2 हेक्टेयर से कम 70% के लिए जिम्मेदार है। बाकी (29%) मध्यम किसान (2-10 हेक्टेयर) थे।
- गेहूं के मामले में, सभी गेहूं बेचने वाले किसानों में से 3% बड़े किसान थे। आधे से अधिक (56%) छोटे और सीमांत किसान थे।

- मध्य प्रदेश में, सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने वालों में से लगभग आधे (45%) छोटे या सीमांत किसान हैं।

निष्कर्ष

तथ्यों को सही तरीके से प्राप्त करना कृषि क्षेत्र और किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनरावृत्ति करने के लिए, तथ्य इस प्रकार हैं:

- एक, सरकारी खरीद नीतियों से (यहां तक कि त्रुटिपूर्ण) लाभ उठाने वाले किसानों का अनुपात महत्वहीन नहीं है।
- दो, पिछले 15 वर्षों में खरीद का भूगोल बदल गया है। यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे पारंपरिक राज्यों में कम केंद्रित है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे डीसीपी राज्यों ने अधिक सख्ती से भाग लेना शुरू कर दिया है।
- तीन, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात - यह मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसान हैं जिन्हें एमएसपी और खरीद से लाभ हुआ है

100 वीं किसान रेल को हाल ही में खाना किया गया (100th Kisan Rail flagged off recently)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने 100 वीं किसान रेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो देवलाली और दानापुर के बीच चलेगी।
- अब इसे सांगोला से मुजफ्फरपुर के बीच चलाने के लिए बढ़ा दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- किसान रेल ट्रेन में अंगूर, संतरा, अनार, आदि जैसी सब्जियाँ और फल होते हैं।
- सभी रास्तों के ठहराव पर खराब होने वाली वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी और खेप का कोई न्यूनतम या अधिकतम आकार नहीं है।
- सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी को बढ़ा दिया है।
- मल्टी-कमोडिटी ट्रेन सेवा लोकप्रिय रही है क्योंकि इसमें छोटे, व्यक्तिगत किसानों द्वारा अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

प्रगति

- अब तक, किसान रेल नियमित रूप से 10 मार्गों पर चलती है।
- एक मार्ग - यशवंतपुर और दिल्ली के बीच - कुछ समय पहले अपनी मौसमी मांग को समाप्त किया।
- किसान रेल गाड़ियों ने अब तक लगभग 27,000 टन का उत्पादन किया है, और अब तक की गई यात्राओं में से आधी महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलने वाली गाड़ियों द्वारा की गई हैं।

पर्यावरण प्रदूषण (ENVIRONMENT/POLLUTION)

पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति (AIPA) का गठन (Apex Committee For Implementation Of Paris Agreement (AIPA) constituted)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सचिव, MoEFCC की अध्यक्षता में पेरिस समझौते (AIPA) के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रिस्तरीय सर्वोच्च समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जो भारत को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में सुनिश्चित करता है।
- चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी AIPA के सदस्य के रूप में काम करेंगे जो भारत के NDC के कार्यान्वयन में प्रगति की देखरेख करेंगे
- मुख्य कार्य:** (1) पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है; (2) अनुच्छेद 6 के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना; (3) कार्बन मूल्य निर्धारण, बाजार तंत्र, और अन्य समान उपकरणों पर दिशानिर्देश जारी करें जिनका जलवायु परिवर्तन और एनडीसी पर असर पड़ता है।

भारतीय मयूर सोफ्टशेल कछुए को बचाया गया (Indian Peacock Softshell Turtle rescued)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जैव विविधता

समाचार में

- भारतीय मोर सोफ्टशेल कछुए, एक कमजोर प्रजाति के कछुए को असम के सिलचर में एक मछली बाजार से बचाया गया था।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- भारतीय मोर सॉफशेल कछुए दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है।
- IUCN लाल सूची में स्थिति: संवेदनशील प्रजाति।
- भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में अनुसूची I प्रजाति
- यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक ही सीमित है।
- भारत में, यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य भागों में व्यापक है।
- ये नदियों, नदियों, झीलों और तालाबों में कीचड़ या रेत में पाए जाते हैं।
- **प्रमुख खतरे:** (1) अपने मांस और कैलीपी के लिए भारी शोषण; (2) मछली के स्टॉक में कमी, अतिवृष्टि, प्रदूषण, नदी के यातायात में वृद्धि, और रेत-खनन, आदि के कारण।

क्या आप जानते हैं?

- गुवाहाटी स्थित संरक्षण एनजीओ, हेल्प अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कछुओं की 29 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें से 20 असम में पाई जाती हैं।

2050 तक भारत में मलायन विशालकाय गिलहरी की संख्या 90% तक गिर सकती है: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (Malayan Giant Squirrel could decline by 90% in India by 2050: Zoological Survey of India -ZSI))

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जैव विविधता

समाचार में

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ZSI) के एक हालिया अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक भारत में मलायन विशालकाय गिलहरी (*Ratufa bicolor*) की संख्या 90% तक गिर सकती है।

- **मंत्रालय:** पर्यावरण मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- ZSI के अनुसार, इसके आवास को नष्ट करने से गिलहरी को केवल दक्षिणी सिक्किम और उत्तर बंगाल में 2050 तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- भारत में गिलहरी के मूल निवास का केवल 43.38% अब इसके अनुकूल है
- 2050 तक, अनुकूल क्षेत्र उस क्षेत्र का 2.94% तक सिकुड़ सकता था, जो इस प्रजाति के निवासियों के लिए था।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- मलायन विशालकाय गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है।
- इसका एक गहरा ऊपरी शरीर है, भागों के नीचे पीला, और एक लंबी, झाड़ीदार पूंछ है।
- **आईयूसीएन स्थिति:** संकटग्रस्त
- यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है।
- भारत में पाया गया: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और नागालैंड।
- **अन्य देश:** दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायन प्रायद्वीप, सुमात्रा, और जावा।
- यह ज्यादातर सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वनों में पाया जाता है, जो मैदानी इलाकों से लेकर समुद्र तल से 50 मीटर से 1,500 मीटर की ऊँचाई पर है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में तीन विशाल गिलहरी प्रजातियों का आवास है।

- अन्य दो - भारतीय विशालकाय गिलहरी और घड़ियाल विशालकाय गिलहरी - प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं।
- निशाचर फ्लाईंग गिलहरी के विपरीत, विशाल गिलहरी डायनरल है, लेकिन आर्बरियल (पेड़-आवास) और उड़ने वाली गिलहरी की तरह शाकाहारी है।

समाचारों में प्रजाति: हाउबारा बस्टर्ड्स (Species in news: Houbara Bustards)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जैव विविधता

समाचार में

- हाल ही में, हाउबारा बस्टर्ड्स समाचार में था।
- पाकिस्तान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शाही परिवार के दो अन्य सदस्यों को शिकार सीजन 2020-21 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित हाउबारा बस्टर्ड्स का शिकार करने के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

हाउबारा बस्टर्ड्स

- यह शुष्क जलवायु में निवास करता है।
- यह दो अलग-अलग प्रजातियों में आता है जैसा कि IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- एक प्रजाति उत्तरी अफ्रीका (क्लैमाइडोटिस अंडुलाटा) में रहती है और दूसरी एशिया (क्लैमाइडोटिस मैक्केनीनी) में है जिसे आमतौर पर मैक्क्वीन के बस्टर्ड के रूप में जाना जाता है।
- एशियाई हाउबारा बस्टर्ड की आबादी मध्य पूर्व, पूरे मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अरब प्रायद्वीप से लेकर सिनाई रेगिस्तान तक फैली हुई है।
- अंतराष्ट्रीय फंड फॉर हाउबारा कंजर्वेशन (IFHC) के अनुसार, आज लगभग 33,000 एशियाई हाउबारा बस्टर्ड हैं।
- वसंत में प्रजनन के बाद, एशियाई बस्टर्ड दक्षिण में पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप और निकटवर्ती पश्चिमी एशिया में सर्दियों का खर्च करने के लिए पलायन करते हैं।
- कुछ एशियाई हाउबारा ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों सहित दक्षिणी सीमा में रहते हैं और प्रजनन करते हैं।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति: संवेदनशील



उत्तराखंड में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए पहला इको-ब्रिज (First eco-bridge for reptiles and smaller mammals in Uttarakhand)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III -पर्यावरण

समाचार में

- उत्तराखंड, ने हाल ही में नैनीताल जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको-ब्रिज बनाया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- इको-डक्ट्स या ईको-पुल का उद्देश्य वन्यजीव कनेक्टिविटी को बढ़ाना है जो राजमार्गों या लॉगिंग के कारण बाधित हो सकते हैं।
- इको-पुलों में शामिल हैं: (1) कैनोपी पुल आमतौर पर बंदरों, गिलहरियों और अन्य जंगली प्रजातियों के लिए); (2) आमतौर पर बड़े जानवरों के लिए कंक्रीट के अंडरपास या सुरंगों या पुल को पार करना; (3) उभयचर सुरंग या पुलिया।
- आमतौर पर इन पुलों को क्षेत्र के साथ रोपण के साथ ओवरलैड किया जाता है ताकि यह परिदृश्य के साथ एक सन्निहित रूप दे सके।

संबंधित लेख:

- इको-ब्रिज का महत्व: [Click here](#)

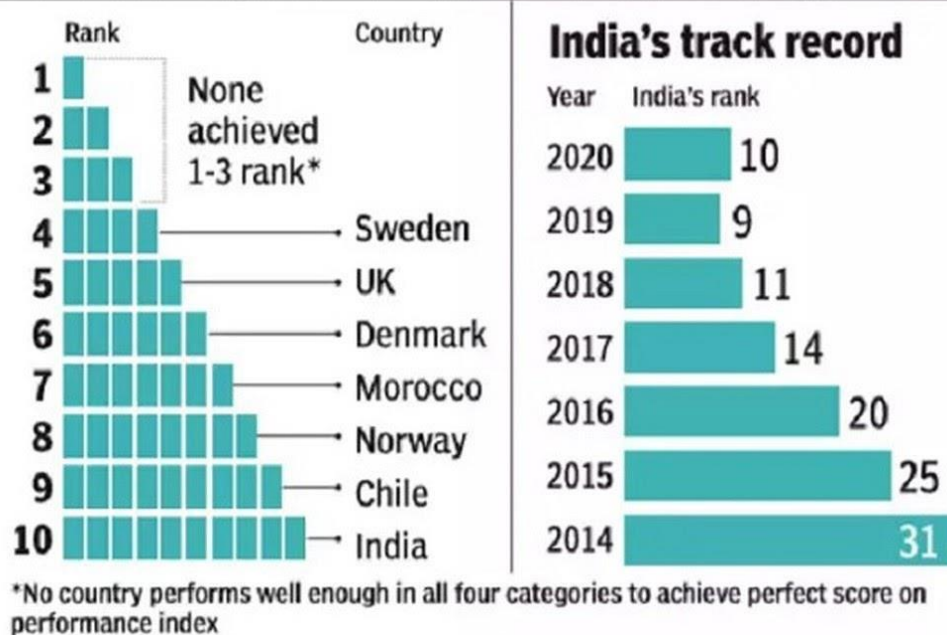
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में भारत शीर्ष 10 में (India in top 10 in Climate Change Performance Index -CCPI)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- जर्मनी में जारी नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है।

Climate Change Performance Index (CCPI) Ranking 2020



महत्वपूर्ण तथ्य

- चीन जो 33 वें रैंक पर ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के आंकड़ों का सबसे बड़ा वर्तमान उत्सर्जक है।
- जबकि यूएसए सूची में सबसे नीचे दिखाई देता है।
- हालांकि भारत इस वर्ष 2019 में 9 वें से 10 वें स्थान पर एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन जलवायु संरक्षण की दिशा में यह यात्रा 2014 में 31 वें स्थान से अपनी रैंकिंग में सुधार के साथ संगत रही है।
- विश्व स्तर पर CCPI की वार्षिक रिपोर्ट के लिए मूल्यांकन किए गए देशों में से कोई भी सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की अपनी पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए रास्ते पर नहीं है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित कर दिया है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल दो जी 20 देश - यूके और भारत - उच्च रैंक वाले हैं।

- जबकि छह अन्य G20 देश - संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस (52 वें) - सूचकांक में सबसे नीचे हैं।

क्या आप जानते हैं?

- CCPI को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN इंटरनेशनल) के साथ नॉट-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट (जर्मनी) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह विभिन्न देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाता है।
- चार देशों में 57 देशों और यूरोपीय संघ (एक पूरे के रूप में) के प्रदर्शन का आकलन करके नवीनतम सूची तैयार की गई है - जीएचजी उत्सर्जन (40%), नवीकरणीय ऊर्जा (20%), ऊर्जा का उपयोग (20%) और जलवायु नीति (20%)) है।
- ये 57 देश और EU सामूहिक रूप से लगभग 90% वैश्विक GHG उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

संबंधित लेख:

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में अधिक जानकारी: [Click here](#)

गोवा में वैज्ञानिकों द्वारा स्पॉट की गई भारतीय मुरिग्रास की नई प्रजातियां (New species of Indian Muraingrasses spotted by scientists in Goa)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- पश्चिमी घाट में गोवा में वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय मुरिग्रास (मुरैन घास) (जीनस इस्चामुम) की एक नई प्रजाति को देखा गया है।
- यह उनके पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है, जैसे कि चारा।



महत्वपूर्ण तथ्य

- खोजी गई प्रजाति का नाम गोवा के पश्चिमी घाट के पठारों से इस्चामुमजनार्थनमी रखा गया था।
- इसका नाम गोवा विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और भारतीय विविधता में योगदान के लिए गोवा विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर प्रो।\ एम.के. जनार्थनम के सम्मान में रखा गया था।
- यह भगवान महावीर नेशनल पार्क, गोवा के बाहरी इलाके में कम ऊंचाई वाले लेटिटिस पठारों पर उगता है।
- प्रजातियों ने कठोर परिस्थितियों, कम पोषक तत्वों की उपलब्धता, और हर मानसून को खिलने के लिए जीवित रहने के लिए अनुकूलित है।

क्या आप जानते हैं?

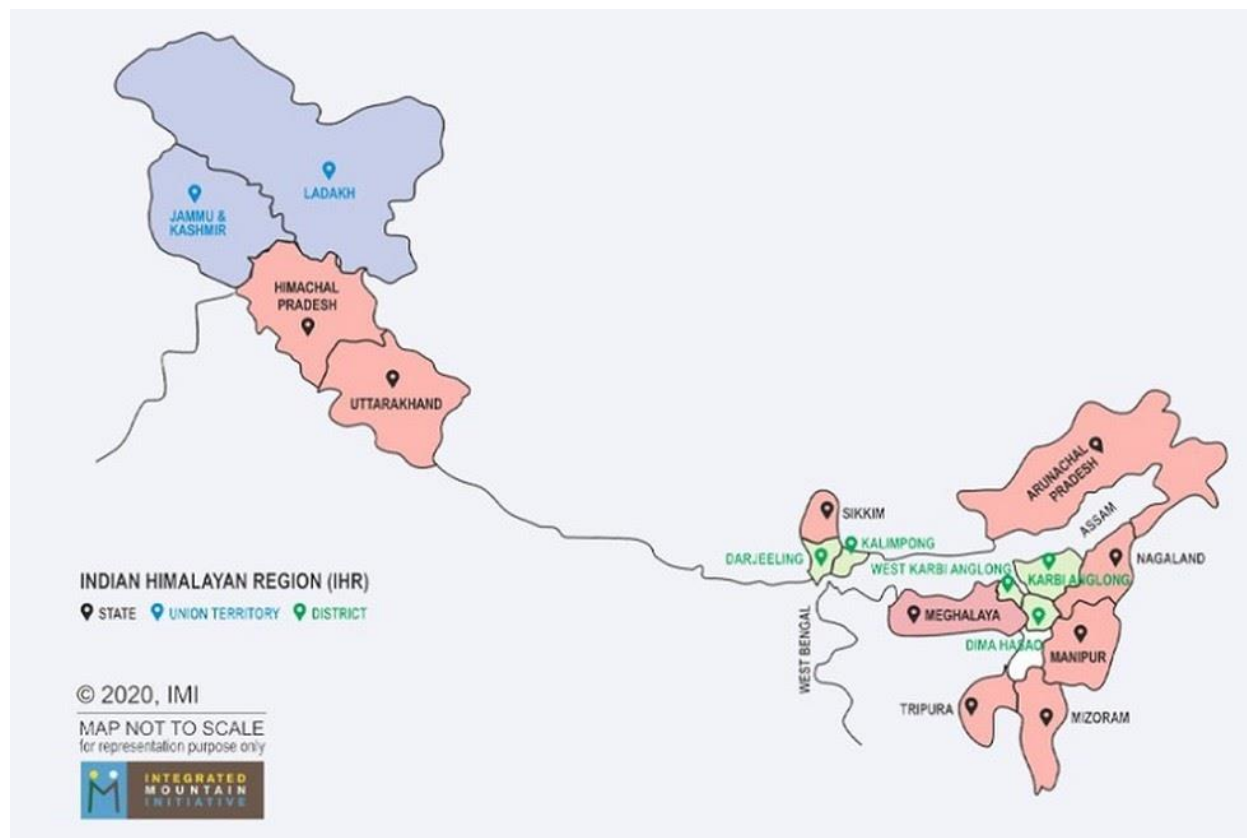
- विश्व स्तर पर 85 प्रजातियाँ इस्चामुम से जानी जाती हैं, जिनमें से 61 प्रजातियाँ विशेष रूप से भारत में पाई जाती हैं।
- पश्चिमी घाट में जीनस की उच्चतम सांद्रता वाली 40 प्रजातियाँ हैं।

सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन (SMDS) शुरू हुआ (Sustainable Mountain Development Summit (SMDS) begins)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- देहरादून में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट (SMDS) का 9 वां संस्करण शुरू हो गया है।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- भारतीय पर्वतीय पहल (IMI) द्वारा आयोजित किया गया
- शिखर सम्मेलन में प्रवासन, जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और कृषि क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान और भारतीय हिमालय में आपदा जोखिम में कमी जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहता है।
- हर साल पहाड़ों और पहाड़ियों के लिए प्रासंगिक और प्रासंगिक ध्यान देने वाले 3-5 सामयिक विषयों को सूत्र चर्चा और बहस के लिए लिया जाता है।
- **2020 का विषय:** Emerging Pathways for Building a Resilient Post COVID-19 Mountain Economy, Adaptation, Innovation and Acceleration.
- इसका पहला संस्करण 2011 में नैनीताल में आयोजित किया गया था।

एकीकृत पर्वतीय पहल (IMI)

- यह एक नागरिक समाज के नेतृत्व वाला नेटवर्क प्लेटफॉर्म है।
- **मिशन:** भारत के विकास संवाद में भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) और इसके लोगों की मुख्यधारा की चिंताओं के लिए।

- यह IHR में काम करने वाले कई हितधारकों के ज्ञान और अनुभवों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, और इसका उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति को सूचित करने और प्रभावित करने के लिए करता है।

जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020 आभासी रूप से आयोजित किया गया (Climate Ambition Summit 2020 held virtually)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 की सह-मेजबानी की जो कि हाल ही में आयोजित की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को अपनाने के पांच वर्षों को चिह्नित किया।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं बनाने के लिए नेताओं को एक साथ लाना है।
- यूनाइटेड किंगडम ने अगले पांच वर्षों में अपने जलवायु वित्त योगदान को 15.5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का वादा किया।
- यूरोपीय निवेश बैंक ने 2025 तक जलवायु और पर्यावरण क्षेत्रों की ओर जाने वाले 50% निवेश के लक्ष्य की घोषणा की।
- इसने सबसे कमजोर और महत्वाकांक्षी अनुकूलन योजनाओं और अंतर्निहित नीतियों का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं का भी आह्वान किया।
- भारतीय प्रधान मंत्री के अनुसार, भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, बल्कि उन्हें अपेक्षाओं से परे है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने 2005 के स्तर पर उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की कमी की है।
- सौर क्षमता 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 36 गीगावाट हो गई है।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है।
- यह 2022 से पहले 175 गीगावाट तक पहुंच जाएगा।
- भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का नया लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
- विश्व मंच पर, भारत ने दो प्रमुख पहल की हैं: (1) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन; (2) आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन।

पेरिस जलवायु सौदा: भारत की प्रगति, महामारी और चुनौतियां Paris Climate Deal: India's Progress, Pandemic and Challenges

संदर्भ: वर्चुअल क्लाइमेट एंबिशन समिट, यूएन द्वारा पेरिस समझौते के पांच वर्षों को चिह्नित करने के लिए बुलाई गई थी।

पेरिस समझौता क्या है?

- **उद्देश्य:** यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के भीतर एक बहुपक्षीय समझौता है; जिसमें ग्रीनहाउस-गैस-उत्सर्जन को कम करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
- **तापमान लक्ष्य:** वैश्विक तापमान को सीमित करके ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए इस सदी को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे अच्छी तरह से बढ़ाएं और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएं।
- **उत्सर्जन लक्ष्य:** इस समझौते में एक और महत्वपूर्ण बिंदु 2050 और 2100 के बीच "शुद्ध शून्य उत्सर्जन" प्राप्त करना था। राष्ट्रों ने "इस सदी के उत्तरार्ध में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत और मानवजनित उत्सर्जन के बीच संतुलन हासिल करने का संकल्प लिया है"।
- **बर्डन शेयरिंग:** विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन उपायों के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए भी कहा गया था। अन्य देशों को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- **गैर-बाध्यकारी स्वैच्छिक लक्ष्य:** पेरिस समझौते के लिए आवश्यक है कि सभी देश - अमीर, गरीब, विकसित और विकासशील - स्लेब ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करें। राष्ट्रों ने स्वेच्छा से अपने उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए और अपने लक्ष्यों को कम करने के लिए कोई दंड नहीं दिया।
- **समीक्षा तंत्र:** 2025 में पहली अनिवार्य विश्व समीक्षा के साथ हर पांच साल में एक समीक्षा। प्रत्येक समीक्षा में पिछली अवधि की तुलना में सुधार दिखाएगा।
- **जलवायु से संबंधित नुकसान:** समझौते में सूखे, बाढ़ आदि जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण कम विकसित राष्ट्रों द्वारा सामना किए गए वित्तीय घाटे को संबोधित करने के लिए एक तंत्र भी शामिल है। हालांकि, विकसित राष्ट्रों को वित्तीय दावों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं हैं या वह इसे प्रदान नहीं करते हैं। यह किसी भी दायित्व या मुआवजे के लिए एक आधार है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) क्या है?

- इसका अर्थ है कि समग्र वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा किए जाने वाले योगदान।
- योगदान को हर 5 साल में UNFCCC को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
- योगदान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
- लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों को जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता तक पहुंच हो।

पेरिस जलवायु क्योटो प्रोटोकॉल से कैसे भिन्न है?

- क्योटो प्रोटोकॉल में, विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर था, जिन्हें क्रमशः एनेक्स 1 देशों और गैर-एनेक्स देशों के रूप में उल्लेख किया गया था।
- हालांकि, पेरिस समझौते में, विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई अंतर नहीं है।

पेरिस 2015 समझौते के दौरान वित्तीय सहायता की प्रतिज्ञा

- विकसित देशों ने एक वर्ष में 100 बिलियन \$ देने के लिए कहा था।
- वित्त शमन और अनुकूलन के बीच संतुलित स्थापित होगा।
- G7 देशों ने जलवायु जोखिम बीमा के लिए 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जलवायु जोखिम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (सीआरआरडब्ल्यूएस) पहल शुरू करने की घोषणा की।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 3 बिलियन \$ की प्रतिबद्धता।

भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, भारत के GHG उत्सर्जन का कुल वैश्विक वैश्विक स्तर पर 2014 में 6.5% के लिए जिम्मेदार है। इसने देश को चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना दिया।

- प्रति व्यक्ति, जीवाश्म ईंधन से भारत का उत्सर्जन (2017 में) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है:
 - भारत: 1.83 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
 - चीन: 7.72 मीट्रिक टन
 - ईयू: 6.97 मीट्रिक टन
 - यूएस: 15.74 मीट्रिक टन

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं क्या हैं?

2015 में, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन से पहले, भारत ने तीन प्रमुख स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं की घोषणा की जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions-NDC) कहा जाता है:

1. 2005 के स्तर पर 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35% की वृद्धि
2. 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी 40% तक बढ़ाना।
3. इसके वन आवरण को बढ़ाता है, जिससे 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है

अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत की प्रगति

- भारत ने 2005 के स्तर पर उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की कमी की है।
- सौर क्षमता 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 36 गीगावाट हो गई है।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है और 2022 से पहले 175 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।

- भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का नया लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
- विश्व मंच पर, भारत ने दो प्रमुख पहल की हैं: (1) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन; (2) आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन।
- यूएनईपी की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 में भारत के 9 G 20 सदस्य शामिल हैं, जो पूर्व-COVID -19 अनुमानों के आधार पर पेरिस समझौते के तहत अपनी बिना शर्त प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर हैं।
- क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वेबसाइट ने अपने जलवायु प्रयासों को "2-डिग्री संगत" के रूप में मूल्यांकित किया है - जो सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को सीमित करने में योगदान कर सकता है;

COVID-19 महामारी ने जलवायु प्रतिबद्धताओं को कैसे प्रभावित किया है?

- महामारी द्वारा उत्पन्न वैश्विक GHG उत्सर्जन में संक्षिप्त कमी ने सभी देशों को अपने विकास के अनुमानों की समीक्षा करने का अवसर दिया है।
- अभूतपूर्व घटना ने उन्हें अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्वास के लिए एक असाधारण राजकोषीय प्रोत्साहन तैनात करने में सक्षम बनाया है - विश्व स्तर पर 12 ट्रिलियन \$ का अनुमान है - जिससे हरित विकास की संभावना है।
- भारत को एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अपने भू-भाग के पुनर्वास को पार करने के लिए पारंपरिक क्षेत्र की नीतियों से दूर जा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग के साथ हरित क्षेत्र में संयोजित है।

भारत के लिए आगे के रास्ते की चुनौती

वनीकरण और कार्बन सिंक के साथ मुद्दे

- हाल ही के शिखर सम्मेलन में, श्री मोदी ने जंगलों के विस्तार का श्रेय लिया, जो कि पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के अनुसार, 2030 तक समतुल्य 2.5 bn से 3 bn टन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा।
- यह एक प्रमुख लक्ष्य है, यह देखते हुए कि इसके कई लाभ हैं, जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, जलवायु प्रणाली को प्रभावित करना और समुदायों के लिए संसाधन प्रदान करना।
- लेकिन यह अनिश्चितता से भरा है। केंद्र ने राज्य वनीकरण आंकड़ों की सत्यता पर सवाल उठाया है और कहा कि उनके द्वारा किए गए दावों में से केवल एक चौथाई को विश्वसनीय माना गया है।
- स्पष्ट रूप से, सत्यापन योग्य वनीकरण पर एक सामंजस्यपूर्ण नीति के बिना, कार्बन सिंक दृष्टिकोण खराब लाभांश का उत्पादन कर सकता है, जिसमें खर्च पर सवाल खड़े होते हैं।

निष्कर्ष

- 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देशों के मिलने से पहले भारत को भविष्य के उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने और वैश्विक जलवायु वित्त पोषण के लिए योग्य हरित निवेश की योजना बनाने की आवश्यकता है।

Connecting the dots

- पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिकी वापसी : Click [here](#)

भारत जल प्रभाव 2020 (India Water Impact 2020)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में आयोजित भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन में देश-विदेश के कई विशेषज्ञों ने संरक्षण और विकास के विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत जल प्रभाव 2020 एक पाँच दिवसीय शिखर सम्मेलन है।
- दुनिया भर के विशेषज्ञ और शिक्षाविद शिखर सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, जल सुरक्षा और नदी के कायाकल्प से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस करते हैं।
- यह आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा सह-आयोजित किया गया है।
- घटना के दौरान, नार्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए cGanga (थिंक-टैंक ऑफ़ NMCG) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

12 वीं GRIHA (एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग) शिखर सम्मेलन (12th GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) Summit)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में 12 वें GRIHA (एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- **आयोजन:** हैदराबाद से GRIHA परिषद में।
- **विषय:** कायाकल्प करने वाले लचीले आवास।
- **उद्देश्य:** नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में सेवा करना जो पूरे समुदाय के लाभ के लिए स्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करेगा।
- उपराष्ट्रपति ने इस आयोजन के दौरान 'शाश्वत' नामक एक पत्रिका और '30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स' नामक पुस्तक का विमोचन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन के 39% के लिए इमारतों और निर्माण उत्तरदायी है।
- भारत ने निर्मित पर्यावरण के कुल डी-कार्बनकरण की प्रक्रिया को तेज करने का आह्वान किया।
- यह भी कहा गया था कि छत का ठंडा होना सभी के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए।
- भारत में, 60% से अधिक छतों को धातु, अभ्रक और कंक्रीट से बनाया जाता है - इस प्रकार इमारतों के अंदर ऊष्मा अवशोषित हो जाती है और शहरी क्षेत्रों में द्वीप प्रभाव को गर्म करने में योगदान होता है।
- पारंपरिक छतों की तुलना में ठंडी छतों में इनडोर तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है।
- यह भी देखा गया कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (ECBC) का कार्यान्वयन पूरे भारत में एक समान नहीं किया गया है।
- इस संबंध में नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सराहना की गई।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

एकीकृत आवास आकलन (GRIHA) के लिए ग्रीन रेटिंग

- यह किसी भी पूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है।
- GRIHA को भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कि भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (INDC) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को प्रस्तुत की गई है।
- **निर्मित:** द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा इसकी कल्पना की गई थी और इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
- GRIHA काउंसिल ने बिल्डिंग फिटनेस इंडेक्स्टर (BFI) उपकरण विकसित किया है - एक निःशुल्क उपयोग में स्व-मूल्यांकन उपकरण है जो संगठनों को COVID -19 के संपर्क को रोकने के लिए कार्यस्थलों की तैयारियों को मापने की अनुमति देता है।

दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए चार-सूत्रीय कार्य योजना (A four-point action plan to improve Delhi's air)

संदर्भ:

दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन करने का नेतृत्व किया है।

हर साल, जैसा कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक अनुपात तक पहुंचती है, स्थिति को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय किए जाते हैं। हालांकि, दीर्घकालिक रणनीति की अनुपस्थिति में, यह समस्या हर सर्दियों में प्रकट हो जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खराब हवा के कारण

- पड़ोसी राज्यों में स्टब-बर्निंग

- निर्माण के कारण उत्पन्न धूल
- औद्योगिक प्रदूषण
- गरीबों की ऊष्मा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीयकृत अलाव
- मोटर वाहनों से उत्सर्जन (सड़क पर वाहनों के निकास के उत्सर्जन में नौ प्रतिशत से वायुमंडल में कण पदार्थ (PM2.5) का 38%

परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करने की एक स्थायी योजना के लिए एक व्यापक और बहु-वर्षीय प्रयास की आवश्यकता है। यह चार-आयामी दृष्टिकोण मदद कर सकता है।

1. स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग
2. साइकल और गैर-मोटर चालित परिवहन को अपनाना।
3. यातायात प्रवाह में सुधार
4. यात्रा मांग को कम करना

निष्कर्ष

- वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए ये कार्य एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, समय की आवश्यकता क्षेत्रों में केंद्रित, व्यापक, व्यवस्थित और बहु-वर्षीय प्रयास है।
- आज, दिल्ली एक लंबी अवधि की दृष्टि के साथ एक वैज्ञानिक योजना विकसित करने के लिए आयोग की ओर देख रहा है, इसे लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित और सशक्त होना चाहिए। इससे उम्मीद की झलक मिलती है कि लोग भविष्य के सर्दियों के मौसम में आसानी से सांस ले सकते हैं।

सेंटिनल द्वीप का कोई भी दोहन आदिवासियों का विनाश कर देगा: एनएसआई (Any exploitation of Sentinel Island will wipe out tribals: AnSI)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - नीतियां और हस्तक्षेप और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एनएसआई) के नीति दस्तावेज ने वाणिज्यिक गतिविधि से संकटग्रस्त समूह के लिए खतरे की चेतावनी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एनएसआई के अनुसार, वाणिज्यिक और रणनीतिक लाभ के लिए अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप के किसी भी दोहन को इस पर रहने वालों के लिए खतरनाक होगा।
- यह भी कहा गया है कि द्वीप के लोगों का अधिकार गैर-परक्राम्य, अप्राप्य है।

- राज्य का मुख्य कर्तव्य इनके अधिकारों की रक्षा करना है।
- उनके द्वीप को किसी भी वाणिज्यिक या रणनीतिक लाभ के लिए नहीं देखा जाना चाहिए।
- दस्तावेज़ भी सेंटिनल द्वीप पर एक ज्ञान बैंक के निर्माण के लिए कहता है।
- चूँकि आदिवासी समुदाय के लिए तात्कालिक अध्ययन संभव नहीं है, मानवविज्ञानी दूरी से एक संस्कृति के अध्ययन का सुझाव देते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- यह सबसे निर्जन, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) है, जो अंडमान पर पूर्ण अलगाव में रहते हैं।
- उत्तरी प्रहरी द्वीप पर इसकी आबादी लगभग 50 से 100 है।
- यह न केवल देश भर में लगभग 70 PVTGs में सबसे अलग-थलग हैं, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पांच में भी शामिल हैं, जिसमें ग्रेट अंडमान, ओंगे, जारवा और शोमपेन्स शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- हालांकि सेंटिनल द्वीप और ग्रेट अंडमानी दोनों को PVGT के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह दोनों जनजातियां पूरी तरह से अलग संपर्क की स्थिति में रहती हैं।
- जबकि सेंटिनल द्वीप के मामले में बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग शून्य है, ग्रेट अंडमानी के पास अपने द्वीप के बाहर की दुनिया के लिए दशकों से संपर्क था।

उष्णकटिबंधीय मोंटेन ग्रासलैंड (TMG) में पहचाने जाने वाले घास के मैदान की बहाली और संरक्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्र (Areas suitable for grassland restoration and conservation identified in Tropical Montane Grasslands -TMG)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीप में उष्णकटिबंधीय मोंटेन घास के मैदान (टीएमजी) में विदेशी पेड़ों के आक्रमण के कारण तेजी से क्षरण हुआ है।
- हालांकि, शोधकर्ताओं ने अब गिरावट को दूर करने के लिए चारागाह बहाली और संरक्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उष्णकटिबंधीय मोंटेन घास के मैदान (Tropical montane grasslands -TMG) उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान(High Elevation Grasslands) हैं जो दुनिया के सभी घास के मैदानों का केवल 2% हैं।

- उष्णकटिबंधीय मॉन्टाने घास के मैदान वैश्विक कार्बन चक्र(Global Carbon Cycle) को विनियमित करते हैं और डाउनस्ट्रीम समुदायों(Downstream Communities) को पानी के स्रोत के रूप में सेवा देते हैं।
- पिछले 44 वर्षों की अवधि में पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय मॉन्टाने घास के मैदानों का विदेशी वृक्षों के कारण लगभग 23% क्षरण हुआ है।
- भारत में, उष्णकटिबंधीय मॉन्टाने घास के मैदानों को वन प्रबंधन योजनाओं(forest management plans) में बंजर भूमि(wastelands) के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वे राजस्व उत्पन्न करने की संभावना नहीं रखते हैं। हालाँकि शोधकर्ताओं का कहना है कि सरकार को अपनी इस रणनीति को बदलना चाहिए।
- उष्णकटिबंधीय मॉन्टाने घास के मैदानों को पश्चिमी घाट के नीलगिरी, पलानी हिल्स और अन्नामलाई आदि क्षेत्रों में काफी अधिक नुकसान हुआ है। जहाँ इनके संरक्षण की अति आवश्यकता है।

क्या आप जानते हैं?

- पश्चिमी घाट में, 44% की अवधि में 23% मॉन्टेन घास के मैदानों को कथित रूप से आक्रामक विदेशी पेड़ के रूप में बदल दिया गया है।

गैस्ट्रोडिया एगनिकेलस को दुनिया का सबसे बदसूरत आर्किड कहा जाता है (Gastrodia Agnicellus named as the ugliest orchid in the world)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जैव विविधता

समाचार में

- गैस्ट्रोडिया एगनिकेलस, एक नए खोजे गए आर्किड को "दुनिया का सबसे बदसूरत आर्किड" नाम दिया गया है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- यह मेडागास्कर के एक जंगल में पाया गया था।
- यह कवक से भोजन प्राप्त करता है।
- इस पर कोई पत्ती नहीं होती है।
- हालांकि इसको एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में मूल्यांकन किया गया है, पौधों को कुछ सुरक्षा है क्योंकि वे एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं।

क्या आप जानते हैं?

- मेडागास्कर हिंद महासागर में एक द्वीप देश है, जो पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है।
- मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।

बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Centre For Monkeys)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- तेलंगाना के निर्मल जिले के चिंचोली गांव के पास गांधी रमन्ना हरितावनम में 'बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र' का उद्घाटन किया गया। यह राज्य का पहला ऐसा केंद्र है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- मानव बस्तियों में प्रवेश करने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा और पुनर्वसन केंद्र में लाया जाएगा।
- पुनर्वसन केंद्र में उनका गर्भ-निरोधी ऑपरेशन किया जाएगा और पुनर्वसन अवधि के बाद जंगलों में छोड़ दिया जाएगा।
- पुनर्वसन केंद्र को प्राइमेट्स के लिए एक स्थायी निवास स्थान बनाने के लिए, कई फल और फूलों की विविधता वाले पौधों एवं पेड़ों की किस्में उगायी जाएंगी।
- बंदरों के लिए यह पुनर्वसन केंद्र दक्षिण भारत की भी पहली ऐसी सुविधा है।
- यह देश में प्राइमेट के लिए दूसरी ऐसी सुविधा है। देश में इस तरह की दूसरी सुविधा हिमाचल प्रदेश में थी।

JSA II: कैच द रेन” अवेयरनेस जनरेशन अभियान प्रारंभ (JSA II: Catch The Rain Awareness Generation Campaign)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- राष्ट्रीय जल मिशन (NWM), जल शक्ति मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से, 'जल शक्ति अभियान II: कैच द रेन' जागरूकता अभियान की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नेहरू युवा केंद्र संगठन देश के 623 जिलों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के मध्य तक 'कैच द रेन' जागरूकता अभियान के इस चरण को चलाएगा।
- राष्ट्रीय जल मिशन ने एक अभियान 'कैच द रेन' शुरू किया है, जिसकी टैग लाइन है- 'बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो' (catch the rain, where it falls, when it falls)।
- इसका उद्देश्य सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल और मानसून के चार/ पांच महीनों में होने वाली वर्षा के रूप में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य

- व्यापक जल डाटाबेस को सार्वजनिक करना तथा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना;
- जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्यवाई को बढ़ावा देना;
- अधिक जल दोहित क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना;
- जल उपयोग कुशलता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना;
- बेसिन स्तर तथा समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- जमीन के ऊपर और नीचे भंडारण बढ़ाएं, वर्षा जल संचयन को लागू करें।
- बड़े पैमाने पर सिंचाई कार्यक्रमों को अपनाना जो स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और रिज और फरो सिंचाई पर निर्भर करते हैं।

भारत में 75% जिले चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं (75% districts in India hotspots of extreme climate events)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन

समाचार में

- काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 75 प्रतिशत से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी चरम जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉटस्पॉट हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पहली बार है जब देश में चरम मौसम की घटना वाले स्थानों पर मैप किया गया है।
- इन चरम घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशितता हाल के दशकों में बढ़ी है।
- जबकि भारत ने 1970 और 2005 के बीच 35 वर्षों में 250 चरम जलवायु घटनाओं को देखा, तब से केवल 15 वर्षों में इस तरह के 310 घटनाओं को दर्ज किया गया है।
- पिछले 50 वर्षों में, बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति लगभग आठ गुना बढ़ गई।
- बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, गरज और बादल फटने जैसी घटनाओं से जुड़ी घटनाओं में 20 गुना से अधिक की वृद्धि हुई।
- पिछले दशक में भारत के आठ सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित जिले- बारपेटा, दारंग, धेमाजी, गोलपारा, गोलाघाट, शिवसागर- असम में हैं।
- 2005 के बाद सूखा प्रभावित जिलों का वार्षिक औसत 13 गुना बढ़ गया। लगभग 68% जिलों में सूखे और सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है।
- पिछले दशक में भारत के सूखा प्रभावित जिले में अहमदनगर, औरंगाबाद (दोनों महाराष्ट्र), अनंतपुर, चित्तूर (दोनों आंध्र प्रदेश), बागलकोट, बीजापुर, चिक्काबल्लापुर, गुलबर्गा, और हासन (सभी कर्नाटक) थे।
- अध्ययन में 40% से अधिक भारतीय जिलों में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों जैसे कि सूखा-प्रवण और इसके विपरीत होने के रूप में चरम जलवायु घटनाओं के पैटर्न में बदलाव पाया गया।

क्या आप जानते हैं?

माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन शिफ्टिंग

- माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन का आशय ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ का मौसम आस-पास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। भारत के अलग-अलग ज़िलों में माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
- माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन में बदलाव के कारण संपूर्ण क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो सकता है। वार्षिक औसत तापमान में मात्र 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के कारण कृषि उत्पादकता में 15-20 प्रतिशत की कमी आ सकती है।
- कारण: इसके कारणों में भूमि उपयोग में बदलाव, निर्वनीकरण, अतिक्रमण के कारण आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को होने वाला नुकसान और अर्बन हीट लैंड आदि शामिल हैं।

त्सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42 वां रामसर साइट बन गया (Tso Kar Wetland Complex becomes India's 42nd Ramsar site)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- भारत ने लद्दाख के त्सो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है।
- यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा ऐसा स्थल है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- त्सो कर बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि परिसर है।
- इसमें दो मुख्य जलप्रपात, स्टार्टअपसुक त्सो, मीठे पानी की झील और त्सो कर स्वयं लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित एक हाइपरसैलिन झील है।

- इसे टोस कार कहा जाता है, जिसका अर्थ है सफेद झील, क्योंकि अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण हाशिये पर पाए जाने वाले सफेद नमक का प्रवाह।
- त्सो कर बेसिन वर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार एक ए 1 श्रेणी का महत्वपूर्ण वर्ड एरिया (आईबीए) और मध्य एशियाई फ्लाइवे में एक महत्वपूर्ण मंचन स्थल है।
- यह साइट भारत में ब्लैक-नेकड क्रेन (ग्रस नाइग्रीकोलिस) के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है।
- यह आईबीए ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे (पॉडिसीसेक्रिस्टेटस), बार-हेडेड गीज (अनसेरिंडिकस), रूडी शेल्डक (टडोर्नफ्रेग्यूनिआ), ब्राउन-हेडेड गाल (लार्सब्रोननिसेफालस), लेसर सैंड-प्लोवर (चारेडियमसोंग) के लिए प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है।
- त्सो कर घाटी एक अत्यधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहां दो प्रमुख जलप्रपात हैं जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत मीठे पानी की झील स्टारत्सपुक त्सो और उत्तर में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत खारे पानी की झील त्सो कर खुद स्थित है।
- इसे त्सो कर कहा जाता है जिसका अर्थ है सफेद नमक। इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर सफेद नमक की पपड़ी पाई जाती है।
- वर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार त्सो कर घाटी ए1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) और यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
- यह स्थान भारत में काले गर्दन वाली सारस पक्षी (ग्रस नाइग्रीकोलिस) का एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। यह आईबीए ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे (पॉडिसीसेक्रिस्टेटस), बार-हेडेड गीज यानी कलहंस (अनसेरिंडिकस), रूडी शेल्डक यानी बतख (टडोर्नफ्रेग्यूनिआ), ब्राउन-हेडेड गाल (लार्सब्रोननिसेफालस), लेसर सैंड-प्लोवर (चारेडियसमुंगोलस) और कई अन्य प्रजातियों के लिए एक प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है।
- रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के जरिये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आर्द्रभूमि क्षेत्र भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन एवं पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। वास्तव में वह पानी का एक बड़ा स्रोत होता है और मीठे पानी की हमारी मुख्य आपूर्ति आर्द्रभूमि के एक समूह से होकर गुजरती है जो वर्षा जल को सोखने और पानी को रिचार्ज करने में मदद करती है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस क्षेत्र का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- त्सो मोरीरी या मोरीरी झील या "माउंटेन लेक", लद्दाख में चांगथांग पठार की एक झील है।
- इसे 2002 में रामसर वेटलैंड साइटों की सूची में रामसर कन्वेंशन के तहत अधिसूचित किया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

रामसर कन्वेंशन

- इसे 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षरित किया गया था।
- यह सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौते में से एक है।
- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना।
- इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए चुनी गई जगहों को 'रामसर साइट' का टैग दिया जाता है।
- **रामसर सूची का उद्देश्य:** आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संबंधित आलेख:

- अन्य हाल ही में जोड़े गए रामसर साइटें: [Click here](#)

व्हेल गीत (Whale Songs)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- पत्रिका में प्रकाशित एक पत्र लुप्तप्राय प्रजाति अनुसंधान में, लेखकों ने एक नए व्हेल गीत का वर्णन किया गया है, जो पहले अज्ञात थी और यह एक ऐसे जनसंख्या के अस्तित्व कि ओर संकेत दे रही है जो पहले अज्ञात थी।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- शोधकर्ताओं ने उत्तरी अरब सागर में ओमान के तट पर, पश्चिमी चागो द्वीपसमूह से दूर, और दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर से दूर अनोखा गीत रिकॉर्ड किया है।
- चूंकि यह पश्चिमी अरब सागर में उनके द्वारा पहचाना जाने वाला एकमात्र ब्लू व्हेल गीत है, इसलिए शोधकर्ताओं ने इसे "उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर" कहा है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि स्रोत या तो ब्लू व्हेल या ब्रायड की व्हेल है क्योंकि दोनों प्रजातियों को पहले ओमान से प्रलेखित किया गया है।
- **महत्व:** यह देखते हुए कि इस गीत-प्रकार को पहले नहीं ज्ञात किया गया है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति पश्चिमी हिंद महासागर में नीले व्हेल की पहले से अपरिभाषित आबादी के संभावित अस्तित्व को इंगित करती है।

क्या आप जानते हैं?

- सभी व्हेल गाती नहीं हैं।
- केवल कुछ, जैसे नीली व्हेल (baleen whale), गाना गाती है।
- व्हेल संवाद और सामाजिकता के लिए गीतों का उपयोग करती हैं।
- उनके गीतों का वर्गीकरण, सीटी और स्पंदित कॉल या "विलाप, खरटि, कलरव और रोने के रूप में किया जा सकता है।
- व्हेल आम तौर पर 4 kHz आवृत्ति से नीचे गाने गाती हैं (मानव श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20 kHz के बीच है)।
- कुछ ब्लू और फिन व्हेल गाने में गाने की आवृत्ति में इतने कम होती हैं कि कुछ भाग, मानव कानों के लिए अश्राव्य हो सकते हैं।

अंटार्कटिक हिमखंड A68 दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के लिए चिंता का कारण बन गया है (Antarctic iceberg A68 becomes cause for concern for South Georgia Island)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण

समाचार में

- विशाल अंटार्कटिक हिमखंड A68 दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के लिए चिंता का कारण बन गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लगभग 5,800 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ अंटार्कटिका से मुक्त होने वाली बर्फ का सबसे बड़ा ब्लॉक विशाल हिमखंड A68, वर्ष 2017 में पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप (West Antarctic Peninsula) के लार्सन आइस शेल्फ (Larsen Ice Shelf) से अलग हो गया था।
- इस हिमशैल का तापमान पृथ्वी के दक्षिणी महाद्वीप के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में तेजी से बढ़ा है।
- 2020 में, एक महासागर की धारा के कारण, आइसबर्ग को दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थानांतरित किया गया था और तब से यह हिमशैल एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र (British Overseas Territory) दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप की ओर खिसक रहा है।
- इसने द्वीप के प्रचुर वन्य जीवन पर हिमशैल के प्रभाव के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं।
- हिमशैल समुद्र की धाराओं के साथ यात्रा करते हैं और या तो उथले पानी में फंस जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं।
- हाल ही में, यूएस नेशनल आइस सेंटर (USNIC) ने पुष्टि की कि A68a से दो नए हिमखंडों को शांत किया गया और नामांकित और ट्रैक किए जाने के लिए यह पर्याप्त बड़े आकर के थे।
- इन्हें A68E और A68F कहा जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- दक्षिण जॉर्जिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जो दक्षिण जॉर्जिया के ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र और दक्षिण सैंडविच द्वीप (SGSSI) का हिस्सा है।
- मुख्य बस्ती Grytviken है।
- यूएस नेशनल आइस सेंटर (USNIC) आइसबर्ग के नामकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसे अंटार्कटिक चतुर्थांश के नाम पर रखा गया है, जिसमें वे धब्बेदार हैं।
- यू.एस. नेशनल आइस सेंटर (US National Ice Center) एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक हिमखंडों का नामकरण करता है और उन पर नज़र रखता है।
- हिमशैलों का नामकरण उस अंटार्कटिक चतुर्थांश (Antarctic Quadrant) के आधार पर रखा जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है।



पोर्टुलका लालजी: वाइल्ड सन रोज (जंगली सूरज गुलाब) की एक नई प्रजाति (Portulaca Laljii: A new species of wild sun rose)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- जैव विविधता

समाचार में

- वनस्पति विज्ञानियों ने भारत में पूर्वी घाट से वाइल्ड सन रोज (जंगली सूरज गुलाब) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

-

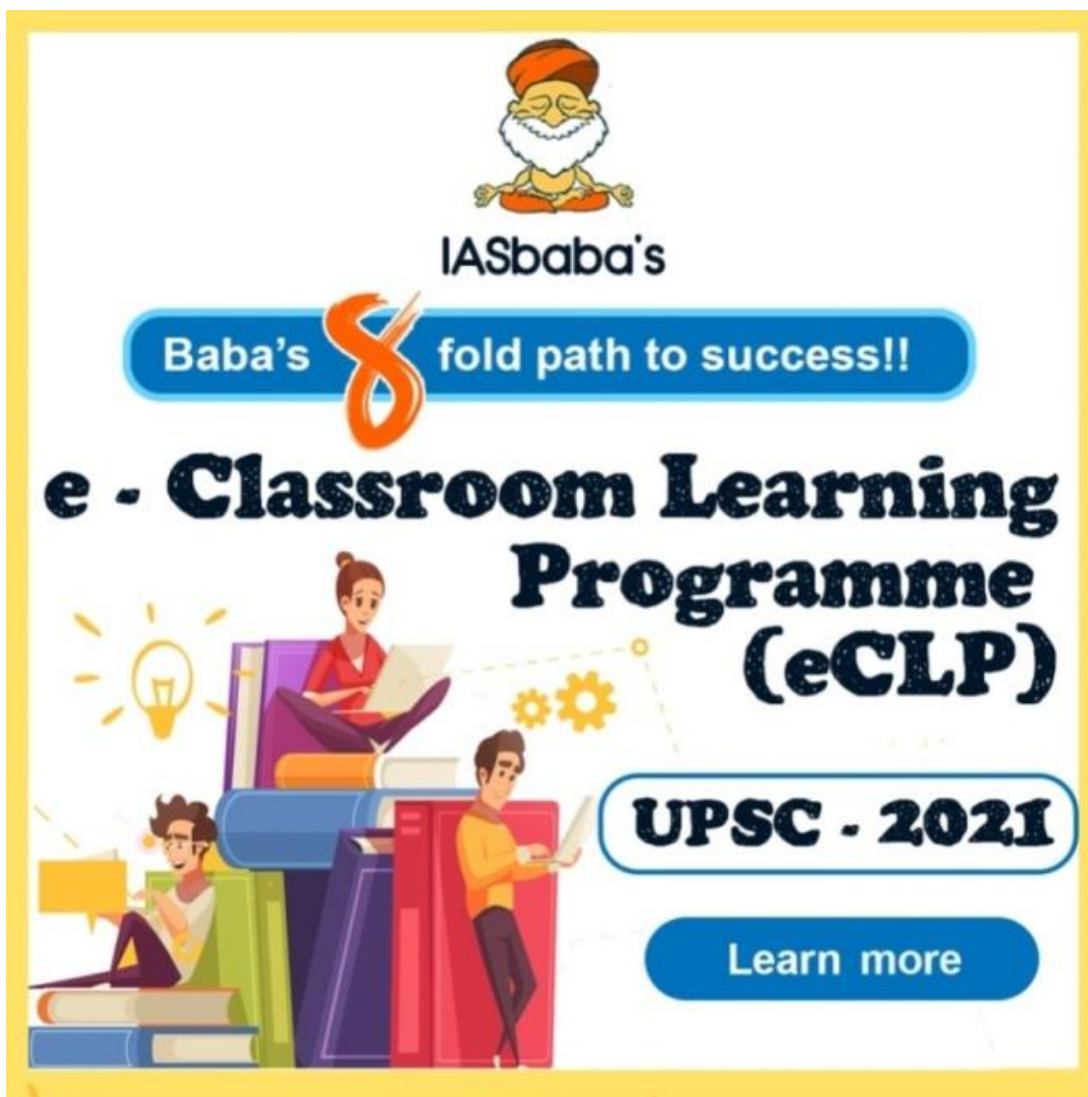
महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- पोर्टुलका लालजी नाम की नई प्रजाति आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से खोजी गई है।
- इसकी अनूठी विशेषताएं इसकी कंद मूल, इसकी पत्ती की धुरी पर किसी बाल का ना होना, इसका लाल गुलाबी फूल, लम्बे आकार का फल और बिना चमक के कॉपर ब्राउन/भूरे रंग के बीज हैं।
- यह फूल बहुत आकर्षक है। यह जून से फरवरी महीने तक खिलते हैं।
- पौधे पर आठ महीने तक सुंदर, छोटे गुलाबी फूल खिलते हैं।
- यह कंद मूलों की सक्कुलेंट(रसीली) प्रकृति के कारण पौधा चट्टानी दरारों पर भी जीवित रह सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- पोर्टुलाका लालजी का नाम लाल जी सिंह के योगदान का सम्मान करने के लिए रखा गया है। लाल जी सिंह अंडमान और निकोबार केंद्र से जुड़े बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रख्यात वनस्पतिशास्त्री हैं।





जीव - जंतु/ समाचारों में राष्ट्रीय पार्क (ANIMALS/NATIONAL PARKS IN NEWS)

ज़ेब्राफिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया गया है और ऐसे जीन की पहचान की है जो हृदय उत्थान को बढ़ावा दे सकते हैं (Zebrafish being used as a research model to promote heart regeneration)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- हाल ही में, पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ज़ेब्राफिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया है और ऐसे जीन की पहचान की है जो हृदय उत्थान को बढ़ावा दे सकते हैं।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- जेब्राफिश एक छोटी मीठे पानी की मछली है जो मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर लंबी होती है।
- यह कुशलता से अपने क्षतिग्रस्त दिल को थोड़े समय की अवधि में पुनर्जीवित कर सकता है।
- जेब्राफिश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पायी जाता है।
- यह मछली दक्षिण एशिया के इंडो-गंगा के मैदानों की मूल निवासी है, जहां वे ज्यादातर धान के खेतों और यहां तक कि स्थिर पानी और धाराओं में पाए जाते हैं।
- यह एक लोकप्रिय मछलीघर की मछली है, जिसे अक्सर व्यापार नाम डैनियो के अंतर्गत बेचा जाता है।
- zebrafish वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कशेरुक मॉडल जीव है, उदाहरण के लिए, दवा विकास में, विशेष रूप से पूर्व-नैदानिक विकास में।
- यह अपनी पुनर्योजी क्षमताओं के लिए भी उल्लेखनीय है और कई ट्रांसजेनिक उपभेदों का उत्पादन करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा इसे संशोधित किया गया है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता (Pilibhit Tiger Reserve bags international award TX2)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- टाइगर रिजर्व; वन्यजीव संरक्षण

समाचार में

- पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR - उत्तर प्रदेश) ने हाल ही में पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है।

- TX2 अवार्ड एक ऐसे स्थल को दिया जाता है जिसने 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल की है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR)

- PTR उत्तर प्रदेश में स्थित है।
- रिजर्व का उत्तरी छोर भारत-नेपाल सीमा के साथ स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिह्नित है।
- पीटीआर अत्यधिक विविध और उत्पादक तराई पारिस्थितिक तंत्र के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है।
- यहाँ 127 से अधिक जानवरों, 326 पक्षी प्रजातियों और 2,100 फूलों वाले पौधों के लिए एक निवास स्थान है।
- जंगली जानवरों में बाघ, दलदल हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, हॉग हिरण, तेंदुआ, आदि शामिल हैं।
- इसमें कई जल निकायों के साथ उच्च लवणीय वन, वृक्षारोपण और घास के मैदान हैं।

TX2 लक्ष्य

- TX2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया के जंगली बाघों को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है।
- लक्ष्य को विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्धारित किया गया है।
- **टाइगर रेंज देश:** भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।
- IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस): लुप्तप्राय
- यह CITES के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

ट्रांसबाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र को संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया (The Transboundary Manas Conservation Area receives the Conservation Excellence Award, 2020)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS- III- - टाइगर रिजर्व; वन्यजीव संरक्षण

समाचार में

- लगभग 1,500 वर्ग किमी. में फैले भारत-भूटान सीमा के संरक्षण वाले क्षेत्र ट्रांसबाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) को संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार एक ऐसे स्थल को मान्यता देता है जिसने इन पांच विषयों में से दो या अधिक में उत्कृष्टता हासिल की है: (1) बाघ और शिकार की निगरानी और अनुसंधान; (2) प्रभावी साइट प्रबंधन; (3) उन्नत कानून प्रवर्तन और संरक्षण और रेंजर कल्याण में सुधार; (4) समुदाय आधारित संरक्षण, लाभ और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन; (5) पर्यावास और शिकार प्रबंधन।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

ट्रांसबाउन्ड्री मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA)

- इसकी स्थापना 2011 में हुई थी।
- **विजन:** लोगों और वन्यजीवों के लाभ के लिए भूटान और भारत के बीच एक बाउन्ड्री संरक्षण क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित और प्रबंधित करना।
- TraMCA परिदृश्य पूर्वी हिमालय में संरक्षण स्थानों का एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- इसमें भारत में पूरे मानस टाइगर रिजर्व, भूटान में चार संरक्षित क्षेत्र और दो जैविक गलियारे शामिल हैं।
- भारत में मानस टाइगर रिजर्व और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क इस जैविक रूप से उत्कृष्ट सीमा-पार क्षेत्र का मूल रूप है।
- यह बाघों, हाथियों, गैंडों और स्तनधारियों, पक्षियों और संवहनी पौधों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है।
- मानस नदी भी उनके माध्यम से होकर बहती है।
- भारतीय मानस में बाघों की संख्या 2010 में 9 से बढ़कर 2018 में 25 हो गई थी
- भूटान मानस में, 2008 में इनकी संख्या 12 से बढ़कर संख्या 2018 में 26 हो गई।

दो नए चिड़िया घरों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी (Two New Zoos Granted Recognition by Central Government)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में दो नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई थी।
- ये हैं - नालंदा, बिहार में राजगीर जू सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालंदा, बिहार

- चिड़ियाघर केवल सफारी बाड़ों पर विशेष रूप से स्थापित है, जो बंदी जानवरों को एक बड़ा स्थान प्रदान करता है।
- जानवर पिंजरे में नहीं रहते हैं, लेकिन वे एक वन क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं।

- चिड़ियाघर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नालंदा के करीब स्थित है।
- शहीद अशफाक उल्ला खान प्राण उद्योग, गोरखपुर, उ.प्र में स्थित है।
- इस चिड़ियाघर की स्थापना के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 9 चिड़ियाघर हैं।
- यह कानपुर प्राण उद्यान के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।

मायरिस्टिका स्वाम्प ट्रीफ्रॉग' (Myristica swamp Treefrog) की उपस्थिति को पहली बार दर्ज किया गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- पश्चिमी घाट में पेड़ों पर पाये जानी वाली दुर्लभ प्रजाति 'मायरिस्टिका स्वाम्प ट्रीफ्रॉग' (Myristica swamp Treefrog) को केरल के त्रिशूर जिले में वाजचल रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार दर्ज किया गया।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- इसका वैज्ञानिक नाम 'मरक्यूराना मायरिस्टिकापेल्युस्ट्रिस' (Mercurana myristicapalustris) है।
- मेंढक को पहली बार 2013 में कोल्लम जिले के अगस्त्यमलाई के पश्चिमी तलहटी में कुलथुपुझा रिजर्व फॉरेस्ट के पास अरिप्पा के मायरिस्टिका दलदल (Myristica swamps) में देखा गया था।
- अगस्त्यमलाई की तलहटी में पाए जाने वाले मायरिस्टिका स्वाम्प ट्रीफ्रॉग के विपरीत, ये मेंढक जून और जुलाई की शुरुआत में सक्रिय पाए गए थे।
- ये मेंढक दुर्लभ और मायावी हैं क्योंकि ये प्रजनन के मौसम में केवल कुछ हफ्तों के लिए पेड़ों पर दिखाई देते हैं और सक्रिय होते हैं।

- ये अद्वितीय प्रजनन व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अन्य मेंढकों के विपरीत इनका प्रजननकाल, मानसून (मई) में शुरू होता है और जून में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने से पहले समाप्त होता है।

समाचार में प्रजातियां: हिमालयन सीरो (Species in news: Himalayan Serow)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- जैव विविधता

समाचार में

- हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार 'हिमालयन सीरो' (Himalayan serow) को देखा गया। इसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हर्लिंग गांव के पास देखा गया।
- वन्यजीव अधिकारियों का मानना है कि यह विशेष जानवर रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश से स्पीति घाटी में भटक गया हो सकता है



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

हिमालयन सीरो

- वैज्ञानिक नाम: हिमालयन सीरो, या मकरिस समत्रेंसिस थार
- हिमालयन सीरो या 'केप्रिकार्निस सुमाट्रेन्सिस थार' (Capricornis sumatraensis thar) मुख्य भूमि सीरो (केप्रिकार्निस सुमाट्रेन्सिस) की एक उप-प्रजाति है।
- 'हिमालयन सीरो' एक बकरी, एक गधा, एक गाय और एक सुअर का संकर (Cross) प्रतीत होता है।
- यह एक बड़े सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, लंबे, खच्चर जैसे कान, और काले बालों के आवरण के साथ एक मध्यम आकार का स्तनपायी है।

- इनकी कई प्रजातियाँ हैं, और ये सभी एशिया में पाई जाती हैं।
- हिमालयन सीरियस आमतौर पर 2,000 मीटर और 4,000 मीटर के बीच ऊँचाई पर पाए जाते हैं।
- वे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाये जाते हैं।
- यह शाकाहारी है।
- **IUCN लाल सूची की स्थिति:** अतिसंवेदनशील (vulnerable)
- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है, जो इसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

खबरों में प्रजातियाँ: भारतीय गौर (Species in news: Indian Gaur)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- जैव विविधता

समाचार में

- भारतीय गौर या बाइसन हाल ही में खबरों में था।
- यह पुणे के शहरी परिदृश्य में देखा गया था जिसके कारण इसे पकड़ लिया गया और परिणामस्वरूप चोट के कारण मृत्यु हो गई थी।
- इसकी मौत की दुखद खबर ने देश में मानव-गौर संघर्ष चर्चा में रहा।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

भारतीय गौड़

- वैज्ञानिक नाम: Bos Gaurus
- वैज्ञानिक नाम- बोस गोरस (Bos Gaurus)

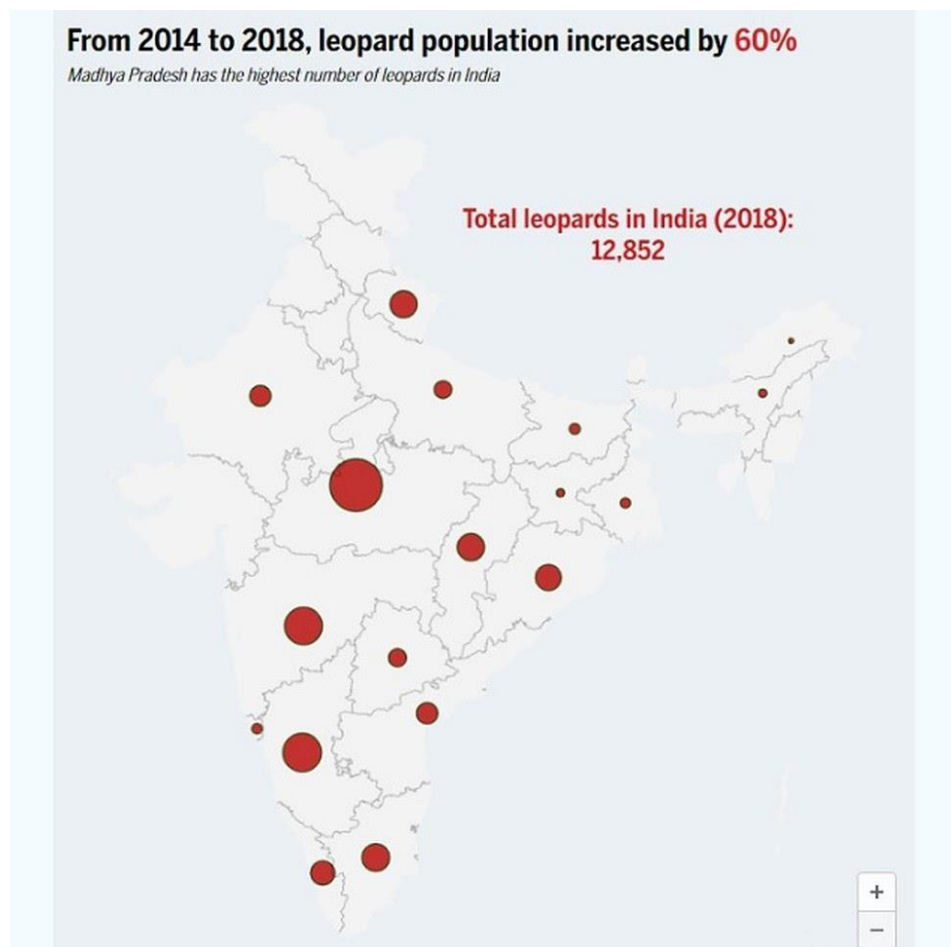
- यह सबसे बड़े विलुप्त बोवाइनों में से एक है।
- यह जंगली मवेशियों में सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है।
- **निवास स्थान:** मूल रूप से यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा, काले लोम (बालों का आवरण) से ढका गोजातीय पशु है।
- ये भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में पाए जाते हैं।
- दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट गौर के सबसे व्यापक मौजूदा स्थल में से एक है, विशेष रूप से वायनाड में - नागरहोल - मुदुमलाई – बांदीपुर, परिसर।
- गौर गोवा और बिहार का राज्य पशु है।
- **आईयूसीएन स्थिति:** अतिसंवेदनशील (vulnerable)
- भारत सरकार ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है।
- यह CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।

तेंदुए की स्थिति 2018' रिपोर्ट जारी (Status Of Leopards Report released)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की।



महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- कैमरा ट्रैपिंग विधि का उपयोग करके तेंदुए की आबादी का अनुमान लगाया गया है।
- भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट-2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है। जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे।
- 2014 से 2018 की इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।
- गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए, दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पाए गए हैं।
- जिस तरह से भारत में टाइगर की निगरानी की गई है, उसका फायदा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हुआ है और उसी वजह से तेंदुए जैसी प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी करना आसान हुआ है।
- तेंदुए शिकार से संरक्षित वन क्षेत्रों के साथ-साथ बहु उपयोग वाले जंगलों में भी पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रेंज सहित कुल 12,852 (12,172-13,535) तेंदुए की मौजूदगी का भी आकलन किया है।

क्या आप जानते हैं?

- तेंदुओं की संख्या की गणना न केवल टाइगर रेंज में की गई बल्कि गैर वन वाले क्षेत्र जैसे कॉफी, चाय के बागान और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भी की गई है, जहां पर तेंदुए पाए जाने की संभावना होती है।
- गणना में हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों को शामिल नहीं करने की प्रमुख वजह यह है कि इन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या बेहद कम होने के आसार हैं।
- तेंदुओं की गणना का कार्य भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया है।

असम के मिनी काजीरंगा में एक सींग वाले गैंड गैंडों में प्रतिस्पर्धा (Cattle competing one-horned rhino's in Assam's Mini Kaziranga)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के एक सींग वाले गैंडों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसे पौष्टिक भोजन के लिए 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

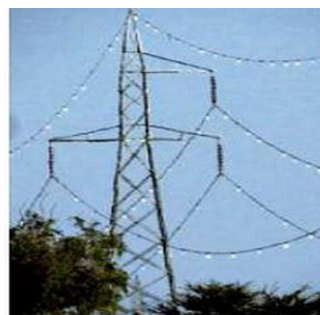
- यह मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है।
- 1987 में, पोबितोरा को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक है और इसमें, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक आबादी पायी जाती है।
- यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और 2000 से अधिक प्रवासी पक्षियों और विभिन्न सरीसृपों के लिए आवास है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु 'फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर' (Firefly bird diverters for Great Indian Bustards)

भाग :GS प्रीलिम्स और GS- III- पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में

- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी (Wildlife Conservation Society- WCS), भारत के साथ मिलकर 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (Great Indian Bustard- GIB) की घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल के माध्यम से उन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों पर "फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर" नामक युक्ति का प्रयोग किया है।



Great Indian Bustards near power lines fitted with firefly detectors.

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- GIB भारत में सबसे गंभीर रूप संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है, जिसमें 150 से कम पक्षी जंगली हैं।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- पर्यावरण मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि थार क्षेत्र में गिब के लिए बिजली की लाइनें, विशेष रूप से उच्च-वोल्टेज संचरण लाइनें, कई ओवरहेड तारों के साथ वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण खतरा हैं, और लगभग 15% में अत्यधिक मृत्यु दर का कारण बन रही हैं।

क्या आप जानते हैं?

- “फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर” विद्युत लाइनों पर स्थापित फ्लैप हैं
- । वे ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ जैसी पक्षी प्रजातियों के लिये परावर्तक के रूप में काम करते हैं। पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और बिजली की लाइनों से टकराव से बचने के लिये अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं।
- छोटे पक्षी उड़ते समय अपनी दिशा बदल सकते हैं लेकिन बड़ी पक्षी प्रजातियों के लिये उनके शरीर के वजन और अन्य कारकों के कारण यह मुश्किल है।
- चूंकि ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ न्यूनतम दृश्य क्षमता, अधिक वजन वाले पक्षी होते हैं, इसलिये उन्हें अपनी उड़ान मार्ग को तेजी से बदलना मुश्किल होता है, भले ही वे एक जीवित तार (Live Wire) के सामने आ जाएं।
- डायवर्टर को फायरफ्लाईज़ कहा जाता है क्योंकि वे रात में बिजली लाइनों पर चमकते हुए जुगनू की तरह दिखते हैं।

अवसंरचना/ऊर्जा (INFRASTRUCTURE/ENERGY)

पेट्रोलियम बोर्ड की नई एकीकृत प्रशुल्क संरचना (Petroleum Board's notifies New Unified Tariff Structure)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board—PNGRB) द्वारा 14 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक नई टैरिफ संरचना अधिसूचित की गयी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नई एकीकृत प्रशुल्क संरचना के तहत, सिंगल पाइपलाइन नेटवर्क पर, किसी स्रोत से 300 किलोमीटर की दूरी तक, क्रेता को गैस परिवहन के लिए एक निश्चित टैरिफ (प्रशुल्क) तथा 300 किलोमीटर की दूरी से अधिक होने पर निर्धारित अलग टैरिफ का भुगतान करना होगा।
- चूंकि, टैरिफ में परिवर्तनों से देश के पश्चिमी तट से दूर स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस अधिक सस्ती हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप गैस परिवहन अवसंरचनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- PNGRB के अनुसार, गैस परिवहन टैरिफ को परिचालन लागत और निवेशित पूंजी पर मानकीय स्तर का 'उचित लाभ' प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है।
- प्राकृतिक गैस का लागत कारक के रूप में उपयोग करने वाली कई उर्वरक इकाइयां और बिजली संयंत्र देश के पश्चिमी तट पर LNG टर्मिनल्स के नजदीक स्थापित किये गए हैं। इनके लिए गैस की कीमतों में काफी वृद्धि हो सकती है।

क्या आप जानते हैं ?

- भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की खपत को वर्तमान में भारत की ऊर्जा टोकरी के 6.2% से 2030 तक 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

शहरी क्षेत्रों के लिए DUET (विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण) (DUET (Decentralised Urban Employment and Training) for urban areas)

संदर्भ

- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम है क्योंकि आवधिक लॉकडाउन के कारण लाखों श्रमिकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। वे अपनी नौकरी पुनः प्राप्त कर पाएँगे या नहीं, इस बात को लेकर भी अनिश्चितता है।

- हमारे सार्वजनिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों (जैसे - स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, जेल, आश्रय स्थल, छात्रावास, पार्क, संग्रहालय, कार्यालय, इत्यादि) के खराब रखरखाव की पुरानी समस्या है।
- कई महीनों की लॉकडाउन के बाद खुल रहे सार्वजनिक संस्थानों के परिसर को बहाल कराने के लिए बहुत सारे काम करवाने पड़ेंगे (जैसे - सफाई, पुताई, निराई, सैनिटाईजिंग, मरम्मत, पेंटिंग, नालसाजी, आदि)।
- लोगों की रोजगार गारंटी अधिनियम में रुचि बढ़ तो रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में राहत कार्यों का बहुत कम अनुभव है। प्रस्तावित ड्यूएट योजना शहरी रोजगार गारंटी की दिशा में एक शुरुआती कदम के रूप में काम कर सकता है।

मूल विचार

- राज्य सरकार 'जॉब स्टैम्प (नौकरी मुहर)' जारी करे और उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी विभागों, स्वास्थ्य केन्द्र, नगर पालिकाओं, पड़ोसी संगठनों, तथा शहरी स्थानीय निकायों जैसे अनुमोदित संस्थानों को वितरित करे। शुरुआत दौर में ये अनुमोदित संस्थान सार्वजनिक संस्थान होंगे (निजी गैर-लाभकारी संस्थानों पर बाद में विचार किया जा सकता है)।
- प्रत्येक जॉब स्टैम्प को एक निर्धारित अवधि के भीतर काम के एक व्यक्ति-दिन में परिवर्तित किया जा सकता है, जहाँ अनुमोदित संस्था के द्वारा काम की व्यवस्था और सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान (वैधानिक न्यूनतम) कर सकता है। श्रमिकों द्वारा नियोक्ता से प्राप्त जॉब स्टैम्प प्रस्तुत करने पर मजदूरी भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा सकता है।
- श्रमिकों को अनुमोदित नियोक्ता द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की एक सूची से चुना जा सकता है, या शायद (मिलीभगत से बचने के लिए) बेहतर यह होगा कि, एक स्वतंत्र 'प्लेसमेंट एजेंसी' द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को चुना जाए (अधिक जानकारी नीचे दी गयी है)।

प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका

- प्लेसमेंट एजेंसी की मुख्य भूमिका जरूरत पड़ने पर पंजीकृत कामगारों को अनुमोदित नियोक्ताओं को आवंटित करना होगा। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी अन्य प्रयोजनों को भी पूरा कर सकती है, जैसे कि श्रमिकों के कौशल को प्रमाणित करना, श्रमिकों को शोषण से बचना और उनके लिए सामाजिक लाभों की व्यवस्था करना।
- प्लेसमेंट एजेंसी के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, जैसे: (a) स्थानीय सरकार द्वारा संचालित नगर पालिका के लिए एक एकल एजेंसी; (b) एक श्रमिक कोऑपरेटिव; (c) कई प्लेसमेंट एजेंसियां, जो गैर-लाभकारी संगठनों या सहकारी समितियों के रूप में काम कर सकती हैं।

संबन्धित अनुभव

- कुछ देशों में इसी तरह की सब्सिडी आधारित रोजगार योजनाएँ हैं, उदाहरण के लिए - कई यूरोपीय देशों की 'सेवा वाउचर योजनाएँ' (एसवीएस)। बेल्जियम में सफाई और इस्तरी जैसी घरेलू सेवाओं के लिए एक बहुत लोकप्रिय एसवीएस है। इस योजना का इस्तेमाल 2016 में हर 5 से 1 घर ने किया था।
- अनुमोदित नियोक्ताओं को बड़ी संख्या में सक्रिय करने से बहुत अधिक रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
- अनुमोदित नियोक्ताओं की यह सुनिश्चित करने में हिस्सेदारी होगी कि काम प्रभावी/सार्थक/उत्पादक हो।
- इस योजना के संचालन के लिए संस्थाओं को खुद के कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी क्योंकि ये संस्थाएँ ही नियोक्ता होंगे।

- श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान करने और संभवतः अन्य लाभों का भी आश्वासन दिया जा सकेगा।

DUET MGNREGA से कैसे अलग है?

- यह प्रस्ताव केवल उन लोगों के लिए एक अस्थायी राहत उपाय नहीं है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है।
- इसे एक स्थायी संस्थान बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जो शहरी बेरोजगारी और क्षय के लिए औषध का काम करेगी। यह भी ध्यान दें कि ड्यूएट की प्रेरणा, मनरेगा की प्रेरणा से काफी अलग है।
- मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों को सुस्त समय या सूखे के वर्ष में कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जैसा शहरी उत्पादन के मामले में नहीं होता। फिर भी, शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है।
- शहरी क्षेत्र कुछ अवसंरचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और वहाँ श्रम बल का उसकी क्षमता से कम उपयोग किया गया है। परंतु, अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए इस श्रम का उपयोग करने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

आगे की संभावनाएं

- दुरुपयोग से बचने के लीये, जॉब स्टैम्प का उपयोग जायज़ कार्यों की एक सूची तक सीमित किया जा सकता है। लेकिन यह सूची काफी व्यापक होनी चाहिए, केवल रखरखाव तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।
- कार्यों की सूची इतनी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि सार्वजनिक संस्थानों की मौजूदा नौकरियों को विस्थापित कर दें।
- सभी ड्यूएट रोजगार योजना मौजूदा श्रम कानूनों में निर्दिष्ट श्रमिक सुरक्षा और कल्याण मानदंडों के अधीन होनी चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी शहरी निवासियों को ड्यूएट के तहत पंजीकरण करने के लिए योग्य माना जाना चाहिए, और विशेष पंजीकरण अभियान या प्लेसमेंट एगेंसियान कम आय वाले इलाकों में स्थापित किया जा सकता है।
- यह योजना कुशल एवं अकुशल, दोनों तरह के श्रमिकों के लिए होगा। किसी कुशल श्रमिक को नियोजित करते वक्त एक अकुशल श्रमिक को सहायक के रूप में नियोजित किया जा सकता है, जो इस योजना को प्रशिक्षित करने तथा कौशल निर्माण करने का तत्व प्रदान करेगा। भविष्य में प्रशिक्षित सुविधाओं विकसित की जा सकती है या ढूँढी जा सकती है, उदाहरण के लिए किसी गैर-लाभकारी प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा, यदि कोई हो।
- कुछ लागत-साझेदारी की व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है, जिसके तहत अनुमोदित नियोक्ता मजदूरी का एक छोटा सा हिस्सा भुगतान करेंगे, या निःशुल्क जॉब स्टैम्प की जगह उन जॉब स्टैम्प को खरीदेंगे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि काम प्रभावी/उत्पादक हो। हालांकि इससे रोजगार सृजन में कमी आएगी। परंतु लागत-साझेदारी की व्यवस्था जटिल है, शायद शुरुआती दौर में इसे न लागू करना सही रहेगा।
- सार्वजनिक संस्थानों के बीच जॉब स्टैम्प के आवंटन के लिए सरल मानदंडों की आवश्यकता होगी। इन संस्थानों के बीच जॉब स्टैम्प के सीमित आदान-प्रदान पर विचार किया जा सकता है।
- कार्यों की निगरानी, निरीक्षण, आडिट और मूल्यांकन के लिए नगर पालिका स्तर पर एक स्वतंत्र प्राधिकरण नियुक्त या नामित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) संभवतः ड्यूएट में भी भूमिका निभा सकता है।
- ड्यूएट आसानी से किसी जिले या नगर पालिका में एक परीक्षण के तौर पर शुरू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ड्यूएट के सहारे मांग-आधारित 'रोजगार गारंटी' की ओर बढ़ना आसान होगा। इसके लिए नगर पालिका को एक अंतिम उपाय नियोक्ता के रूप में काम करना होगा जो उन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा जो काम की तलाश/मांग कर रहे हैं, पर उन्हें अन्य अनुमोदित नियोक्ताओं से कोई काम नहीं मिल रहा। वैकल्पिक रूप से, ड्यूएट शहरी क्षेत्रों में एक बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है।

फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के तकनीकी विनिर्देशों के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी (Draft Guidelines Of Technical Specifications Of Floating Structures)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय तटरेखा पर विश्व स्तर के फ्लोटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के उद्देश्य से फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के तकनीकी विनिर्देशों के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को संकलित किया है और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।

फ्लोटिंग जेटी के लाभ

- अपने अंतर्निहित लाभों के कारण फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स एक आकर्षक समाधान हैं और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसे बढ़ावा दे रहा है। पारंपरिक क्वे और फिक्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की तुलना में फ्लोटिंग जेटी के लाभ इस प्रकार हैं:
- यह कम लागत वाला समाधान है और पारंपरिक संरचनाओं की कीमत से काफी सस्ता है।
- पारंपरिक जेटी की तुलना में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स काफी तेजी से स्थापित किए जा सकते हैं। आमतौर पर, पारंपरिक संरचनाओं की स्थापना में 24 महीने का समय लगता है, इसकी तुलना में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स 6-8 महीनों में बनाए जा सकते हैं।
- पर्यावरण पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
- मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों के कारण इसका विस्तार करना आसानी से संभव है।
- बंदरगाह के नवीनीकरण की स्थिति में इसे आसानी से दूसरी जगहों पर ले जाया जा सकता है।
- यह जेटी और नौकाओं के बीच निरंतर फ्री बोर्ड प्रदान करता है।

बांग्लादेश द्वारा प्रथम अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर (Bangladesh Signs First Preferential Trade Agreement-PTA)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में, बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement : PTA) पर हस्ताक्षर किया, जिससे दोनों देशों के मध्य एक सीमा तक वस्तुओं की शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित हो सके।

AT A GLANCE

- Bangladesh signs its maiden PTA with Bhutan today
- 100 Bangladeshi goods will enter Bhutan duty-free
- 34 Bhutanese items will enjoy duty-free benefit in Bangladesh
- In 2018-19, Bangladesh exported goods worth \$7.56m to Bhutan and imported goods worth \$42.09m
- The figures were \$0.61m and \$12.16m respectively ten years ago



प्रमुख बिंदु

- बांग्लादेश द्वारा विश्व के किसी देश के साथ हस्ताक्षर किया गया यह पहला अधिमान्य व्यापार समझौता है। बांग्लादेश और भूटान के बीच 50 वर्ष के राजनयिक सम्बंधों के उपलक्ष्य में ढाका में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस समझौते के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में, जबकि भूटान की 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। इस सूची में अन्य वस्तुओं को बाद में जोड़ा जा सकता है।
- बांग्लादेश को अगले वर्ष जून तक इंडोनेशिया और नेपाल जैसे देशों के साथ 11 और अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने की योजना है।

क्या आप जानते हैं ?

- वर्ष 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले प्रथम दो देशों में भूटान और भारत शामिल हैं।

सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क()

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप और GS- III - बुनियादी ढांचा

समाचार में

- सरकार ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए देश भर में फैले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क। स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM-WANI के नाम से जाना जाएगा।
- PM-WANI इको-सिस्टम विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा संचालित किया जाएगा:
- पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ): यह केवल WANI अनुपालन वाई-फाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना, रखरखाव और संचालन करेगा और ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा।
- **पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए):** यह पीडीओ का एक एग्रीगेटर होगा और प्राधिकरण और लेखा से संबंधित कार्य करेगा।
- ऐप प्रदाता: यह उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और आस-पास के क्षेत्र में WANI अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट की खोज करने के लिए एक ऐप विकसित करेगा और इंटरनेट सेवा तक पहुंचने के लिए ऐप के भीतर ही प्रदर्शित करेगा।
- केंद्रीय रजिस्ट्री: यह ऐप प्रदाता, पीडीओए और पीडीओ के विवरण को बनाए रखेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव C-DoT द्वारा किया जाएगा।
- पीडीओ के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- पीडीओएस और ऐप प्रदाता किसी भी पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना, DoT के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल (SARALSANCHAR) के माध्यम से खुद को पंजीकृत करेंगे।
- इन सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा।
- यह प्रस्ताव देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा।
- यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार, आय में वृद्धि और रोजगार और लोगों के सशक्तीकरण में मदद करेगा।

पीएम वाणी योजना (PM WANI Scheme)

- हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (Public Wi-Fi Access Network Interface) स्थापित करने हेतु लाए गए एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
- सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे 'पीएम वाणी' (PM-WANI) के नाम से भी जाना जाएगा, को पहली बार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा वर्ष 2017 में अनुशंसित किया गया था।

पीएम वाणी योजना की मुख्य विशेषताएं

- यह थ्री टियर सिस्टम है जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट मुहैया करायी जाएगी।
- फर्स्ट टियर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के लिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, उनके आस-पास की वाई-फाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है।
- सेकेंड टियर में पब्लिक डेटा ऑफिस जोकि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा।
- इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाई-फाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

क्या आप जानते हैं ?

- वर्ष 2015 से जून 2020 के बीच भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 302 मिलियन से बढ़कर 750 मिलियन हो गई। यह 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) ही भारत को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते इंटरनेट बाजारों में से एक बनाती है।
- डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को इंटरनेट वहनीयता (Internet Affordability) के मामले में 9वें स्थान पर रखा गया, इस श्रेणी में भारत ने यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि इंटरनेट गुणवत्ता और ई-बुनियादी ढाँचे के मामले में भारत को क्रमशः 78वें और 79वें (कुल 85 में से) स्थान पर रखा गया था।

संभावित लाभ:

- इस योजना में बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी के लिये लागत-प्रभावी साधन उपलब्ध कराने के अलावा 2 करोड़ से अधिक नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन की क्षमता है।
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के तहत वर्ष 2022 तक 1 करोड़ सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के लक्ष्य और वर्तमान में केवल 3.5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट की छोटी संख्या को देखते हुए, पीएम-वाणी के माध्यम से इस राष्ट्रस्तरीय पहल के लिये आवश्यक उपकरणों की मांग और स्थानीय स्तर पर उनके निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- PDOs सामग्री (शिक्षा/समाचार या मनोरंजनसे संबंधित डिजिटल सामग्री) के लिये स्थानीय वितरण केंद्र बन सकते हैं।
- इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र बिना इंटरनेट का उपयोग किये ऑफलाइन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- इस पहल को अन्य सेवा प्रदाताओं (OSPs) के विनियम के उदारीकरण से साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि भारत दुष्कर अनुपालन के बोझ के बिना ही डिजिटल SME (लघु और मध्यम आकार के उद्यम) के लिये ऑनलाइन पहुँच बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
- यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) और ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यह छोटे दुकानदारों को वाई-फाई सेवा प्रदान करने में सक्षम करेगा।

चुनौतियाँ:

नेटवर्क सुरक्षा:

- अधिकांश वाई-फाई हॉटस्पॉट इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को कूटबद्ध (Encrypt) नहीं करते हैं, इसलिये वे सुरक्षित नहीं होते हैं। सार्वजनिक वाई-फाई की सुरक्षा में यह कमी उपकरणों पर व्यक्तिगत जानकारी की संभावित हैकिंग या अनुचित/गैर-अनुमोदित पहुँच का कारण बन सकती है।
- हालाँकि भारतीय सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट नेटवर्क प्रणाली के तहत यह परिकल्पना की गई है कि इन वाई-फाई पॉइंट्स के माध्यम से इंटरनेट पहुँच की अनुमति केवल इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (KYC) और ओटीपी (OTP) तथा मैक आईडी-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी जिससे नेटवर्क सुरक्षा के जोखिम को कम किया जा सकेगा।
- मैक प्रमाणीकरण की विधि के तहत नेटवर्क तक पहुँच के लिये उपकरणों को प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें एक सुरक्षित नेटवर्क तक पहुँच प्रदान की जाती है।

परियोजना की व्यावहारिकता:

- भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं क्योंकि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई तकनीकी-दिग्गज (जैसे-गूगल और फेसबुक) बड़े प्रयासों के बाद भी असफल रहे हैं।
- वर्ष 2017 में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने 'एक्सप्रेस वाई-फाई' की शुरुआत की थी। हालाँकि यह परियोजना बहुत अधिक प्रभावी नहीं हुई।
- गूगल द्वारा वर्ष 2015 में पूरे भारत में 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों और हज़ारों अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क वाई-फाई प्रदान करने के लिये 'स्टेशन प्रोजेक्ट' नामक पहल की शुरुआत की गई थी, परंतु सफल न होने के कारण इसे वर्ष 2020 की शुरुआत में बंद कर दिया गया।
- गूगल द्वारा इसकी असफलता के लिये सस्ते और अधिक सुलभ मोबाइल डेटा, सभी के लिये इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने हेतु सरकारी पहलों तथा अलग-अलग तकनीकी आवश्यकताओं एवं बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों को उत्तरदायी बताया गया।

निष्कर्ष

- यह ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) और ईज ऑफ़ लिविंग (Ease of Living) को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यह छोटे दुकानदारों को वाई-फाई सेवा प्रदान करने में सक्षम करेगा।

रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन: ग्रीन पावर मार्केट पर दांव लगाना (Renewable Energy Generation: Betting on the green power market)

संदर्भ:

- भारत का हाल ही में लॉन्च किया गया रीयल-टाइम बिजली बाजार, जो ग्रीन मार्केट के साथ मिलकर, अक्षय ऊर्जा को सबसे कुशल और प्रतिस्पर्धी तरीके से एकीकृत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ग्लोब में अक्षय ऊर्जा की क्षमता

- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीकरणीय 2020 रिपोर्ट के अनुसार, शुद्ध रूप से स्थापित अक्षय क्षमता 2020 में विश्व स्तर पर लगभग 4% बढ़ जाएगी, लगभग 200 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी।
- वैश्विक स्तर पर, नवीकरणीयों को कोयले से आगे निकलने और 2025 में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बनने की उम्मीद है और इससे दुनिया की एक तिहाई बिजली की आपूर्ति हो सकती है।

क्या आपको पता है?

- पेरिस जलवायु समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता की अपनी हिस्सेदारी को 450 गीगावॉट तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 30 सितंबर तक, भारत में 89 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है।

- पिछले छह वर्षों के दौरान, अक्षय क्षेत्र ने निवेश के 4.7 लाख करोड़ रुपये को आकर्षित किया है, जिसमें लगभग 42,700 करोड़ रुपये का एफडीआई शामिल है।

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विकास

- **दोगुनी पीढ़ी की क्षमता:** नवीकरणीय पीढ़ी, 138 बिलियन यूनिट्स की, वित्त वर्ष 2015 में, वित्त वर्ष 2016 में 66 बिलियन यूनिट्स से दोगुनी हो गई है।
- **क्षेत्र का मजबूत विकास:** देश में वित्त वर्ष 2016 से अक्षय उत्पादन में 20% सीएजीआर वृद्धि देखी गई, जबकि इसी अवधि में कुल बिजली उत्पादन में 4.3% की वृद्धि देखी गई।
- **घटती लागत:** भारत में बड़े पैमाने पर सौर के लिए ऊर्जा की मौजूदा स्तर की लागत (LCOE) लगभग 2.5 रुपये प्रति किलोवाट है, जबकि 2010 में यह 12 रुपये थी। हालिया बोली में, यह घटकर 2 रुपये हो गया।

नवीकरणीय क्षेत्र में प्रगति को गति देने वाली सरकार द्वारा किए गए उपाय:

- सौर और पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए अंतर-राज्य संचरण शुल्क की छूट
- राज्यों के लिए अक्षय खरीद दायित्व (RPO) से सम्बंधित अनुमान
- अनुबंधों की सुविधा बनाए रखने पर ध्यान दें
- अक्षय क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियां

- **मौसम की स्थिति के प्रति कमजोर:** जबकि पारंपरिक बिजली संयंत्र - जो कोयला आधारित या बड़े हाइड्रो हैं - जरूरत के अनुसार पीढ़ी को अलग-अलग करने की क्षमता रखते हैं, अक्षय पीढ़ी प्रकृति की दया पर अधिक है। ऐसे खरीदार हैं जो वाणिज्यिक पर केंद्रित हैं अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए उत्सुक हैं।
- **बाजार हस्तक्षेप की चुनौतियां:** अक्षय ऊर्जा की मौसमी और रुक-रुक कर देखते हुए, यह बाजार के हस्तक्षेप के लिए आसानी से अतिसंवेदनशील नहीं है।

यह उपरोक्त संदर्भ में है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने ऊर्जा विनिमय पर ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) के तहत नवीकरणीय ऊर्जा अनुबंधों के व्यापार को मंजूरी दी।

- जीटीएम एक वैकल्पिक नया मॉडल है जो खुले बाजार में नवीकरणीय डेवलपर्स द्वारा बिजली बेचने के लिए पेश किया गया है, दीर्घकालिक पीपीए में शामिल हुए बिना।
- जीटीएम के माध्यम से लेन-देन प्रकृति के अनुरूप होगा, जो कि संबंधित खरीदारों और विक्रेताओं की स्पष्ट पहचान के साथ नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) के लिए लेखांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जीटीएम के लिए सकारात्मक शुरुआत:

- ग्रीन मार्केट ने 21 अगस्त को व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू होने के लगभग 90 दिनों में, बाजार ने 400 मिलियन से अधिक इकाइयों की संचयी कारोबार मात्रा हासिल की है, जो पहल के आत्मविश्वास को दर्शाती है।
- जीटीएम के तहत अधिक विकल्प: बाजार में प्रतिभागियों को तीन घंटे से 11 दिन आगे तक नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए, ग्रीन मार्केट ने अब दो और विकल्प शुरू किए हैं।
- यह बाजार को और मजबूत करेगा और प्रतिभागियों को सभी क्षेत्रों में व्यापार के लिए उपलब्ध अनुबंधों के माध्यम से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति देगा।

जीटीएम पहल का महत्व और लाभ:

- **निर्माता को लाभ:** जीटीएम प्लेटफॉर्म पैन-इंडिया बाजार तक पहुंच प्रदान करके अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को लाभान्वित करेगा। ग्रीन मार्केट अंततः ग्रीन जनरेटर को बिक्री और व्यापार के कई मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- **क्रेता को लाभ:** यह प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के खरीदारों को लाभान्वित करेगा।
- **राज्य सरकारों को प्रोत्साहन:** यह नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों पर बोझ को कम करेगा और आरई क्षमता को अपने स्वयं के आरपीओ से परे विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा।
- **आरईएन बाजार को मजबूत करता है:** पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, लचीलेपन, और भुगतान सुरक्षा और वित्तीय बचत के मजबूत मूल्य प्रस्ताव के साथ, जो विनिमय बाजार प्रदान करता है, एक अखिल भारतीय हरित बाजार संख्या को बढ़ाकर अक्षय ऊर्जा बाजार को मजबूत बनाने की क्षमता रखता है। क्षेत्र में प्रतिभागियों की।
- **राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है:** पारदर्शी मंच देश के आरई क्षमता संवर्धन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार के पास 2022 तक 175 GW RE क्षमता का लक्ष्य है।

निष्कर्ष

- जीटीएम जैसे कदम स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के भीतर उत्पन्न सभी अक्षय ऊर्जा को पैन इंडिया वाइड एक्सचेंज-आधारित ऊर्जा बाजारों के माध्यम से सबसे कुशल तरीके से भेजा जाए।

पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना Comprehensive Telecom Development Plan (CTDP) For North Eastern Region (NER) approved

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा।
- अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगा। इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पूरे होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की उच्च पूंजी लागत के अलावा, ये क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व, कम आय और वाणिज्यिक गतिविधि की कमी के कारण कम राजस्व भी उत्पन्न करते हैं।
- इस प्रकार सामान्य बाजार बल अकेले दूरसंचार क्षेत्र को पर्याप्त रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए निर्देशित नहीं करेंगे।
- एक ओर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों की सेवा के लिए बाजार तंत्र की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर महत्वपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दुनिया के अधिकांश देशों ने आईसीटी को यूनिवर्सल एक्सेस और यूनिवर्सल सर्विस प्रदान करने के लिए नीतियां बनाई हैं।
- **भारत की नई दूरसंचार नीति - 1999 (NTP'99)** ने कहा कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) को पूरा करने के लिए संसाधनों को 'यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL)' के माध्यम से जुटाया जाएगा, जो राजस्व का एक प्रतिशत होगा। विभिन्न लाइसेंस के तहत ऑपरेटरों।
- यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी 01.04.2002 से लागू हुई।
- भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को वैधानिक दर्जा देते हुए दिसंबर 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (2003, 2006 और 2008 में संशोधित) के अनुसार, फंड का उपयोग सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए विशेष रूप से किया जाना है।

KLI प्रोजेक्ट: सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का प्रावधान (KLI Project: Provision of Submarine Optical Fibre Cable Connectivity)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मुख्य भू-भाग कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों (के.एल.आई. परियोजना : KLI Project) के मध्य सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को स्वीकृति प्रदान की।

प्रस्तावित योजना

- इस परियोजना के अंतर्गत एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) के माध्यम से कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच सीधे दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
- इन द्वीपों में कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्लतान और कदमतत शामिल हैं।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपए है, जिसमें पांच वर्षों के लिये संचालन व्यय को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष (Universal Service Obligation Fund: USOF) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- भारत संचार नगर लिमिटेड को इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी तथा टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) को यू.एस.ओ.एफ. की सहायता करने के लिये तकनीकी सलाहकार नामित किया गया है।
- इस परियोजना के तहत सम्पत्तियों के स्वामित्व का अधिकार यू.एस.ओ.एफ. के पास रहेगा। इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2020 में चेन्नई और अंडमान-निकोबार के मध्य सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक का उद्घाटन किया गया था।

प्रभाव

- दूरसंचार के बुनियादी ढाँचे में वृद्धि देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण है।
- इस सम्पर्क योजना की मंजूरी से लक्षद्वीप के द्वीपों में दूरसंचार सुविधाओं में उच्च क्षमता के बैंडविड्थ की उपलब्धता से काफी सुधार होगा। सबमरीन कनेक्टिविटी परियोजना नागरिकों को घर पर ही ई-सुशासन सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

- इसके अलावा, मत्स्य क्षेत्र में क्षमता विकास, नारियल आधारित उद्योगों, पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, ब्लू इकॉनमी के विकास में योगदान मिलेगा।
- इस परियोजना से अनेक उद्यमों की स्थापना के साथ-साथ ई-कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और शैक्षिक संस्थानों में ज्ञान साझा करने में पर्याप्त मदद मिलेगी। लक्षद्वीप के द्वीपों में लॉजिस्टिक सेवाओं के एक विशाल हब बनने की क्षमता है।

सम्बंधित आलेख (Related article):

- Optical Fibre Connectivity to Andaman and Nicobar Islands: [Click here](#)

भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना (Indian Railways launches Hospital Management Information System -HMIS)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II- स्वास्थ्य और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर एक और बड़ी आईटी पहल शुरू की है।
- एचएमआईएस भारतीय रेलवे द्वारा तैयार स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एक बड़ा बदलाव लाएगा।
- नई प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और पारदर्शी तरीके से संसाधनों के उपयोग में सहायता करेगी। अस्पतालों में मरीजों के प्रतीक्षा समय को कम-से-कम करेगा और हर समय डॉक्टरों की टीम को मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा।
- हाल ही में, भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) शुरू की है।
- रेलवे द्वारा अपने कार्यबल की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए यह एक और बड़ी पहल है।



- एचएमआईएस के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को हेड क्वार्टर से संबद्ध अस्पतालों और सहायक केन्द्रों के एकीकरण का लाभ होगा। इस परियोजना में 20 से अधिक मॉड्यूल होने की संभावना है और इससे चिकित्सा बिरादरी और अस्पताल के लाभार्थियों को अत्यधिक लाभ होगा।

रेलवे में एचएमआईएस के बारे में:

- एचएमआईएस को भारतीय रेलवे ने रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समन्वय में विकसित किया है। एचएमआईएस का उद्देश्य अस्पताल प्रशासन गतिविधियों के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करना है जैसे कि नैदानिक, निदान, फार्मसी, परीक्षा, औद्योगिक स्वास्थ्य आदि। परिकल्पित समाधान के प्राथमिक उद्देश्य निम्न हैं:
 - प्रभावी रूप से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं और उसके संसाधनों का प्रबंधन करना
 - प्रशासनिक चैनल में अस्पतालों के प्रदर्शन पर नजर रखना
 - अपने लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराना
 - मरीज के प्रतीक्षा समय में सुधार करना
 - सभी रोगियों का ईएमआर (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड) बनाना और उसे कायम रखना।
- वर्तमान में, एचएमआईएस के 3 मॉड्यूल - पंजीकरण, ओपीडी डॉक्टर डेस्क और फार्मसी - लागू किए गए हैं। ये तीनों मॉड्यूल केन्द्रीय अस्पताल, लालगुडा में परीक्षण के आधार पर लागू होने जा रहे हैं और एससीआर पर सभी स्वास्थ्य इकाइयों में धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे।
- पंजीकरण मॉड्यूल रोगी को कोई भी दिक्कत दिए बिना सहज तरीके से उसके स्वतः सत्यापन के साथ यूएमआईडी का एकीकरण करता है।
- ओपीडी डेस्क मॉड्यूल रोगी परीक्षा और निदान विवरण की सभी प्रक्रियाओं को कवर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा। फार्मसी मॉड्यूल डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं को आसानी से वितरित करता है और इन्वेंट्री प्रबंधन का अनुकूलन करता है।

भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा (Draft Indian Ports Bill, 2020)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक भारतीय पत्तन कानून, 1908 (कानून संख्या 15) को निरस्त कर उसका स्थान लेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा भारतीय पत्तनों की ढांचागत प्रगति और सतत विकास के लिए निवेश आकर्षित करने और पत्तनों के प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन के जरिए भारतीय तट रेखा के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करता है। प्रस्तावित विधेयक गैर-परिचालन योग्य पत्तनों की बड़ी संख्या को देखते हुए पत्तनों के संरक्षण के उपाय प्रदान करेगा। यह नए पत्तनों के निर्माण और मौजूदा पत्तनों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियामक ढांचे का निर्माण कर भारतीय समुद्री क्षेत्र और पत्तनों में अधिक निवेश सुनिश्चित करेगा।
- यह विधेयक मोटे तौर पर निम्नलिखित तरीकों से भारत में पत्तन क्षेत्र की प्रगति और सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की कोशिश करता है :
 - समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण का गठन।
 - तटीय राज्यों की सरकारों, राज्यों के समुद्री बोर्डों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना तैयार करना।
 - पोर्ट क्षेत्र में किसी भी गैर-प्रतिस्पर्धी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और एक त्वरित और वहन योग्य शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए विशेष समुद्री न्यायाधिकरणों जैसे - समुद्री पत्तन न्यायाधिकरण और समुद्री पत्तन अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करना।

‘डाकपे’ नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप (DakPay: New digital Payment App)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- II - गवर्नेंस और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) ने 15 दिसंबर, 2020 को ‘डाकपे’ नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया।

- उद्देश्य: समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों (Pay) को पूरा करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'डाकपे' केवल एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि देशभर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक और आईपीपीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है।
- अपने प्रियजनों को पैसा भेजना (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर-डीएमटी), क्यूआरकोड को स्कैन कर विभिन्न सेवाओं के लिए दुकानदार को भुगतान करना (यूपीआई सुविधा और वर्चुअल डेबिट कार्ड), बायोमेट्रिक के माध्यम से नकदरहित व्यवस्था को सक्षम बनाना, किसी भी बैंक के ग्राहकों को अंतर-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना तथा जरूरी सेवाओं के बिलों का भुगतान जैसी तमाम सेवाओं का लाभ इस ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है।
- भारत के आम नागरिकों तक सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया था।

आईएफएससी ने प्रस्तावित एयरक्राफ्ट लीजिंग विनियमों पर परामर्श पत्र जारी किया (IFSCA issues consultation paper on proposed Aircraft Leasing Regulations)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारत 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। जनवरी 2019 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट 'परियोजना रुपया रफ्तार' प्रकाशित की थी, जिसमें भारत में एक विमान वित्तपोषण और पट्टे पर उद्योग विकसित करने का रोडमैप दिया गया था। इस रिपोर्ट ने देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग ईको-सिस्टम के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (जीआईएफटी सिटी) की पहचान की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में बजट भाषण में कहा था कि यह समय भारत के लिए विमान वित्तपोषण और भारतीय तटों से गतिविधियों को पट्टे पर देने का है।
- भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के अलावा, यह आत्मनिर्भर विमानन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और विमानन वित्त में रोजगार उपलब्ध कराता है।

- भारत सरकार ने 16 अक्टूबर, 2020 को आईएफएससीए की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत एयरक्राफ्ट लीज, जिसमें विमान या हेलीकॉप्टर के संचालन और विमान या हेलीकॉप्टर के इंजन या किसी भी हिस्से से संबंधित वित्तीय पट्टे भी शामिल हैं, को वित्तीय उत्पाद अधिसूचित किया था।
- एयरक्राफ्ट लीजिंग भारत में एक अपेक्षाकृत नया उद्योग है और एयरक्राफ्ट लीजिंग संबंधित नियम विभिन्न वित्तीय केंद्रों में भिन्न हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए हितधारकों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने को लेकर मसौदा नियम तैयार किए हैं।
- कई वैश्विक लीजिंग संस्थाओं ने भारत में आईएफएससीए में लीजिंग इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई है क्योंकि यह उन्हें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। घरेलू एयरलाइंस ने भी भारत में आईएफएससीए से इन लेन-देन को करने के लिए रुचि दिखाई है क्योंकि यह उन्हें वैश्विक पट्टाकार तक आसान पहुंच प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं

- IFSCA का उद्देश्य GIFT सिटी, गांधीनगर (गुजरात) में IFSC में एक विश्व स्तरीय FinTech हब विकसित करना है।
- इस प्रकार, यह बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और निधि प्रबंधन के क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वित्तीय तकनीकों (echn फिनटेक) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

संबंधित आलेख:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 अनुमोदित: [Click here](#)
- अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास पर IFSCA समिति की रिपोर्ट: [Click here](#)
- रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई: [Click here](#)

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की समीक्षा (National Hydrology Project reviewed)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (जल शक्ति मंत्रालय की विश्व बैंक समर्थित पहल) की समीक्षा जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा की गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) की शुरुआत वर्ष 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया गया था, जिसके तहत 8 वर्ष की अवधि में 3680 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ व्यय का प्रावधान किया गया था।

- इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत बनाना है। इस प्रकार एनएचपी कुशलतापूर्वक विश्वसनीय सूचना के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान कर रही है जिससे एक प्रभावी जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इस परियोजना की मध्यावधि के दौरान ही जल संसाधन निगरानी प्रणाली, जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस), जल संसाधन संचालन और नियोजन प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान को मंजूरी (Revised Cost Estimate of North Eastern Region Power System Improvement Project (NERPSIP) approved

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) की लागत के संशोधित अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दे दी।
- इसकी अनुमानित लागत 6,700 करोड़ रुपये है। अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक प्रमुख कदम है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह योजना विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) पावर ग्रिड के जरिए लागू की जाएगी। यह योजना पूर्वोत्तर के छह राज्यों – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा – के सहयोग से और उनके लाभ के लिए लागू की जाएगी जिसे दिसम्बर, 2021 में शुरू किए जाने का लक्ष्य है। योजना की शुरुआत के बाद इसे उत्तर-पूर्वी राज्य यूटिलिटीस द्वारा अपनाया जाएगा और वही इसका रखरखाव करेगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास और इस क्षेत्र में अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण संरचना को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है।
- इस योजना के लागू होने के बाद एक भरोसेमंद पावर ग्रिड बनाई जा सकेगी और पूर्वोत्तर राज्यों की भावी विद्युत भार केन्द्रों (लोड सेंटरों) तक संपर्क और पहुंच में सुधार होगा। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं तक ग्रिड के संपर्क से बिजली की पहुंच का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इस योजना से इन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में वृद्धि की जा सकेगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सकेगा।

- इस योजना को लागू करने के काम में शामिल एजेंसियां निर्माण के कार्य में स्थानीय मानव बल का इस्तेमाल करेंगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करेंगी।
- योजना के पूरा हो जाने के बाद इन नव-सृजित केन्द्रों के, उचित मापदंडों के अनुरूप परिचालन और रखरखाव के लिए भी काफी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिससे क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का विकास होगा।

क्या आप जानते हो ?

- यह परियोजना विद्युत मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत दिसम्बर, 2014 में पहली बार मंजूर की गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने योजना को विद्युत मंत्रालय के लिए बजट सहायता के तहत 50:50 प्रतिशत वहनीयता (50 प्रतिशत विश्व बैंक : 50 प्रतिशत भारत सरकार) के आधार पर शुरू किया है लेकिन इसमें क्षमता निर्माण पर होने वाला 89 करोड़ रुपये का खर्च पूरी तरह भारत सरकार उठाएगी

भारत सरकार और एनडीबी के बीच 100 करोड़ डॉलर का समझौता, इसके जरिए आत्म निर्भर अभियान के तहत मनरेगा स्कीम में वित्तीय सहयोग दिया जाएगा(Government of India and New Development Bank sign a loan agreement for \$1,000 million to provide support to Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan through MGNREGS)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच आज 100 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए समझौता हुआ है। इस राशि का इस्तेमाल ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा। जो कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत इस्तेमाल होगी। इन कदमों से कोविड-19 से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से उबरने में भी मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

समझौते से सरकार को कोविड-19 महामारी से हुए आर्थिक असर से उबरने में सहयोग मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रिकवरी भी तेजी से होगी।

1. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में सहयोग करेगा
2. इसके अलावा नए रोजगार के सृजन से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। इससे कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम के तहत एनआरएम से जुड़े टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत संसाधनों का भी विकास होगा। साथ ही गरीब तबके के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। खास तौर से उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जो कि कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी कमाई का जरिया शहरों में खो चुके हैं और अपने गांव वापस आ गए हैं।

क्या आप जानते हैं?

- एनडीबी का गठन, 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की सरकारों के मध्य हुए समझौते के तहत किया गया है।
- इस बैंक के गठन का उद्देश्य ब्रिक्स और दूसरे उभरते बजार, विकासशील देशों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
- जिसके जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास और दूसरे विकासपरक प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाया जा सके। एनडीबी ने 100 करोड़ डॉलर का कर्ज 30 साल के लिए दिया है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है।
- मुख्यालय: शंघाई, चीन।
- NDB का पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी (Proposal of Spectrum Auction approved)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। यह स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा। कुल 3,92,332.70 करोड़ रुपये (आरक्षित मूल्य पर) के मूल्य निर्धारण के साथ कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे, जबकि नया सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं शुरू करने में समर्थ होगा।
- इस नीलामी में बोलीदाताओं को मानदंडों/शर्तों यानी ब्लॉक साइज जिसमें बोलीदाता अपनी बोलियां प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे, स्पेक्ट्रम कैप यानी बोली की समाप्ति के बाद प्रत्येक बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली स्पेक्ट्रम की अधिकतम राशि, शुरू करने की बाध्यताएं, भुगतान शर्तों आदि का अनुपालन करना होगा।
- सफल बोलीदाताओं को पूरी बोली राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा या निश्चित राशि (प्राप्त किए गए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में 25 प्रतिशत या 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम के लिए 50 प्रतिशत) का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प चुना जाए और बकाया राशि का दो वर्ष के ऋण स्थगन के बाद अधिकतम 16 एकसमान वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा।
- बोली राशि के अलावा सफल बोलीदाता को इस बोली के माध्यम से प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के रूप में वायरलाइन सेवाओं के अलावा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की 3 प्रतिशत राशि का भी भुगतान करना होगा।
- स्पेक्ट्रम नीलामी सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम प्रदान करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया है। स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाती है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिये नए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (Cabinet Committee on Security approves the setting up of a new National Security Directive)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित नए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसका उद्देश्य दूरसंचार उत्पादों और उनके स्रोतों को 'विश्वसनीय' तथा 'गैर-विश्वसनीय' श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करना है।

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) को इसके लिये निर्दिष्ट प्राधिकरण नामित किया गया है और इसके द्वारा दूरसंचार उत्पादों को 'विश्वसनीय' तथा 'गैर-विश्वसनीय' के रूप में वर्गीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) द्वारा दूरसंचार पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अनुमोदन के आधार पर अपना निर्णय लिया जाएगा।
- इस समिति की अध्यक्षता उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy-NSA) द्वारा की जाएगी और इसमें अन्य विभागों तथा मंत्रालयों के सदस्यों एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ दूरसंचार उद्योग के दो सदस्य भी शामिल होंगे।
- निर्दिष्ट प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) द्वारा जिन स्रोतों को 'विश्वसनीय स्रोत' के रूप में नामित किया जाएगा, उनमें से जो भी दूरसंचार विभाग 'प्रेफरेंशियल मार्किट एक्सेस' पॉलिसी के मापदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें 'भारतीय विश्वसनीय स्रोत' के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
- यह नीति दूरसंचार क्षेत्र में उपकरण और हैंडसेट के स्थानीय निर्माताओं को अन्य देशों के विनिर्माताओं से मुकाबला करने का अवसर प्रदान करेगी।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के लिये 'विश्वसनीय' उत्पाद के रूप में नामित उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा।

भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा जारी किया (Indian Railways issues draft National Rail Plan)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने और देश के माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में अपनी औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के प्रयास के तहत, भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा पेश किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य 2030 तक ऐसी क्षमता का निर्माण करना है, जो मांग से अधिक रहे तथा 2050 तक की मांग में वृद्धि संबंधी जरूरतों को पूरा करे। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के एक अंग के रूप में 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी वर्तमान के 27% से बढ़ाकर 45% करना है।
- माल ढुलाई और यात्री क्षेत्रों में वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए, पूरे देश में सर्वेक्षण टीमों द्वारा पूरे साल के दौरान सौ से अधिक प्रतिनिधि स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया।

- माल ढुलाई और यात्री, दोनों क्षेत्रों में 2030 तक वार्षिक आधार पर और वर्ष 2050 तक दशकीय आधार पर यातायात में वृद्धि का पूर्वानुमान करना।
- 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहलों पर आधारित रणनीति तैयार करना।
- मालगाड़ियों की औसत गति को वर्तमान के 22 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा करके माल ढुलाई के समय में कमी लाना।
- रेल परिवहन की कुल लागत को लगभग 30% कम करना और उससे अर्जित लाभों को ग्राहकों को हस्तांतरित करना।
- भारतीय रेल मार्ग के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में मांग में वृद्धि का आकलन करना और भविष्य में नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करना।
- उपरोक्त अनुरूपता के आधार पर उन अवसंरचनात्मक अड़चनों की पहचान करना, जो भविष्य में मांग में वृद्धि के साथ उत्पन्न होंगी।
- इन अड़चनों को समय रहते दूर करने के लिए ट्रैक कार्य, सिग्नलिंग और रोलिंग स्टॉक में उपयुक्त तकनीक के साथ परियोजनाओं का चयन करना।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय रेल योजना के एक अंग के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रैकिंग, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर गति को 160 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बढ़ाना, अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्णिम विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर गति का 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नयन और सभी जीक्यू/जीडी मार्गों पर सभी स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त करना आदि, के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विज़न 2024 शुरू किया गया है।

परिवहन मंत्रालय ने ई 20 ईंधन को अपनाने के संदर्भ में जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की (Government publishes a draft notification on E20 Fuel)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 दिसंबर, 2020 को मसौदा अधिसूचना प्रकाशित कर 'ई20 ईंधन' (E20 fuel) और इस ईंधन के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अपनाए जाने पर जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'ई20 ईंधन' के अंतर्गत गैसोलीन में 20% एथेनॉल को मिलाकर आटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह अधिसूचना ई20 के अनुरूप वाहन विकसित किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जन में भी कमी करने में सहायक होगा साथ ही साथ इससे खनिज तेलों के आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन उपयोग योग्य वाहनों में गैसोलीन में एथेनॉल के प्रतिशत संबंधी विवरण वाहन निर्माता द्वारा दिया जाएगा और इस संबंध में वाहन पर एक स्पष्ट दिखाई देने वाला स्टीकर प्रदर्शित किया जाएगा।

जीपीएस आधारित टोल संग्रहण व्यवस्था (GPS-Based Toll Collection System)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने देश भर में वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए टोल संग्रहण हेतु जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) को लागू किए जाने को अंतिम रूप दे दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इससे भारत को अगले दो वर्षों में टोल बूथ मुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- टोल के लिए वसूला जाने वाला शुल्क वाहनों के परिचालन के आधार पर सीधे बैंक खातों से लिया जाएगा।
- अब सभी वाणिज्यिक वाहनों में पहले से ही वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लग कर आ रही है, पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाने के लिए सरकार जल्द ही कोई योजना लेकर आएगी।
- आगामी मार्च तक टोल संग्रहण 34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। टोल संग्रहण के लिए जीपीएस तकनीक के इस्तेमाल से आगामी 5 वर्षों में टोल से होने वाली आय बढ़ते हुए 1,34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।

सम्बंधित लेख:

- About FASTag: [Click here](#)

तटीय रडार चेन नेटवर्क स्थापित करने के लिए उन्नत चरणों में प्रयास(Efforts in advanced stages to set up Coastal Radar Chain Network)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश के हिंद महासागर के तटीय राज्यों में तटीय राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रयास उन्नत चरण में हैं।
- **उद्देश्य:** खतरों के लिए उच्च समुद्रों की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने के लिए तटीय राडार श्रृंखला नेटवर्क का और विस्तार करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका को पहले ही देश के तटीय राडार श्रृंखला नेटवर्क में एकीकृत किया जा चुका है।
- इसी तरह की योजनाएं मालदीव और म्यांमार के साथ पाइपलाइन में हैं और बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ चर्चा चल रही है।
- तटीय राडार श्रृंखला नेटवर्क के चरण- I के तहत, देश के समुद्र तट पर 46 तटीय राडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- परियोजना के दूसरे चरण के तहत, जो वर्तमान में चल रहा है, 38 स्थिर राडार स्टेशन और चार मोबाइल राडार स्टेशन तटारक्षक द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं और पूरा होने के उन्नत चरण में हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

अन्य घटनाक्रम

- गुरुग्राम में स्थित भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC), जो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था, समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है।
- उच्च समुद्रों पर यातायात के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में, नौसेना को 36 देशों और तीन बहुपक्षीय निर्माणों के साथ सफेद शिपिंग समझौतों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।
- अब तक 22 देशों और एक बहुपक्षीय निर्माण के साथ समझौते संपन्न हुए हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र के लिए नौसेना के सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) पर जो समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है, तीन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी (ILO) के जल्द ही शामिल होने की उम्मीद है।
- फ्रांस, जापान और अमेरिका के ILO केंद्र में शामिल हो गए हैं।

भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की परियोजना पर हस्ताक्षर किए ((India and World Bank sign USD 500 million worth project for Green National Highway Corridors))

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य योजना

- इस परियोजना से हरित और सुरक्षित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की क्षमता का भी विस्तार होगा।
- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों जैसे स्थानीय और उप-मानक सामग्री, औद्योगिक उपोत्पाद (बाइप्रोडक्ट) और अन्य बायोइंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के जरिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किमी राजमार्ग का निर्माण करने में MORTC का सहयोग करेगी। यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
- अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से 500 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि पांच साल की रियायत के साथ 18.5 साल है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

पुनर्निर्माण और विकास के लिए इंटरनेशनल बैंक (IBRD)

- यह एक अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है।
- इसे 1944 में स्थापित किया गया
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डीसी, यूएसए
- यह विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा है।
- यह मध्यम-आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है।
- यह विश्व बैंक समूह की रचना करने वाले पाँच सदस्यीय संस्थानों में से प्रथम है।
- IBRD और इसके रियायती ऋण, अंतराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे समान नेतृत्व और कर्मचारियों को साझा करते हैं।

बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उत्पाद विशेष माल गोदाम/साइलो होंगे (Products Specific Warehouses/Silos to come up at Ports and National Waterways)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का विभिन्न बंदरगाहों (जिनमें मेजर और नॉन-मेजर बंदरगाह दोनों शामिल हैं) पर उत्पाद विशेष माल गोदाम/ साइलो, बंदरगाह क्षेत्र के नजदीक और राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का इरादा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस बुनियादी सुविधा के विकास का उद्देश्य भंडारण के नुकसान को कम करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और समुद्र तट क्षेत्र में कार्गो के वितरण को सुविधाजनक बनाना है।
- एमओपीएसडब्ल्यू, सीमेंट साइलो, लिक्विड टैंक, केमिकल्स टैंक, कोल्ड / रेफ्रिजरेटेड भंडार, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद भंडार, फार्मास्युटिकल भंडार, वाहनों के कलपुर्जों और पुर्जों के भंडार या किसी अन्य सुझाए गए उत्पादों के लिए बंदरगाहों पर विशेष वेयरहाउस / साइलो विकसित करने का लक्ष्य बना रहा है।
- जबकि बड़े उद्योगपतियों के पास अपना माल गोदाम और भंडारण स्थान होता है, छोटे प्रतिस्पर्धियों को विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पादों के विशेष माल गोदाम साइलो प्राप्त करना मुश्किल होता है। विश्व स्तर के इन माल गोदामों के विकास से, विशेष रूप से ऐसे छोटे लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए बेहतर योजना बनाने और माल सूची प्रबंधन के साथ कारोबार करना सरल होगा। छोटे प्रतिस्पर्धियों के पास विश्व स्तर की इस बुनियादी सुविधा का उपयोग करने के लिए नाममात्र का शुल्क भुगतान करने का विकल्प होगा। इस विकल्प से उन्हें बहुत लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में उनके माल से भरे ट्रक बंदरगाहों के नजदीक उचित भंडारण खोजने के लिए अक्सर प्रतीक्षा करते रहते हैं। बदले में, यह पारंपरिक वेयरहाउसिंग की तुलना में नुकसान को कम करेगा और अधिक मजबूत तथा लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- मंत्रालय का उद्देश्य महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उपयुक्त बुनियादी ढांचे के हस्तक्षेप के साथ लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, जिसे 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
- यह भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और जहाजों के चलने योग्य ~ 21000 किमी. जलमार्गों की संभावना का पता लगाकर देश में बंदरगाह की मुख्य भूमिका के साथ विकास को बढ़ावा देने का मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है।

भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो (India's First Driverless Metro to be inaugurated)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की लाइन-8 यानी मैजेंटा लाइन पर देश की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल (ड्राइवर-रहित मेट्रो) का उद्घाटन किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCCMC) का विस्तार किया है।
- इस उपलब्धि के साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) विश्व के उस अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गया है, जहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है।
- वर्ष 2014 में देश के केवल पाँच शहरों में मेट्रो रेल थी और वर्तमान में देश के कुल 18 शहरों में मेट्रो रेल मौजूद है और इसी के साथ मेट्रो उपयोगकर्ताओं की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है।
- दिल्ली मेट्रो की ड्राइवर-रहित मेट्रो रेल पूर्णतः स्वचालित होगी, जिससे मानव त्रुटि की संभावना समाप्त हो जाएगी।

असम में 27 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन (Foundation stone for highway projects in Assam inaugurated)

भाग : GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इन परियोजनाओं में लगभग 429 किलोमीटर की लंबाई की, 2,366 करोड़ रुपये की निर्माण लागत के साथ, एक सड़क भी शामिल है। इन सड़कों से पूरे राज्य में व्यवसायिक वस्तुओं की दुलाई आसान होगी, सीमाओं से संपर्क सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, समय और ईंधन की बचत होगी, पर्यटन में सुधार आएगा और ढांचागत विकास होगा, और इन सबसे कृषि उत्पादों के लिए बड़े बाजार तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण की घोषणा। यह जोगीगोपा के बाद असम में बनने वाला दूसरा एमएमएलपी होगा।
- इसके जरिए विकसित सड़क और जलमार्ग संपर्क लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
- मंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुबरी-फुलबाड़ी पुल का निर्माण अगले महीने में शुरू हो जाएगा।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का उद्घाटन(National Common Mobility Card (NCMC) inaugurated)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS- III- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उद्घाटन किया,
- यह कार्ड सेवा 2019 में अहमदाबाद में शुरू की गई थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक कार्ड यात्रियों को जहां भी वे ले जाते हैं, जो भी यात्रा करते हैं, उन्हें एकीकृत पहुंच प्रदान करेगा।
- NCMC का विचार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा जारी किया गया था।
- एनसीएमसी रुपये डेबिट कार्ड वाले यात्रियों को पिछले 18 महीनों में 23 बैंकों द्वारा मेट्रो यात्रा के लिए स्वाइप करने की अनुमति देगा।
- यह सुविधा 2022 तक पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी।
- NCMC एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली है।
- यह स्मार्टफोन को एक अंतर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड में बदल देगा जिसका उपयोग यात्री मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं।

- यह एक स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों से प्रवेश और निकास की अनुमति देगा, जिसे स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

वन नेशन, वन सिस्टम उदाहरण है

- वन नेशन, वन फास्टैग ने देश भर के राजमार्गों पर यात्रा को सहज बना दिया है।
- वन नेशन, वन टैक्स: जीएसटी ने कर प्रणाली में जटिलताओं को समाप्त कर दिया है और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकरूपता ला दी है।
- वन नेशन, वन पावर ग्रिड, देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।
- वन नेशन, वन गैस ग्रिड, निर्बाध गैस कनेक्टिविटी के साथ उन हिस्सों को सुनिश्चित किया जा रहा है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था अनुपस्थित थी।
- वन नेशन, वन हेल्थ इश्योरेंस स्कीम, यानी आयुष्मान भारत जिसके माध्यम से भारत के लाखों लोग देश में कहीं भी लाभ ले रहे हैं।
- एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले नागरिकों को वन नेशन, वन राशन कार्ड के माध्यम से नए राशन कार्ड बनाने की परेशानी से मुक्ति मिली है।
- इसी तरह, देश नए कृषि सुधारों और ई-एनएएम जैसी व्यवस्थाओं के कारण वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जैव ईंधन कैसे कृषि आय को दोगुना कर सकती हैं(How biofuels can double farm incomes)

संदर्भ:

- भारत वर्तमान में ऊर्जा की वैश्विक औसत खपत का केवल एक तिहाई उपभोग करता है। इसके अलावा, भारत तेल का लगभग 84% और घरेलू उपयोग के लिए गैस का 56% आयात करता है।
- जैसा कि हम अधिक मजबूत ऊर्जा खपत के आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, देश को निम्नलिखित की अनूठी चुनौती का सामना करना पड़ता है
 - आयात पर निर्भरता में कटौती
 - सामर्थ्य सुनिश्चित करते हुए ग्रिड का उपयोग
 - रोजगार को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा उत्पादन के पुराने रूपों को बदलना
 - लोगों की मानवीय और आर्थिक पूंजी में सुधार।
- उपरोक्त संदर्भ में, जैव ईंधन परिणामों के इन नाजुक संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण बन गया है।

1. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

- **योजना का उद्देश्य:** उद्देश्य 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करना है - कुछ ऐसा जो वाहनों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा।
- **इथेनॉल उत्पादन के लिए स्रोत:** भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना और उसके उप-उत्पाद हैं, जो केंद्र सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत 90% से अधिक ईंधन इथेनॉल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। गन्ने के अलावा, क्षतिग्रस्त अनाज, बी-हैवी गुड़ और गन्ने के रस से भी इथेनॉल का उत्पादन होता है।
- **लाभ चीनी उद्योग:** ईबीपी कार्यक्रम तनावग्रस्त चीनी क्षेत्र में तरलता को इंजेक्ट करता है। इस कार्यक्रम से इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की पैदावार को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चीनी की कमी होती है।
- **किसानों की आय दोगुनी करने में मदद:** ईबीपी योजना किसानों को एक वैकल्पिक राजस्व धारा प्रदान करती है। पिछले छह वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ रुपये की राशि चीनी मिलों और डिस्टिलरी के माध्यम से किसानों को वापस भेज दी गई है क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) निर्धारित कीमतों पर ऑफ-टेक गारंटी प्रदान करती हैं।
- **किसानों के लिए भुगतान चक्र में सुधार:** निर्धारित मूल्य पर ऑफ-टेक गारंटी प्रदान करने वाली ओएमसी की व्यवस्था भी किसानों को भुगतान चक्र के स्वास्थ्य में सुधार करती है क्योंकि ओएमसी ने महीनों के बजाय 21 दिनों में अपने इथेनॉल के बकाया को भट्टियों में व्यवस्थित कर दिया है, जिससे किसानों को इंतजार करना पड़ा चीनी मिलों से उनके भुगतान के लिए।
- **चावल के उत्पादन के लिए वैकल्पिक बाजार:** भारतीय खाद्य निगम और मक्का के साथ उपलब्ध अधिशेष चावल के उपयोग का हालिया निर्णय, इस साल से शुरू होने वाले इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में है, जिसका अर्थ है कि किसानों के पास अब अपनी उपज के लिए एक वैकल्पिक बाजार होगा।
- **बढ़ा हुआ उत्पादन भारत को सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है:** इथेनॉल की आपूर्ति 2013-14 में 380 मिलियन लीटर से बढ़कर 2019 में 1.89 बिलियन लीटर हो गई है। चीनी / गुड़ और अनाज आधारित भट्टियों से 2020 में लगभग 3.5 बिलियन लीटर के पेशकश की उम्मीद है।
- **दृढ़ संकल्प:** 2019 में, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए पहली बार, भारतीय वायु सेना ने विमान उड़ाया, जिसमें मुख्य ईंधन पारंपरिक ईंधन और जैव ईंधन के मिश्रण का उपयोग करके, ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था।

2. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति

- **उद्देश्य:** 2021 में तैयार की गई नीति 2030 तक डीजल में बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखती है।
- **स्रोत:** नीति गैर-खाद्य तिलहनों से जैव-डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, खाना पकाने के तेल और शॉर्ट-जेस्चर फसलों का उपयोग किया जाता है।
- **बेहतर भूमि उपयोग और किसान की आय में वृद्धि:** इन फसलों को विभिन्न राज्यों में आसानी से खेती की जा सकती है जो बंजर है या खाद्य फसलों के लिए फिट नहीं है, इस प्रकार कुशल भूमि उपयोग और खेत की आय को बढ़ावा मिलता है।
- **बढ़ी हुई किसान आय:** सम्मिश्रण के लिए निकट भविष्य में हर साल कुल 1 लाख करोड़ रुपये के जैव ईंधन की खरीद ओएमसी द्वारा की जाएगी। इस पैसे को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वापस रखा जाएगा, इस प्रकार किसानों की आय दोगुनी की जाएगी।
- **बढ़ा हुआ उत्पादन भारत को सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है:** उच्च गति के डीजल के सम्मिश्रण के लिए OMCs द्वारा खरीदी गई बायोडीजल 2015-16 में 11.9 मिलियन लीटर से बढ़कर पिछले वर्ष 105.5 मिलियन लीटर हो गई है।

3. स्थायी वैकल्पिक वहन योग्य परिवहन (SATAT)

- **उद्देश्य:** अक्टूबर 2018 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य देश में विभिन्न अपशिष्ट बायोमास स्रोतों से संपीड़ित बायोगैस (CBG) के उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- **SATAT के तहत:** 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की कुल उत्पादन क्षमता वाले 5000 CBG प्लांट, जो 2023 तक 54 MMSCMD गैस के बराबर है, की योजना बनाई गई है।
- **निवेश क्षमता:** यह पहल लगभग 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए, लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता प्रदान करती है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** SATAT योजना से न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होगा, बल्कि कृषि अवशेषों को जलाने में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली जैसे शहरों में महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण होगा।
- **किसान की आय में वृद्धि :** CBG पौधों के उपोत्पादों में से एक बायोमेन्योर है, जिसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। यह योजना ग्रामीण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में भी रोजगार पैदा करती है, और किसानों को उनके अनुपयोगी जैविक कचरे से आय बढ़ाती है।

निष्कर्ष

- जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के घटक एक परिपत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुदायों में पर्याप्त पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

Connecting the dots

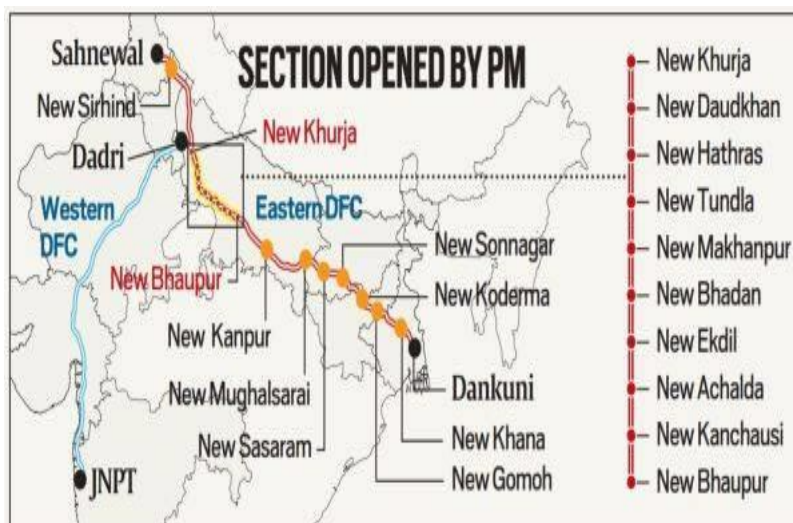
- पेरिस जलवायु समझौता
- भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के 'न्यू भाऊपुर- न्यू खुरजा सेक्शन' का उद्घाटन(New Bhaupur-New Khurja Section of Eastern Dedicated Freight Corridor)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश (यूपी) में पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के महत्वाकांक्षी न्यू भूपुर-न्यू खुरजा खंड को राष्ट्र को समर्पित किया।



महत्वपूर्ण बिंदु

- 351 किलोमीटर का न्यू भूपुर- ईडीएफसी का नया खुर्जा खंड रुपये की लागत से बनाया गया है। 5,750 करोड़ और इसका अधिकांश हिस्सा यूपी से गुजरता है।
- यह खंड मौजूदा कानपुर-दिल्ली मुख्य लाइन को हटा देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनों चलाने में सक्षम करेगा।
- यूपी के कृषि उत्पाद अब देश के अन्य हिस्सों में तेज गति से पहुंचेंगे।
- यह राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाएगा जो कि एक भू-भाग क्षेत्र है और इसमें विदेश भेजने के लिए कोई बंदरगाह नहीं है।

क्या आप जानते हैं?

- प्रधान मंत्री ने यूपी के प्रयागराज में पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया।
- यह EDFC की संपूर्ण रूट लंबाई के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा।
- ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर उन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जो स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई हैं।

प्रधानमंत्री ने छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) की आधारशिला रखी PM to lay Foundation Stone of Light House Projects under GHTC-India

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत छह राज्यों में छह स्थानों पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) की आधारशिला रखी।
- उन्होंने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स- इंडिया (आशा- इंडिया) के तहत विजेताओं की घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार दिए।

- उन्होंने एनएवीएआरआईटीआईएच (भारतीय आवास के लिए नवीन, सस्ती, विधिमान्य, अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी) नाम के नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम भी जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और नवीन प्रक्रियाओं से बने होंगे और निर्माण के समय को कम करेंगे और गरीबों के लिए अधिक लचीले, किफायती और आरामदायक घर बनाएंगे।
- इन लाइट हाउसों में निर्माण प्रौद्योगिकी में नवाचार हैं।
- उदाहरण के लिए इंदौर में परियोजना में ईंट और मोर्टार दीवारों नहीं होंगी, इसके बजाय वे पूर्वनिर्मित सैंडविच पैनल प्रणाली का उपयोग करेंगे।
- राजकोट में लाइट हाउसों को फ्रेंच तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा और सुरंग का उपयोग करके एक पत्थर की ठोस निर्माण तकनीक होगी। ये घर आपदाओं को झेलने में अधिक समर्थ होंगे।
- चेन्नई में, यूएस और फिनलैंड की प्रौद्योगिकियां प्रीकास्ट कंक्रीट प्रणाली का उपयोग करेंगी, जिससे घर का निर्माण तेजी से और सस्ता होगा।
- जर्मनी की 3 डी निर्माण प्रणाली का उपयोग करके रांची में मकान बनाए जाएंगे। प्रत्येक कमरे को अलग से बनाया जाएगा और फिर पूरी संरचना को उसी तरह से जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक के खिलौनों को जोड़ा जाता है।
- अगरतला में स्टील के फ्रेमों के साथ न्यूजीलैंड की तकनीक का उपयोग करते हुए मकान बनाए जा रहे हैं जो भूकंप के बड़े जोखिम को झेल सकते हैं।
- कनाडा की प्रौद्योगिकी का उपयोग लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टर और पेंट की आवश्यकता नहीं होगी और तेजी से मकान बनाने के लिए पहले से तैयार की गई पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा।
- प्रत्येक स्थान पर 12 महीनों में हजारों घर बनाए जाएंगे जो इंक्यूबेशन केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे योजनाकार, वास्तुकार, इंजीनियर और छात्र नई तकनीक के साथ अध्ययन और प्रयोग कर सकेंगे।
- इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र में नई तकनीक से संबंधित कौशल उन्नयन के लिए लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को घर के निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और सामग्री मिल सके।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

किफायती स्थायी आवास त्वरक - भारत (ASHA- भारत) (Affordable Sustainable Housing Accelerators – India- ASHA-India))

- इसका लक्ष्य संभावित भावी प्रौद्योगिकियों को ऊष्मायन और त्वरण सहायता प्रदान करके घरेलू अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- आशा-भारत पहल के तहत, ऊष्मायन और त्वरण सहायता प्रदान करने के लिए पांच आशा-भारत केंद्र स्थापित किए गए हैं।

PMAY- U मिशन

- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) मिशन “2022 तक सभी के लिए आवास” को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान को पहचानने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएमएवाई-शहरी के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार पेश किए हैं।

बिजली के वाहन (Electric Vehicles)

मुद्दे

- भारत में कुल कार बिक्री के प्रतिशत के रूप में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री लगभग 0.2% से कम है।
- इलेक्ट्रिक स्कूटर कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री का 0.4% पर थोड़ा बेहतर किराया - इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 5% तक कम करने, आयकर लाभ और सड़क कर माफ करने जैसे प्रोत्साहनों के बावजूद एक चिंताजनक संकेत।
- भारत में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन हैं।
- सबसे बड़ी चुनौती इन चार्ज स्टेशनों पर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता है, खासकर राजमार्गों के साथ।

आगे का रास्ता

- ईवी उत्थान को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को 2025 तक ईवी के लिए हाईवे टोल शुल्क माफ करने पर विचार करना चाहिए।
- ईवी खरीदारों के लिए कार निर्माताओं और खरीद मूल्य सब्सिडी पर विचार करना चाहिए।
- भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक, सालाना बेची जाने वाली 30% कारें ईवी होनी चाहिए। लेकिन इस लक्ष्य को महसूस करने के लिए, खरीदार, सरकार और उद्योग को अपने-अपने हिस्से को प्रभावी ढंग से निभाने की जरूरत है।
- सरकार को पीपीपी मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार पर आक्रामक तरीके से काम करना चाहिए।
- सरकार को सौर-आधारित चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
- भारत को इंडक्शन चार्ज जैसी वैकल्पिक तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है।
- राजमार्ग, पार्किंग स्थल इत्यादि के लिए एक किफायती जन-बाजार समाधान बनाने पर कोई भी शोध भारत के ईवी बाजार में क्रांति लाएगा। अनुसंधान के लिए एक अन्य क्षेत्र ईवीएस के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में सॉलिड स्टेट बैटरी विकसित करने पर है।
- FAME (फास्टर अडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और EV) स्कीम सही दिशा में एक कदम है, जबकि सरकार को ईवी मैनुफैक्चरिंग और कंपोनेंट्स स्पेस में भारत का अग्रणी खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम बनाना होगा।

विज्ञान और तकनीक (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

CSIR-CCMB को ड्राई स्वेब RT-PCR कोविड -19 टेस्ट की अनुमति मिली (CSIR-CCMB gets permission for Dry Swab RT-PCR Covid-19 Test)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II- स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- हाल ही में,
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सीएसआइआर-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology) द्वारा विकसित कोरोना वायरस के लिए एक ड्राई स्वेब RNA- एक्सट्रैक्शन (dry swab RNA- extraction) की पद्धति का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- ड्राई स्वेब विधि में 96.9% की स्थिरता है।
- एक साधारण बफर समाधान में सीधे सुखाए गए सूखे स्वेब सार्क-सीओवी -2 की आणविक पहचान का समर्थन कर सकते हैं, जो बिना किसी समझौता किए संवेदनशीलता के साथ समापन बिंदु आरटी-पीसीआर के माध्यम से किया जा सकता है।
- ड्राई स्वेब तकनीक को वीटीएम और आरएनए निष्कर्षण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
- सीसीएमबी द्वारा विकसित की गयी यह जांच पद्धति, कोरोना के सबसे सटीक और मानक माने जाने वाली आरटी-पीसीआर परीक्षण विधि का सरल रूपांतरण है। ड्राई स्वाब पद्धति पारम्परिक आरटी- पीसीआर जांच के मुकाबले कहीं अधिक किफायती और शीघ्रता से परिणाम देने वाली जांच है।
- इसका उपयोग सीधे RT-PCR परीक्षण के लिए किया जा सकता है।
- इसमें परीक्षण की लागत और समय को 40-50% तक नीचे लाने की क्षमता है।
- स्क्रीनिंग को तत्काल प्रभाव से कई गुना बढ़ाया जा सकता है
- पूरी प्रक्रिया भी सुरक्षित है।
- नई किट की आवश्यकता के बिना इसे लागू करना आसान है।
- मौजूदा जनशक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के यह प्रदर्शन कर सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

RT-PCR टेस्ट

- अमेरिकी बायोकैमिस्ट Kary Mullis ने पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था।
- उन्हें 1993 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- परीक्षण के तहत, पॉलिमर के एक एंजाइम का उपयोग करके डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) के एक खंड की प्रतियां बनाई जाती हैं।
- 'चेन रिएक्शन' दर्शाता है कि डीएनए के टुकड़े कैसे तेजी से कॉपी किए जाते हैं, जहां एक को दो में कॉपी किया जाता है, दो को चार में कॉपी किया जाता है, और इसी तरह।
- "जांच" नामक एक फ्लोरोसेंट डीएनए बाइंडिंग डाई को डीएनए में जोड़ा जाता है, जो एक फ्लोरोमीटर पर वायरस की उपस्थिति को दर्शाता है।
- कोविड -19 आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड) से बना है।
- इसका पता लगाने के लिए, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक तकनीक का उपयोग करके डीएनए में परिवर्तित हो जाता है।
- डीएनए की प्रतियां तब बनाई और बढ़ाई जाती हैं।

C32-LH2 टैंक: सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को दिया गया (C32-LH2 Tank: Biggest cryogenic propellant tank delivered to ISRO)

भाग:GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस निर्माण कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C32-LH2 दिया।



महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- C32-LH2 टैंक एल्यूमीनियम मिश्र धातु का एक विकासात्मक क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है।
- इसे इसरो के लॉन्चिंग वाहन GSLV MK-III की पेलोड क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है।
- टैंक 5755 किलोग्राम प्रणोदक ईंधन लोड कर सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

क्रायोजेनिक ईंधन

- क्रायोजेनिक ईंधन वे ईंधन हैं जिन्हें तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए बेहद कम तापमान पर भंडारण की आवश्यकता होती है।
- इन ईंधनों का उपयोग अंतरिक्ष में काम करने वाली मशीनरी में किया जाता है क्योंकि साधारण ईंधन का उपयोग अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान के कारण अक्सर नहीं किया जा सकता है, और दहन का समर्थन करने वाले वातावरण की अनुपस्थिति के कारण होता है।
- क्रायोजेनिक ईंधन अक्सर तरल हाइड्रोजन जैसे तरलीकृत गैसों का गठन करते हैं।

अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्न ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के लिए आवेदन किया (US drugmaker

Moderna applies for Emergency Use Authorisation -EUA)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्न ने कहा कि वह कोविड -19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के एक संस्करण का परीक्षण कर रहा है, ने कहा है कि यह अगले दो हफ्तों के भीतर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के पास आवेदन करने की उम्मीद करते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- टीके, दवाइयां, नैदानिक परीक्षण और चिकित्सा उपकरण, को एक नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है इससे पहले कि वे प्रशासित हो सकें।
- भारत में, एक नियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) है।
- टीकों और दवाओं के लिए, परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता के आकलन के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

- यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक दवा या टीका बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी है।
- आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि COVID-19, दुनिया भर के नियामक अधिकारियों ने अंतरिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है यदि एक चिकित्सा उत्पाद के पास सुरक्षित और प्रभावी होने का सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तो वह आवेदन कर सकता है।
- परीक्षण और पूर्ण डेटा के विश्लेषण के पूरा होने के बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाती है; तब तक, आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) दवा या वैक्सीन को जनता पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।

‘डमरू’इंस्पायर्ड लैटिस (Damaru’ Inspired Lattice)

भाग: GS ग्रीलिम्स और GS- I- संस्कृति और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने डमरू ‘इंस्पायर्ड लैटिस’ विकसित किया है, जिसका छुपी हुई पनडुब्बियों और उच्च गति वाली ट्रेन में कंपन अलगाव के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग हैं।
- **प्रायोजित:** यह शिक्षा मंत्रालय की एक स्पार्क परियोजना।



अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- लैटिस में एक माइक्रो-संरचित घंटे-कांच के आकार का मेटा-संरचना के उपयोग के साथ, एक प्रचार और स्टॉप बैंड की व्यापक विविधता प्राप्त कर सकता है।
- जाली की प्रेरणा 'डमरू' नामक दो सिर वाले ड्रम से आई है या जिसका उपयोग प्राचीन हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म में किया जाता है।
- यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस संगीत वाद्ययंत्र के माध्यम से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न की है और ब्रह्मांड को विनियमित किया था।
- इस आवेदन में, शोधकर्ताओं ने यह भी दिखाया है कि नियमित रूप से मधुकोश से सुक्ष्म छत्ते की संरचना में जाली सूक्ष्म संरचना को नियंत्रित करके एक कंपन माध्यम की कठोरता की प्रकृति में भारी बदलाव किया जा सकता है।
- इसमें उच्च गति वाली ट्रेनों, स्टील्थ पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर रोटार में कंपन अलगाव के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग हैं।

आर्टपार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया (Artpark set up in Bengaluru)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- हाल ही में बेंगलुरु में एक AI & Robotics Technologies Park (ARTPARK) स्थापित किया गया था।
- यह महत्वाकांक्षी मिशन मोड आर एंड डी परियोजनाओं को निष्पादित करके एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकीय नवाचारों को बढ़ावा देगा, जो सामाजिक प्रभाव के लिए अग्रणी होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- ARTPARK, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक अद्वितीय नॉट-फॉर-प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो एक सार्वजनिक-निजी मॉडल में AI फाउंड्री को समर्थन प्रदान करता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), सरकार सरकार, अंतर-अनुशासनिक साइबर-भौतिक प्रणालियों (NM-ICPS) पर राष्ट्रीय मिशन के तहत इसने 170 Cr (\$ 22mn) वित्त पोषण प्राप्त किया।
- यह उद्योग, शिक्षा और सरकारी निकायों के भागीदारों के सहयोगी को एक साथ लाएगा।
- ARTPARK DataSetu को विकसित करेगा - जो गोपनीयता और निजता-संरक्षण ढांचे को डेटा साझा करने और डेटा-साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को फैलाने वाले एनालिटिक्स को चलाने और AI अनुप्रयोगों और समाधानों को बढ़ाने के लिए डेटा बाजार बनाने में सक्षम करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

अंतर-अनुशासनात्मक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS)

- कार्यान्वित: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- अवधि: पांच साल
- NM-ICPS में पूरे भारत को शामिल किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, उद्योग और अकादमिक शामिल हैं।
- यह साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) और संबंधित तकनीकों में प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग विकास, मानव संसाधन विकास और कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप विकास को संबोधित करेगा।
- **उद्देश्य:** 15 प्रौद्योगिकी नवाचार हब (TIH), छह अनुप्रयोग नवाचार हब (AIH) और चार प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क (TTRP) की स्थापना।
- **चार केंद्रित क्षेत्र:** (1) प्रौद्योगिकी विकास; (2) एचआरडी और कौशल विकास; (3) नवाचार, उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकास; (4) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (ASKAP) लाखों आकाशगंगाओं का मानचित्र बनाता है (Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) maps millions of galaxies)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- अंतरिक्ष; विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (ASKAP) ने हाल ही में अपने पहले ऑल-स्काई सर्वेक्षण के दौरान रिकॉर्ड 300 घंटों में तीन मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं का मानचित्रण किया है।
- ASKAP ऑस्ट्रेलिया की विज्ञान एजेंसी CSIRO द्वारा विकसित और संचालित एक शक्तिशाली दूरबीन है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- ASKAP वर्तमान में 2021 से बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को शुरू करने से पहले आकाशगंगाओं का पायलट सर्वेक्षण कर रहा है।
- ASKAP सर्वेक्षण ब्राह्मण की संरचना और विकास को मैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि यह आकाशगंगाओं और हाइड्रोजन गैस को देखकर मानचित्र तैयार करता है।
- इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका विस्तृत क्षेत्र है।
- यह आकाश के नयनाभिराम चित्रों को बड़े विस्तार से लेने में सक्षम रहा है।
- टेलीस्कोप में उच्च सर्वेक्षण गति प्राप्त करने के लिए एक "रेडियो कैमरा" तकनीक का उपयोग करता है और इसमें 36 डिश एंटेना होते हैं, जो प्रत्येक 12 मीटर व्यास के होते हैं।
- ASKAP टेलीस्कोप द्वारा लिया गया वर्तमान रैपिड ASKAP कॉन्टिनुम सर्वे (RACS) ब्रह्मांड के "Google मानचित्र" की तरह है, जहाँ लाखों-करोड़ों स्टार-पॉइंट्स में से अधिकांश दूर की आकाशगंगाएँ हैं, जिनमें से लगभग कई मिलियन पहले नहीं देखी गई हैं।

HL-2M टोकामक: चीन का कृत्रिम सूर्य (HL-2M Tokamak: The Artificial Sun of China)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- चीन ने पहली बार अपने "कृत्रिम सूर्य" परमाणु संलयन रिएक्टर को देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में एक महान उन्नति के लिए सफलतापूर्वक संचालित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- HL-2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है।
- **मिशन का नाम:** प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व)।
- **स्थान:** सिचुआन प्रांत
- रिएक्टर को अक्सर प्रचंड गर्मी और शक्ति के कारण "कृत्रिम सूर्य" कहा जाता है।
- यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है और 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान तक पहुंच सकता है जो सूर्य की कोर से लगभग दस गुना अधिक गर्म है।
- वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि डिवाइस एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को संभावित रूप को अनलॉक कर सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- परमाणु संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिकों को एक या एक से अधिक विभिन्न परमाणु नाभिक और उप-परमाणु कणों (न्यूट्रॉन या प्रोटॉन) के रूप में संयोजित किया जाता है।
- संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य और अन्य तारे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करते हैं।
- यह एक परमाणु प्रक्रिया है, जहाँ प्रकाश परमाणुओं के एक साथ नष्ट होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- यह विखंडन की विपरीत प्रतिक्रिया है, जहां यूरेनियम और थोरियम जैसे भारी तत्व अलग हो जाते हैं।
- एक परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होने के लिए, दो नाभिकों को इतना करीब लाना आवश्यक है कि परमाणु बल सक्रिय हो जाएं और नाभिक को एक साथ संयुक्त हो जाये।

क्या आप जानते हैं?

- परमाणु बल छोटी दूरी की ताकतें हैं और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जहां सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नाभिक एक दूसरे को पीछे हटाते हैं।
- यही कारण है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं ज्यादातर उच्च घनत्व, उच्च तापमान वातावरण में होती हैं जो प्रयोगशाला परिस्थितियों में प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है।



भारत और प्रौद्योगिकी के भू-राजनीति (India and the geopolitics of technology)

संदर्भ:

- स्पीन्टरनेट, इंटरनेट का थोककरण, डिजिटल संप्रभुता और डेटा स्थानीयकरण कुछ अधिक लोकप्रिय शब्द हैं जो डेटा के भविष्य पर बहस को परिभाषित करते हैं, और अधिक व्यापक रूप से, यह प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा को परिभाषित करते हैं।
- यह तर्क अलग-अलग तरीकों से उत्तेजित करता है जिसमें सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जैसे यूरोपीय संघ) सीमाओं तक पहुंचने के लिए डेटा का उपयोग, और अनुमति देते हैं।

विभिन्न प्रकार के डिजिटल बाजार

- **डिजिटल अधिनायकवादी:** वे देश जिन्होंने अपने डेटा बाजारों को बाहरी अभिनेताओं के लिए बंद कर दिया है - जैसे कि चीन - आमतौर पर डिजिटल अधिनायकवादी के रूप में जाना जाता है।
- **डिजिटल लोकतंत्र:** जो न्यायिक मानकों, कानून के शासन द्वारा निर्देशित होते हैं, और फ्रीयर का समर्थन करते हैं - लेकिन हमेशा मुक्त नहीं होते हैं - डेटा की इस प्रक्रिया को डिजिटल लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है।

डिजिटल जियोपॉलिटिक्स एंड डेटा डिप्लोमेसी

- राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक तनाव, और भीतर, अभिनेताओं की विभिन्न श्रेणियां आकार लेती हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी का भू-राजनीति कहा जा सकता है
- जियो पॉलिटिक्स का यह रूप घरेलू विनियमों, विरोधी ट्रस्ट कानूनों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और गोपनीयता विधानों पर घरेलू मानकों के बारे में उतना ही है, जितना कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में है।
- विभिन्न देशों में संस्थाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों पर अधिक से अधिक सहयोग, सीमाओं पर मध्यस्थता और सहयोग की आवश्यकता है। यह डेटा डिप्लोमेसी का मामला है।
- कम से कम 14 देशों ने डेटा कूटनीति को आकार देने के लिए वार्ताकारों को नियुक्त किया है।
- तकनीकी राजदूत, नवाचारों के राजदूत, डिजिटल मामलों के राजदूत और साइबर कूटनीति के राजदूत जैसे पदनाम तेजी से सामान्य हो रहे हैं।

भारत में विशाल क्षमता

- **सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र:** सभी डेटा अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ सौदा करना चाहती हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा खुला डेटा बाजार है। 600 मिलियन के करीब भारतीय वर्तमान में 4 जी डेटा का उपयोग करते हैं।
- **डेटा की खपत में वृद्धि:** भारत में दुनिया में कहीं भी डेटा की प्रति व्यक्ति खपत (10 जीबी प्रति माह से अधिक) है।

भारत के लिए चुनौतियां

- **डेटा ओपननेस का प्रश्न:** भारत के किस तरह के डिजिटल लोकतंत्र है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह अपनी सीमाओं के पार डेटा की आवाजाही के लिए कितना खुला या बंद होगा, यह वैश्विक " तकनीकी राजदूतों " की तेजी से बढ़ती संख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक हद तक, डेटा के खुलेपन का सवाल भारत के पर्सनल डेटा के रूप में हल हो जाएगा। बिल (PDPB) 2021 को संभावित रूप से एक कानून बनाया जायेगा।
- **भारत के उद्देश्यों पर स्पष्टता:** भारत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि वह वास्तव में तेजी से बदल रही भू-राजनीति से बाहर क्या चाहता है, जो प्रौद्योगिकी के आसपास है जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से परे है। भारत के विकसित घरेलू डेटा आर्किटेक्चर को इसके लाभ के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ, अपने अंतरराष्ट्रीय हितों का समर्थन करना चाहिए।
- **संतुलन अधिनियम:** भारत की डेटा नीति का उद्देश्य डेटा में अपने वजन पर बातचीत करना और स्थानीयकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के बीच भारत के भविष्य के लिए सही संतुलन खोजना होगा। यह संतुलन अधिनियम का केंद्रीकरण की दृष्टि के साथ-साथ प्रशासनिक संगठन की अवधारणा के साथ भी सम्बंधित है।

आगे का रास्ता

- शुरू करने के लिए, सरकार प्रौद्योगिकी के लिए अपने समन्वयक नियुक्त करने पर विचार कर सकती है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक टेक राजदूतों की बीन काउंट में जोड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति को प्रभावी रूप से देखने के लिए भारत की स्पंदित कहानी को संश्लेषित करने के लिए कम से कम राज्य के दर्जा प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए।

जापान का हायाबुसा 2 मिशन वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है (Japan's Hayabusa2 Mission set to return back to Earth)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- स्पेस

समाचार में

- जापान के हायाबुसा 2 मिशन के लॉन्च होने के छह साल बाद, यह पृथ्वी पर वापस आने के लिए तैयार है।
- यह Ryugu क्षुद्रग्रह से नमूने ले कर वापस आयेगा, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- हायाबुसा 2 मिशन दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था।
- अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह रायुगु का अध्ययन करने और नमूने एकत्र करने के लिए छह साल की लंबी यात्रा पर भेजा गया था।
- नासा के OSIRIS-REX मिशन भी अक्टूबर, 2020 के अंत में क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने वापस लाया है।
- जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के अनुसार, यह पहली बार है कि एक जांच ने एक खगोलीय पिंड का दौरा किया है जो 100 मीटर से कम व्यास का है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Important value addition)

- Ryugu को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों (PHAs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसकी खोज 1999 में हुई थी।
- इसे 2015 में माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा यह नाम दिया गया था।
- यह पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर दूर है।
- इस तक पहुंचने के लिए हायाबुसा 2 को 42 महीने से अधिक का समय लगा।
- हायाबुसा 2 के पूर्ववर्ती, हायाबुसा मिशन 2010 में क्षुद्रग्रह इटोकावा (asteroid Itokawa) से नमूने वापस लाया था।

संबंधित लेख:

- हायाबुसा 2 प्रोब : [Click here](#)

सिंगापुर एजेंसी ने लैब-ग्रोन मीट के बिक्री को मंजूरी दी (Singapore Agency approves sale of Lab-Grown Meat)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- सिंगापुर खाद्य एजेंसी (SFA) ने एक प्रयोगशाला में मांस उत्पाद की बिक्री को मंजूरी दी है।
- यह पहली बार है कि दुनिया में कहीं भी बिक्री के लिए संवर्धित मांस को मंजूरी दे दी गई है।
- SFA द्वारा अनुमोदित उत्पाद संवर्धित चिकन है, जो यूएस-आधारित ईस्ट जस्ट द्वारा निर्मित है।

लैब-विकसित मांस और पौधे-आधारित मांस के बीच अंतर

- सोया या मटर प्रोटीन जैसे उत्पाद को पौधों के स्रोतों से बनाया जाता है, जबकि सुसंस्कृत मांस को प्रयोगशाला में कोशिकाओं से सीधे उत्पाद किया जाता है।
- दोनों का उद्देश्य एक ही है: पारंपरिक मांस उत्पादों के विकल्प के रूप में इसे पेशकश करना, जिसे बहुत अधिक लोगों को खिलाया जा सकता है, यह जूनोटिक रोगों के खतरे को कम कर सकते हैं और मांस की खपत के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- सेलुलर संरचना के संदर्भ में, सुसंस्कृत मांस पारंपरिक मांस के समान है सिवाय इसके कि सुसंस्कृत मांस सीधे जानवरों से नहीं आता है।
- **लाभ:** (1) संवर्धित मांस भूमि उपयोग को 95% से अधिक कम कर सकता है; (2) यह जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन को 74-87% और पोषक तत्वों के प्रदूषण को 94% तक कम कर सकता है; (3) साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे रोगजनकों द्वारा संदूषण का खतरा काफी कम हो जाता है; (4) इसमें एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा कम हो जाता है।

बृहस्पति व शनि ग्रह के मिलन की अद्भुत खगोलीय घटना (Jupiter and Saturn to be seen in Great Conjunction)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, बृहस्पति और शनि 21 दिसंबर, 2020 को एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई देंगे, यह एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संबंध तब होता है जब दो खगोलीय पिंड नेत्रहीन पृथ्वी से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं।
- 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी लगभग 0.06 डिग्री रह जाएगी।
- ये दोनों ग्रह इतने करीब में आ जाएंगे कि एक-दूसरे में मिलते हुए दिखाई देंगे।
- यानी साल की सबसे लम्बी रात को आसमान में बृहस्पति -शनि का मिलन होगा। सामान्य एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयरस इन्हे एक ओक्युल्टेशन (तारा प्रच्छादन) की घटना के रूप में दिखा रहे हैं।

- यह प्रत्येक 20 साल में होता है।
- यह संयोजन पृथ्वी से देखे गए बृहस्पति और शनि के कक्षीय रास्तों का परिणाम है।
- बृहस्पति हर 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है, और शनि हर 29 साल में।
- यह दूरी के संदर्भ में 1623 के बाद से शनि और बृहस्पति का निकटतम संरेखण होगा।
- अगली बार यह ग्रह इतने करीब 2080 में होंगे।
- भले वह एक साथ दिखाई देंगे, परन्तु वह 400 मिलियन मील से अधिक दूर होंगे।

BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड-IoT की घोषणा की (BSNL announces Satellite-Based Narrow Band-IoT)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- बीएसएनएल ने स्काइलोटैक इंडिया के साथ साझेदारी में भारत में दुनिया का पहला 'सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड-आईओटी' [Satellite-based Narrow Band- IoT (Internet of Things)] नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस 'मेड इन इंडिया' सॉल्यूशन को भारत में ही स्काइलो द्वारा विकसित किया गया है, जोकि बीएसएनएल के सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर (टॉवर आदि) के जरिए लोगों को कनेक्ट करेगा।
- पूरे भारत के साथ-साथ यह सुविधा भारतीय समुद्री क्षेत्र में भी उपलब्ध होगी।
- यह दुनिया का पहला उपग्रह-आधारित NB-IoT नेटवर्क है।
- यह नई तकनीक भारत के प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी आईओटी कनेक्टिविटी करने के दूरसंचार विभाग और नीति आयोग की योजना का सहयोग करती है।
- इस तकनीक का पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारतीय रेलवे, मछली पकड़ने वाले जहाज और दूसरे जरूरी वाहनो में इसका इस्तेमाल परीक्षण के दौरान किया गया है।
- इस तकनीकी के तहत एक छोटा सा स्मार्ट बॉक्स है, जिसमें स्काइलो का यूजर टर्मिनल (Skylo User Terminal) है, जिसमें सेंसर लगा हुआ है, जो स्काइलो नेटवर्क और लोगों तक डेटा पहुंचायेगा।

भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV-C50 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया (India's communication satellite CMS-01 was successfully launched by PSLV-C50)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक में भारतीयों की उपलब्धियां

समाचार में

- भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) SHAR, श्रीहरिकोटा से PSLV-C50 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- CMS-01 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित-सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित संचार उपग्रह है, जिसमें भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल होंगे।
- यह भारत का 42 वां संचार उपग्रह, इसकी सात वर्ष की मिशन आयु होगी।
- यह भारत का 42 वां संचार उपग्रह था जिसमें सात साल से अधिक का मिशन जीवन था।
- उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में निर्दिष्ट स्लॉट में रखा जाएगा।
- इसके बाद, यह 11 साल पहले लॉन्च किए गए GSAT 11 की निरंतरता के रूप में कार्य करेगा।
- PSLV-C50 PSLV की 52 वीं उड़ान है और 'XL' कॉन्फिगरेशन (6 स्ट्रेप-ऑन मोटर्स के साथ) में PSLV की 22 वीं उड़ान है।

● CMS-01 is the 42nd communication satellite from India

● Will replace GSAT-12 satellite, launched in 2011

● Will provide telecom services in the Extended-C Band of the frequency spectrum

● Extended-C Band coverage will include Indian mainland, Andaman-Nicobar and Lakshadweep Islands

● Mission life: 7 years

PSLV-C50

● **52nd** flight of PSLV

● **22nd** flight of PSLV 'XL' variant

77 launch vehicle mission from Sriharikota spaceport

‘चांग ई 5’ मिशन चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लेकर लौटा (Chang’e 5 returns with first fresh rock samples from the moon)

भाग: GS प्रीलैम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- चीन का का चंद्रयान ‘चांग ई 5’ मिशन 44 वर्षों बाद चांद की सतह से 2 किलोग्राम चट्टानों और मलबे के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया।
- यह अंतरिक्ष यान हाल ही में उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र के सिजिवांग जिले में उतरा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रोब, जिसे चीन की प्राचीन देवी जिसे चंद्रमा का नाम पर दिया गया , पहली बार 24 नवंबर को हैनान में वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से रवाना हुई।
- ‘चांग ई 5’ मिशन में से दो चार मॉड्यूल 1 दिसंबर को चंद्रमा पर उतरा और सतह से स्कूपिंग करके और चंद्रमा की पर्पटी में 2 मीटर ड्रिलिंग करके लगभग 2 किलोग्राम (4.4 पाउंड) नमूनों को एकत्र किया।
- नमूने एक सील कंटेनर में जमा किए गए थे, जिसे एक वाहक द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया था।
- चांग ई 5 के पुनः प्राप्त कैप्सूल को बीजिंग में प्रसारित किया जाएगा, जहां कैप्सूल खोला जाएगा और नमूने विश्लेषण के लिए तैयार होंगे।

- इसके साथ, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद तीसरा देश बन गया, जिसने चंद्रमा के नमूने एकत्र किए हैं।
- ये 1976 में रूस के बाद किसी भी देश द्वारा एकत्र किए जाने वाले पहले नमूने भी हैं।

क्या आप जानते हैं?

- नमूनों को चंद्रमा के पहले से अनविजित क्षेत्र से पुनर्प्राप्त किया गया था।
- नवीनतम नमूने चंद्रमा के एक हिस्से से आते हैं जिसे ओशनस प्रोसेलरम, या स्टॉर्म के महासागर के रूप में जाना जाता है, इसके निकट एक साइट जिसे मॉन्स रुम्कर कहा जाता है और ऐसा माना जाता था कि यंहा प्राचीन काल में ज्वालामुखी था।
- मॉन्स रुम्कर, जिसका पहले कभी नमूना प्राप्त नहीं किया गया था, अमेरिकी और सोवियत मिशनों के नमूने क्षेत्रों की तुलना में भौगोलिक रूप से छोटा है।

इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन : आरंभिक आँकड़े सार्वजनिक रूप से जारी किये (ISRO released to public the initial data from Chandrayaan-2)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीकी

समाचार में

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान -2 के आरंभिक आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए जारी किया।
- यह भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन था, जिसे 22 जुलाई 2019 को प्रमोचित किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऑर्बिटर, जिसे 22 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में अंतःक्षेपित किया गया था, उसमें चंद्रयान-2 पर कई खुले प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ने के लिए 8 परीक्षण हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर (ISSDC) बायलालु (बेंगलुरु) में संग्रहित सार्वजनिक रिलीज डेटा मानक रूप से तैयार किया जाता है, सार्वजनिक रूप से रिलीज होने के लिए वैश्विक डेटा सिस्टम -4 (PDS4) प्रारूप का पालन किया जाता है।
- ISSDC ISRO के ग्रहीय मिशनों के लिए ग्रहों के डेटा संग्रह का नोडल केंद्र है।

चंद्रयान -2 मुख्य तथ्य:

- चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था
- भारतीय अभियान, स्वदेशी तकनीक के साथ चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर रहा है
- यह दो महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है: परियोजना निदेशक एम वनिता और मिशन निदेशक रितु कारिदला।

- स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चंद्र क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय मिशन
- चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश

BBX11: एक जीन जो पौधों की हरियाली में सुविधा प्रदान करता है (BBX11: A gene that facilitates in the greening of plants)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के शोधकर्ताओं ने एक जीन की पहचान की है जो पौधों के हरियाली में सुविधा प्रदान करता है।
- यह जीन प्रोटोक्लोरोफिल के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हरे वर्णक क्लोरोफिल के जैवसंश्लेषण में एक मध्यवर्ती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- IISER वैज्ञानिकों ने जीन 'BBX11' की पहचान की है।
- यह अध्ययन हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका न्यू फाइटोलॉजिस्ट में प्रकाशित हुआ था।
- पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण एक लंबी, बहु-चरण प्रक्रिया है।
- जब एक अंकुर मिट्टी के नीचे से निकलता है तो उसे अपने स्वयं के विकास का समर्थन शुरू करने के लिए क्लोरोफिल को जल्दी से संश्लेषित करना चाहिए।
- क्लोरोफिल के त्वरित संश्लेषण की सुविधा के लिए, पौधे अंधेरे में y प्रोटोक्लोरोफिलाइड नामक क्लोरोफिल बनाते हैं, जो पौधे पर नीली रोशनी पड़ने पर लाल रंग का चमकता है।
- जैसे ही पौधे मिट्टी के नीचे से प्रकाश में निकलता है, प्रकाश पर निर्भर एंजाइम प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिल में बदल देते हैं।
- प्रोटोक्लोरोफिलाइड संश्लेषित की मात्रा को क्लोरोफिल में बदलने के लिए उपलब्ध एंजाइमों की संख्या के लिए आनुपातिक होने की आवश्यकता है।
- यदि मुक्त प्रोटोक्लोरोफिलाइड की अधिकता है, तो प्रकाश के संपर्क में आने से यह अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, जो 'फोटोब्लिचिंग' का कारण बनता है।

वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला संभव रेडियो संकेत पाया (Scientists find first possible radio signal from a planet beyond our solar system)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने संभवतः पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है। यह संकेत 51 प्रकाशवर्ष दूर स्थित ग्रह प्रणाली से आ रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नीदरलैंड में एक रेडियो टेलीस्कोप, कम आवृत्ति सरणी (LOFAR) का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने ताऊ बूट्स स्टार-सिस्टम से उत्सर्जन फटने को उजागर किया, जो एक तथाकथित गर्म बृहस्पति, एक गैसीय विशाल ग्रह की मेजबानी कर रहा था, जो अपने सूर्य के बहुत करीब है।
- नीदरलैंड स्थित रेडियो दूरबीन ने लो फ्रिक्वेंसी ऑर् (लोफर) का इस्तेमाल कर टाऊ बूट्स तारे की प्रणाली से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है जिसके बहुत करीब गैस से बना ग्रह चक्कर लगा रहा है और जिसे कथित 'गर्म बृहस्पति' के नाम से भी जाना जाता है।
- ये संकेत टाऊ बूट्स प्रणाली से आ रहे हैं जिसमें दो तारे और ग्रह है।
- अनुसंधानकर्ता ने कहा कि अगर इस ग्रह की पुष्टि बाद के अध्ययन से होती है तो रेडियो संकेतों के जरिये सौर मंडल के बाहर के ग्रहों का पता लगाने का एक नया मार्ग खुलेगा और सैकड़ों प्रकाशवर्ष दूर की दुनिया के बारे में जानने का नया तरीका मिलेगा।

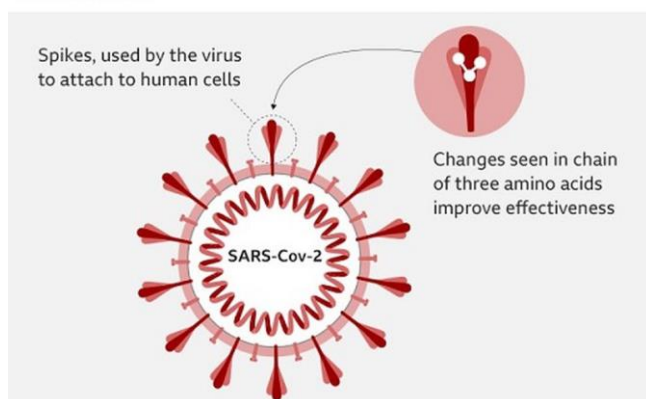
यूके में कोरोनावायरस वैरिएबल परिसंचारी कई म्यूटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है (Coronavirus variant circulating in the UK defined by many mutations)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- यूके में कोरोनावायरस वेरिएंट का प्रसार कई म्यूटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है।

One coronavirus mutation has become dominant



महत्वपूर्ण बिंदु

- एक उत्परिवर्तन का मतलब आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन है।

- SARS-CoV-2 जैसे RNA वायरस में प्रोटीन अमीनो एसिड के अनुक्रम से बनता है।
- इस तरह के वायरस में लगभग 30,000 जोड़े पर आधारित होता है, यह संरचना बनाने के लिए एक दूसरे के बगल में रखी ईंटों की तरह होते हैं।
- इसके बेस में एक परिवर्तन उत्परिवर्तन हो सकता है, प्रभावी रूप से वायरस के आकार और व्यवहार को बदल सकता है।
- यूके संस्करण में, एक उत्परिवर्तन ने वायरस को रिसेप्टर्स नामक मानव प्रोटीन के साथ जुड़ने की अधिक संभावना है। इसे N501Y कहा जाता है।

N501Y

- सरल शब्दों में, अमीनो एसिड को N अक्षर से दर्शाया गया है, और कोरोनावायरस आनुवंशिक संरचना में स्थिति 501 पर मौजूद है, उस स्थिति में एक अन्य एमिनो एसिड के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व Y है।
- जिस स्थान पर यह परिवर्तन हुआ है, वह स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन में है।
- इसलिए, उत्परिवर्तन ने कोरोनावायरस के बंधन को बढ़ा दिया है।
- उत्परिवर्तित वायरस लंदन में हाल ही में संक्रमण के 60% के लिए जिम्मेदार है।

क्या आप जानते हैं?

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, N501Y के अलावा, ऐसे म्यूटेशन जो "मनुष्यों में वायरस की प्रसार क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं" P681H और HV 69/70 हैं।

- **P681H:** यह उत्परिवर्तन 681 में मौजूद अमीनो एसिड में हुआ है। एमिनो एसिड P को H के साथ बदल दिया गया है।
- **एचवी 69/70:** यह उत्परिवर्तन 69 और 70 के स्थान पर अमीनो एसिड के विलोपन का परिणाम है।
- ये स्थिति फिर से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में होती हैं।
- यह विलोपन फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में भी देखा गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की योजना है (USA's plan to have Nuclear Reactor On Moon)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में, इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसके तहत उन्होंने नासा को 2027 तक चंद्र सतह प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह शक्ति परियोजना शुरू करने के लिए कहा, जिसमें 40 किलोवाट-इलेक्ट्रिक की पावर रेंज और अधिक निरंतर लुनार उपस्थिति और मंगल की खोज का समर्थन करने की उच्च क्षमता है।
- इसके पीछे नासा का उद्देश्य एक उड़ान हार्डवेयर प्रणाली स्थापित करना था जो 2026 के अंत तक चंद्र लैंडर के साथ एकीकरण के लिए तैयार है।
- परमाणु रिएक्टर को फ्यूजन पावर प्रणाली के रूप में जाना जाता है जो भविष्य के रोबोट और मानव अभियान मिशनों के साथ-साथ मंगल ग्रह को भी लाभान्वित करेगा।
- सुरक्षित, कुशल और आसानी से उपलब्ध बिजली की उपलब्धता इन मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है
- एक विखंडन सतह शक्ति प्रणाली उन आवश्यकताओं को पूरा करती है। विखंडन सतह शक्ति प्रणाली पूरी तरह से निर्मित और पृथ्वी पर इकट्ठी होगी और पेलोड के रूप में एक लैंडर पर एकीकृत होगी।
- इस प्रणाली में एक परमाणु रिएक्टर सहित चार प्रमुख उपतंत्र शामिल हैं जो एक विद्युत ऊर्जा रूपांतरण इकाई, ऊष्मा अस्वीकृति सरणी और शक्ति प्रबंधन और वितरण उपतंत्र है और इसे 10 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया (Digital Ocean web-based application inaugurated)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- नीतियां और हस्तक्षेप और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- वेब आधारित डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का हाल ही में उद्घाटन किया गया था
- मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- विकसित: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के INCOIS

महत्वपूर्ण बिंदु

- डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म में उन एप्लीकेशन्स का सेट शामिल है जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में प्रगति को अपनाकर विषम समुद्र संबंधी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए विकसित किए गए हैं।
- यह प्लेटफॉर्म यूजर्स की विस्तृत श्रृंखला की डेटा संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करेगा।
- इसमें अनुसंधान संस्थान, रणनीतिक उपयोगकर्ता, परिचालन एजेंसियां, शैक्षणिक समुदाय, नीति निर्माता, समुद्री उद्योग शामिल हैं।
- यह महासागर डेटा प्रबंधन के लिए इस प्रकार का पहला प्लेटफॉर्म है।

- यह प्लेटफार्म डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह प्लेटफार्म समुद्र संबंधी सुविधाओं के विकास का आकलन करने के लिए डेटा एकीकरण, डेटा विश्लेषण, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा फ़्यूज़न और डेटा विश्लेषण के लिए एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव वेब-आधारित वातावरण की सुविधा देता है।

महत्व:

- यह हमारे महासागरों के स्थायी प्रबंधन और हमारी ब्लू इकोनॉमी पहल का विस्तार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा।
- इसे सभी हिंद महासागर रिम देशों के लिए महासागर डेटा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रॉक्सिमा सेन्टॉरी की दिशा से रेडियो तरंग उत्सर्जन का पता चला (Radio wave emission detected from the direction of Proxima Centauri)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- 100 मिलियन \$ Breakthrough Listen project के खगोलविदों ने हाल ही में हमारे सूर्य के सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेन्टॉरी की दिशा से रेडियो तरंग उत्सर्जन को प्राप्त किया है।
- Breakthrough Listen project की शुरुआत भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई थी,

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस खबर ने प्रॉक्सिमा सेन्टॉरी में नए सिरे से दिलचस्पी जगाई है, जिसके एक ग्रह के बारे में माना जाता है कि वह तारों के रहने योग्य क्षेत्र में घूमता है, और इस संभावना को जन्म देता है कि वह जीवन को बनाए रख सकता है।
- प्रॉक्सिमा सेन्टॉरी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है।
- इसका द्रव्यमान सूर्य के आठवें हिस्से के बराबर है, और यह पृथ्वी से नम आंखों से नहीं देखा जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्रॉक्सिमा B

- प्रॉक्सिमा B, दो ग्रहों में से एक है जो तारे के चारों ओर घूमता है, यह महत्वपूर्ण जिज्ञासा का विषय है।
- यह पृथ्वी से 1.2 गुना बड़ा है, और हर 11 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है, Proxima b, Proxima Centauri के गोल्डीलॉक्स ज़ोन में स्थित है।
- गोल्डीलॉक्स ज़ोन एक तारे के आस-पास का वह क्षेत्र है जहाँ यह बहुत गर्म नहीं है और आसपास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी के लिए बहुत ठंडा नहीं है (जैसे पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स ज़ोन में है)।

- हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पानी प्रॉक्सिमा बी पर मौजूद है।
 - यह जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण भी हो सकता है, अगर इसका वातावरण प्रॉक्सिमा सेंटॉरी से सौर फ्लेयर्स द्वारा प्रभावित हुआ है।
-



ILP 2021

IASbaba's INTEGRATED LEARNING PROGRAMME (ILP) ONLINE-2021

ONLINE Integrated (Prelims, Mains, Interview) Program

Key Features of ILP BASIC 2021:

- **COMPREHENSIVE PROGRAM** - Covers Prelims, Mains, Interview
- **DETAILED STUDY PLAN** (for 1.5 Years) with DAILY TARGETS/PLANNING
- **VALUE ADD NOTES (VAN)** - MAINS + PRELIMS
- **BABAPEDIA** - One-Stop Destination of Current Affairs Preparation
- **ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (AIPTS)** - TOTAL 62 Tests
- **ALL INDIA RANKING**
- **SELF-ASSESSMENT SYSTEM** - in the PRELIMS TEST SERIES
- **MAINS TESTS & SYNOPSIS** - TOTAL = 50 TESTS
- **MIND MAPS** for GS MAINS
- **ESSAY GUIDANCE** - Model Essays & Mainspedia Content
- **ABHIYAKTI** - SOCIAL MEDIA OF ILP

Available both
in English
and
हिन्दी

Key Features of ILP PLUS (+) 2021:

- **All the Features of ILP Basic.** Additionally it consists of Video Classes.
- **AIPTS (Prelims Test) DISCUSSION** - 62 Discussion Videos (52 GS & 10 CSAT)
- **Strategy and Approach Classes of Each Subject** - 30 Classes
- **Current Affairs Classes every Month** - 10 Classes

Key Features of ILP CONNECT PLUS (+) 2021

- **All the Features of ILP Basic & ILP Plus.**
- **Additionally the special feature of this Program is ONLINE MENTORSHIP** - A Dedicated Mentor to monitor your progress, give you feedback, motivate and guide you in the Right Path!

WHY IASbaba?

VISION: Enabling an aspirant located at the remotest corner of the country, in not only fulfilling his/her dreams of clearing the toughest UPSC/Civil Services Exam, but securing Rank 1.

2M+

MONTHLY ACTIVE
USERS

350+

RANKS FROM
ILP/TLP

1200+

RANKS FROM
WEBSITE

>70%

HIT RATIO IN
UPSC PRELIMS

>80%

HIT RATIO IN
UPSC MAINS

Contact us

Admission Centre
#38, 3rd Cross Rd, 60feet Main Road,
Chandra Layout, Bengaluru-560040
Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit

Vijayanagara Centre
1737/37, Mrcr Layout, Vijayanagar Service Road,
Vijayanagar, Bengaluru - 560040
Landmark: Opp. to Vijayanagar Metro Station

Delhi Centre
5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro
Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

www.iasbaba.com

ilp@iasbaba.com

+91 91691 91888

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा (DEFENCE/INTERNAL SECURITY/SECURITY)

MARCOS को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा रहा है (MARCOS being deployed in the Eastern Ladakh)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- चीनी सेना के खिलाफ भारतीय सेना के साथ पूर्वी लद्दाख में MARCOS की तैनाती की जा रही है।
- वे पैंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं जहां वे जल्द ही नावों का उपयोग करके मिशन का संचालन करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- मरीन कमांडो को MARCOS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स (MCF) कहा जाता है।
- यह भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है जो विशेष संचालन करने के लिए जिम्मेदार है।
- MARCOS की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी।
- MARCOS सभी प्रकार के वातावरण में संचालित करने में सक्षम हैं; समुद्र में, हवा में और जमीन पर।
- बल ने धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त किया है और व्यावसायिकता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है।
- MARCOS नियमित रूप से झेलम नदी और वुलर झील के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विशेष समुद्री संचालन करता है।

सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (रणनीति) की मंजूरी दी (Government approves Deputy Chief of Strategy post)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- सेना मुख्यालय में एक प्रमुख पुनर्गठन अंततः सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- सेना के तीसरे उप-प्रमुख की स्थिति बनाने के लिए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है।
- वह परिचालन मुद्दों पर सेना के उपाध्यक्ष के लिए "एकल-बिंदु सलाह" व्यक्ति के रूप में कार्य करेगा।

- वह ऑपरेशन, खुफिया, परिप्रेक्ष्य और सूचना युद्ध का नेतृत्व करेंगे।
- सैन्य संचालन महानिदेशालय और सैन्य खुफिया महानिदेशालय, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल-रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में, उसके अधीन होंगे।
- परिप्रेक्ष्य योजना और रणनीतिक संचार के लिए दो नए कार्यालय, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल-रैंक के निदेशक जनरलों के नेतृत्व में भी होंगे, नए उप प्रमुख के तहत भी आएंगे।
- यह बदलाव तुरंत शुरू हो जायेगा।
- वर्तमान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को पहले उप प्रमुख (रणनीति) नियुक्त किए जाने की संभावना है।

खालिस्तान की धमकी: लगातार सतर्कता की जरूरत (Khalistan threat: Need for Constant vigilance)

संदर्भ:

- दिल्ली में पांच आतंकवादी संदिग्धों की गिरफ्तारी - जिनमें से दो, अक्टूबर में पंजाब में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे – जिसके कारण खालिस्तान आंदोलन फिर से सुर्खियों में है

खालिस्तान आंदोलन क्या है?

- खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है, जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। ऐसा राज्य पंजाब में 1709 से 1849 तक अस्तित्व में था।

खालिस्तान के लिए कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जिम्मेदार हैं?

- 1947 भारत का विभाजन - भारत की निर्भरता सिखों के लिए एक खुशी की घटना नहीं थी, विभाजन ने पाकिस्तान में अपनी पारंपरिक भूमि खो जाने के संबंध में बहुत असंतोष व्याप्त कर दिया था।
- एक अलग सिख राज्य की लड़ाई पंजाबी सूबा आंदोलन की उत्पत्ति का कारण है। अकाली दल - एक सिख बहुल राजनीतिक दल - ने एक अलग सिख सूबा या प्रांत बनाने की मांग की।
- जब भाषाई समूहों द्वारा अलग राज्यों की मांग का आकलन करने के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें दीं, तो उसने अकाली दल की मांग को खारिज कर दिया।
- लेकिन कई हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में भरोसा दिया।
- राज्य को पंजाबी बहुल पंजाब, हिंदी-बहुमत वाले हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विभाजित किया गया था। राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था।
- हालांकि, अनादपुर साहिब संकल्प ने सिखों के जुनून को राज किया और खालिस्तान आंदोलन के बीज बोए

आनंदपुर साहिब संकल्प क्या था?

- पंजाब सूबे ने अकाली दल के लिए काफी राजनीतिक समर्थन हासिल किया और एक संक्षिप्त विभाजन के बाद, पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में एक साथ आए, जिससे कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर मिली।
- 1972 का चुनाव, हालांकि, अकालियों के बढ़ते राजनैतिक ग्राफ में फूला साबित हुआ। अकाली दल को आत्मसमर्पण करने के लिए उकसाने वाली कांग्रेस सत्ता में आ गई।
- इस आत्मनिरीक्षण का स्थान आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा था, जहाँ पार्टी ने एक संकल्प अपनाया जो पार्टी के भविष्य के एजेंडे के लिए एक खाका के रूप में काम करेगा।
- प्रस्ताव में पंजाब राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग की गई है, ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जो एक अलग राज्य का हिस्सा होंगे, और अपने स्वयं के आंतरिक संविधान को लागू करने के अधिकार की मांग करेंगे। यह आनंदपुर साहिब संकल्प था।

कौन थे जरनैल सिंह भिंडरावाले?

- हो सकता इसके मूल लेखकों ने अपने घोषित उद्देश्यों को पीछे छोड़ दिया है, आनंदपुर साहिब संकल्प ने जरनैल सिंह भिंडरावाले में एक प्रशंसक को जन्म दिया – यह एक धार्मिक विद्वान था जो पंजाब भर में यात्रा कर रहा था और खालसा या सिख धर्म के अधिक रूढ़िवादी रूप की वापसी की वकालत कर रहा था।
- उन्होंने हिंदुओं और आधुनिकीकरण वाले सिखों को निशाना बनाया, जिन्होंने अपने बाल काटे थे और शराब का सेवन करते थे।
- यदि अकालियों एक उदारवादी गुट सिख गौरव और राजनीति के धनी थे, तो भिंडरावाले ने चरमपंथी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया और अन्य बातों के अलावा एक अलग राज्य का आह्वान किया।
- खालिस्तान विचारधारा से प्रेरित जरनैल सिंह भिंडरावाले ने खालिस्तान को एक चरमपंथी आंदोलन के रूप में नेतृत्व किया और भारत सरकार के विरुद्ध परिवर्तित हो गया।
- पंजाब के लिए अलग राष्ट्र की मांग हिंसक विरोध प्रदर्शन और भारत सरकार में उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों की हत्याओं के माध्यम से की गई थी।

वे कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने खालिस्तान आंदोलन को तेज किया है?

- जरनैल सिंह भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अंदर निवास किया, प्रदर्शनों और पुलिस झड़पों का निर्देशन किया।
- ऑपरेशन ब्लू स्टार का आयोजन स्वर्ण मंदिर परिसर में भिंडरावाले को पकड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इस अभियान के परिणामस्वरूप भारत विरोधी भावना प्रबल हो गई।
- तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को सिखों के दुश्मन के रूप में देखा गया था और उनके दो सिख गाड़ों ने 1984 में उनकी हत्या कर दी थी।
- उनकी हत्या के बाद दिल्ली और अन्य हिस्सों में सिखों के खिलाफ व्यापक प्रसार के दंगे हुए, पूरे भारत में सिखों के जनसंहार ने भारत विरोधी भावना को हवा दी।

- 1980 के दशक से 1990 के दशक तक, पंजाब व्यापक प्रसार आतंकवाद के दौर से गुजरा, जहां पाकिस्तान के आईएसआई ने चरमपंथी समूहों को समर्थन देकर हिंसा को रोकने की कोशिश की (यह वही समय था जब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कश्मीर में भारत को हराने का सपना देखा)
- खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा और उम्मी अन्य जैसे कई गुना उग्रवादी समूहों ने प्रमुखता हासिल की और पूरे पंजाब में स्वतंत्र रूप से घूमते रहे।
- 31 अगस्त 1995 को एक आत्मघाती हमलावर ने चंडीगढ़ में पंजाब के सिविल सचिवालय के अंदर पंजाब के सीएम बेअंत सिंह को बाहर निकाला दिया। सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया गया था, जो ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद शुरू हुआ था।
- सिख देशभक्त समूह होने के कारण प्रचलित आतंकवादी संघर्ष के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया और भारतीय राष्ट्र के साथ पक्षपात किया, तत्कालीन पंजाब पुलिस विभाग 1990 के दशक में आंदोलन को समाप्त करने में सफल रही।

आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वर्तमान में, खालिस्तान आंदोलन भारत में एक निष्क्रिय आंदोलन है।
- यह पंजाब के शहरी या स्थानीय आबादी में ज्यादा आकर्षण नहीं रखता है।
- लेकिन आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या यूएसए में रहने वाले सिखों से वैचारिक समर्थन मिलता है।
- वे संघर्ष के लिए पैसा, वैचारिक समर्थन देते हैं, पाकिस्तान का आईएसआई अभी भी आंदोलन को पुनर्जीवित करने में पैसा और प्रयास लगा रहा है।

आगे की चुनौतियां

- दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) कश्मीर में आतंकी संगठनों को खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ने के लिए फिर से कोशिश कर रही है।
- खालिस्तान आंदोलन की अप्रासंगिकता के बावजूद, पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसियों ने सीधे तौर पर हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की है, या तो सीधे तौर पर फ्रिंज वर्गों को फंडिंग करके या उन्हें कश्मीर में आतंकी समूहों से जोड़कर।
- भले ही खालिस्तान आंदोलन में हस्तक्षेप किया गया हो, कश्मीर में आतंक का खतरा अच्छी तरह से और सही मायने में सक्रिय है।

निष्कर्ष

- खालिस्तान आंदोलन वर्तमान में सक्रिय नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसे फ्रिंज सेक्शन के रूप में देखना चाहिए

यूएस ने एस -400 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों के अधिग्रहण पर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है (USA imposes sanctions on Turkey over S-400 Air Defence Missile System)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी एस -400 वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण पर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- एस -400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एसएसएम) है।
- यह दुनिया में सबसे लंबी अवधि के लिए आधुनिक रूप से लंबी दूरी के एसएसएम (एमएलआर एसएसएम) को सबसे खतरनाक रूप से तैनात किया गया है, जिसे यूएस-विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (टीएचएडी) से बहुत आगे माना जाता है।
- यह प्रणाली विमान, मानव रहित हवाई वाहनों - यूएवी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को 400 किमी की सीमा के भीतर, 30 किमी तक की ऊंचाई पर भेद सकती है।
- प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह को एक साथ संलग्न कर सकती है।
- रक्षा प्रणाली बहुक्रिया राडार, स्वायत्त पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणाली, विमान भेदी मिसाइल प्रणाली, लांचर और कमांड और नियंत्रण केंद्र को एकीकृत करती है।
- यह एक स्तरित रक्षा बनाने के लिए तीन प्रकार की मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है।



स्वदेशी रूप से विकसित DRDO प्रणाली सेना, नौसेना और वायु सेना को सौंपी गई (Indigenously developed DRDO systems handed over to Army, Navy and Air Force)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- केंद्रीय रक्षा मंत्री ने हाल ही में तीन स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) प्रणाली सेना, नौसेना और वायु सेना को सौंपी।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भारतीय समुद्री परिस्थिति-संबंधी जागरूकता प्रणाली (IMSAS) नौसेना प्रमुख को, ASTRA Mk-I मिसाइल को एयर चीफ मार्शल को और बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम (BOSS) को थल सेनाध्यक्ष को सौंप दिया।
- BOSS एक सभी मौसम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है।
- प्रणाली सुदूर संचालन क्षमता वाले कठोर उच्च ऊंचाई वाले उप-शून्य तापमान क्षेत्रों में घुसपैठ का स्वतः पता लगाकर निगरानी करने की सुविधा प्रदान करती है।
- IMSAS उच्च प्रदर्शन वाला बुद्धिमान सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ग्लोबल नेवीटाइम सिचुएशनल पिक्चर, मरीन प्लानिंग टूल्स और भारतीय नौसेना को विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करता है।

- एस्ट्रा एमके- I स्वदेशी रूप से विकसित पहली पोर दृश्य रेंज (बीवीआर) मिसाइल है, जिसे सुखोई -30, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए), मिग -29 और मिग -29 के से लॉन्च किया जा सकता है।

सोलर विंड्स हैक: संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया एक साइबरहमला (SolarWinds Hack: A cyberattack discovered in the USA)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- साइबर स्पेस

समाचार में

- सोलर विंड्स हैक, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया एक साइबरहमला है
- यह अमेरिकी सरकार, इसकी एजेंसियों और कई अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़े लक्षित संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।
- यह एक वैश्विक साइबर हमले की संभावना है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- इसे 'आपूर्ति श्रृंखला' हमला कहा जा रहा है।
- संघीय सरकार या एक निजी संगठन के नेटवर्क पर सीधे हमला करने के बजाय, हैकर्स एक तृतीय-पक्ष विक्रेता को लक्षित करते हैं, जो उन्हें सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करता है।
- इस मामले में, लक्ष्य एक IT प्रबंधन सॉफ्टवेयर था, जिसे टेक्सास स्थित कंपनी सोलरविंड्स द्वारा आपूर्ति किया गया था।
- ओरियन ग्राहकों के साथ सोलरविंड्स का एक प्रमुख सॉफ्टवेयर रहा है, जिसमें 33,000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं।
- हैकर्स ने सोलरवाइंड्स ओरियन आईटी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए ट्रोजन अपडेट के जरिए पीड़ितों तक पहुंच हासिल की।
- एक बार स्थापित होने के बाद, मैलवेयर ने हैकर्स को सोलरविंड्स के ग्राहकों के सिस्टम और नेटवर्क में एक बैकडोर एंट्री दी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी देती है (The Defence Acquisition Council (DAC) approves proposals to procure equipment)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने अपनी बैठक में 28,000 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- स्वीकृत अधिग्रहण प्रस्तावों में डीआरडीओ में भारतीय वायु सेना के लिए एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW & C) सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुल शामिल हैं।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की नई व्यवस्था के तहत डीएसी की यह पहली बैठक है।
- ये स्वीकार किए गए आवश्यकता (AoNs) की स्वीकृति का पहला सेट हैं।
- AoNs की अधिकांश खरीद भारतीय (IDDM) के उच्चतम श्रेणीकरण में की जा रही है।
- 7 प्रस्तावों में से 6, जिनके लिए AoNs को मंजूरी दी गई थी, सरकार के “मेक इन इंडिया” और “एतमानबीर भारत” पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा।

संबंधित आलेख:

- रक्षा अधिग्रहण परिषद: [Click here](#)
- रक्षा खरीद नीति का समालोचनात्मक विश्लेषण करें: [Click here](#)

मीडियम रेंज सतह से मिसाइल (MRSAM) लॉन्च की गई (Medium Range Surface To Air Missile (MRSAM) launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर से आर्मी वर्जन, मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल (Medium Range Surface to Air Missile-MRSAM) का सफल परीक्षण किया गया, पहले लॉन्च के साथ यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।



महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- मिसाइल ने एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो एक विमान को सीधे हिट के साथ नकल कर रहा था।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) इस मिसाइल प्रणाली का उत्पादन इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ मिलकर किया है। बताया जा रहा है
- MRSAM आर्मी हथियार प्रणाली में कमांड पोस्ट, मल्टी-फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल हैं।

बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज (Baroda Military Salary Package)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- अर्थव्यवस्था; रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज' के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- इस समझौते के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध की जायेगी।
- **लाभ-** इस वेतन पैकेज में निशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी तौर पर दिव्यांग सेनाकर्मियों, आंशिक रूप से दिव्यांग कर्मियों और वायु दुर्घटना बीमा सुविधाओं सहित अन्य आकर्षक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा

और सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी बालिकाओं की शादी में होने वाले खर्च दिये जाने की सुविधा भी होगी। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

- अन्य सुविधा: सभी बैंक एटीएम में असीमित मुफ्त एटीएम लेनदेन, खुदरा ऋणों में विभिन्न सेवा शुल्क पर छूट या रियायतें, आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से मुफ्त प्रेषण सुविधा, मुफ्त डिमांड ड्राफ्ट / बैंक चेक, लॉकर किराए में पर्याप्त छूट, और विभिन्न अतिरिक्त लाभ।

भारतीय सेना ने कामोव -226 टी हेलिकॉप्टरों सौदे को आगे बढ़ाने के लिए एक छूट का अनुरोध किया है (Indian Army to request waiver to take Kamov-226T Utility Helicopters)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- सुरक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- भारतीय सेना ने कामोव -226 टी उपयोगिता हेलिकॉप्टरों सौदे को आगे बढ़ाने के लिए एक छूट का अनुरोध किया है

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- 2015 में, भारत और रूस ने 200 केए 226T हेलिकॉप्टरों के लिए एक अरब डॉलर से अधिक की अनुमानित अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर सहमती व्यक्त की।
- कामोव -226 टी भारतीय सेना और वायु सेना के चीता और चेतक बेड़े को बदलने के लिए है।
- Ka-226T रूस के प्रसिद्ध कामोव डिजाइन ब्यूरो का एक डिजाइन है।
- यह एक हल्का हेलिकॉप्टर है, जिसका अधिकतम भार 3.5 टन है और यह 1 टन तक का पेलोड ले जा सकता है।
- Ka-226T समाक्षीय रोटार का उपयोग करता है जो विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में लाभप्रद है।
- Ka-226T में एक अद्वितीय, अलग करने योग्य 'मिशन' कम्पार्टमेंट भी है जो हेलिकॉप्टर को निगरानी और कार्गो डिलीवरी जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

हेलिकॉप्टरों के पुराने बेड़े के साथ मुद्दे

- चीता और चेतक हेलिकॉप्टरों की सेना के बेड़े में लगभग 75% 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिन्हें तत्काल प्रतिस्थापन की आवश्यकता है।
- प्रतिस्थापन की कमियों और अनुपलब्धता के कारण परिचालन क्षमता प्रभावित हुई है।

अमेरिकी साइबर हमला: सोलर विंड हैक (US Cyber Attack: SolarWinds hack)

संदर्भ:

- अमेरिका की एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी सोलरविंड्स, एक साइबरअटैक से सम्बंधित थी जो अपने ग्राहकों तक फैल गई थी और महीनों तक बिना रुके चलती रही।

एक असामान्य हैक

- इस साल की शुरुआत में, हैकर्स ने टेक्सास स्थित सोलरविंड के सिस्टम को चुपके से तोड़ दिया और कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम में दुर्भावनापूर्वक कोड को जोड़ दिया।
- सिस्टम, जिसे "ओरियन" कहा जाता है, आईटी कंपनियों के प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सोलरविंड के 33,000 ग्राहक हैं जो ओरियन का उपयोग करते हैं।
- अधिकांश सॉफ्टवेयर प्रदाता नियमित रूप से अपने सिस्टम में अपडेट भेजते हैं, चाहे वह बग को ठीक कर रहा हो या नई सुविधाओं को जोड़ रहा हो। सोलर विंड इसका कोई अपवाद नहीं है।
- मार्च 2020 की शुरुआत में, सोलर विंड ने अनजाने में अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर अपडेट भेज दिया जिसमें हैक कोड शामिल था।
- FireEye नामक एक निजी साइबर सिक्योरिटी फर्म ने दिसंबर 2020 में सर्वप्रथम ब्रीच को नोटिस किया, जब यह देखा कि इसकी अपनी प्रणाली हैक हो गई थी।
- कोड ने ग्राहक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के लिए एक पिछले दरवाजे का निर्माण किया, जो हैकर तब और भी अधिक मैलवेयर इंस्टॉल करते थे जो उन्हें कंपनियों और संगठनों की जासूसी करने में मदद करते थे।

पीड़ित

- सोलरविंड्स ने अमेरिकी नियामक अधिकारियों को बताया कि उसके ग्राहकों में से 18,000 ने अपडेट्स इंस्टॉल किए जो उन्हें हैकर्स के लिए असुरक्षित बना दिया।
- चूंकि सोलर विंड के कई उच्च प्रोफाइल ग्राहक हैं, जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां और अमेरिकी सरकार में कई एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो सकता है।
- अमेरिकी एजेंसियों, पेंटागन के कुछ हिस्सों, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, राज्य विभाग, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन और ट्रेजरी पर भी हमला किया गया।
- इसमें निजी कंपनियाँ भी शामिल थीं, जैसे Microsoft, सिस्को, इंटेल और डेलोइट, और अन्य संगठन जैसे कैलिफोर्निया राज्य अस्पताल, और केंट स्टेट यूनिवर्सिटी।
- चूंकि हैक इतनी चुपके से किया गया था, और महीनों के लिए अनिच्छुक हो गया, सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ पीड़ितों को कभी पता नहीं चल सकता है कि वे हैक किए गए थे या नहीं।

यह किसने किया?

- संघीय जांचकर्ताओं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की विदेश खुफिया सेवा, जिसे एसवीआर के रूप में जाना जाता है, संभवतः हमले के लिए जिम्मेदार है।

- 2014 और 2015 में व्हाइट हाउस, विदेश विभाग और संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ में ईमेल सर्वर में सेंध लगाने के लिए रूसी खुफिया को भी श्रेय दिया गया था।
- बाद में, उसी समूह ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति अभियान के सदस्यों पर हमला किया।
- रूस ने उल्लंघन के साथ किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है और राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबूत के बिना, सुझाव दिया है कि चीनी हैकर्स अपराधी हो सकते हैं।

यह क्यों मायने रखता है?

- अब जबकि कई हैकर्स नेटवर्क में घुस चुके हैं, यह महंगा है और सिस्टम को सुरक्षित करना बहुत मुश्किल है।
- ऐसी आशंकाएं हैं कि सरकारी नेटवर्क तक पहुंच के साथ, हैकर्स डेटा को नष्ट या बदल सकते हैं, और वैध लोगों को प्रतिरूपित कर सकते हैं।
- हालिया मेमोरी में यह न केवल सबसे बड़ा उल्लंघन है, बल्कि यह संघीय साइबर सुरक्षा प्रयासों के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में भी है।
- अमेरिकी साइबर कमांड, जिसे फंडिंग में अरबों डॉलर मिलते हैं और अमेरिकी नेटवर्क की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है, उसे इस हमले के द्वारा "अंधा कर दिया गया" था। इस प्रकार, हैक साइबर सुरक्षा उपकरण में व्यापक बदलावों में तेजी ला सकता है।
- अमेरिकी सरकार साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से स्वतंत्र करके अपने साइबर सुरक्षा प्रयासों को पुनर्गठित कर सकती है।
- कंपनियां यह मानने के एक नए तरीके की ओर रुख कर रही हैं कि पहले से ही उल्लंघनों के बजाय हमलों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय वे पाए जाते हैं।

कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी (Cabinet Approves Export of Akash Missile System)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III- ट्रेड; रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी।
- आत्म निर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफार्मों और मिसाइलों के निर्माण की अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Key takeaways)

- आकाश 96% से अधिक स्वदेशीकरण के साथ देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है।
- आकाश 25 किलोमीटर की दूरी के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।

- इस मिसाइल को 2014 में IAF और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था
- निर्यात में तेजी से मंजूरी के लिए एक समिति बनाई गयी है।
- यह समिति विभिन्न देशों को प्रमुख स्वदेशी प्लेटफार्मों के बाद के निर्यात को अधिकृत करेगी।
- समिति सरकार-से-सरकार मार्ग सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का भी पता लगाएगी।
- भारत सरकार ने 5 बिलियन अमरीकी डालर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया है।
- आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा।

विविध (MISCELLANEOUS)

समाचार में	विवरण
1. चक्रवात बुरेवी (Cyclone Burevi)	- हाल ही में, बंगाल के दक्षिणपश्चिमी खाड़ी पर गहन गर्त (Deep Depression) के कारण चक्रवात बुरेवी तेज हो गया। - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की है कि बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात का प्रकोप है, इस चक्रवात से तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करने की संभावना है, एक सप्ताह से भी कम समय पहले चक्रवात निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था। - यह चक्रवात 2 दिसंबर को श्रीलंका के तट को पार करेगा और तमिलनाडु और केरल पर भारी बारिश ला सकता है।
2. आदि महोत्सव (Aadi Mahotsav)	- केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ किया जायेगा। यह महोत्सव वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जायेगा। - यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) की संयुक्त पहल है। - आदि महोत्सव पहल को 2017 में शुरू किया गया था। - यह त्योहार पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। - यह देश भर में आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प, संस्कृति से लोगों को परिचित कराने का प्रयास है। - आदि महोत्सव का आभासी संस्करण- मध्य प्रदेश हाल ही में लॉन्च किया गया था।
3. रामायण क्रूज टूर (Ramayan Cruise Tour)	- अयोध्या में सरयू नदी पर 'रामायण क्रूज टूर' (Ramayan Cruise Tour) शुरू करने की घोषणा की। मंत्रालय: बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जलमार्ग - सरयू एक नदी है, जो उत्तराखंड से निकलती है। - यह भारत में उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। - यह शारदा नदी की एक सहायक नदी है।
4. कावन (Kaavan)	सार्वजनिक आक्रोश और अभियान के वर्षों के बाद कई सालों से अकेलेपन से जूझ रहे , कावन हाथी के अच्छे दिन आ गए हैं। वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से निकलकर कंबोडिया की एक सैंक्चुरी में पहुंच गया है।

	● एक पाकिस्तानी चिड़ियाघर में सालों तक अकेले रहने के बाद कावन को "दुनिया का सबसे अकेला हाथी" कहा जाता है।
5. बीएनटी 162 बी 2 (BNT162b2)	● 'फाइजर और बायोएनटेक बीएनटी 162 बी 2 को कोविड -19 वैक्सीन के उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया। ● इसे अगले सप्ताह की शुरुआत से रोल आउट किया जाएगा। ● ब्रिटिश नियामक मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (एमएचआरए) ने घोषणा की कि टीका 95% तक की सुरक्षा प्रदान करता है और कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना सुरक्षित है। ● अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज फाइजर और इसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने पिछले महीने सभी प्राथमिक प्रभावकारिता समापन बिंदुओं को पूरा करते हुए अपने mRNA आधारित कोविड -19 वैक्सीन BNT162b2 के चरण 3 का परीक्षण किया। ● यह एक आरएनए वैक्सीन है जो न्यूक्लियोसाइड-संशोधित एमआरएनए से बना है, जो कि एसएआरएस-सीओवी -2 के स्पाइक प्रोटीन का एक उत्परिवर्तित रूप है, और लिपिड नैनोपार्टिकल्स से लिप्त है।
6. आरसीबो टेलिस्कोप (Arecibo Telescope)	● प्यूर्टो रिको में बड़े पैमाने पर निर्मित अरेसिबो टेलीस्कोप, जो हाल ही में खगोल विज्ञान के लिए अपने शानदार योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ● यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल-डिश रेडियो टेलीस्कोप है। ● आरसीबो को पहली बार 1963 में बनाया गया था। ● स्वामित्व : यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ● यह ग्रहों, क्षुद्रग्रहों और आयनमंडल का निरीक्षण करने के लिए नियोजित किया गया था। ● इसने दूर की आकाशगंगाओं, पहले एक्सोप्लैनेट्स, और पहले मिलीसेकंड पल्सर में प्रीबायोटिक अणुओं को खोजा था। ● 1967 में, आरसीबो यह पता लगाने में सक्षम थे कि बुध ग्रह 59 दिनों में घूमता है, न कि 88 दिनों में जैसा कि पूर्व से सोचा गया था। ● 1993 में, वैज्ञानिकों रसेल हुलसे और जोसेफ टेलर को बाइनरी पल्सर के अध्ययन में वेधशाला पर उनके काम के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को एक परीक्षण प्रदान करता है और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व के लिए पहला साक्ष्य प्रदान करता है।
7. ऑपरेशन ट्राइडेंट (Operation Trident)	● हर साल, भारत 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट (Operation Trident) की सफलता को मनाने के लिए इसे नौसेना दिवस के रूप में मनाता है। ● यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण आक्रमण था, जब भारतीय

	नौसेना ने कराची बंदरगाह में पाकिस्तानी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया था। ● 4 दिसंबर को, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची के पास तीन जहाजों को डूबो दिया। ● इस मिशन की सोवियत ओसा मिसाइल नौकाएं, को हाल ही में अधिग्रहीत किया है, जो 4 एसएस-एन -2 (पी -15) स्टाइलएक्स मिसाइलों से सुसज्जित थीं।
8. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक बताई गई है (Mount Everest reported to be 86cm higher)	● नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर प्रमाणित किया – यह 1954 में मान्यता प्राप्त ऊंचाई से 86 सेमी अधिक है। ● पूर्व में इसकी ऊंचाई 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें थियोडोलाइट्स और चेन जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया था। ● अप्रैल 2015 के विनाशकारी भूकंप ने वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी कि क्या इससे पहाड़ की ऊंचाई प्रभावित हुई है। ● माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हिमालय की महालंगुर हिमालय उप-श्रेणी में स्थित है।
9. ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 (Global Teacher Prize 2020)	● महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है। ● परितेवाडी गाँव के रंजीतसिंह डिसाले को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोडित पाठ्यपुस्तक क्रांति शुरू करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ● उन्होंने घोषणा की है कि वह एक मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा अन्य नौ फाइनलिस्टों के साथ साझा करेंगे ताकि वे भी अपना अच्छा काम जारी रख सकें। ● यह पुरस्कार लंदन स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे यूनेस्को के साथ साझेदारी में दिया गया था। ● अतीत में, डिसाले को वर्ष 2016 के अभिनव शोधकर्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सत्य नडेला की पुस्तक 'हिट रिक्रेश' में छपा था।
10. को-विन (CO-WIN)	● भारत सरकार ने COVID-19 वैक्सीन वितरण के लिए 'CO-WIN' नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। ● इसी नाम से एक नया मोबाइल ऐप भी होगा जो लोगों को वैक्सीन के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देगा। ● को-विन ऐप को जल्द ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की उम्मीद है।

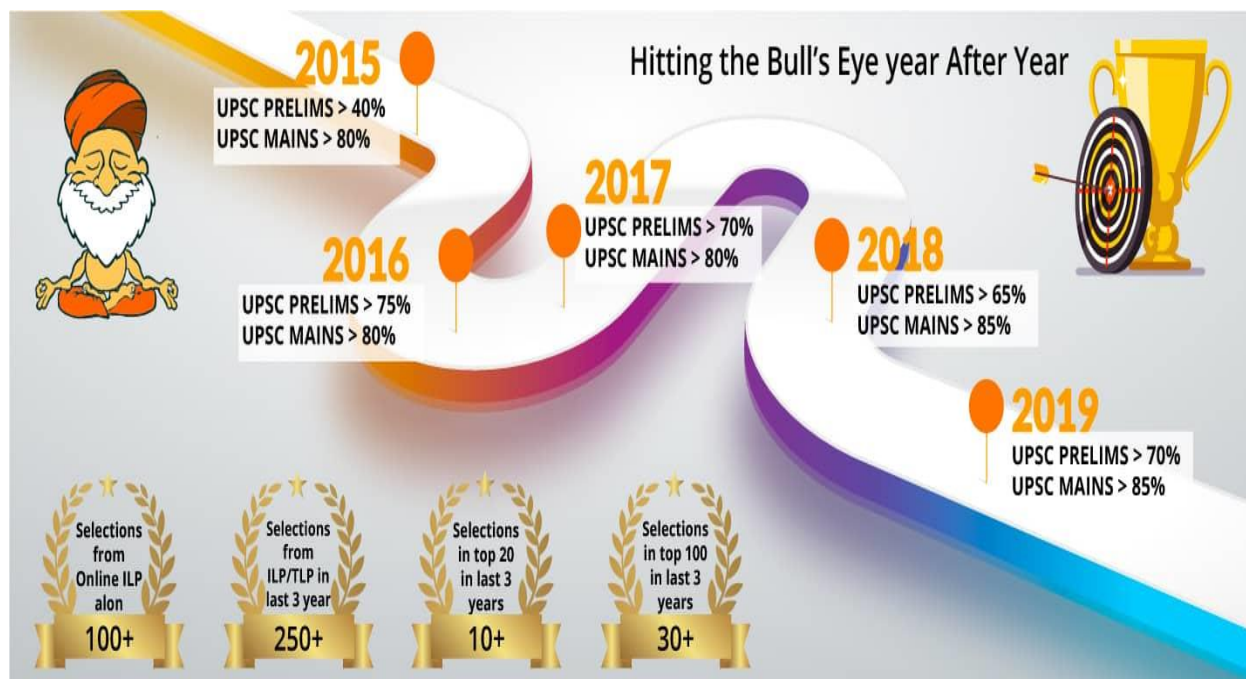
	● प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैक्सीन डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा और हेल्थकेयर वर्कर्स का एक डेटाबेस भी तैयार करेगा। ● टीके के वितरण के लिए आवश्यक सभी COVID-19 संबंधित डेटा वर्तमान में CO-WIN प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जा रहे हैं। ● ऐप में व्यवस्थापक, पंजीकरण, टीकाकरण, लाभार्थी पावती और रिपोर्ट के लिए अलग-अलग मॉड्यूल होंगे। ● एक बार जब लोग ऐप के लिए पंजीकरण करना शुरू करते हैं, तो प्लेटफॉर्म स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सह-रुग्णता पर बल्क डेटा अपलोड करेगा।
11. मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day)	● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ● यह हर साल 10 दिसंबर को यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स (यूडीएचआर) को मनाने के लिए मनाया जाता है। ● उन्होंने घोषणा की है कि अंतर्निहित गरिमा और मानव जाति के समान और अयोग्य अधिकार दुनिया में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की नींव हैं। ● 2020 का विषय : Recover Better - Stand Up for Human Rights.
12. भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	● 12 अक्टूबर, 1993 को अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ● एनएचआरसी संसद द्वारा पारित मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण के अनुसार एक सलाहकारी निकाय है।
13. रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए यूनेस्को पुरस्कार (UNESCO Award For Creative Economy)	● यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर 'रचनात्मक अर्थव्यवस्था' के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। ● यह नवंबर 2021 से शुरू होगा। ● युवाओं को वैश्विक आर्थिक पहल के लिए 50,000 \$ का पुरस्कार दो साल में एक बार दिया जाएगा। ● यह पुरस्कार रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा की गई असाधारण पहलों को मान्यता देगा। ● यूनेस्को ने 2021 को 'सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है।
14. शेख मुजीबुर रहमान (Sheikh Mujibur Rahman)	● वह एक बांग्लादेशी राजनेता थे। ● उन्हें बांग्लादेश में "राष्ट्रपिता" कहा जाता है। ● उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में 1971 - 1975 तक बांग्लादेश के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।

	● 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी। ● उन्हें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता है। ● वह बांग्लादेश के लोगों द्वारा "बंगबंधु" के शीर्षक से लोकप्रिय है।
15. जेमिनिड मीटियोर शॉवर यानी उल्कापात (Geminids Meteor Shower)	● जेमिनिड मीटियोर शॉवर यानी उल्कापात हाल ही में खबरों में था। ● यह इस वर्ष का सबसे प्रबल उल्कापात माना जाता है जो 4 दिसंबर -20 दिसंबर से सक्रिय है। ● यह उल्कापात वर्षा अद्वितीय हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति धूमकेतु में नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि यह एक क्षुद्रग्रह या विलुप्त धूमकेतु है। ● जेमिनिड मीटियोर शॉवर 3200 फेथॉन से निकलते हैं, जिसे उल्का वैज्ञानिक एक क्षुद्रग्रह मानते हैं। ● उल्काएं, चट्टान और बर्फ के टुकड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति धूमकेतु से होती है क्योंकि वे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में फैले होते हैं। ● जब कोई उल्का पृथ्वी पर पहुंचता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है और उल्कापिंडों की एक श्रृंखला काजब एक बार सामना होती है, तो उसे उल्का बौछार कहा जाता है।
15. हिमगिरि (Himgiri)	● हिमगिरि 'कोलकाता के मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में बनाए जा रहे तीन प्रोजेक्ट 17 ए जहाजों में से पहला है। ● इसे 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। ● प्रोजेक्ट 17 ए कार्यक्रम के तहत, कुल सात जहाज उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत स्वदेशी हथियार और सेंसर के साथ-साथ कई अन्य सुधारों के साथ बनाए जा रहे हैं। ● P17A जहाज जीआरएसई में निर्मित पहला गैस टरबाइन प्रणोदन और अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू प्लेटफार्म है।
16. विजय दिवस (Vijay Diwas)	● भारत ने 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जीत को चिह्नित करने के लिए हाल ही में (16 दिसंबर) विजय दिवस मनाया। ● दिसंबर 1971 में, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान सेना पर एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप एक राष्ट्र-बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इसके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ।
17. शीत अयनांत (Winter Solstice)	● 21 दिसंबर को शीत अयनांत था, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन था। ● दक्षिणी गोलार्ध में, इसके विपरीत, 21 दिसंबर को ग्रीष्मकालीन संक्रांति था, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन था। ● पृथ्वी अपनी धुरी लंबवत से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है।

	● यह झुकाव, पृथ्वी के परिभ्रमण और कक्षा में सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता को प्रदर्शित करता है जो ग्रह पर किसी भी स्थान को वर्ष के विभिन्न दिनों में प्राप्त होता है। ● शीत अयनांत या हिमाल संक्रांति या हाइबरनल संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य से अधिकतम झुकाव होता है। ● यह वर्ष में दो बार होता है, एक बार प्रत्येक गोलार्द्ध (उत्तरी और दक्षिणी) में। ● इसका विपरीत ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति (Summer Solstice) होती है।
18. गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब (Gurudwara Rakab Ganj Sahib)	● भारतीय प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब का दौरा किया जहां पवित्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के नश्वर अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। ● यह संसद भवन, नई दिल्ली के पास स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ● यह 1783 में बनाया गया था, सिख सैन्य नेता बघेल सिंह धालीवाल (1730-1802) ने 11 मार्च 1783 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ● यह नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के दाह संस्कार के स्थल को चिह्नित करता है।
19. 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार ('Legion Of Merit' Award)	● अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया। ● श्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट के सर्वोच्च डिग्री चीफ कमांडर के साथ प्रस्तुत किया गया था जो केवल राज्य या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। ● अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी मेरिट ऑफ लीजन भेंट की।
20. शाहीन-IX (Shaheen-IX)	● शाहीन-IX चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास है। ● चीन ने पाकिस्तान की वायु सेना के साथ एक नियमित व्यवस्था के रूप में "शाहीन-IX" अभ्यास किया, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के प्रति यह एक बड़ा रणनीतिक कदम है। ● यह भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। ● भारत ने हाल ही में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार 2020 के नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की, जिसे चीन के राज्य मीडिया ने चीन को कोने-कोने में ले जाने के एक अयोग्य प्रयास के रूप में करार दिया।
21. अब्दुल रहीम खान-ए-खाना (Abdul Rahim Khan-I-Khana)	● रहीम खान की कब्र को बहाली के छह साल बाद जनता के लिए खोला गया था - शायद भारत में राष्ट्रीय महत्व के किसी भी स्मारक के लिए सबसे बड़ी संरक्षण परियोजना है। ● अब्दुल रहीम खान-ए-खाना (1556 - 1627), जिसे बस रहीम के नाम से जाना जाता है, एक कवि थे, जो मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में निवास करते थे। ● अब्दुल रहीम, अकबर के भरोसेमंद संरक्षक और बैरम खान के बेटे थे।

	● वह अकबर के दरबार में नौ महत्वपूर्ण मंत्रियों (दीवान) में से एक थे, जिन्हें नवरत्नों के रूप में भी जाना जाता है। ● रहीम अपने हिंदी दोहे (दोहे) और ज्योतिष पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। ● रहीम ने बाबर के संस्मरण, बाबरनामा का छगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। ● संस्कृत में, उन्होंने ज्योतिष पर दो पुस्तकें लिखीं, खेततुकुटम और द्वात्रिंशयोगावली।
22. अब्दुल रहीम खान-ए-खाना का मकबरा (Tomb of Abdul Rahim Khan-I-Khana.)	● उनका मकबरा नई दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के पास स्थित है। ● इसे उनके द्वारा उनकी पत्नी के लिए 1598 में बनाया गया था, और उनके शरीर को 1627 में यहाँ रखा गया था। ● यह एक महिला के लिए बनाया गया पहला मुगल मकबरा था।
23. भारत का नौसैनिक जहाज, वियतनाम ने युद्ध अभ्यास के लिए इसे रोक लिया (Navies of India, Vietnam to hold passage exercise.)	● भारतीय नौसेना के जहाज INS Kiltan, जो गुरुवार को मिशन सागर- III के तहत राहत सामग्री देने के लिए वियतनाम पहुंचे, दक्षिण चीन सागर (SCS) में इस सप्ताह के अंत में वियतनामी नौसेना के साथ एक पैशन एक्सरसाइज (PASSEX) आयोजित करेंगे। ● INS Kiltan बंदरगाह न्हा रोंग पर पहुंचा और राष्ट्रीय आपदा रोकथाम और नियंत्रण के लिए वियतनाम की केंद्रीय संचालन समिति को 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री वितरित करेंगे। ● वर्तमान यात्रा दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करती है। ● यह दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन को और बढ़ाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देगा।
24. भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF) - 2020 का समापन हुआ (India International Science Festival (IISF)-2020 concluded.)	● भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF-2020) का 6 वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। ● IISF एक वार्षिक आयोजन है। ● संयुक्त रूप से आयोजित: भारत सरकार और विज्ञान भारती के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालय और विभाग द्वारा। ● पहला और दूसरा IISF नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में और पांचवा IISF कोलकाता में आयोजित किया गया है। ● यह भारत और विदेशों के छात्रों, नवोन्मेषकों, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट के साथ भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का जश्न मनाने का त्योहार है। ● IISF-2020 आभासी मंच पर आयोजित किया गया था। ● थीम: 'विज्ञान के लिए आत्मानिभर भारत और वैश्विक कल्याण'।

25. थोउबल बहुउद्देशीय परियोजना (Thoubal Multipurpose Project)	थोउबल बहुउद्देशीय परियोजना को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इंफाल में शुरू किया गया था।
26. थर्मोपॉलियम (Thermopolium)	- शोधकर्ताओं ने रोमन साम्राज्य के पोम्पेई शहर में एक थर्मोपॉलियम (गर्म पेय काउंटर के लिए लैटिन शब्द) का खुलासा किया है। - यह एक नेरीड की छवि के साथ एक समुद्री-घोड़े, सजावटी अभी भी जीवन भित्तिचित्रों, खाद्य अवशेषों, जानवरों की हड्डियों और पीड़ितों की सवारी के साथ पूर्ण पाया गया जो 79 ई के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मारे गए थे। - यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर के निवासियों द्वारा खपत किए गए भोजन की विविधता को दर्शाता है - स्टाल के कंटेनरों में सूअर का मांस, मछली, घोंघे और गोमांस के निशान पाए गए हैं। - यह पहली बार है जब एक पूरे थर्मोपॉलियम की खुदाई की गई है, पित्तरो या कांस्य पीने के कटोरे के साथ पूरा, सिरेमिक स्टार्स खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सूप, वाइन फ्लास्क आदि भी प्राप्त हुए हैं।



अपने ज्ञान का परीक्षण करें (TEST YOUR KNOWLEDGE)

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक - प्लस के संवाद भागीदार हैं?

1. ऑस्ट्रेलिया
2. जापान
3. भारत
4. यूएसए
5. दक्षिण अफ्रीका

सही कोड का चयन करें:

- a) केवल 1, 2, 3 और 4
- b) केवल 2, 3 और 5
- c) केवल 1 और 2
- d) केवल 2 और 4

Q.2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- a) मध्य प्रदेश
- b) राजस्थान
- c) उत्तराखंड
- d) उत्तर प्रदेश

Q.3 निम्नलिखित में से कौन बाघ श्रेणीका देश(tiger range country) नहीं है?

- a) भारत
- b) बांग्लादेश
- c) भूटान
- d) पाकिस्तान

Q.4 पहला हनी किसान निर्माता संगठन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत किया गया है?

- a) बिहार
- b) मध्य प्रदेश
- c) राजस्थान
- d) पश्चिम बंगाल

Q.5 साधारण ईंधन का उपयोग उन मशीनों में नहीं किया जा सकता है जो निम्नलिखित कारणों से अंतरिक्ष में काम करती हैं:

1. अंतरिक्ष में कम तापमान का सामना करना पड़ा।
 2. दहन का समर्थन करने वाले वातावरण की अनुपस्थिति।
- उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.6 zebrafish के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बड़ी ताजे पानी की मछली है।
2. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
3. यह वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3

- c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Q.7 सरयू नदी का भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य उद्भव होता है?

- a) उत्तराखंड
b) उत्तर प्रदेश
c) महाराष्ट्र
d) मध्यप्रदेश

Q.8 पांगोंग त्सो झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्थल-रुद्ध झील है।
2. यह ताजे पानी की झील है।
3. यह सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र का एक हिस्सा है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 1 और 3

Q.9 उच्च प्रभाव के लिए उच्च बोझ (Implementation of the High Burden to High Impact -HBHI) पहल का कार्यान्वयन निम्नलिखित राज्यों में से किस में शुरू किया गया है:

1. पश्चिम बंगाल
2. झारखंड
3. छत्तीसगढ़
4. उत्तर प्रदेश

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 4
d) केवल 4

Q.10 अंतर-अनुशासनात्मक साइबर-भौतिक प्रणालियों (NM-ICPS) पर राष्ट्रीय मिशन के निम्नलिखित केंद्रित क्षेत्रों पर विचार करें:

1. प्रौद्योगिकी विकास
2. एचआरडी और कौशल विकास
3. नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकास
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

सही कोड का चयन करें:

- a) केवल 1 और 4
b) केवल 1, 2 और 4
c) 1, 2 3 और 4
d) केवल 2 और 3

Q.11 भारतीय मोर सॉफ्ट-शेल कछुआ (Indian peacock softshell turtle) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. IUCN के रेड लिस्ट की इसकी स्थिति संकटग्रस्त है।
2. यह प्रजाति केवल भारत और बांग्लादेश तक ही सीमित है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (ASKAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आकाशगंगाओं और हाइड्रोजन गैस का अवलोकन करके ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है जिसमें वे शामिल हैं।
2. यह देखने के बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1

- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.13 भारत निम्नलिखित विशाल गिलहरी प्रजातियों में से किसका आवस है:

1. मलयायन विशालकाय गिलहरी
2. भारतीय विशालकाय गिलहरी
3. ग्रिजल्ड विशालकाय गिलहरी

सही कोड का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 1
- d) 1, 2 और 3

Q.14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
2. परमाणु विखंडन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिकों को एक साथ जोड़ दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 हाल ही में, IIT- बॉम्बे ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया। रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर जयपुर में सबसे अधिक है लेकिन पटना में यह सबसे कम है।
2. आर्थिक विकास मुंबई में सबसे अधिक और पटना में सबसे कम है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 हबलारा बस्टर्ड (houbara bustard) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IUCN में इसकी स्थिति संकटग्रस्त है।
2. एशियाई बस्टर्ड्स दक्षिण में पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप और पास के दक्षिण पश्चिम एशिया में शीतऋतु बिताने के लिए पलायन करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 हायाबुसा 2 जांच जिसमें हाल ही में क्षुद्रग्रह रयगु से नमूने वापस लाए गए थे, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था?

- a) जापान
- b) रूस
- c) भारत
- d) यूएसए

Q.18 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है:

- a) मंगल
- b) बृहस्पति
- c) शनि
- d) शुक्र

Q.19 भारत में पत्थर के रथ कहाँ स्थित हैं?

1. कर्नाटक
2. ओडिशा
3. तमिलनाडु
4. मध्य प्रदेश

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1 और 4
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

Q.20 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. करसोग कुलथ हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाने वाला एक फल है
2. पांगी की थंगी एक प्रकार का हेज़लनट है जो उत्तराखंड के पांगी घाटी में उगता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21 थारू जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश की मूल निवासी है?

1. उत्तराखंड
2. उत्तर प्रदेश
3. बिहार
4. झारखंड
5. छत्तीसगढ़

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 2, 3 और 5
- b) केवल 1 और 5
- c) केवल 1, 2 और 4
- d) केवल 1, 2 और 3

Q.22 निम्नलिखित का मिलान करें:

चिड़िया घर	स्थान
1. राजगीर चिड़ियाघर सफारी	A. चेन्नई
2. शहीद अशफ़ाक़ उल्लाह	B. भुवनेश्वर

खान प्राणी उद्यान	
3. नंदनकानन प्राणी उद्यान	C. गोरखपुर
4. अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान	D. नालंदा

सही कूट का चयन करें:

- a) 1-C;2-D;3-B;4-A
- b) 1-A;2-B;3-C;4-D
- c) 1-D;2-C;3-B;4-A
- d) 1-B;2-A;3-C;4-D

Q.23 वंचित इकाइयों समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS) योजना निम्न में से किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है?

- a) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- b) कृषि मंत्रालय
- c) वित्त मंत्रालय
- d) MSME मंत्रालय

Q.24 ग्वालियर और ओरछा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में जोड़ा गया था। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओरछा पर बुंदेला वंश का शासन था।
2. ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था।

उपरोक्त में से कौन सही है / सही है:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में पूरी तरह से जैविक घोषित की गई थी?

- a) लक्षद्वीप
- b) दादरा और नगर हवेली

- c) दिल्ली
d) दमन और दीव

Q.26 इस्चामुमंजनार्थनामी (Ischaemumjanarthanamii) नाम की भारतीय मुरेनग्रास की एक नई प्रजाति हाल ही में भारत के किस हॉटस्पॉट में देखी गई?

- a) पश्चिमी घाट
b) हिमालय
c) इंडो-बर्मा
d) सुन्दालैंड

Q.27 भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?

- a) केरल
b) गोवा
c) राजस्थान
d) उत्तराखंड

Q.28 निम्नलिखित में से कौन सा ADMM-PLUS का संवाद सहयोगी नहीं है?

- a) ऑस्ट्रेलिया
b) चीन
c) सिंगापुर
d) न्यूजीलैंड

Q.29 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र / महासागर मोरक्को के साथ सीमा बनाता है?

- a) अटलांटिक महासागर
b) भूमध्य सागर
c) कैस्पियन सागर
d) दोनों (a) और (b)

Q.30 निम्नलिखित में से किस अरब देश ने हाल ही में इजरायल के साथ सामान्य संबंध स्थापित किए हैं?

1. तुर्की

2. बहरीन
3. कतर
4. मोरक्को
5. सूडान
6. यूएई
सही कूट का चयन करें:
a) केवल 1, 2, 4 और 6
b) केवल 2 और 5
c) केवल 1, 2 और 3
d) केवल 2, 4, 5 और 6

Q.31 लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है?

- a) केरल
b) गोवा
c) तमिलनाडु
d) महाराष्ट्र

Q.32 वाज़चल रिजर्व फ़ॉरेस्ट (Vazhachal Reserve Forest) कहाँ स्थित है?

- a) केरल
b) तमिलनाडु
c) तेलंगाना
d) कर्नाटक

Q.33 एलुरु बीमारी, जिसे समाचार में देखा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई?

- a) तमिलनाडु
b) झारखंड
c) आंध्र प्रदेश
d) तेलंगाना

Q.34 प्लाज़मोडियम ओवले निम्न में से किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है?

- a) दक्षिण एशिया

- b) दक्षिण-पूर्व एशिया
- c) पश्चिमी अफ्रीका
- d) पूर्वी अफ्रीका

Q.35 हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2021 को 'सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है?

- a) यूनेस्को
- b) आईएमएफ
- c) डब्ल्यूटीओ
- d) ओईसीडी

Q.36 भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करने के लिए लैंसेट सिटीजन्स कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल गैर-संचारी रोगों को कवर करेगा।
2. इसका एक उद्देश्य सभी तक पहुंच है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.37 विजन 2035: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी?

- a) स्वास्थ्य मंत्रालय
- b) नीति आयोग
- c) विश्व स्वास्थ्य संगठन
- d) एम्स

Q.38 हिमालयन सीरो के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है।
2. "IUCN" में इसकी स्थिति संकटग्रस्त है।

उपरोक्त में से कौन सा / सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.39 रुपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?

- a) राजस्थान
- b) हिमाचल प्रदेश
- c) उत्तराखंड
- d) असम

Q.40 हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक, 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बहुत कम है।
2. भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 2018 की तुलना में 2019 में बढ़ी है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 मानव विकास सूचकांक, 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है?

- a) यूनेस्को
- b) यूएनडीपी
- c) WHO
- d) UNFCCC

Q.42 निम्नलिखित में से कौन सा देश करेंसी मैनिपुलेटर्स वाच लिस्ट (currency manipulator watch list) जारी करता है?

- a) यूएसए
- b) चीन

- c) रूस
- d) यूके

Q.43 प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसके लिए शुरू की गई है?

1. जम्मू और कश्मीर
2. पुदुचेरी
3. लद्दाख
4. दमन और दीव
5. दादरा और नगर हवेली

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 2 और 5
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) केवल 3 और 4

Q.44 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) निम्नलिखित में से किसकी वित्तीय उधार संस्था है?

- a) विश्व बैंक
- b) आईएमएफ
- c) ब्रिक्स
- d) WEF

Q.45 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT शहर) कहाँ स्थित है?

- a) दिल्ली
- b) गांधीनगर
- c) गुरुग्राम
- d) लखनऊ

Q.46 न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है?

- a) शंघाई
- b) जोहान्सबर्ग

- c) नई दिल्ली
- d) मास्को

Q.47 हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दूरसंचार उत्पादों और उनके स्रोतों को 'विश्वसनीय' और 'गैर-विश्वसनीय' श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करेगा।
2. इसकी अध्यक्षता उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करेंगे।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.48 भारत की निम्नलिखित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से कौन सी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं:

1. कुटियाड्रम
2. योग
3. नवरोज
4. कुंभ मेला
5. कथक नृत्य

सही कोड का चयन करें:

- a) केवल 1 और 5
- b) 2, 4 और 5 केवल
- c) केवल 1, 2, 3 और 4
- d) 2 और 4 ही

Q.49 भारत के हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रह CMS-01 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें आवृत्ति स्पेक्ट्रम होगा जो केवल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को कवर करेगा।
2. इसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.50 सेंटिनली निम्नलिखित में से किसकी मूल जनजाति हैं?

- a) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- b) लक्षद्वीप
- c) पश्चिमी घाट
- d) छत्तीसगढ़

Q.51 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से बांग्लादेश सीमा नहीं मिलती है?

- a) बिहार
- b) असम
- c) त्रिपुरा
- d) पश्चिम बंगाल

Q.52 हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने हाल ही में तीन स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) प्रणाली को थल सेना, नौसेना और वायु सेना को सौंपी। निम्नलिखित के बारे में विचार करें:

1. BOSS एक सभी मौसम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है।
2. IMSAS उच्च प्रदर्शन इंटेलीजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर प्रदान करता है

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 हाल ही में जारी किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पिछले साल से भारत की रैंक में काफी सुधार हुआ है।
2. दुनिया ने 2008 से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उल्लेखनीय गिरावट देखी है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब निम्नलिखित में से किस गुरु के अंतिम संस्कार का स्थल है?

- a) गुरु अमर दास
- b) गुरु अंगद देव
- c) गुरु तेग बहादुर
- d) गुरु गोविंद सिंह

Q.55 शीतकालीन अयनांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तब होता है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य पर न्यूनतम झुकाव होता है।
2. यह दोनों गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 शोला स्काई द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसका भाग है?

- a) पश्चिमी घाट
- b) पूर्वी घाट
- c) हिमालय

d) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Q.57 'मातृ सहयोगिनी समिति' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नियुक्त की जाएगी?

- a) मध्य प्रदेश
- b) उत्तर प्रदेश
- c) राजस्थान
- d) गुजरात

Q.58 गतका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गतका की उत्पत्ति राजस्थान राज्य से हुई है।
2. इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट दोनों के रूप में किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 थांग ता एक मार्शल आर्ट है, जो भारत के निम्नलिखित राज्य से सम्बंधित है?

- a) मणिपुर
- b) मिजोरम
- c) त्रिपुरा
- d) असम

Q.60 *Gastrodia agnicellus* एक नया खोजा गया ऑर्किड है जिसका नाम "दुनिया का सबसे बदसूरत ऑर्किड" है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है?

- a) यह मेडागास्कर के एक जंगल में पाया गया था
- b) यह कीट से भोजन प्राप्त करता है।
- c) इसमें कोई पत्ती नहीं होती है।

d) इसे एक संकट-निकट (Near Threatened) प्रजाति माना जाता है

Q.61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हिंद महासागर क्षेत्र के लिए नौसेना का सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है।
2. मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका को भारत के तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में एकीकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 WHO के 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में जारी किए गए थे:

1. हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है।
2. 2000 की तुलना में HIV/AIDS के मामले दस गुना बढ़ गए हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.63 अब्दुल रहीम खान-ए-खाना एक प्रसिद्ध कवि थे जो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे?

- a) अकबर
- b) शाहजहाँ
- c) हुमायूँ
- d) जहाँगीर

Q.64 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) निम्नलिखित में से किसकी उधार देने वाली शाखा है?

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- विश्व बैंक
- विश्व आर्थिक मंच
- आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन

Q.65 आयुष्मान भारत PM-JAY SEHAT को निम्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी निवासियों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा?

- गुजरात
- लद्दाख
- जम्मू और कश्मीर
- सिक्किम

Q.66 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह भारत में 40% लोगों के लिए मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है।
 - यह कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित है।
- उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?**

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.67 त्सो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हाल ही में भारत का 42 वां रामसर स्थल बना। यह कहा स्थित है?

- सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश
- कश्मीर
- लद्दाख

Q.68 ज़ोमी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय हैं?

- असम
- मिजोरम
- त्रिपुरा
- मणिपुर

Q.69 असम की सीमाएँ निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलती हैं?

- पश्चिम बंगाल
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- मेघालय

सही कूट का चयन करें:

- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3 केवल
- केवल 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4

Q.70 ई-सम्पदा, एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था?

- जल शक्ति मंत्रालय
- कृषि मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

Q.71 नामघर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- ये पारंपरिक वैष्णव मठ हैं।
- ये विशेष रूप से असम के मूल निवासी हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2

- c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.72 BBX11 जीन निम्नलिखित में से किसके लिए हाल ही में समाचार में था?

- a) यह पौधों की हरियाली में सुविधा प्रदान करता है।
b) यह जीन थेरेपी के माध्यम से ऑटोइम्यून बीमारियों के उपचार में मदद करेगा।
c) यह मक्का के पौधे में पहचाने जाने वाला एक हर्बिसाइड प्रतिरोधी जीन है।
d) इस जीन में कोविड -19 के नए उत्परिवर्तन की पहचान की गई थी।

Q.73 हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला संभव रेडियो संकेत पाया है। उसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. पहली बार ताऊ-बूट्स स्टार सिस्टम से खोजा गया था।
2. ताऊ-बूट्स एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमारे ग्रह से 51 प्रकाश वर्ष दूर है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.74 खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्वायत्त निकाय है।
2. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.75 पोर्टुलका लालजी, जंगली सूरज की एक नई प्रजाति हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई गई थी?

- a) पूर्वी घाट
b) पश्चिमी घाट
c) हिमालय
d) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Q.76 न्यूमोसिल जो हाल ही में समाचार में था, निम्नलिखित में से किसके लिए एक संयुग्म टीका है?

- a) लिवर कैंसर
b) कोरोनावायरस
c) निमोनिया
d) मलेरिया

Q.77 राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है?

- a) स्वास्थ्य मंत्रालय
b) रसायन और उर्वरक मंत्रालय
c) आयुष मंत्रालय
d) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Q.78 राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटीकार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह स्मार्टफोन को एक अंतर-परिवहन परिवहन कार्ड में बदल देगा जिसका उपयोग यात्री मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं।
2. कार्ड सेवा की शुरुआत सबसे पहले मुंबई में 2019 में हुई थी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.79 डिजिटल महासागर वेब आधारित ऐप हाल ही में शुरू किए गए इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ महासागर के बारे में ज्ञान साझा करने में मदद करेगा।
2. यह आम जनता और आम आदमी को सूचना तक मुफ्त पहुँच प्रदान करता है

उपरोक्त में से कौन सही है या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 80 निम्न में से कौन सूर्य के सबसे नजदीक का तारा तंत्र है?

- a) प्रॉक्सिमा सेंटॉरी
- b) अल्फा सेंटॉरी ए और बी
- c) बरनार्ड्स स्टार
- d) सीरियस ए और बी

Q.81 भारत के कौन से राज्य की सीमा भूटान से लगती है?

1. सिक्किम
2. पश्चिम बंगाल
3. असम
4. बिहार
5. अरुणाचल प्रदेश

सही कोड का चयन करें:

- a) केवल 1, 2, और 4
- b) केवल 1, और 5
- c) केवल 2, 3 और 5
- d) केवल 1, 2, 3 और 5

Q.82 PRAGATI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- a) यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है

b) PRAGATI प्लेटफॉर्म केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करता है।

c) मंच का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना है।

d) PRAGATI के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है

Q.83 निम्नलिखित में से कौन सा सागर तुर्की के उत्तर में है?

- a) लाल सागर
- b) काला सागर
- c) एजियन सागर
- d) मरमारा सागर

Q. 84 रूथेनियम -73 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दुर्लभ भारी धातु रूथेनियम का एक रेडियोधर्मी रूप है।
2. यह कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से आंख और त्वचा के ट्यूमर के लिए।

उपरोक्त में से कौन सही है या सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

दिसम्बर 2020 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	A	22	C	43	B	64	B
2	D	23	A	44	A	65	C
3	D	24	C	45	B	66	B
4	B	25	A	46	A	67	D
5	C	26	A	47	C	68	D
6	B	27	B	48	C	69	D
7	A	28	C	49	B	70	D
8	C	29	D	50	A	71	C
9	A	30	D	51	A	72	A
10	C	31	A	52	C	73	C
11	D	32	A	53	B	74	B
12	A	33	C	54	C	75	A
13	D	34	C	55	D	76	C
14	D	35	A	56	A	77	C
15	B	36	B	57	A	78	A
16	B	37	B	58	B	79	C
17	A	38	D	59	A	80	A
18	B	39	B	60	B	81	D
19	D	40	D	61	C	82	B
20	A	41	B	62	A	83	B
21	D	42	A	63	A	84	C



IASbaba
One Stop Destination for UPSC Preparation

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (AIPTS+) – 2021

BOTH in ENGLISH and Hindi (हिन्दी)

- ✓ **TOTAL NO. OF TESTS = 62 TESTS**
 - 52 General Studies (Paper 1) Tests
 - 10 CSAT (Paper 2) Tests.
- ✓ **ONLINE All India Prelims Test Series (AIPTS) - 2021 is available BOTH in ENGLISH and HINDI**
- ✓ **DETAILED SOLUTION & TECHNIQUES** to Decipher the Correct Answer (Elimination Technique)
- ✓ **With increasing IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS (CA)** in the exam, we have Current Affairs Test held every 15 days.
- ✓ All the Tests are **FLEXIBLE** and will be Valid till next Prelims Exam (2021)
- ✓ **ALL INDIA RANKING** - the scores and ranks will be displayed after every test.
- ✓ **DOUBTS RESOLUTION PAGE** - We have a comment section for every question in a Test.
- ✓ **DETAILED ASSESSMENT OF YOUR PERFORMANCE** - For you to analyse your performance we provide 2 tools Time Analytics and Subject-wise Analytics.

NEW!

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES+ (AIPTS+): ALL THE FEATURES OF AIPTS with Video Discussions of BOTH GS & CSAT TESTS

Register Now

